हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही
21 फरवरी, 2023
खण्ड–1, अंक–2
अधिकृत विवरण

विषय सूची
मंगलवार, 21 फरवरी, 2023

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

उडयान केयर, एन.जी.ओ., कुरुक्षेत्र के विद्यार्थियों एवं वरिष्ठ व्यक्ति का अभिनंदन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देना

शून्यकाल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना

श्री भव्य बिश्नाई, विधायक द्वारा माननीय सदस्यों को आज दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

राज्य में कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाले की जांच के लिए गठित एस.ई.टी. की रिपोर्ट की स्थिति के संबंध में

वॉक–आउट

बैठक का स्थगन

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक के विरूद्ध विशेषाधिकार के कथित हनन का प्रश्न उठाना

सदस्य को नामित करना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

सदस्य को नामित करना (पुनरारम्भ)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

आर.पी.एस. इंटरनैशनल स्कूल, करनाल के विद्यार्थियों तथा अध्यापकगण का स्वागत

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा की जाने वाली चर्चा के समय के वितरण के बारे में सूचना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की सूचना

हरियाणा विधान सभा
मंगलवार, 21 फरवरी, 2023

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

————————

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न–काल शुरू होता है।

चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वीकृत पद

***1. चौ. आफताब अहमदः** क्या चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान मंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) राज्य में सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है तथा रिक्त पड़े पदों की जिलेवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह तथ्य है कि शहीद हसन खान मेवाती चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों का विशेष मेवात भत्ता बंद कर दिया गया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; तथा

(ग) क्या उक्त भत्ते को आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार को विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

@स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) जी हां, विवरण इस प्रकार है: -

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	पीजीआईएमएस, रोहतक	5144	2385
2.	केसीजीएमसी, करनाल	944	459
3.	एसएचकेएमजीएमसी, नलहर	1062	670
4.	बीपीएस जीएमसी, सोनीपत	1019	473
5.	सबवी जीएमसी, फरीदाबाद	878	692

(ख) नहीं श्रीमान जी।

@ सहकारिता मंत्री (डॉ0 बनवारी लाल) द्वारा उपरोक्त प्रश्न का जवाब दिया गया।

(ग) हाँ महोदय, अभी तक यह भत्ता डॉक्टरों को दिया जा रहा था। अब यह भत्ता ग्रुप ए, बी, सी, डी के उन कर्मचारियों को देने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जो मेवात जिले के नहीं हैं।

श्री आफताब अहमद : सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह मैडीकल कॉलेज पहले से ही डॉक्टर्ज की कमी से बहुत बुरी तरह से जूझ रहा था और इसी वजह से वहां पर डॉक्टर्ज के लिए स्पैशल अलाऊंस का प्रॉविजन रखा गया था और वर्ष 2012 से डॉक्टर्ज और दूसरे स्टॉफ सदस्यों को यह स्पैशल अलाऊंस दिया जा रहा था लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले दो साल से उनको स्पैशल अलाऊंस देने के बारे में इस सरकार ने कोई फैसला नहीं किया जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब 15 फरवरी, 2022 को नूंह में बैठक लेने के लिए गए थे तब मैंने अपने दोनों विधायक साथियों के साथ मिलकर उस समय दो ही मांग इनके समक्ष रखी थी कि एक तो वहां पर रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जाये और दूसरी वहां के डॉक्टर्ज और दूसरे स्टॉफ को स्पेशल अलाऊंस दिया जाये। उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वे इसको करवायेंगे। अब फरवरी, 2023 आ गया है लेकिन अभी तक वहां पर रेडियोलॉजिस्ट तो कोई आया ही नहीं है उसकी तो कोई प्रक्रिया ही नहीं है लेकिन वहां पर जो स्पेशल अलाऊंस मिल रहा था उसके लिए भी सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। मैं समझता हूं कि अगर मुख्यमंत्री के लैवल पर भी इस प्रकार की कार्यशैली है तो यह चिंता का विषय है। यह मैडीकल कॉलेज बर्बाद तो कर ही दिया है। सरकार का 1000 करोड़ रूपये बर्बाद तो हो ही गया है क्योंकि अब उसमें इलाज नहीं होता न उसमें ऑपरेशन होते हैं क्योंकि ओ. टी. बंद है। उसमें कोई दवाई भी नहीं मिलती। वह हॉस्पिटल केवल मात्र रैफरल हॉस्पिटल बनकर रह गया है। सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जब मैडीकल कॉलेज बनाये जाते हैं तो उनसे आम जनता को इलाज की सुविधा मिलती है। हर रोज सरकार द्वारा यह घोषणा की जाती है कि मैडीकल कॉलेज सब जगह

बनाये जायेंगे लेकिन इस मामले में सरकार द्वारा बने बनाये मैडीकल कॉलेज को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। मैं दो बार वी.उमाशंकर जी से मिला क्योंकि वे उस बैठक में मौजूद थे। मैं उनको चिट्ठी देकर आया। हमेशा इस मामले को परश्यू करता हूं। सरकार अगर इस तरीके से कार्य करती है तो वह किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे इलाके से कोई द्वेष है? जो हमारा मैडीकल कॉलेज आम जनता की इतनी बड़ी सेवा कर रहा था उसको बंद कर दिया। सरकार ने इसमें कह दिया कि विचाराधीन है। अभी भी विचाराधीन है। इस समय भी सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगा कि अगर हमारे मैडीकल कॉलेज को चलाना सरकार के बस की बात नहीं है तो इसको बंद ही कर दिया जाये। मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमने यह बात उठाई थी उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की कार्यशैली मुख्यमंत्री जी के लैवल पर है तो फिर हम क्या कह सकते हैं। मेरा यह भी कहना है कि वह मैडीकल कॉलेज हमारी लाईफलाईन है इसलिए हम उसके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और उसके सुचारू संचालन के लिए आपसे कहते रहते हैं लेकिन अगर इस तरह का रवैया है तो फिर इस मैडीकल कॉलेज को चलाकर रखने का कोई फायदा नहीं है, बेहतर रहेगा कि इसको बंद ही कर दिया जाये।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष जी, जिस तरह से ये भत्ते की बात कर रहे हैं इससे पहले यह भत्ता सिर्फ डॉक्टर्ज को ही मिलता था बाकी स्टॉफ को नहीं मिलता था। अब हमने जो प्रपोजल भेजी है उसमें ए, बी, सी और डी सभी कैटेगरीज को यह भत्ता मिलेगा। पहले अण्डर ग्रेजुएट डॉक्टर्ज को 25 हजार रूपये और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्ज को 35 हजार रूपये प्रति माह के हिसाब से एक्स्ट्रा इंसैंटिव मिलता था लेकिन अब हमने बेसिक पे का 10 परसैंट और प्लस डी.ए. यह प्रॉविजन बनाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से फाईल को एप्रूव करवा लिया है। अब यह मामला एफ.डी.

के पास गया हुआ है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही यह काम हो जायेगा। दूसरी बात जहां तक स्टॉफ का सम्ब्ध है यहां पर स्टॉफ भर्ती करने के लिए हमने एच.पी. एस.सी. को भी केस भेजा हुआ है। उनके इंटरव्यूज भी हो गये हैं। हम कुछ असिसटैंट प्रोफैसर वगैरह लगा रहे हैं। हमने 187 असिसटैंट प्रोफसर की पोस्ट की रिक्वीजिशन भेजी हुई थी। अब 12 पोस्ट्स स्पैशिलियटीज की रिकमण्ड की हैं। इसी प्रकार से 21 पोस्ट्स असिसटैंट प्रोफसर्ज की रिकमण्ड की हैं। ये सभी पोस्टिंग होनी हैं। बाकी की जो 32 पोस्ट्स स्पैशियलिस्ट्स की हैं वे सिलैक्शन प्रोसीजर के अंदर चल रही हैं। जहां तक डॉक्टर्ज की कमी का सम्बन्ध है, डॉक्टर्ज की कमी तो पूरे प्रदेश में है। इसको पूरा करने के लिए हम स्टेट लैवल का एक कॉडर बना रहे हैं ताकि दूसरे मैडीकल कॉलेजिज से भी वहां पर स्टॉफ की नियुक्ति की जा सके।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि डॉक्टरों को तो भत्ता मिल रहा था लेकिन वह भी बंद कर दिया गया है। इस कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यह समस्या आई है। उससे पहले यह समस्या नहीं थी। डॉक्टरों का यह भत्ता बंद करने के कारण ही आज डॉक्टर्स वहां से नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ग्रुप–ए से लेकर ग्रुप–डी तक यह भत्ता देने की बात कह रहे हैं लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप पहले डॉक्टरों को तो भत्ता दे दीजिए।

डॉ. बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में किसी और डॉक्टर को यह भत्ता नहीं मिलता है। यह सिर्फ मेवात के डॉक्टर्स को मिलता है और यह सितम्बर, 2022 तक मिला भी है। अब हम ग्रुप–ए से ग्रुप–डी तक यह भत्ता देना चाह रहे हैं और सी.एम. साहब ने वह फाइल अप्रूव कर दी है और मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द यह भत्ता मिल जायेगा।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूं कि इस समस्या का हल निकाला जाये ताकि डॉक्टर्स वहां से नौकरी छोड़ कर न जायें और लोगों को असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी जिले में इस प्रकार का स्पेशल इनसैन्टिव दिया जाता है तो वह सिर्फ सरकार की प्राथमिकता होती है, वह किसी जिले का अधिकार नहीं होता है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि पहले यह भत्ता दिया जाता था और अब बंद कर दिया गया है। यह कोई अधिकार नहीं है कि हमेशा के लिए दिया ही जाता रहेगा। जब तक वहां की डिमांड को पूरा करने के लिए लोग आगे नहीं आते तब तक यह सुविधा दी जाती है ताकि लोगों को इनसैन्टिव मिले और लोग वहां जाने के लिए तैयार हो जायें। यह नूंह के लोगों के लिए नहीं है बल्कि नूंह से बाहर के कर्मचारियों के लिए है क्योंकि वहां पर कोई कर्मचारी जाना नहीं चाहता है। आज जब हम ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों से विकल्प मांगते हैं तो सभी नूंह से निकलना चाहते हैं इसलिए यह इनसैन्टिव दिया जाता है। अब विभाग का प्रस्ताव था कि डॉक्टर्स के अलावा दूसरे स्टाफ को भी यह इनसैन्टिव दिया जाये तो वह फाइल पर अप्रूव हो गया है और सितम्बर, 2022 के बाद का उसका एरियर भी दिया जायेगा। इसलिए माननीय सदस्य इसकी चिन्ता न करें।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, सी.एम. साहब ने इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया था इसीलिए इसकी गम्भीरता को समझते हुए ही मैंने यह प्रश्न लगाया है।

————————

औद्योगिक पार्क स्थापित करना

***2 डॉ. अभय सिंह यादवः** क्या उप–मुख्यमन्त्री कृपया बताएँगे किः–

(क) क्या नारनौल के पास लॉजिस्टिक हब के साथ एक औद्योगिक पार्क स्थापित करना उपयुक्त नहीं है ताकि इस योजना का, डब्ल्यू.डी.एफ.सी के माध्यम से तीव्र रेलवे कनेक्टिविटी तथा तीन राष्ट्रीय राजमार्गों से कनेक्टिविटी का लाभ उठा सके,

(ख) क्या उपरोक्त क्षेत्र में एक औद्योगिक पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा

(ग) क्या उक्त उद्देश्य के लिए उपरोक्त क्षेत्र में जमीन खरीदने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala):

(a) Sir, it is advisable to set up an Industrial Park, alongwith the logistic hub, near Narnaul.

(b) Yes sir.

(c) HSIIDC is in the process of identifying suitable land for expansion of Integrated Multi-Modal Logistic Hub (IMLH) Project. The said process is at initial stage. If the Corporation succeeds in procurement of land for expansion of IMLH Project, then part land will be utilized for Industrial use as per the requirement.

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है और इन्होंने इस बात को भी माना है कि वहां पर लॉजिस्टिक हब के साथ इंडस्ट्रियल पार्क बनाना भी उचित है। इन्होंने यह भी कहा है कि लॉजिस्टिक हब की कुछ जमीन का एक्सपैन्शन चल रहा है और वह मिलने के बाद वह जमीन दे दी जायेगी। इस बारे में पहली बात तो यह है कि हमारा प्रांत 3–4 तरफ से नैशनल कैपिटल से जुड़ा हुआ है लेकिन एक ट्रेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में जुड़ा हुआ है जो काफी वर्षों से चला आ रहा है वह यह है कि सारी की सारी इंडस्ट्री का डिवल्पमैंट सिर्फ दिल्ली के आसपास के इलाकों में हो रहा है।

श्री अध्यक्षः अभय जी, आप स्पीच न दें, आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वहां जिन इलाकों में औद्योगिक विकास नहीं है उनके बारे में सरकार की विशेष योजना क्या है? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जमीन खरीदने की बात जब माननीय उप–मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू करें तो जमीन भी मिल जायेगी। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जमीन किसी जमींदार के लिए बहुत कीमती होती है क्योंकि जमींदार की जब जमीन जाती है तो वह चीज जाती है जिससे उसकी पीढ़ियां कमा कर खाती हैं। इसलिए जब जमींदार को उसकी जमीन से वंचित किया जाता है तो उसकी कीमत पर लोभ नहीं किया जाना चाहिए। खरीदी हुई जमीन कभी भी महंगी नहीं होती है। आज महंगी लग सकती है लेकिन आगे चल कर जब जमीनों के रेट बढ़ जाते हैं तो वह सस्ती भी लगेगी। मेरा आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर जमीन खरीदें और इसका एक्सपैन्शन करें क्योंकि वहां पर औद्योगिक विकास के बहुत चांसिज हैं। इससे 20 किलोमीटर दूर बहरोड़ और नीमराना में बहुत अधिक औद्योगिक विकास हुआ है जबकि वहां पर तो कुछ भी नहीं था। हमारे यहां तो नैशनल हाईवे और रेलवे का बहुत अच्छा नैटवर्क है इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाये ताकि उस इलाके में औद्योगिक विकास हो सके।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सारी डिवैल्पमैंट दिल्ली के आस पास होने की बात कही है उसको मैं डैफर करता हूं। हमारी सरकार के विजन के अन्दर जो डिवैल्पमैंट हुई है उसको हमने हरियाणा के प्रत्येक कोने में ले जाने का प्रयास किया है। हमारा खरखौदा जैसे कस्बे के अन्दर 900 एकड़ में मारूती सुजुकी स्थापित करके उस पूरे एरिया को विकसित करने का प्रयास है। एन.एस.आई.

डी.सी. के साथ जो ये लोजैस्टिक हब की प्रक्रिया शुरू हुई है। नांगल चौधरी जैसे रेतीले इलाके के अन्दर एक नया डिवैल्पमैंट कैसे हो उसका कदम था। हिसार एवियेशन हब होने के नाते से उस एरिया को एवियेशन से रिलेटिड नई इंडस्ट्री कैसे स्थापित करके दे उसके लिए कदम उठाए हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि उसको और डिवैल्प कैसे किया जाए? उसके लिए हमारी सरकार दो तरह के प्रयास कर रही है। माननीय सदस्य तो आई.ए.एस. ऑफिसर रहे हैं उस समय इक्वीजिशन चला करती थी। हमारी सरकार ने इक्वीजिशन प्रक्रिया की ओर नहीं देखा । हमारी सरकार ने जितने भी प्रोजैक्ट बनाए हैं और उनके लिए जो लैंड खरीदी है वह ई–भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदी है। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि नेशनल हाई–वे 152 डी भी और जो हमारा पुराना हाई–वे नारनौल से नांगल चौधरी तक बना हुआ है इन दोनों हाई–वेज पर हम 500–500 एकड़ की चार साईट्स ई–भूमि पोर्टल पर पुटअप कर देंगे। जहां पर भी माननीय सदस्य हमें 500 एकड़ जमीन कंसोलिडेट करके दे देंगे तो हम पहला इंडस्ट्रीयल टाउनशिप वहां पर बनाएंगे। उसके साथ–साथ जैसा इन्होंने कहा है कि किसान की पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन से जुड़ी हुई रहती है। इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार की लैंड पुलिंग पॉलिसी आ चुकी है। अगर किसान 500 एकड़ के अन्दर लैंड पुलिंग करके देना चाहे तो कोस्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको भी हम उस इंडस्ट्रीयल टाउनशिप के अन्दर हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि इससे विन–विन सिचवेशन इंडस्ट्रियल एरिया को डिवैल्प करने के लिए और किसान की जमीन में उनकी हिस्सेदारी जीवन भर बनी रहे ऐसा उदाहरण हरियाणा प्रदेश के इतिहास में कोई भी नहीं है लेकिन आज मौका है उसके लिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के अन्दर इंडस्ट्रीयल टाउनशिप चाहते हैं तो वे इस काम में लगकर सरकार का ज्यादा सहयोग करने का काम करें।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री जी ने हमें जो ऑफर दी है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं उनको आश्वासन देता हूं कि इसमें हमारी तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा। जहां तक विकास की बात है उसमें मैंने यह नहीं कहा कि सरकार ने दिल्ली के आस पास विकास किया है मैंने यह कहा है कि इंडस्ट्री का विकास दिल्ली के आस पास हो रहा है और कंसंट्रेशन उसमें हो रहा है लेकिन ज्यादा कंसंट्रेशन में जब ऑवर बर्डन होता है तो उससे दूसरी रिजल्टैंट प्रॉब्लम भी साथ आती है तो इसमें मेरा निवेदन है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें भी विशेष इंडस्ट्रियल इंसैंटिव देकर वहां इंडस्ट्री की ग्रोथ सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद।

————————————

घरों/प्लाटों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

***3. श्री असीम गोयल नन्न्योला :** क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृप्या बताएंगे कि क्या नगर निगम अम्बाला द्वारा घरों/प्लाटों की बिक्री तथा खरीद के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र समय पर जारी किए जा रहे हैं; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

@शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता): हां महोदय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने अपने ऑनलाइन नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल (i.e., www.ulbhryndc.org) के माध्यम से सभी प्रकार के बकायों की अदायगी उपरान्त नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने की एक ऑनलाइन प्रक्रिया बनाई हुई है और पोर्टल दर्शाये गये बकाया कर/फीस/चार्जिज की अदायगी उपरान्त नो ड्यूज सर्टिफिकेट स्वतः जारी हो जाता है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट को स्थानीय निकायों के प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह स्वतः जारी हो जाता है। इस प्रकार, कोई भी नागरिक जो नो ड्यूज

@ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) द्वारा उपरोक्त प्रश्न का जवाब दिया गया।

सर्टिफिकेट पोर्टल पर बकाया देय राशि का भुगतान करता है, तो उसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है, जो कि सरकार द्वारा संपत्ति के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए आवश्यक किया हुआ है। राजस्व विभाग का वेब-हेलरिस पोर्टल पूरी तरह से शहरी स्थानीय निकाय विभाग के नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है।

श्री असीम गोयल नन्योलाः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं अम्बाला शहर नगर निगम की बात करूं तो आज से पहले जब से हमारे जो भी ये आयुक्त महोदय हैं और जितने भी आयुक्त पहले रहे हैं उनके पास पुराने शहर की एक लिमिट बनी हुई थी उस नाते से एन.डी.सी. जारी हो जाती थी लेकिन आज के समय में यह स्थिति हो गई है कि एक भी एन.डी.सी. जारी नहीं हो रही है। उसका कारण यह बताते हैं कि हमारे पास उस शहर की लिमिट का कोई रिकॉर्ड न नगर निगम अम्बाला के पास है और न ही हैडऑफिस के पास है। यह अपने आप में इतना ज्वलंत और चिंतनीय मुद्दा है कि लगभग 25 से 30 हजार रजिस्ट्री ऑनर्स अपनी रजिस्ट्री को अपने प्लॉट को बेचने के लिए या डिवाईड करवाने के लिए दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं। विभाग यह कह देता है कि हमने तो प्रोपर्टी आई.डी. और एन.डी.सी. को पोर्टल पर डाल दिया है लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि विभाग ने प्रोपर्टी आई.डी. और एन.डी.सी. के पोर्टल को इक्ट्ठा जोड़ दिया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि सबसे पहले तो प्रोपर्टी आई.डी. और एन.डी.सी. का जो पोर्टल है, उसे अलग–अलग करने का काम किया जाये। जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन इससे जुड़ी 60 से 70 परसेंट दिक्कतें दूर हो जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां 3 से लेकर 5 महीने की समयावधि से ज्यादा कोई भी आयुक्त नहीं रूकता है और जो आते भी हैं वे अपना कानून साथ लेकर आते हैं। वे कह रहे हैं कि उनके पास कोई रिकार्ड नहीं है। मैंने नगर निगम के रिकार्ड से नक्शे की कापी निकलवाई है जिसके आधार पर नगर निगम, अंबाला शहर की एन.डी.सी. हो रही थी और नक्शे

में ये नम्बर बाकायदा तौर पर चढ़े हुए भी थे जबकि इस संदर्भ में जो रिप्लाई दिया गया है उसमें कहा गया है कि कोई रिकार्ड नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने नगर निगम से यह रिकार्ड निकलवाने का काम किया है। अत, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि सही गाइडलाइन्ज जारी करके, टाइम बाउंड मैनर में इस समस्या का हल किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं नगर निगम, अम्बाला शहर के बारे में बोल रहा हूँ । मैंने इस संदर्भ में आदरणीय कमल गुप्ता जी से मिल चुका हूँ और डायरेक्टोरेट में भी गया हूँ और डायरेक्टर साहब ने तो बड़े ही पोजीटिव तरीके से इसको टेक–अप करने का भी काम किया है लेकिन जब तक रिजल्ट सामने निकलकर नहीं आता है तब तक मैं समझता हूँ कि कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसकी वजह से लगभग 25 से 30 हजार रजिस्ट्री आनर्ज बहुत परेशान हैं। अगर आप चाहे तो नगर निगम में जाकर सर्वे भी करवा सकते हैं। आज जनता के अंदर एन.डी.सी. को लेकर त्राही–त्राही मची हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा पुनः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस विषय की गंभीरता को समझें और इसे टाइम बाउंड मैनर में खत्म कराने का काम करें।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, जहां तक चालू वित्त वर्ष 2022–23 का विषय है, के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि 1 अप्रैल, 2022 से लेकर 16 फरवरी, 2023 तक नगर निगम, अंबाला शहर में 3555 नो ड्यूज सर्टिफिकेट इशू हुए हैं। मैंने इस बारे में पहले भी बताया कि सारे सिस्टम को आटोमैटिक कर दिया गया है। अगर किसी का नो ड्यूज नहीं बनता है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत पोर्टल के माध्यम से नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिल जाता है।

श्री असीम गोयल नन्योलाः अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि जो नये आयुक्त महोदय आये हैं, उन्होंने कहा है कि वह इस सीमा को नहीं मानते हैं और इसलिए जो माननीय मंत्री जी ने भी सदन में नम्बर बताये हैं कि 3555 नो ड्यूज

सर्टिफिकेट इशू हुए हैं, ये सभी एन.डी.सी. पुराने आयुक्त महोदय के समय में जारी हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से इसीलिए मंत्री जी से निवेदन किया है कि एक बार माननीय मंत्री जी वस्तु स्थिति को जान लें। मेरे पास यह नक्शा है। मैं इस नक्शे को इनको सबमिट भी कर दूंगा। अभी जो नए आयुक्त महोदय आये हैं, उन्होंने एक ऐसा नया तुगलकी फरमान जारी कर दिया है, जिसकी वजह से जो हमारे जन प्रतिनिधि हैं चाहे एम.सी. हों या एम.एल.ए. हों सभी बहुत दुखी हैं। माननीय मंत्री जी ने जिन एन.डी.सी. की बात की हैं, ये सभी पिछले आयुक्त के समय जारी हुई थी। ।

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, यह समस्या पूरे हरियाणा की है। अतः मुझे भी इस पर बोलने की इजाजत दी जाये।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल यही बात है। यह समस्या आज सारे हरियाणा की समस्या बन गई है।

श्री अध्यक्षः पंवार साहब और किरण चौधरी जी माननीय सदस्य ने प्रश्न किया और माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया है। अगर इस परिपेक्ष्य में पूरे हरियाणा की चर्चा करने लग गए तो फिर सदन में केवल यही विषय ही डिस्कस होगा। पंवार जी आप सोनीपत की बात बतायेंगे तो दूसरा सदस्य पानीपत की बात बताने लग जायेगा और तीसरा सदस्या गुरूग्राम की बात बताने लग जायेगा। असीम गोयल जी ने प्रश्न किया था और माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया। अतः आप लोग प्लीज बैठिए। कुलदीप वत्स जी आप अपना प्रश्न पूछिए।

————————————

परिवार पहचान पत्र के लिए अनुचित सर्वेक्षण

***4. श्री कुलदीप वत्स :** क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः

(क) क्या यह तथ्य है कि न केवल बादली विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में अपितु पूरे राज्य में भी परिवार पहचान पत्र के लिए अनुचित सर्वेक्षण करवाने के कारण लाखों परिवार बी.पी.एल. राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड तथा पेंशन आदि सरकारी योजनाओं से वंचित हो गए।

(ख) यदि हां, तो उस ऐजेंसी का नाम क्या है जिसके द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया था जिसमें उपरोक्त भाग 'क' में वर्णित उक्त योजनाओं से पात्रध्योग्य परिवार वंचित हो गए।

(ग) क्या उक्त ऐजेंसी द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण उचित ढंग से किया गया है अथवा नहीं, तथा

(घ) क्या इस संबंध सरकार ने कोई संज्ञान लिया है;यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) नहीं श्री मान जी। सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार, 1.8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को पीले राशन कार्ड दिए गए। पंजीकरण के समय परिवार पहचान पत्र में परिवारों द्वारा प्रदान किए गए स्व-घोषित डेटा का सत्यापन करके, दिसंबर 2022 में 9,60,235 परिवारों के पीले राशन कार्ड बंद कर दिए गए थे।

पीपीपी डेटाबेस में स्व-घोषित आय का सत्यापन निम्नलिखित तरीकों से किया गया हैः

(क) पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) के आधार पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से,

(ख) हरियाणा सरकार, उसके बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों का डेटा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) से एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से,

(ग) सरकार में सेवा के लिए सरकार से पेंशन या मानदेय प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त सरकारी पेंशनरों का डेटा एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से,

(घ) राज्य सरकार, उसके बोर्डों और निगमों में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों का डेटा एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से,

(ङ) निजी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों को भुगतान की गई मजदूरी के आंकड़ों का एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से, जिसके संबंध में पंजाब उपकर अधिनियम के तहत एक उपकर देय है, जैसा कि हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है,

(च) ई-खरीद पर कृषि उपज की खरीद के लिए किसानों को किए गए भुगतान का एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से,

(छ) बिजली निगमों से प्राप्त वार्षिक बिजली खपत और उस आधार पर आय का अनुमान लगाने का एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से,

(ज) सरकारी कर्मचारी, एक स्थानीय कंप्यूटर ऑपरेटर, एक स्थानीय स्वयंसेवक, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक छात्र की टीम से मिलकर बने पांच सदस्यों वाली स्थानीय समितियों द्वारा आय सत्यापन के माध्यम से प्रत्येक सदस्य ने स्वतंत्र रूप से आय का आकलन किया है और अंतिम सत्यापित आय तर्क-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (**Artificial Intelligence**) पर आधारित होती है।

पीपीपी में दी गई आय के सत्यापन को और **exclusion** को परिवार नामित ऑनलाइन तंत्र, नामतः 'सुधार' और 'शिकायत' पोर्टल के माध्यम से चुनौती दे सकते हैं। प्रत्येक **exclusion** की चुनौती इलेक्ट्रॉनिक रूप से और स्वचालित रूप से ऑनलाइन सत्यापन के लिए उपयुक्त स्थान पर भेज दी जाती है। स्थानीय समिति द्वारा निर्धारित आय को चुनौती देने वाले अनुरोधों को समान संरचना वाली उच्च स्तरीय समितियों, जिन्हें सेक्टर समितियाँ कहा जाता है, को भेजा जाता है।

मई 2022 से पीपीपी में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर केवल 21,034 नागरिकों का वृद्धावस्था सम्मान एवं अन्य पेंशन संबंधित भत्ता रोका गया है।

ऐसा कोई मामला नहीं है जहां किसी परिवार के पास पहले आयुष्मान भारत कार्ड था और अब वह आयुष्मान भारत के लाभों से वंचित रह गया हो। पीपीपी में आय के सत्यापन के आधार पर निरस्तीकरण के लिए 4.43 लाख परिवारों की पहचान की गई है लेकिन ऐसे परिवारों का निरस्तीकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा।

(ख) कोई क्षेत्र सर्वेक्षण करने के लिए किसी एजेंसी को नियुक्त नहीं किया गया था।

(ग) भाग (ख) के दृष्टिगत प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है।

(घ) भाग (ख) के दृष्टिगत प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय कुलदीप वत्स जी ने परिवार पहचान पत्र के संदर्भ में प्रश्न किया है। इस प्रश्न के 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' चार भाग हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि 'क' भाग की बजाय पहले 'ख' 'ग' और 'घ' इन तीनों का उत्तर पहले दे दिया जाये। 'ख' भाग में पूछा गया गया है कि उस एजेंसी का नाम क्या है जिसके द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया था, जिसमें उपरोक्त भाग 'क' में वर्णित उक्त योजनाओं से पात्र/योग्य परिवार वंचित हो गए तो इस संदर्भ में मेरा कहना है कि हमने किसी एजेंसी से काम नहीं कराया है बल्कि यह पूरा काम सरकारी तंत्र के माध्यम से ही हुआ है इसलिए जब कोई एजेंसी से काम ही नहीं करवाया गया है तो 'ख' भाग का कोई औचित्य नहीं

रह जाता। इसके बाद 'ग' भाग है जिसमें वर्णित है कि क्या उक्त ऐजेंसी द्वारा जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण उचित ढंग से किया गया है अथवा नहीं, मैं समझता हूँ कि 'ख' भाग का उत्तर देने के बाद 'ग' भाग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसी प्रकार 'घ' भाग में वर्णित है कि क्या इस संबंध में सरकार ने कोई संज्ञान लिया है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है, 'ख' और 'ग' भाग का उत्तर देने के बाद 'घ' भाग का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है क्योंकि एजेंसी से यह काम कराया ही नहीं गया है। अब मैं प्रश्न के 'क' भाग पर आता हूँ। इसमें कहा गया है कि क्या यह तथ्य है कि न केवल बादली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में अपितु पूरे राज्य में भी परिवार पहचान पत्र के लिए अनुचित सर्वेक्षण करवाने के कारण लाखों परिवार बी.पी.एल. राशन कार्ड, आयुषमान कार्ड तथा पैंशन आदि सरकारी योजनओं सें वंचित हो गए हैं, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि हमारा जो परिवारों की पहचान करने वाला कार्यक्रम है, इसको लगभग दो साल पहले शुरू किया गया था। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पूरे देश में यह एक तरह से सरकार का यूनिक प्रयोग है। हमारे प्रदेश में बाहर देशों से जब कोई एम्बेसडर वगैरह आते हैं तो 'परिवार पहचान पत्र' में रूचि लेकर हमसे समझते हैं। अभी तक सारी दुनिया में एक व्यक्ति की पहचान आधार के नाते से होती है, जो हमारे देश में भी है और अमेरिका जैसे देशों में भी है। समाज में परिवार ही एक इकाई है। उसको पहचान करके चिन्हित किया गया और उसकी एक आईडैंटी बनाई गई। पहले हमने एच.आर.डी. (हरियाणा रैजीडैंस डाटा बेस) बनाया था लेकिन किन्ही कारणों से उसको छोड़कर उसके साथ आधार नं0 जोड़ा गया। अध्यक्ष महोदय, आधार का नम्बर हम किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती से नहीं पूछ सकते। हमारे पास जिन सेवाओं में आधार नम्बर हैं, उसका उपयोग करेंगे। जो व्यक्ति अपना आधार नहीं बताना चाहे, वे ना बताएं। हमने 'परिवार पहचान पत्र' बनाया और 'परिवार पहचान पत्र' के आधार पर आज लगभग 72 लाख परिवारों का डाटा हमारे पास है और उसमें 2 करोड़ 87 लाख

नागरिक हैं। यह बात ठीक है कि उसमें भी लगभग अढ़ाई–तीन परसेंट ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ डिक्लेयर करके डाटा दिया है लेकिन हम जो साईन परफॉर्मा भरवाते हैं कि वे उससे सहमत हैं, उसमें अभी तक लगभग 3 परसेंट लोग बाकी हैं। बहुत सारे लोग उसमें मिल भी नहीं रहे हैं। जिस समय 'परिवार पहचान पत्र' बनाया, हो सकता है कि कुछ माइग्रेटिड फैमिलिज हो और कुछ बाहर चली गई हों। उसको भी कम्पलीट करके डाटा को पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जिनका हमने डाटा कम्पलीट करवाया है उसके आधार पर जो बी.पी.एल. की व्याख्या है वो पहले 1 लाख 20 हजार रुपये के बाद एक्सक्लूड हो जाते थे। Speaker Sir, by exclusion, they were not BPL families. हमने उसको 1 लाख 80 हजार रुपये किया अर्थात् 10 हजार रुपये प्रति महीने के हिसाब से नहीं बल्कि 15 हजार रुपये प्रति महीने की आय हो तो वह बी.पी.एल. की श्रेणी में है, इसलिए उसमें संख्या बढ़ी है। संख्या बढ़ने के बाद बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनकी आय कम रही हो और बाद में आय बढ़ गई हो। बी.पी.एल. का पैमाना जो वर्ष 2011 से लगातार चलता आ रहा था जो अभी तक 'परिवार पहचान पत्र' बनने से पहले था। अध्यक्ष महोदय, सारे सर्वेक्षण में कुछ परिवार कट गये और कुछ नये बन गये। इस तरह से लगभग 9 लाख 60 हजार परिवार ऐसे थे, जिनको उस समय डिलिट किया और 12 लाख 46 हजार परिवार ऐसे थे जो नये जुड़े अर्थात् नेट एडिशन लगभग 3 लाख परिवार हमारी पहली वाली संख्या से बढ़ गये। अध्यक्ष महोदय, जो परिवार कट गये हैं, वो किन कारणों से कट गये हैं, उनकी जानकारी भी अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को दे देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, 1 लाख 32 हजार परिवार ऐसे निकले जो इंकम टैक्स रिटर्न भरते थे अर्थात् इंकम टैक्स रिटर्न भरने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से नीचे नहीं हो सकता। उनकी इंकम टैक्स की रिटर्न आज भी उपलब्ध है कि कौन कितना टैक्स भरता है। इस नाते से 1 लाख 32 हजार के नाम कटे हैं। आय निर्धारण के नाते से

हमने समितियां बनाई थी। जब इसका सर्वे किया, सर्वे के आधार पर कुछ पैरामीटर्ज बनाये गये हैं। हमारी ब्लॉक स्तर पर भी समितियां हैं और नीचे लोकल स्तर पर भी कमेटी भी बनाई हैं। उसमें दो सरकारी अधिकारी शामिल हैं। उसमें वहां के इलाके का एक सोशल वर्कर जो ध्यान में आता है उसको शामिल करते हैं। एक वहां का जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी का छात्र होता है उसको शामिल करते हैं। इस प्रकार से पांच लोगों की एक समिति बनाते हैं। उसके बाद सैक्टर समिति उसको वैरीफाई करती है। उसके आधार पर 3 लाख 44 हजार ऐसे आदमी निकले जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से ऊपर आंकी गई है, वे छोड़े गये हैं। जो निजी क्षेत्र के प्राईवेट कर्मचारी हैं, जिन्होंने कहा कि हम कर्मचारी हैं, इस प्रकार से 1 लाख 95 हजार परिवार निकले हैं। सरकारी अथवा कंट्रैक्च्यूअल कर्मचारी 51489 निकले हैं। इसी प्रकार से किसान की 'मेरी फसल–मेरा ब्यौरा' के तहत 4 लाख से ज्यादा सेल हुई हैं, उनको भी यह माना कि उनकी इंकम 1.80 लाख से ऊपर है। जो सरकारी पेंशन भोगी हैं उनकी संख्या 2119 है। अध्यक्ष महोदय, जिन परिवारों का वार्षिक डोमेस्टिक बिजली का बिल 9 हजार रुपये या इससे ऊपर आता है, उनको भी ऐसे ही माना गया है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हर एक व्यक्ति अपनी इंकम का 5 परसेंट पैसा अपने घर के बिजली बिल के खर्चे में देता है। यह मानना है कि इंकम का 5 परसेंट से नीचे का खर्चा बिजली के बिल में होता है लेकिन यह 5 परसेंट से ज्यादा नहीं होता है। इस नाते से यह भी मान लिया गया है। कुछ शिकायतें यह भी आई थी कि हमारी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये नहीं है। ऐसी 3.41 लाख शिकायतें प्राप्त हुई थी और उनमें से 1.77 लाख शिकायतें रिजॉल्व भी कर दी गईं हैं। यह मान लिया गया कि वास्तव में इनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से नीचे है और उनकी सभी सुविधाएं बहाल कर दी हैं । अभी भी 1.64 लाख ग्रिवैंसिज ऐसी हैं जिनका सर्वे होकर फैसला होना बाकी

है । इस प्रकार टोटल ग्रिवैंसिज के लगभग 50 परसैंट ग्रिवैंसिज का फैसला हो चुका है और 50 परसैंट ग्रिवैंसिज का फैसला होना अभी शेष है । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 50 परसैंट ग्रिवैंसिज जिनका अभी फैसला नहीं हुआ है उनका फैसला कब तक हो जाएगा ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने इस कार्य को जनवरी माह में शुरू किया था । मुझे लगता है कि यह कार्य महीने–भर में कम्पलीट हो सकता है । मैं बताना चाहता हूं कि जिनकी ग्रिवैंस ठीक पाई जाती है उनको जनवरी माह का भी पूरा राशन मिलता है क्योंकि इसे जनवरी में बंद किया गया था । हमने इस कार्य को जनवरी माह में शुरू किया था, इसलिए जिनकी ग्रिवैंस ठीक पाई जाती है उनको जनवरी, फरवरी और मार्च माह का भी पूरा राशन इकट्ठा मिलेगा । इसमें कोई समस्या नहीं है । इसमें कुछ तथ्य बड़े मजेदार हैं । मैं इन तथ्यों को सदन में बताना चाहता हूं । एक परिवार है 'लेबर एक्सक्लूजन', यह परिवार महेन्द्रगढ़ से है और परिवार पहचान पत्र में उसका नाम सुमेर सिंह है । उसने परिवार पहचान पत्र में लिखा है कि वह विप्रो में काम करता है और उसके पिताजी गवर्नमैंट इम्पलाई है । उनकी एक साल की कुल इंकम 19 लाख रुपये है । वह परिवार पहले पीले कार्ड का लाभ ले रहा था । इसी प्रकार से एक व्यक्ति हैल्थ डिपार्टमैंट में एक कांट्रैक्चूअल इम्पलाई है । उसकी भी हैल्थ डिपार्टमैंट से 7.66 लाख रुपये सालाना कमाई वैरीफाई हुई है जबकि उसकी सैल्फ डिक्लेयर्ड इंकम 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष थी । बहुत लोगों को पता नहीं होता कि इसका वैरीफिकेशन भी होता है । हमने लेबर बोर्ड और अन्य विभागों से इंकम वैरीफाई करने के बाद यह सारा कार्य किया है । इसमें गवर्नमैंट इम्पलाई भी है जिसकी सालाना इंकम 13.05 लाख रुपये थी। यह ठीक है कि उसने स्वयं भी अपनी सालाना इंकम 11.25 लाख रुपये डिक्लेयर की थी । वह भी पीले कार्ड का लाभ ले रहा था जोकि अब कट गया है । ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने यह मान लिया है कि हमारी

इंकम ज्यादा थी और उन्होंने सरकार के पास इसकी कोई शिकायत भी नहीं की । कुल 9 लाख में से केवल 3.75 लाख लोगों ने शिकायत की थी । इसके बारे में मैंने बताया है कि लगभग 1.64 लाख शिकायतों का फैसला होना अभी बाकी है । उनका हम सर्वे करवायेंगे और फिर उसको ठीक भी करेंगे । अतः इन सभी आधारों पर इस प्रयोग को चलाया जा रहा है । मेरा कहना है कि यह एक नया प्रयोग है । अतः मैं इसमें कोई ऐसा दावा नहीं करता कि इसमें गलतियां नहीं हुई होंगी । अगर कोई गलती हुई है तो उसको ठीक करना भी हमारा ही काम है । इनको ठीक करने के लिए ग्रिवैंसिज पोर्टल लगातार खुला रहेगा । पोर्टल एक बहुत जानदार चीज है जो समाज को लाभ पहुंचा रहा है । मेरा कहना है कि इस पोर्टल से किसी को भी नहीं घबराना चाहिए ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बहुत इम्पोर्टेन्ट इशू पर बोलना चाहती हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, यह प्रश्न माननीय सदस्य श्री कुलदीप वत्स का है, इसलिए पहले अनुपूरक प्रश्न वे पूछेंगे । अब माननीय सदस्य श्री कुलदीप वत्स अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

श्री कुलदीप वत्स : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़े विस्तार में लम्बी–चौड़ी बातें बताई हैं । मैं हर चीज को तो यह नहीं कह सकता कि ये सब चीजें गलत हैं । जिनकी पैंशन गलत बनी थी और अगर उनकी कटी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है । इस समय सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बैठे हैं और उनके अधिकारी भी बैठे हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 2–3 सुधार करने की बातें बताना चाहूंगा । जिन परिवारों की इंकम केवल 50 हजार रुपये है उनकी इंकम अधिकारियों ने 15 लाख रुपये दर्शाई हुई है । 15 लाख रुपये देने का जो एक जुमला था कहीं यह भी वैसी ही बात तो नहीं है । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमजन

की बात बताना चाहता हूं । मैं सदन में आज सारा डाटा लेकर आया हूं । जिन गरीब परिवारों की आंखों से आंसू बह रहे हैं और जिनकी रोते–बिलखते हुए वीडियोज वायरल हो रही हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। मेरे पास ऐसे लगभग 200–300 लोग प्रतिदिन आते हैं । जो वास्तव में गरीब लोग हैं और अगर उनकी पैंशन कटी है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनकी अवश्य जांच करवायें और दोबारा सर्वे करवायें । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो सी.एम. विण्डो शुरू की है उस पर डिस्ट्रिक्ट लैवल पर नीचे से ऊपर के अधिकारी पैसे लेकर काम करते हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस पर जरूर ध्यान दें । मेरे पास पैंशन से संबंधित कागजों का एक पूरा बण्डल है । मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसे चैक करवा लें कि क्या इनके साथ नाजायज हुआ है या नहीं । इन लोगों की संख्या लगभग 10 हजार है । ऐसे लोग हर हल्के में हैं । इसे सरकार मानें या न मानें यह उनकी मर्जी है । मैं इससे संबंधित सभी कागजात माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दे दूंगा । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ठीक है कुलदीप जी, अब आप बैठिये । आपका विषय सरकार के ध्यान में आ गया है । आप इस विषय से संबंधित सभी कागजात माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दे दें । (विघ्न)

श्री कुलदीप वत्स : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि –

नजर नहीं नजारों की बात करते हो,
जमीन पर चांद सितारों की बात करते हो ।
जिन्होंने गरीब की थाली से छीन ली रोटी,
वे भरी सभा में सुधार की बात करते हैं ।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात का उत्तर दे देता हूं। यह बात ठीक कही है और जैसा मैंने भी कहा है कि इसमें शिकायतें नहीं होंगी, ऐसा

मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। लेकिन हमने इसके लिए कई रास्ते खोले हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए एक ग्रिवैंस पोर्टल बना हुआ है, उसके लिए कॉल सैंटर भी है और टेलिफोन नम्बर भी दिये हुए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि हो सकता है उस पर कम्पलेनैंट का भरोसा न हो क्योंकि वह कहता है कि उसकी करैक्शन तुरंत ठीक होनी चाहिए। हमारे माननीय विधायक/जनप्रतिनिधियों का भी कहना है कि यह पोर्टल काम नहीं करेगा और फ्लां–फ्लां बातें होंगी। इसके लिए मेरा माननीय विधायकों के अलावा दूसरे पब्लिक रिप्रजेंटेटिव्ज से कहना है कि जिनके पास इस संबंध में लोग शिकायतें लेकर आते हैं, उसके लिए केवल एक कागज पर 2 चीजें लिखकर दे दें। इसमें एक तो संबंधित शिकायतकर्त्ता का परिवार पहचान पत्र और एक सिंगल वन सैंटेंस कम्पलेंट लिखकर दे दे कि उसकी फ्लां दिक्कत है। इतनी बात लिखकर हमारे ऑफिस में पहुंचवा दें या चाहे प्रिंसिपल सैक्रेटरी श्री वी. उमाशंकर जी के ऑफिस में पहुंचवा दें। चूंकि इस सारे कार्यक्रम को मैं और श्री वी. उमाशंकर जी मिलकर देख रहे हैं और डिपार्टमैंट कार्यवाही करता है। चूंकि यह नया प्रयोग है और हरियाणा प्रदेश की सारी जनता से जुड़ा हुआ है। हमारे प्रदेश के पौणे 3 करोड़ लोग हैं और हमें उन सबको सैटिसफाई करना है। हम उनकी सैटिसफैक्शन के लिए गम्भीरता से काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर आह्वान करता हूं कि माननीय सदस्यगण इस संबंध में चाहे हर सप्ताह कम्पलेंट्स की फाईल बनाकर भिजवा दें। जैसे माननीय सदस्य श्री कुलदीप वत्स जी संबंधित कम्पलेंट्स की फाईल बनाकर लाये हैं। इसी तरह की फाईल बनाकर मेरे ऑफिस में भिजवा दें या प्रिंसिपल सैक्रेटरी साहब के ऑफिस में भिजवा देंगे तो हम उन सब कम्पलेंट्स का समाधान करवाएंगे और किसी का काम छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार सबको न्याय मिलेगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई शिकायत हो तो उसके बारे में लिखकर भिजवा दें।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अतिरिक्त एक सूचना और देना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि यह बहस करने का विषय नहीं है।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इसमें 2 विषय ऐसे हैं जिनमें विवाद हो सकता है। एक विषय किसानों की 4 लाख रुपये की सेल के बाद वह कह सकता है कि उनकी वार्षिक इन्कम 1.80 लाख रुपये नहीं है। दूसरा विषय यह है कि बिजली का बिल 9,000 रुपये है। लेकिन फिर भी कहता है कि उसकी वार्षिक इन्कम 1.80 लाख रुपये से कम है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह बिजली का बिल गलती से भी ज्यादा आ जाता है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे एक साल के बिजली के बिल की एवरेज बता रहा हूं कि टोटल साल में कितना होता है? इसके बाद भी मेरे पास एक कम्पलेंट आयी क्योंकि हम भी कम्पलेंट्स सुनते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि उसका धोबी का काम है और कपड़े प्रैस करने के कारण उसका बिजली का बिल ज्यादा ही आएगा। लेकिन उसकी इन्कम उतनी नहीं है। उसकी बात बिल्कुल जायज है। इस प्रकार की

जो भी कम्पलेंट्स हैं फिर उनमें चाहे 9,000 रुपये बिजली के बिल की बात हो या किसान की इन्कम की बात हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पहले मेरी बात सुन लें। ये बहस का विषय नहीं है। मैंने इसके लिए एक फॉर्मूला बताया है कि इसके लिए सर्वे करवाएंगे।

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं, इसलिए आपके द्वारा बोला गया एक भी वर्ड रिकार्ड नहीं होगा।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जो किसान ऐसा कहते हैं कि उनकी वार्षिक इन्कम 1.80 लाख रुपये से कम है। चाहे भले ही उसने 4 लाख की फसल की सेल की हो। इसके लिए सर्वे करवा लेंगे और सर्वे करवाने के बाद संबंधित किसानों की बात ठीक निकली तो हमें इस 4 लाख रुपये वाले क्रायटेरिया को बढाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए कहीं पर एक पैमाना तो लगाना पड़ेगा। आखिर पैमाना इन्कम का है और यह पैमाना किसान का, कर्मचारी का या दुकानदार का नहीं है। अगर किसी की वार्षिक इन्कम 1.80 लाख रुपये से नीचे है तो उसको बी.पी.एल. के लाभ मिलेंगे और अगर इससे ऊपर इन्कम है तो उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह सिंपल पैमाना है। इसमें सर्वे करने के बाद ही हो सकता है कि हम महीना या 20 दिनों में दोनों चीजों पर फिर से पुनःविचार कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

.....

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

कॉलोनियों को नियमित करना

***5. श्री ईश्वर सिंह:** क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या यह तथ्य है कि गुहला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में चीका नगर निकाय समिति के अन्तर्गत पड़ने वाले **ईश्वर** नगर, वार्ड नं0 2 का टील्ला प्लाट, वार्ड नं. 10 का अम्बेडकर नगर, वार्ड नं 8 एंव 9, की संजय कॉलोनी, वार्ड नं 1 की बेगा बस्ती, वार्ड नं 6 की धानक बस्ती तथा अन्य कॉलोनियां जो कि लम्बे समय से बसी हुई हैं, नियमित नहीं है; तथा

(ख) क्या उपरोक्त कॉलोनियों को नियमित करने तथा वहां बसे हुए लोगों को मालिकाना हक देने का कोई प्रावधान सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

@शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ कमल गुप्ता): (क) हां, श्री मान जी, **ईश्वर** नगर, वार्ड नं0 2 का टील्ला प्लाट, वार्ड नं0 10 का अम्बेडकर नगर, वार्ड नं0 8 और 9 की संजय कॉलोनी, वार्ड नं 1 की बेगा बस्ती, वार्ड नं 6 की धानक बस्ती ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करके विकसित की गई कॉलोनियां है। ये कॉलोनियां वर्ष 1982 में नगर पालिका चीका के गठन से पहले ही स्थापित की गई थी। वर्तमान में जिस भूमि पर ये कॉलोनिया स्थापित है, वह नगर पालिका चीका की भूमि है।

(ख) राज्य में नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण करके बसे लोगों को मालिकाना हक देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खुद ही डिटेल में इस बात को मान लिया है। इसमें पहली बात तो यह है कि यह कमेटी 1982 में बनी थी। मैंने माननीय मंत्री जी को बस्तियां के बारे में लिखकर दिया है वह वर्ष 1964 से ही आबाद हो गई थी और इसमें यह प्रावधान भी किया गया था कि जो म्युनिसिपल कमेटी बनने से पहले वहां अगर कोई चीज आबाद है तो आप उसको कैसे अवैध मान लोगे, फिर भी मैं माननीय मंत्री जी की इस बात का ताईद करता हूं कि वहां पर रोड और गलियां आदि बना दी गई। वहां की नगर पालिका की जितनी भी फैसिलिटी थी, वह उनको सारी दे दी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से

@कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) द्वारा उपरोक्त प्रश्न का जवाब दिया गया।

पूछना चाहता हूं कि सरकार ने पैसा भी दे दिया, सीवरेज भी दे दिया, पानी भी दे दिया और बिजली आदि भी दे दी। मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कॉलोनी कमेटी से पहले की बनी हुई है तो सरकार किन कारणों से यह बात कहती है कि वहां बनाने का प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में भी लाना चाहता हूं और म्युनिसिपल कमेटी भी प्रस्ताव पास करने के लिए तत्पर है कि यह सारी की सारी आबादी पहले की बसी हुई है। इस प्रकार से समय चलता चला जायेगा जबकि आधी सदी का समय तो बीत चुका है और आज तक उनको किसी ने पूछा नहीं है। माननीय मंत्री जी अभी भी यह बात कहते हैं कि ये अवैध कॉलोनियां हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कमेटी बाद में आई और कॉलोनियां पहले बस गई और उसके बावजूद भी यह बात कहते हैं कि ये अवैध कॉलानियां हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इन कॉलोनियों को वैध किया जायेगा या नहीं?

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, कमेटी बनने से पहले वहां पर पंचायत थी और पंचायत की जमीन पर अवैध रुप से कब्जा किया हुआ था और वह कॉलोनी इल्लीगल थी और वहां पर बाद में कमेटी आ गई। अभी जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है तो उसको वैध करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूं। अगर किसी ने कोई और कॉलोनी बनाई है तो उसके लिए सरकार ने पॉलिसी बना रखी है हम उसको रैगुलराइज या डिवैल्प कर देंगे लेकिन सरकारी जमीन पर जो लोग कब्जा किये हुए बैठे हैं हमने उनके लिए अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई हैं।

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात का रिटन के अंदर सबूत देना चाहूंगा। मेरे पास इसका लैटर दिनांक 21.12.2004 का है और सरकार ने इस लैटर के हैडिंग में लिखा है कि पालिकाओं की भूमि पर अवैध रूप से काबिज

लोगों को बेचने बारे। इस लैटर में इन बातों का हवाला दिया गया है। आज इन बातों को 19 साल हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : ईश्वर जी, बेचने का तो कोई आदेश नहीं हुआ है।

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसका लैटर है जो मैं माननीय मंत्री जी को दे रहा हूं और मैं इसको पढ़कर भी सुना देता हूं कि उपरोक्त संदर्भित मामले में अवगत करवाया जाता है कि सरकार द्वारा उक्त वर्णित पत्र में नगर पालिकाओं की भूमि पर अवैध रूप से बसी कॉलोनियों में काबिज लोगों को कलैक्टर रेट पर पालिका भूमि बेचने के लिए हिदायत जारी की है। यह मैं माननीय मंत्री जी को लैटर दे रहा हूं। इस संबंध में मैं आपका पुनः ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने के आदेश हुए हैं कि आप द्वारा राज्य की पालिकाओं की सिर्फ वहीं भूमि अवैध रूप से काबिज लोगों को बेची जानी है जो बस्ती के रूप में हो, पालिका की भूमि पर न हो। पालिका की भूमि पर किये गये इक्का–दुक्का कब्जे वाली वाणिज्य औद्योगिक इकाइयां या रिहायशी मकान अनुरोध है कि पालिकाओं की भूमि पर बेची जाये व अवैध रूप से बस्तियों को काबिज लोगों के कब्जे में हो।

श्री अध्यक्ष : ईश्वर जी, ये आदेश किसके हैं?

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में सरकार ने आदेश पारित किये हैं।

श्री अध्यक्ष : ईश्वर जी, सरकार ने आदेश पारित तो कर दिये लेकिन इम्पलीमैंट नहीं किये।

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही बात कह रहा हूं और मेरा विषय भी यही है।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारी सरकारी जमीन पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। वर्ष 2014 की चिट्ठी वाली सरकार भी चली गई फिर भी हम इसका अध्ययन कर लेंगे। हमने एक

बार इस बारे में सोचा था कि सर्कल रेट पर दुगुने रेट पर विचार किया जा सकता है और इसकी पॉलिसी बनाने का विचार किया जा सकता है लेकिन आज के दिन कोई पॉलिसी नहीं है।

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इसका जवाब क्या होगा। माननीय मंत्री जी इसका जवाब तो बताएं। यह तो मैं छोटी सी बात पूछ रहा हूं ?

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, ने इसी के संबंध में कहा तो है कि वे विचार कर रहे हैं।

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, अगर कमेटी प्रस्ताव पास कर देती है तो क्या उसको मान्यता देंगे।

श्री अध्यक्षः नहीं, यह तो सरकार ने करना है, कमेटी को नहीं करना है।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, कमेटी सारी जमीन थोड़ी दे सकती है।

.....

उडयान केयर, एन.जी.ओ., कुरुक्षेत्र के विद्यार्थियों एवं वरिष्ठ व्यक्ति का अभिनन्दन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि उडयान केयर, एन.जी.ओ. कुरुक्षेत्र के विद्यार्थी एवं वरिष्ठ व्यक्ति आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ।

————————————

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

विकास कार्यों को पूरा करना

*6. **श्री इन्दु राजः** क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि –

(क) क्या यह तथ्य है कि दिनांक 17.05.2021 को एच.आर.डी.एफ. मुख्यमंत्री घोषणा योजना कोड 25284 के अंतर्गत बऱौदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए रुपये 2,79,91,000/– की राशि जारी की गई थी तथा उन कार्यों की संख्या कितनी है जो उक्त घोषणा से पूरे हुए हैं तथा उन कार्यों की संख्या कितनी है जो लंबित हैं; तथा

(ख) इन कार्यों के अब तक पूरा न किए जाने के कारण क्या हैं तथा उक्त कार्यों के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है तथा उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेंद्र सिंह बबली): (क) हाँ, श्रीमान जी, मु0 2,79,91,000/– (दो करोड़ उन्यासी लाख इकानवे हजार मात्र) की राशि दिनांक 17-05-2021 को मुख्यमंत्री घोषणा कोड 25284 के तहत हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के बजट से बऱौदा विधानसभा क्षेत्र के 26 विकास कार्यों के लिए जारी की गई थी। स्वीकृत 26 कार्यों में से 8 कार्य पूर्ण हो चुके हैं व 9 प्रगतिधीन हैं तथा 8 अभी शुरू नहीं किए जा सके हैं तथा एक कार्य जमीन उपलब्ध न होने के कारण नहीं करवाया जा सका।

(ख) उपरोक्त कार्यों की राशि प्रारम्भ में संबधित ग्राम पंचायतों को जारी की गई थी। मई 2022 के महीने में 21 कार्यों की राशि कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज सोनीपत को स्थानतरित की गई। 5 कार्यों की राशि अभी भी ग्राम पंचायतों के पास है। अब कार्य हरियाणा इंजिनीयरिंग वर्क्स प्रोर्टल पर ई–निविदा प्रकिया के तहत आमंत्रित करके करवाये जा रहे हैं। 17 (प्रगतिधीन व शुरू ना किए गए) कार्य दिनांक 30.09.2023 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। गांव जागसी सहरावत में चौपाल के लिए स्थान उपलब्ध न होने के कारण राशि वापिस भेजी जा चुकी है।

श्री इंदु राजः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो 2 करोड़ 80 लाख रुपये की ग्रांट दी गयी थी, इसे दिये हुए दो साल के करीब हो गए और यह ग्रांट जब स्वर्गीय विधायक श्री कृष्ण जी हुड्डा विधायक थे उनके द्वारा दी गई थी। जब मैं विधायक बनकर आया तब मैंने डायरेक्टर से मिलकर एक चिट्ठी एक्सीयन सोनीपत को लिखवाई थी कि इनमें से कई काम हैं जो पूरे हो चुके हैं। जब उप चुनाव हुआ तब वहां सरकार के मंत्री विधायक गये उन्होंने वोट लेने के लिए इधर–उधर से वे काम पूरे करवाए लेकिन एक्सीयन साहब ने लिखा कि

इनमें से कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। उसके बाद राशि जारी की गई है और माननीय मंत्री जी ने जिन आठ कामों का जिक्र किया कि वे पूरे हो गए। ये कार्य वर्ष 2019 और 2020 में पूरे हो चुके हैं। एक्सीयन के द्वारा टेंडर द्वारा कोई भी काम आज तक न तो पूरा हुआ न ही कोई लगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पंचायती राज एक्सीयन का जो जवाब है उसने कहा कि एक काम का 17 बार टेंडर हो गया, एक काम का 15 बार टेंडर हो गया तथा एक काम का 7 बार टेंडर हो गया लेकिन कोई टेंडर नहीं ले रहा इसलिए मैं इन कार्यों को कहां से पूरा करवाऊं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि जब एक काम का 17 बार टेंडर हो गए और कोई ठेकेदार उस काम को नहीं ले रहा तब उस काम को सरकार कैसे पूरा करवायेगी। हमने कुछ उम्मीद लगाई थी कि कुछ दिन में सरपंच बन जाएंगे और हम सरपंचों द्वारा काम करवाएंगे लेकिन मैं तो सही कहता हूं कि सरकार विकास रोको प्रस्ताव ई–टेंडरिंग का जो लेकर आई है इसका सारा उदाहरण आपके सामने है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बड़ी झूठ बोली और कहा कि मुंडलाना गांव के तालाब में पानी है। माननीय मंत्री जी मेरे पास इस तालाब की फोटो है और इसमें कोई पानी नहीं है यह सूखा तालाब है। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि बरौदा ठुठाणी चौपाल वर्ष 2019 में बन गई और एक्सीयन कह रहा है कि हमने टेंडर लगा रखा है जो 6 महीने में पूरी हो जाएगी जबकि चौपाल पहले ही बन चुकी है। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने कहा है कि सामड़ी गांव में चौपाल बन गई है जबकि यह ऐसे की ऐसे ही अधूरी पड़ी है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, अभी यह नहीं बनी हुई है।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली : स्पीकर सर, इस मामले में मेरा यही कहना है कि इस बारे में मुझे जो विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है और जो इस समय मेरे पास उपलब्ध

है मैं उसी के बारे में यहां पर स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं। इनके हल्के में जिन गांवों में कार्य पूर्ण करवाये जा चुके हैं उनके नाम भी मेरे पास हैं। ये सभी कार्य हमारे इंजीनियर विंग द्वारा करवाये गये हैं। नौ गांवों में अभी टैण्डर की प्रक्रिया जारी है। उनके काम भी जल्दी शुरू हो जायेंगे। दो–तीन काम जो छोटी–छोटी अमाउंट के थे वे अभी पैंडिंग हैं। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनके नाम इनको बता सकता हूं। ये काम छोटी अमाउंट के थे इनके दो–तीन बार टैण्डर किये लेकिन टैण्डर में कोई पार्टी नहीं आई। जिन कामों की ये डिटेल दे रहे हैं कि ये एक्स.ई. एन. के थ्रू नहीं करवाये गये हैं उनके बारे में मैं आपको इंश्योर करता हूं ये सभी काम एक्स.ई.एन. के थ्रू करवाये गये हैं। ये सभी काम पंचायती राज के एक्स.ई.एन. ने ही करवाये हैं। जिन नौ कामों के टैण्डर लगे हुए है वे भी जल्दी ही शुरू करवा दिये जायेंगे। जो काम पैंडिंग हैं उनको भी जल्दी से जल्दी करवाने का काम किया जायेगा। अगर इसके बावजूद भी माननीय सदस्य को लगता है कि कहीं न कहीं विभागीय अधिकारी के द्वारा गलत इनफर्मेशन दी गई है मैं उसकी जांच करवाने का भी काम करूंगा और अगर यह पाया गया कि उसने गलत इनफर्मेशन देकर मिसलीड करने का काम किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने का भी काम करूंगा।

श्री इंदु राज : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जिन आठ कामों के बारे में उनके द्वारा आज बताया जा रहा है ये वर्ष 2019–20 के काम हैं। अब इनके लिए दोबारा भी पैसा रिलीज हो गया। इसी प्रकार से कई काम ऐसे बता दिये कि वर्ष 2019–20 में जो काम 18 लाख रूपये में होना था आज एक्स.ई.एन. कह रहा है कि वह काम 28 लाख रूपये में होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस 10 लाख रूपये की राशि की भरपाई कहां से होगी। मैं एक विधायक हूं। मैं विधान सभा में पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको यह जानकारी दे रहा हूं कि एक्स.ई.एन. साहब ने सारे काम गलत किये हैं। कोई भी काम टैण्डर प्रोसैस के माध्यम से नहीं हुआ

है। मंत्री जी मुझे यह बता दें कि क्या मंत्री जी उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है मैं फिर से कहता हूं कि दोषी अधिकारी की मैं जांच करवाउंगा। अगर उसने आपको व सदन को मिसलीड किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, इसको जरा टाईम–बाउंड करें कि 15 दिन के अंदर जांच करवाकर जांच रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करें।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली : ठीक है स्पीकर सर।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, जो तथ्य माननीय सदस्य ने सदन के अंदर दिखाये हैं और यह कहा कि गलत रिपोर्टिंग की है जो वहां पर काम हुआ नहीं है यह दिखाया गया है या जो भी गलत जानकारी सदन के अंदर दी गई है उसकी आप इंक्वॉयरी करवाईये और 15 दिन के बाद सदन के अंदर उसकी रिपोर्ट दीजिए।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली : ठीक है स्पीकर सर, मैं इस मामले की जांच करवाकर उसकी रिपोर्ट आपको और माननीय सदस्य को भेजने का काम करूंगा।

श्री इंदु राज : अध्यक्ष जी, वर्ष 2019–20 में जो काम 18 लाख रूपये में होना था आज एक्स.ई.एन. कह रहा है कि वह काम 28 लाख रूपये में होगा। ये 10 लाख रूपये कहां से लेकर आयेंगे यह भी बताया जाये।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली : स्पीकर सर, यह राशि हमारा डिपार्टमैंट देने का काम करेगा।

————

कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए एक समिति का गठन करना

***7. श्री प्रदीप चौधरी :** क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि मांधना से रायपुर रानी वाया टिक्करताल तक रिटेनिंग वाल तथा सड़क का निर्माण सरकार द्वारा निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया है तथा निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग की जा रही है**;** यदि हां**,** तो क्या उपरोक्त कार्य की गुणवत्ता जांच करने के लिए स्थानीय विधायक सहित एक समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है**?**

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): No, Sir. The retaining wall and the road from village Mandhana to Raipur Rani via Tikkartal is being constructed as per PWD specifications and as per provisions of contract agreement. No sub-standard material is being used in the construction work and requisite quality control measures are being taken.

श्री प्रदीप चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह सवाल किया था कि टिक्करताल होते हुए मांदना से रायपुर रानी तक जो रिटेनिंग वॉल और सड़क का निर्माण हो रहा है उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इसकी जांच के लिए एम.एल.ए. की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों और स्थानीय लोगों की कोई कमेटी बनाई जायेगी। इनका जवाब आया कि पूरी तरह से क्वॉलिटी के हिसाब और सरकार के निर्देशानुसार काम हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि एक निष्पक्ष समिति का गठन करके वहां पर हुए कार्यों की जांच करवा ली जाये। उसमें दीवार/स्पोर्ट पिल्लर्ज की नींव को भी पूरा नहीं डाला गया और जो उसमें रेता, बजरी व सीमेंट यूज किया गया उसका अनुपात भी ठीक नहीं है। वहां पर 70 प्रतिशत रेत डस्ट का यूज किया गया है। वहां पर दीवार/स्पोर्ट पिल्लर्ज की तराई भी नहीं होती। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा सीमेंट आ गया है जिसमें तराई की भी जरूरत नहीं होती। वहां के आम लोगों ने इस बारे में सी.एम. विंडो पर भी शिकायत डाली लेकिन विभाग द्वारा विभागीय इंक्वॉयरी बिठा दी जाती है। उसमें जो कम्पलेनेंट होता है उसको बुलाया नहीं जाता और कह दिया जाता है कि वह काम ठीक है। इस मामले में मेरा यही कहना है कि जिस कम्पलेनेंट ने सी.एम. विंडो पर शिकायत दी होती है उसके ऊपर सुनवाई के दौरान कम्पलेनेंट को भी जरूर बुलाना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि गुणवत्ता सही है तो सामग्री की

गुणवत्ता की जांच के लिए एक समिति बनाई जाये जिसमें वहां के दो–चार मौजिज लोगों को भी शामिल किया जाये तथा मुझे भी इसमें शामिल किया जाये। आप अपने विभाग के अधिकारियों को भेज कर जांच करवा लीजिए तो आपको पता चल जायेगा कि कितना बुरा हाल है तथा इसमें कितना घपला है। इसी प्रकार से नन्दपुर केदारपुर की सड़क का मैंने विधान सभा में जिक्र किया था जिसकी जांच शुरू हो चुकी है। इसी प्रकार से एक गांव बवाना की सड़क बनी थी वह भी टूट गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं 4–5 दिन पहले झाझड़ से कोलावाली भूड किसी सामाजिक समारोह में शामिल होने गया था तो उन लोगों ने बताया कि हमारी सड़कों को बने हुए 4–5 साल हो गये हैं। उनका कहना है कि हमारी सड़कें कभी नहीं टूटी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस सड़क में इस्तेमाल हो रही सामग्री की एक समिति बना कर जांच करवाई जाये। इस जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। अगर हम सही हैं तो उसका भी पता चल जायेगा और मंत्री जी सही हैं तो उसका भी पता चल जायेगा।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार–बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसमें स्थानीय विधायक को भी शामिल किया जाये। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह इंजीनियरिंग का काम है और माननीय विधायक के कहने पर हमने अपने विभाग की इंजीनियरिंग विंग द्वारा दो बार टैस्टिंग करवाई है और टैस्टिंग के बाद स्पेसिफिकेशन के अनुसार वहां रोड वर्क हुआ है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसका तीसरी बार इंस्पैक्शन हो तो हम क्वालिटी कंट्रोल की टीम के साथ जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रिएविंसिज विंग के दो सदस्य हैं उनको ऐसासिएट करके हम इसकी तीसरी बार भी जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्षः उप–मुख्यमंत्री जी, अगर आप मानें तो इस बारे में मेरा एक सुझाव है। इसके लिए विधान सभा की एक अलग से कमेटी बनी हुई है अगर आप उसको इस जांच में शामिल कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, अगर आप कह रहे हैं तो मैं उस समिति को इस जांच में अवश्य शामिल करूंगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला बार–बार क्यों उठा रहा है। वहां पर एक मोरनी कॉन्टिनेंटल रिजॉर्ट है, उसकी मलकियत किसकी है तथा इसको लीज पर किसको दिया गया है उसकी भी जांच हाउस अवश्य करवाए। वहां पर जो कंस्ट्रक्शन चल रही है उसमें लोकल इन्वॉल्वमैंट ज्यादा है। इसमें क्वालिटी का मामला बार–बार इसीलिए उठाया जा रहा है कि वहां के लोकल लोग चाहते हैं कि उस रिजॉर्ट तक जो सड़क जा रही है उसको भी इसी कांट्रैक्ट के तहत ठीक करवाया जाये लेकिन कानूनी रूप से वह सम्भव नहीं है।

श्री प्रदीप चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हमारे पास विभाग का अप्रूव्ड नक्शा है लेकिन उसके विपरीत काम हो रहा है। वहां पर जो डंगे लगाये जा रहे हैं वे भी नक्शे के अनुसार नहीं लगाये जा रहे हैं। उसकी गहराई भी नक्शे के अनुसार नहीं है तथा उसका जो पिछला रद्दा 90 डिग्री पर लगना चाहिए था वह भी नहीं लग रहा है। उसमें रेत और पत्थर भर दिया जाता है। आगे का जो स्लोप होना चाहिए वह भी ठीक नहीं बना है इसलिए मेरा आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि एक समिति बना कर इसकी जांच करवाई जाये ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये।

श्री अध्यक्षः प्रदीप जी, वहां के लोकल लोगों का अपना इंट्रस्ट हो सकता है। अब यह मामला विधान सभा की समिति के पास जायेगा और उस समिति में सत्ता पक्ष के भी

सदस्य हैं और विपक्ष के भी सदस्य हैं।

श्री प्रदीप चौधरीः धन्यवाद, सर।

————————————

कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत रोजगार

***8. श्री मेवा सिंह**: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में कौशल रोजगार निगम पोर्टल के गठन के बाद अब तक कितने युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्री मान जी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा विभिन्न सरकारी संगठनों में कार्यरत 1,06,464 मौजूदा अनुबंधित कर्मचारियों को डिप्लॉयमेंट ऑफर लैटर(डी0ओ0एल) जारी किया गया है, जिसमें से 95,424 अनुबंधित कर्मचारियों ने निगम के पोर्टल पर ज्वाइन कर लिया है और विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं | इसके अतिरिक्त निगम द्वारा 6736 नए उम्मीदवारों को जॉब एक्टिविटीज़ जैसे योग सहायक, चालक, सहायक लाइनमैन, कला शिक्षा सहायक इत्यादि में डी0ओ0एल0 जारी किया गया है, जिनमें से 4,380 उम्मीदवारों ने ज्वाइन कर लिया है और विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं | अध्यक्ष महोदय, यह एक नया विषय है जो हमने अभी शुरू किया है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे देना पड़ रहा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एच.के.आर.एन.) नया विषय है। इसके तहत जो उत्तर है वह तो यही है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा विभिन्न सरकारी संगठनों में कार्यरत 1,06,464 मौजूदा अनुबंधित कर्मचारियों को डिप्लॉयमेंट ऑफर लैटर (डी.ओ.एल.) जारी किया गया है, जिसमें से 95,424 अनुबंधित कर्मचारियों ने निगम के पोर्टल पर ज्वाइन कर लिया है जो विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा 6,736 नए उम्मीदवारों को जॉब एक्टिविटीज जैसे योग सहायक, चालक, सहायक लाइनमैन, कला शिक्षा सहायक इत्यादि में डी.ओ.एल. जारी किया गया है, जिनमें से 4380 उम्मीदवारों ने ज्वाइन कर लिया है और विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं तथा बाकियों को भी ज्वाइन करवा लिया जायेगा।

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आज जो एच.के.आर.एन. के माध्यम से बच्चों को लगाया जा रहा है

क्या यह एक पक्की नौकरी है और अगर यह पक्की नौकरी नहीं है तो फिर सरकार पक्की नौकरी कब देगी? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, प्लीज आप बैठ जाईये।

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय,———(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, प्लीज आप बैठ जाईये नहीं तो मुझे आपको नेम करना पड़ेगा।(विघ्न)

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय, यह तो आपकी पावर है।———(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बैठ जाईये।

श्री बलराज कुंडू : अध्यक्ष महोदय,—————(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुंडू जी, मैं आपको बार–बार टाईम दे रहा हूं फिर मुझे बोलना पड़ेगा। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। उनका भी यह जरूरी मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, जब आपका बोलने का नम्बर आएगा तब आप बोल लेना। पहले बोलने का राईट उसका है जिसका प्रश्न लगा हुआ है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह तो पूरे हरियाणा का मुद्दा है। इसको तो कोई भी उठा सकता है।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, अगर इस तरह से एक ही मुद्दे पर बोलते रहेंगे तो फिर शाम तक एक ही मुद्दे पर चर्चा हो पाएगी। उसके बाद तो किसी दूसरे प्रश्न पर चर्चा होगी ही नहीं। अगर आपने भी बोलना है तो आप प्रश्न लगाईये।(विघ्न) बिना प्रश्न लगाए डिस्कशन नहीं हो सकती है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमैंट्री तो पूछा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, एक प्रश्न पर दो सप्लीमैंट्री पूछे जा सकते हैं।(विघ्न) फिर तो पूरे प्रश्न हावर में एक ही प्रश्न पर डिस्कस होगी। अगर इस बात पर सभी सहमत हों तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।(विघ्न) अभी भी सिर्फ आठ प्रश्न हुए हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, इनको अपने ही मैंबर पर इतना एतबार नहीं है कि उसमें इतनी योग्यता है कि वह अपना प्रश्न पूछ सके। माननीय सदस्य ठीक प्रश्न पूछ रहा है तो ये उसी को अपना प्रश्न पूछने दें। ये अपने सदस्य पर विश्वास रखें कि वह अपना प्रश्न विस्तार से पूछ सके।(विघ्न)

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप युवाओं को किस आधार पर चयनित करके कौशल रोजगार के तहत रोजगार दिलवा रहे हैं, क्या यह रोजगार प्रमानैंट है और यह रोजगार कितने समय के लिए दिया जा रहा है?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह बता दूं कि यह व्यवस्था शुरू क्यों की गई क्योंकि हमारे बहुत से कर्मचारी आउटसोर्सिंग व ठेकेदार प्रथा के माध्यम से आते थे। अब कर्मचारियों और भिन्न–भिन्न ऑर्गनाईजेशंज ने लगातार कहा कि इस ठेकेदारी प्रथा को किसी तरीके से खत्म किया जाए क्योंकि जितने भी कर्मचारी आउटसोर्सिंग से लगे होते थे उनका बहुत शोषण होता था। न उनको ई.पी.एफ. का लाभ मिलता था, न उनको ई.एस.आई. का लाभ मिलता था। इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं थी जिसमें से लम्बे विचार के बाद हमने कहा कि ठीक है सरकार को आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों को रखना तो पड़ता ही है क्योंकि स्थाई नौकरियों के लिए तो हमारी व्यवस्थाएं अलग हैं। उसके लिए स्टाफ सलैक्शन कमीशन है, एच.पी. एस.सी. है या कहीं परमानैंट नौकरी की अलग से जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वे सब अलग से हैं लेकिन जो किसी विभाग की इमीजियेटली आउटसोर्सिंग की डिमांड है उसको पहले ठेकेदारों के माध्यम से लिया जाता था अब उसके लिए ही यह एच.के.

आर.एन. बनाया गया है। यह ठीक है कि यह बिल्कुल अस्थाई नौकरी है और एक साल के लिए होती है। एक साल के बाद जैसे पहले भी उसमें एक्सटैंशन मिलती है अब भी उसी हिसाब से ही होगा। यह परमानैंट नौकरी नहीं है। परमानैंट नौकरी के लिए तो जैसे ग्रुप–सी के लिए सी.ई.टी. हुआ है। उसमें से लगभग 30–35 हजार नौकरियों की रिक्विजीशन आ गई है। उसके बाद ग्रुप–डी की नौकरियों के लिए भी सी.ई.टी. होना है। वह सब प्रक्रिया अलग है। यह एच.के.आर.एन. तो तुरन्त आवश्यकता को पूरा करने की व्यवस्था है। अब मैं यह बताता हूं कि इसके तहत किस आधार पर

12:00 बजे

भर्ती की जाती है। इसमें हमारा बिल्कुल ट्रांसपैरेंट आधार है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि एक पोर्टल बनाया गया है जोकि बिल्कुल ट्रांसपैरेंट है। उसमें पहली प्राथमिकता उनको दी जाती है जो पहले से अनुभवी हैं और उनको लिया जाता है। अगर अनुभवी लोग उपलब्ध न हों तो फिर उस पोस्ट के लिए उसी पोर्टल में एक एडवर्टाइजमैंट देकर कि हमारे पास इतनी सीट्स हैं अगर उसमें कोई और अप्लाई करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। उसकी सैलरी भी निश्चित है लैवल–1, लैवर–2, लैवल–3, लैवल–4 जो एक आउटसोर्सिंग की सैलरी होती है, वह निश्चित की गई है। इसमें भी बिल्कुल रैंकिंग के हिसाब से जो मैरिट लिस्ट सबकी बनी हुई है, उसके हिसाब से सबको पता है कि मैरिट लिस्ट में वे कहां पर स्टैंड करते हैं। मैरिट लिस्ट बनाते समय जो मार्क्स दिए जाते हैं उसके लिए परिवार की वार्षिक आय कितनी है, को आधार बनाकर काम किया जाता है। अगर परिवार की वार्षिक आय कम है तो ऐसे परिवार वाले बच्चों को प्राथमिकता देने का काम किया जाता है क्योंकि वैलफेयर स्कीम के माध्यम से हम भी यह चाहते हैं कि जिसके घर में नौकरी नहीं है और गरीब परिवार है तो ऐसे लोगों को कम से कम आउटसोर्सिंग के आधार पर नौकरी का अवसर जरूर मिल जाये। इसके बाद मैरिट लिस्ट में उम्मीदवार की आयु भी एक आधार होती है क्योंकि काम करने की मध्यम आयु लगभग 30–35 साल की मानी

जाती है और ऐसी उम्र वालों को मैरिट लिस्ट मैं ज्यादा वेटेज दी जाती है क्योंकि अगर ऐसी अवस्था में यदि बिना नौकरी के उम्र निकल रही है तो वह ठीक बात नहीं होती तो ऐसी उम्र में व्यक्ति नौकरी पर आ जाये या उसको कोई काम मिल जाये, इस बात के लिए 30–35 साल की उम्र को भी मैरिट लिस्ट में एक आधार बनाकर तरजीह देने का काम किया जाता है। यही नहीं कौशल योग्यता और क्वालिफिकेशन को भी मैरिट लिस्ट में आधार बनाया जाता है। इसके बाद यदि किसी ने सी.ई.टी. का एग्जाम पास किया है तो उसके अलग से 10 मार्क्स देने का काम किया जाता है। सामाजिक और आर्थिक मापदंड के लिए भी 5 नम्बर देने का काम किया जाता है। जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है उनके लिए भी अलग से 5 नम्बर रखने का प्रावधान किया गया है। इज ऑफ डिप्लायमैंट यानि जो लोकलाइज्ड व्यक्ति होगा उसको भी अलग से मार्क्स देने का काम किया जाता है। सेम जिले में नौकरी मिलेगी तो उसे 10 नम्बर अलग से मिलेंगे और अगर वह जिले से बाहर नौकरी लेना चाहता है तो उसको 10 नम्बर नहीं मिलेंगे। अब तो हम आगे की भी सोच रहे हैं क्योंकि हमारे पास शिकायतें मिल रही थी कि आउटसोर्सिंग बेसिज नौकरियों में दूर–दूर की नियुक्तियां मिल जाती हैं। पहले तो इन नोकरियों को ज्वॉयन कर लिया जाता है लेकिन बाद में शिकायत की जाती है कि उन्हें 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जबकि उनकी सेलरी कम है। अब हम सोच रहे हैं कि ब्लॉक में उनको काम मिले। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि कौशल रोजगार निगम की भर्ती की ट्रांसपेरेंसी पर ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। बी.पी.एस. यूनिवर्सिटी में ऐसी घटना सामने आई है कि पहले जो लड़के यहां पर काम कर रहे थे उनकी जगह पर दूसरों को लगा दिया गया।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्या के पास कोई ऐसी शिकायत है तो सरकार के ध्यान में लाने का काम करे।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि हरियाणा विधान सभा की पैटीशन कमेटी के समक्ष यह मामला आया है। पैटीशन कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और सदन में सबमिट भी हो जायेगी।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट अभी मेरे पास नहीं आई है। हमारे पास पहले इसको आने तो दो।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, यह मामला चीफ सैक्रेटरी साहब के नॉलेज में भी है, ए.सी.एस. हैल्थ के नॉलेज में भी है। बी.पी.एस. यूनिवर्सिटी में इस विषय पर एफ.आई.आर. भी दर्ज हो चुकी है और एस.पी. भी इंक्वायरी कर चुके हैं। लास्ट इयर भी इस बात का जिक्र किया गया था और हमने यह बताया था कि कौशल रोजगार निगम के विषय पर there is a question mark on the transparency और इस वजह से बहुत सारे लोग जो बी.पी.एस. यूनिवर्सिटी में आलरेडी सर्विस कर रहे थे, सैटिंग करके इनके नाम के हाजिरी रजिस्टर फाड़ दिए गए और बी.पी.एस. यूनिवर्सिटी में काम कर रहे इन लड़कों की जगह पर दूसरे लड़कों को लगा दिया गया। सबसे ज्यादा बी.पी.एस. यूनिवर्सिटी के 32 लोग हैं। इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट बहुत ही मोटी अर्थात ज्यादा कागजों के रूप मे निकलकर आई है जिसमें डायरेक्टर मैडिकल और ए.सी.एस. हैल्थ ने माना है कि उनसे गलती हुई है। अतः action should be taken against them. तो सर आपसे हमारा अनुरोध है कि इस तरह के मामले जो संज्ञान में आये हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसका सारा रिकार्ड है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मुझे इस केस का ध्यान आ गया है। यह केस पूरी तरह से मेरे ध्यान में है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इसी तरह की समस्या आई.टी.आई. तौशाम में भी देखने में आई है। वैसे तो सभी जगह ही यह हाल हो रहा है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, पहले जितने भी कांट्रैक्चुअल एम्पलाईज रखे जाते थे, उनकी सूची प्रदेश में नहीं होती थी बल्कि महज एक संख्या भर होती थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, बी.पी.एस. में सर्विस कर रहे लड़कों को हटा दिया गया और उनकी जगह पर दूसरों को लगा दिया गया। ये लड़के पैटीशन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत हुए थे।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, गीता जी को भी कहना चाहूंगा कि यह केस मेरे ध्यान में है। मैं इसी तरह की बातों के बारे में ही अब सदन में बता रहा हूँ कि ये सारी बातें नीचे–नीचे होती थी और मान लो यदि चार लोग छोड़कर चले जाते थे तो अपनी मर्जी से चार अन्य लोग रख लिए जाते थे क्योंकि सैलरी चार लोगों की आलरेडी मिल ही रही थी तो ऐसी अवस्था में उस सैलरी का उपयोग वे लोग किया करते थे लेकिन जब से हमने बाई नेम इनको आउटसोर्स बेसिज लगाने का काम शुरू किया है और उनको यह भी कहा है कि जो लोग पक्के लगे हुए है, उनको कोट कर दीजिए, तब ये खेल शुरू हुआ कि जो पुराने लोग थे उनको हटाकर नए लोगों को रखकर, इन नए लोगों के नाम कोट कर दिए गए। जब इसकी इंक्वायरी हुई है तो सारा मामला सामने आया और अब जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खानपुर का जो केस अभी गीता जी ने और मलिक साहब ने बताया है, यह केस मुझे ध्यान में है, निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई की जायेगी यदि इसके

अतिरिक्त और भी कोई केस सामने आता है तो उस पर भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि तौशाम, आई.टी.आई. में भी इसी तरह का मामला सामने आया है। वहां पर जो पुराने लोग लगे हुए थे उनके साथ भी यही किया गया। आप इसका भी संज्ञान लीजिए और इंक्वॉयरी करवाइये।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए हमने सरकार जानकारी में कोई विषय ला दिया और सरकार उस पर कार्रवाई करेग लेकिन इस तरह के जो विषय जानकारी में नहीं आयेंगे तो ऐसी स्थिति में तो ऐसे मामले दबे ही रहेंगे। अतः प्रश्न उठता है कि कौशल रोजगार निगम की ट्रांसपेरेंसी को हम कैसे सही मान लें ? जब एच.पी.एस.सी. और एच.एस.एस.सी. की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं तो कौशल रोजगार निगम की ट्रांसपेरेंसी पर कैसे विश्वास किया जा सकता है ?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जहां– जहां पर जो भी अनियमिततायें हुई हैं, उसका रिकार्ड मैंने अभी सदन में बताते हुए कहा है कि जो पहले वाले लोग लगे हुए हैं उसकी जानकारी नीचे से लेकर उपर तक, पोर्टल पर कोट करनी पड़ेगी। इस पोर्टल में अब जो जानकारी नीचे से आयेगी उसमें कोई शिकायत मिलेगी तो उसकी इंक्वायरी होगी वरना तो वो सारा रिकार्ड हमारे पास भी नहीं होता है कि कौन सा व्यक्ति आउटसोर्सिंग बेसिज पर कितने साल से कहां पर लगा हुआ है लेकिन नीचे से जानकारी जब पोर्टल पर आयेगी तो फिर यह समस्या नहीं रहेगी।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि तौशाम के अंदर आई.टी.आई. की जो मैं बात कर रही हूँ, ये पूरे हरियाणा के अंदर 500 ऐसे लोग हैं, जिनको हटाने का काम किया गया है। मैं आपको लिखित में भी यह सब दे दूंगी।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या के पास जो भी लिखित में जानकारी हैं, हमें दे सकती हैं। हम उसकी इंक्वॉयरी करवायेंगे। जहां तक ट्रांसपेरेंसी का विषय है, बिल्कुल मार्किंग तय होती है, कंसंर्ड को उनके मार्क्स बता दिए जाते हैं कि इतने मार्क्स तक की रैकिंग वालों को नौकरी दी गई है और इनमें से अगर कोई ज्वॉयन करने नहीं आयेगा तो दोबारा से जो नीचे वाले लोग हैं उनसे उनकी ऑफर ली जाती है और जो ऑफर एसैप्ट करता है वह नौकरी पर आ जाता है और जो एसैप्ट नहीं करता है तो 15 दिन की समयावधि में उसकी ऑफर समाप्त कर दी जाती है और नए व्यक्ति को ऑफर भेज दी जाती है।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, कौशल रोजगार निगम में नाम भेजने के लिए 28.9.2021 की कट ऑफ डेट तय की गई थी अर्थात जो व्यक्ति इस तारीख तक बी.पी.एस. खानपुर में ठेकेदार के अधीन कांट्रैक्ट पर नौकरी कर रहा था, उनके नाम कौशल रोजगार निगम में भेजे जाने थे लेकिन ये नाम नहीं भेजे गए और आलरेडी लगे हुए लोगों की जगह नए लोगों के नाम भेजने का काम किया गया। मेरे पास उन लोगों के हाजिरी रजिस्टर की कापी भी है। काम किसी ने किया और पोर्टल पर नाम किसी और का चढ़वा दिया गया और इस मामले में एस.पी. की भी इंक्वायरी हुई है और उसमें पता चला है कि पैसों का लेन देन हुआ है।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, आपके पास जो पेपर्ज हैं उनको मुख्यमंत्री महोदय को दे दीजिए। पहले भी इंक्वायरी हो चुकी है और अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो उसको भी देख लेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मैं यह सारा रिकार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी को सुपुर्द करता हूँ।

(इस समय श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक द्वारा संबंधित रिकार्ड की कापीज मुख्यमंत्री महोदय को सुपुर्द की गई।)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

————————

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

जी.बी.एस.एम. लिंक चैनल का विस्तार

***9. श्री अमित सिहागः** मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि –

(क) क्या सरकार ने कालुआना खरीफ चैनल के लिए वर्ष 2013 में वास्तविक अलाईनमैंट प्लान के अनुसार डबवाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जी.बी.एस.एम. लिंक चैनल को 79217 अंतिम छोर से गांव चक फरीदपुर तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है; तथा

(ख) उन गांवों की संख्या कितनी है जो कालुआना खरीफ चैनल के लिए बनाई गई वास्तवित योजना की तुलना में घग्गर के पानी द्वारा सिंचित होने से वंचित रह जाएंगे?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) श्रीमान जी, वर्ष 2013 के जी बी एस एम के अंतिम छोर की बुर्जी संख्या 79217 से कालुआना गांव में बुर्जी संख्या 143717 तक के विस्तार के मूल प्रस्ताव को वर्ष 2022 में चक फरीदपुर गांव में बुर्जी संख्या 105117 तक सीमित कर दिया गया है।

(ख) श्रीमान जी, वर्ष 2021–22 में जीबीएसएम की बुर्जी संख्या 79217 के मौजूदा अंतिम छौर पर पानी की उपलब्धता का आंकलन करने के बाद, चक फरीदपुर से कालुआना तक की संरेखण (alignment) में पड़ने वाले गोदीकां, कालुआना, गंगा और मूनांवली नामतः चार गांव को तत्काल योजना में शामिल नहीं किया गया है, चक फरीदपुर गांव में बुर्जी संख्या 105117 तक जीबीएसएम का विस्तार करने का प्रस्ताव वर्ष 2022 में किया गया था। हालांकि इन गांवो को शामिल करने के लिए चक फरीदपुर में बुर्जी संख्या 105117 से कालुआना गांव में बुर्जी संख्या 143717 के आगे विस्तार करने की सम्भावना, आने वाले वर्षो में जीबीएसएम चैनल के पुनर्वास द्वारा

बुर्जी संख्या 105117 पर पानी की उपलब्धता और सिंचाई के विकास उपरांत दूसरे चरण में जांची जाएगी।

———————————

सड़क का निर्माण करना

*__10. श्री लीला राम :__ क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) क्या जिला कैथल में गांव क्योडक से गांव कठवाड़ वाया ग्योंग सड़क तक कैथल माईनर (रजबहा) की पटरी पर सड़क का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त पटरी पर कब तक उपरोक्त सड़क के निर्मित किए जाने की संभावना है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) नही, श्रीमान जी।

(ख) उपरोक्त (क) के संदर्भ में इसका कोई औचित्य नहीं है।

.....

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करना

***11. श्री सुभाष सुधा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) क्या यह तथ्य है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करने के लिए सैक्टर–7, कुरुक्षेत्र में मकान न. 215–ए के सामने लगभग एक एकड़ भूमि खाली पड़ी है; तथा

(ख) क्या उक्त खाली पड़ी जमीन पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द का निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है; यदि हां, तो इसके कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): (क) तथा (ख) नहीं, श्रीमान जी।

.....

पार्कों की स्थिति सुधारना

*12. **श्रीमती गीता भुक्कलः** क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) क्या यह तथ्य है कि झज्जर के निम्न पार्कों की स्थिति बुरी अवस्था में है जिसके कारण इनमें आवारा पशु घूमते रहते हैं, शौचालय जर्जर हैं, सफाई नहीं है तथा पानी एकत्रित हो जाता हैः–

1 – राव मांगली राम पार्क ;

2– चौ. मातू राम पार्क ;

3– शहीदी पार्क ; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त पार्कों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए हैं ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता): (क) श्रीमान जी, पूछे गए प्रश्न में जिन पार्कों का उल्लेख किया गया है, उनका रख–रखाव नगर परिषद झज्जर द्वारा किया जा रहा है और वित्त वर्ष 2022–23 में इन पार्कों के रख–रखाव के लिए लगभग 25.00 लाख रुपये की राशि वहन की जा चुकी हैं। वर्तमान में इन पार्कों की स्थिति संतोषजनक है ।

(ख) झज्जर शहर में पार्कों की दशा सुधारने के लिए, नगर परिषद द्वारा दिनांक 25.02.2022 को पार्कों के रख–रखाव का कार्य एक एजेंसी को 25.84 लाख रुपये में एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किया है।

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि नगरपालिका क्षेत्रों में पार्कों के रख–रखाव का कार्य आर.डब्ल्यू.ए, एन.जी.ओ., एसोसिएशन या सी.एस.आर के माध्यम से किया जाएगा। तदनुसार, नगर परिषद झज्जर द्वारा दिनांक 02.02.2023 को आर.डब्ल्यू.ए,/एन.जी.ओ.,/कंपनियों/संस्थाओं के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया हैं।

पार्कों में सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत एवं रख–रखाव के लिए नगर परिषद द्वारा रू. 29.54 लाख के कार्य दिनांक 02.02.2023 को एक एजेंसी को आंवटित किया है। यह कार्य एक माह में पूरा होने की संभावना है।

————————————

एन.सी.सी. अकादमी का निर्माण कार्य को पूरा करना

***13. श्री हरविंदर कल्याण**: क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) क्या यह तथ्य है कि घरौंडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (करनाल) में एन.सी.सी. अकादमी का निर्माण कार्य उच्च शिक्षा विभाग के अनुरोध पर आरम्भ किया गया था;

(ख) क्या यह तथ्य है कि है कि वर्तमान में निर्माण कार्य नहीं चल रहा है; तथा

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उपरोक्त एन.सी.सी. अकादमी के निर्माण कार्य के कब तक पुन: आरम्भ /पूरा किया जाने के संभावना है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

(क) हाँ जी श्रीमान।

(ख) हाँ जी श्रीमान, वर्तमान में संविदा एजेंसी द्वारा जनवरी, 2022 से कार्य बंद कर दिया गया है।

(ग) वर्तमान में, कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

————————————

मनरेगा योजना के अंतर्गत बजट की सीमा

***14 श्री मामन खान:** विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) वर्ष 20.02.2021 से 30.11.2022 की अवधि के दौरान फिरोजपुर झिरका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मनरेगा योजना के अंतर्गत सामग्री पर सरकार द्वारा कितना बजट खर्च किया गया तथा मजदूरों पर कितना बजट खर्च किया

गया तथा उक्त योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए रास्तों का ग्रामवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख फिरोजपुर झिरका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 20.02.2021 से 30.11.2022 तक पी.आर. आई. योजना, 14 वें वित्त आयोग ,पंचायत निधि तथा सरचार्ज वैट एच.आर.डी.एफ (के अंतर्गत कुल कितनी ग्रांट प्राप्त हुई है ;

(ग)पी.आर.आई.योजना, 14 वें वित्त आयोग, पंचायत निधि तथा सरचार्ज वैट एच.आर.डी.एफ(के अंतर्गत कुल कितनी निधियां उपयोग की गई तथा स्टॉक रजिस्ट्ररर, मेजरमैंट बुक, बिलज़, वाउचर तथा मस्ट्रोल सहित सभी कार्यों की फोटो का ब्यौरा क्या है ;

(घ) दिनांक 20.02.2021 से 30.11.2022 तक की अवधि के दौरान फिरोजपुर झिरका विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में सरकार द्वारा उपलब्ध ड्राईंग के अनुसार पशु शैडों के निर्माण के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत कितनी ग्रांट प्राप्त हुई है तथा गांववार लाभानुभोगियों की संख्या कितनी है ?

***विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली):** श्रीमान, (क) महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र में 20.02.2021 से 30.11.2022 की अवधि के दौरान रुपये 42.19 करोड़ की राशि सामग्री मद पर जिसमें 82.90 करोड़ रूपये पिछले वर्ष की देनदारिया शामिल है तथा रुपये 29.51 करोड़ मजदूरी मद पर खर्च की गई है। उक्त योजना के अंतर्गत निर्मित किये गये रास्तों का ग्राम पंचायत वार तथा स्थानवार ब्यौरा अनुलग्नक" क" पर सलग्न है।

————————————

* उपरोक्त तारांकित प्रश्न के उत्तर के अनैक्चर्ज 608 पेजिज का होने के कारण चेयर के आदेशानुसार पूर्व प्रथा के अनुसार हरियाणा विधान सभा के पुस्तकालय में रखवाये गये।

(ख)विधान सभा हल्का फिरोजपुर झिरका में 20.2.2021 से 30.11.2022 तक की समय अवधि के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग ,एच०आर०डी०एफ० एवं पंचायत निधि के तहत कुल 16.23 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई। वर्ष 2018-19 में जी०एस०टी० प्रणाली लागू होने के कारण सरचार्ज आन वैट स्कीम में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई।

(ग)हल्का फिरोजपुर झिरका में 20.2.2021 से 30.11.2022 तक की समय अवधि के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग एवं पंचायत निधि के तहत कुल 4.66 करोड रूपये की राशि खर्च की गयी हैं। एच0आर0डी०एफ० स्कीम के तहत कोई राशि प्रयोग नहीं की गई। जिला उपायुक्त नूहं से प्राप्त संबंधित कार्यो की माप-पुस्तिका, बिल, वाउचर, मस्टर रोल की फोटों प्रतियां पताका" ख "पर रखे गये है।

(घ) महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदान किये गये नक्शे के अनुसार फिरोजपुर झिरका निर्वाचन क्षेत्र में 20.02.2021

से 30.11.2022 की अवधि के दौरान पशु शैडों के निर्माण हेतू रुपये 2.57 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। ग्राम पंचायतवार लाभानुभोगियों का ब्यौरा अनुलग्नक"घ"पर सलग्न है।

————————————

स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा करना

*15. **श्री शमशेर सिंह गोगी**: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:—

(क) गांव बल्ला में स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा न करने के क्या कारण है; तथा

(ख) गांव बल्ला में स्टेडियम के निर्माण पर कितनी आबंटित राशि खर्च की गई तथा उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिन पर उक्त राशि खर्च की गई है;

(ग) यदि खर्च नहीं की गई, तो उसके क्या कारण है; तथा

(घ) गांव बल्ला में स्टेडियम का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): श्रीमान,

(क) गांव बल्ला, जिला करनाल में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए एच0आर0डी0एफ बोर्ड ने पत्र क्रमाकं **1960** दिनाकं **07.06.2012** द्वारा **1** करोड रू की राशि स्वीकृत करते हुए मु**0 50** लाख रू की राशि प्रथम किस्त के रूप में जारी की थी। स्टेडियम का निर्माण अधूरा है क्योंकि क्रियान्वन संस्था (ग्राम पंचायत) ने कभी भी शेष धनराशि की मांग नहीं की है;

(ख) पहली किस्त के रूप में जारी की गई मु**0 50** लाख रुपये की राशि उपयोग कर खेल स्टेडियम की चारदीवारी का निर्माण किया गया है;

(ग) जैसा कि जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, करनाल द्वारा रिपोर्ट में बताया गया है कि उक्त कार्य के लिए जारी की गई 50 लाख रुपये की पहली किस्त का उपयोग किया जा चुका है।

(घ) शेष निर्माण कार्य राशि जारी होने के बाद जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। संबंधित ग्राम पंचायत से अपेक्षित व्यय के नए अनुमान और प्रस्ताव प्राप्त होने पर तुरंत धनराशि जारी कर दी जाएगी।

————————————

अनाधिकृत कॉलोनी **को नियमित करना**

*** 16. श्री राकेश दौलताबाद :** क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि –

(क) क्या यह तथ्य है कि 1996 के एस.एल.पी. (सी.)11023 में पारित 21 मार्च 1997 को अपने आदेश में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य को अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए या न्यू पालम विहार कॉलोनी, गुरूग्राम को उक्त कानून के लागू होने से बाहर रखने के लिए कभी भी भविष्य में कानून बनाने पर रोक नही लगाई है; तथा

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि हरियाणा नागरिक सुविधाओं और अवसंरचना की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्र प्रंबधन (विषेश प्रावधान) अधिनियम, 2016 की धारा-4 किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिग्री या आदेष के लिए गैर-बाधित खंड के साथ आती है इसलिए 2016 अधिनियम के प्रावधानों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 21 मार्च 1997 के निर्णय पर अधिभावी प्रभाव है जिसके कारण न्यू पालम विहार कॉलोनी को स्वीकृत किया जा सकता है यदि वह 2016 अधिनियम की धारा-3 के तहत आवष्यक शर्तों को पूरा करती है?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता): हां श्रीमान जी,

(क) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. (सी.) नं0 11023 ऑफ 1996 में पारित आदेश दिनांक 21 मार्च 1997 में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए भविष्य में कभी भी कानून बनाने

के लिए राज्य को कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है। तदानुसार, राज्य ने समय-समय पर हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्रों (विशेष प्रावधान) अधिनियम को लगाया तथा अनाधिकृत कॉलोनियों का नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र में अधिसूचित किया यानी वर्ष 2013-14 में 887 कॉलोनियां, वर्ष 2018-19 में 685 कॉलोनियां तथा वर्तमान में नगर निकाय क्षेत्र में आने वाली लगभग 2237 कॉलोनियां विचाराधीन है।

हांलाकि, न्यू पालम विहार कॉलोनी के मामले में हरियाणा के महाधिवक्ता ने 28.02.2021 को राय दी है कि "न्यू पालम विहार कॉलोनी के मामले में 2016 अधिनियम के प्रावधानों के तहत विचार करने की आवष्यकता है और यदि वे उसमें निर्धारित मापदंडों को पूर्ण करता है, तो आगे की कार्यवाही अधिनियम अनुसार की जाए।"

(ख) हरियाणा प्रबंधन की नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगर पालिका क्षेत्र (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 (1) राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, हुक्मनामा या आदेष के लिए एक गैर-प्रतिरोधी खंड है।

इसके अलावा, कोई भी राज्य कानून भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लघंन नही कर सकता है।

हालांकि, महाधिवक्ता, हरियाणा के दिनांक 28.02.2021 के उक्त मत को ध्यान में रखते हुए न्यू पालम विहार कॉलोनी के प्रस्ताव की 2016 के

अधिनियम के तहत जांच की गई है और पाया गया है कि कॉलोनी का प्रस्ताव इस अधिनियम के नियमों के तहत परिभाषित शर्तों/मापदंडों जिसमें सभी आंतरिक सडकों की चौ़डाई 3 मीटर से अधिक हो, को पूर्ण नहीं करता है।

———————————

गांवों में सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करना

*17. **श्री बलबीर सिंह** एवं

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे-

(क)क्या यह तथ्य है कि राज्य में वर्ष 2006-07 में प्रत्येक गांव की जनसंख्या के आधार पर लगभग 11000 ग्राम सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए थे जो वर्ष 2023 तक भी इतने ही हैं जबकि प्रत्येक गांव में जनसंख्या में वृद्धि हुई है; तथ्य

(ख)यदि हां, तो क्या गांव की बढी हुई जनसंख्या के अनुसार राज्य में नए ग्राम सफाई कर्मचारी नियुक्त करने तथा उक्त नियुक्तियां के कब तक किए जाने की संभावना है ताकि सफाई का कार्य सुचारू रूप से निष्पादित किया जा सके?

विकास एवं पंचायत मंत्री (देवेन्द्र सिंह बबली) :श्रीमान जी (क) ग्रामीण सफाई कर्मियों की नियुक्ति गांव की जनसंख्या के आधार पर की जाती है 2000 जनसंख्या वाले गांव में 1 सफाई कर्मी नियुक्त किया जाता हैं। 2000 से 5000 तक जनसंख्या वाले गांव में 2 सफाई कर्मी नियुक्त किये जाते है। 5000 से 10000 तक जनसंख्या वाले गांव में 4 सफाई कर्मी नियुक्त किये जाते है। 10000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में 6 सफाई कर्मी नियुक्त किये जाते है।

(ख) सफाई कर्मियों की नियुक्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। वर्तमान में जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है।

————————————

नगर निगम फरीदाबाद के बैंक खातों का ब्यौरा

***18. श्री नीरज शर्मा:** क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री बताएंगे कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि नगर निगम, फरीदाबाद में राशि की कमी के कारण विकास कार्य नहीं हो रहे हैं;

(ख) उन बैंकों की संख्या क्या है जिनमें नगर निगम, फरीदाबाद के खाते है; तथा

(ग) 31 जनवरी, 2023 तक विभिन्न बैंकों में नगर निगम, फरीदाबाद के खातों में कुल कितनी राशि जमा हुई तथा उसका खाते वार ब्यौरा क्या है?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता):

(क) नहीं श्रीमान् जी । राशि के अभाव में विकास कार्य प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

(ख) नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा 11 बैंकों में अपने खाते संचालित किये जा रहे हैं ।

(ग) इन 11 बैंकों में 31 जनवरी 2023 तक 645.56 करोड़ रुपये हैं। खातेवार ब्यौरा अनुलंग्नक 'ए' में दिया गया है।

Annexure 'A'						
MUNICIPAL CORPORATION FARIDABAD						
Account wise bank balance as on 31.01.2023						
						Rs. in Lakhs
Sr. No.	**Bank Name**	**Branch Name & Address**	**Name of Scheme**	**Account No.**	**Account type**	**Balance as on 31.01.2023**
1	**Axis Bank Ltd.**	1-2 Chowk Faridabad	General Payment A/c	348010200012315	Current	155.05
		1-2 Chowk Faridabad	EMD Collection	918020075061612	Current	33.45

Annexure 'A'

MUNICIPAL CORPORATION FARIDABAD

Account wise bank balance as on 31.01.2023

Rs. in Lakhs

Sr. No.	Bank Name	Branch Name & Address	Name of Scheme	Account No.	Account type	Balance as on 31.01.2023
		1-2 Chowk Faridabad	Labour Cess Account	911020019398685	Current	340.88
		1-2 Chowk Faridabad	General ESCROW Account	914020032501562	Current	30.05
		1-2 Chowk Faridabad	Online Challan Income 311 App	920020068717028	Current	9.63
		1-2 Chowk Faridabad	Tax Collection/ Stamp Duty	348010200012324	Current	29.53
		1-2 Chowk Faridabad	General Grant Account/ Covid-19 CM Announcement Grant	910010027462590	Saving	110.70
		1-2 Chowk Faridabad	CFC Grant/NCAP	920010074152070	Saving	3486.28
Total						**4195.57**
2	**Indian Bank**	NIT Faridabad	General Fund	50041385467	Saving	29.71
Total						**29.71**
3	**HDFC Bank**	Sector-14, Faridabad	E-Auction	50100298949546	Saving	840.17
		NIT Faridabad	Khori Flat	50100475659403	Saving	42.90
		NIT Faridabad	New Gram Panchayat Funds	50100475659416	Saving	141.00
		Sector-9 Faridabad	Online Tax Collection	06191450000043	Saving	0.05
		1-2 Chowk, Faridabad	CFC Grant	50100331225188	Saving	0.03
		B.K Chowk NIT Faridabad	Slaughter House Grant	00931450000251	Saving	871.27
		B.K Chowk NIT Faridabad	AMRUT Security New Account	50100540764671	Saving	2140.31
		B.K Chowk NIT Faridabad	AMRUT, Parent Child Account	50100469305837	Current	56.70
		B.K Chowk NIT Faridabad	AMRUT (Parent Child Holding Account) Statutory dues	50100551494443	Current	0.00
		B.K Chowk NIT Faridabad	CM Announcement, Parent Child Account	50100503539438	Current	1008.35
		B.K Chowk NIT Faridabad	CSR Account	50100505980144		203.00
Total						**5303.78**

Annexure 'A'

MUNICIPAL CORPORATION FARIDABAD

Account wise bank balance as on 31.01.2023

Rs. in Lakhs

Sr. No.	Bank Name	Branch Name & Address	Name of Scheme	Account No.	Account type	Balance as on 31.01.2023
4	**Indusind Bank Ltd.**	Sec-16 Faridabad	Online Payment EPF	100011703997	Saving	5.00
		Commissioner MCF at Panchkula	Online collection	151341050070	Saving	123.14
		Neelam Bata NIT Faridabad	General Account	100165372124	Saving	0.00
		Sector-16, Faridabad	General Fund/D-Plan	100025706496	Saving	5.37
		Neelam Bata Road, Faridabad	Pond Account	100116538876	Saving	228.64
		Neelam Bata Road Faridabad	MC Fund/Panchayat	100165372124	FD	10100.00
			Total			**10462.15**
5	**State Bank of India**	NIT Faridabad	EMD	11081541320	Current	445.70
		NIT Faridabad	Stamp Duty/General	40047060229	Saving	2861.12
		Neelam Chowk, NIT Fbd	MC Fund/Panchayat	41360792385	FD	10000.00
			Total			**13306.82**
6	**Equitas Small Finance Bank Ltd.**	NIT Faridabad	Stamp Duty/General	100003244937	Saving	0.00
		NIT Faridabad	Current Account	200000414715	Current	1.96
			Total			**1.96**
7	**Canara Bank**	Neelam Bata Road, NIT Faridabad	Pension	82981010000102	Saving	539.20
		Neelam Bata Road, NIT Faridabad	General Escrow Account (ARC)	82981010001567	Saving	0.70
		NIT Faridabad	SFC Grant, Parent Child Account	110077619950	Current	11822.00
		Neelam Bata Road	MC Fund/Panchayat	489203	FD	7500.00
			Total			**19861.90**
8	**IDFC Bank Gurugram**	Golf Course Gurugram	Online Tax Collection	10017926620	Saving	19.94
			Total			**19.94**
9	**ICICI Bank Ltd.**	NIT Faridabad	EMD	102501002191	Saving	199.90
			Total			**199.90**

Annexure 'A'						
MUNICIPAL CORPORATION FARIDABAD						
Account wise bank balance as on 31.01.2023						
						Rs. in Lakhs
Sr. No.	**Bank Name**	**Branch Name & Address**	**Name of Scheme**	**Account No.**	**Account type**	**Balance as on 31.01.2023**
10	**IDBI Bank, NIT Faridabad**	NIT Faridabad	SBM, Parent Child Account	0003104000351058	Current	1098.43
Total						**1098.43**
11	**Yes Bank**	Neelam Bata Road Faridabad	MC Fund/Panchayat	0531404000566612	FD	10000.00
		Neelam Bata Road Faridabad	Depriciation Fund	053140400059359	FD	76.20
Total						**10076.20**
Grand Total (1 to 11)						**64556.36**
645.56 Crores						

पंजीकृत मामलों की संख्या

*** 19. राव चिरंजीव: क्या गृह मंत्री कृपया बताएंगे कि:-**

(क) गत 8 वर्षों के दौरान राज्य में हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, फिरौती, जबरन वसूली, मॉब लिंचिंग तथा दंगों के पंजीकृत मामलों का ब्यौरा क्या है; तथा

(ख) क्या राज्य में गत 8 वर्षों के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ी है; तथा

(ग) यदि हां, तो राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : महोदय, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

वक्तव्य

(क) विगत 8 वर्षों के दौरान राज्य में दर्ज मामलों का विवरण-

अपराध शीर्षक	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (upto 15.02.23)
हत्या (302 आईपीसी)	1,002	1,057	1,046	1,104	1,137	1,143	1,112	1,007	106
बलात्कार (376-376 ई आईपीसी)	1,070	1,187	1,099	1,296	1,480	1,373	1,716	1,968	198
पॉक्सो एक्ट (4 & 6)	224	532	656	1,068	1,174	1,101	1,293	1,358	110
फिरौती के लिए अपहरण (364ए आईपीसी)	19	30	16	15	18	23	25	27	1
अपहरण (363-364, 365-369 आईपीसी)	3,501	3,902	4,385	5,000	4,005	2,926	3,529	3,953	447
डकैती (395/396/397 आईपीसी)	201	177	196	194	153	151	156	105	11
जबरन वसूली और ब्लैकमेल (384-389 आईपीसी)	317	320	320	323	354	306	361	431	40
मॉब लिंचिंग	हरियाणा में मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। हत्या के सभी मामले आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज हैं।								
दंगे (147-151 आईपीसी)	1,875	2,844	2,408	2,683	2,268	2,467	2,253	1,843	269

नोट- भारत में अपराध के संकलन के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट से 2014-2021 के आंकड़े निकाले गए हैं। सीसीटीएनएस डेटा का इस्तेमाल साल 2022 व 2023 के लिए किया गया है।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

(ग) सरकार ने हर समय राज्य में विधि-व्यवस्था को दुरुस्त रखा है और इसके लिए इसने पुलिस की रणनैतिक तैनाती की है, संकटग्रस्त की सूचना पर उन्हें त्वरित सहायता पहुँचाया है, साइबर थाना, स्पेशल टास्क फ़ोर्स एवं हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जैसे विशेष बल का गठन किया है, साइबर फॉरेंसिक एवं सीसीटीवी सहित उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया है, अतिरिक्त पुलिस बल की भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षित एवं सुसज्जित किया है, समाज-विरोधी तत्वों के ख़िलाफ़ विशेष अभियान चलाया है एवं अपराधियों के ख़िलाफ़ क़ानूनसम्मत सख़्त कार्रवाई की है ताकि उन जैसों को संदेश जाए कि राज्य में क़ानून की अवहेलना सहन नहीं की जाएगी।

———————————

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रुप में दर्जा बढ़ाना

***20.** **श्री धर्म सिंह छोकर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) क्या यह तथ्य है कि समालखा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गांव चुलकाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है तथा उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आस पास कई गांव स्थित हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि साथ लगते विभिन्न गांव उक्त सामुदायिक केन्द्र का लाभ उठा सकें ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): (क) हॉ, श्रीमान् जी।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

———————————

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

सड़कों का निर्माण करना

1. डॉ0 कृष्ण लाल मिड्डा: क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगें किः-

(क) क्या जींद शहर में बाई-पास (एन.एच.) से निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में सीधे प्रवेश करने के लिए कोई नई सड़क का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो इसके कब तक पूरा किए जाने की संभावना है तथा

(ख) क्या ठप्प पड़े रजबाहे को सड़क में रूपांतरित करने के पश्चात् चिकित्सा महाविद्यालय की क्नेक्टिविटी को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है?

उप मुख्यमंत्री (श्री **दुष्यंत चौटाला**): (क) एवं (ख) नहीं श्रीमान जी,

---

रिंग रोड का निर्माण करना

2. डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा: क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या जींद शहर में एक रिंग रोड का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा अलाईनमैंट एन.एच.ए.आई को सौंप दिया गया है; तथा

(ग) यदि हां, तो डी.पी.आर के कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

उप मुख्यमंत्री (श्री **दुष्यंत चौटाला**):

(क) हां, श्रीमान् जी। जींद बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई) के पास विचाराधीन है। एन.एच.ए.आई द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए सलाहकार

नियुक्त किया गया है। इस बाईपास के निर्माण के लिए अभी कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

(ख) जिस अलाईनमैंट विकल्प को हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, उसे एन.एच.ए.आई को सौंप दिया गया है।

(ग) डीपीआर जून, 2023 तक तैयार होने की संभावना है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय का दर्जा बढ़ाना

3. डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा: क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि:–

(क) क्या जींद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव हैबतपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, तथा

(ख) यदि हां, तो इसका दर्जा कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): (क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) इस प्रश्न का इसलिए औचित्य नहीं है।

पंचायतों को जारी की गई राशि

4. श्री बिशन लाल सैनी : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि:

(क) क्या यह तथ्य है कि रादौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 160 गांवों तथा तीन ब्लॉकों अर्थात रादौर ब्लॉक, जगाधरी ब्लॉक तथा सरस्वती नगर ब्लॉक पड़ते हैं;

(ख) 25 फरवरी, 2021 के पश्चात् रादौर विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले तीन ब्लॉकों के गांवों को एन.जी.टी. तथा अन्य योजनाओं से पंचायतों को कितनी

राशि जारी की गई है तथा उक्त खातों का ब्यौरा क्या है जिनमें उक्त राशि जमा की गई थी; तथा

(ग) उपरोक्त राशि से निष्पादित किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा अधूरे पड़े विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): (क) हाँ श्रीमान, रादौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 158 गाँव हैं जो तीन ब्लॉक में पड़ते हैं जिनका नाम जगाधरी ब्लॉक, रादौर ब्लॉक तथा सरस्वती नगर ब्लॉक है;

(ख) 25 फरवरी, 2021 के पश्चात् रादौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तीन ब्लॉकों की पंचायतों के खाते में हरियाणा ग्रामीण विकास योजना, पंद्रहवें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत मु0 22,82,33,825/–रू0 (22.82 करोड रू0) की राशि जारी की गई है। खातों का विवरण **अनुबन्ध "क"** पर संलग्न है; तथा

(ग) उपरोक्त जारी राशि में से 81 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 25 अभी पूर्ण नहीं हैं तथा 32 अभी शुरू किए जाने हैं (कार्यवार विवरण **अनुबन्ध "ख"** पर सलंग्न है)।

Annexure - A

Annexure-A (Un-Starred Question no. 14/15/119) Amount Released to Gram Panchayats

Details of works in which funds released

Sr No.	Name of the Block	Name of the Gram Panchayat in Assembly Constituency	Amount received in gram panchayat after 23-02-2021	Name of the Scheme	Account No. and Bank Name in which amount was received
1	JAGADHRI	RATTAN GARH	211000	HGVY	50100230921996-HDFC BANK
2	JAGADHRI	SUDHAIL	42000	HGVY	50100230960900 & HDFC BANK YNR-II
3	JAGADHRI	SUDHAIL	786000	HGVY	50100230934586-HDFC BANK
4	JAGADHRI	GOLANPUR	652000	HGVY	50100231079621 & HDFC BANK JORION
5	JAGADHRI	KHURDI	693000	HGVY	50100231198894 & HDFC BANK SHADIPUR
6	JAGADHRI	NAGAL	1000000	HGVY	50100231065238 & HDFC BANK SHADIPUR
7	JAGADHRI	HAFIJ PUR	352000	HGVY	50100231065659 & HDFC BANK SHADIPUR
8	JAGADHRI	KARERA KHURD-II	352000	HGVY	50100231062867 & HDFC BANK
9	JAGADHRI	SABHAPUR	667000	HGVY	50100231065251-HDFC BANK SHADIPUR
10	JAGADHRI	TAPU KAMALPUR	313000	HGVY	50100231291188-HDFC BANK
11	JAGADHRI	TAPU KAMALPUR	646000	HGVY	50100231291188-HDFC BANK
12	JAGADHRI	TODARPUR	1509000	HGVY	50100231063860-HDFC BANK
13	JAGADHRI	AKALGARH	222380	XVFC	37010001021720 93 & PNB BANK
14	JAGADHRI	BAHADURPUR	383333	XVFC	4059000105047364 & PNB BANK
15	JAGADHRI	DAMLA	1853311	XVFC	0471000102261875 & PNB BANK
16	JAGADHRI	DAULATPUR JAGIR	298576	XVFC	0471000102262388 & PNB BANK
17	JAGADHRI	DHORANG	513893	XVFC	4059000105047382 & PNB BANK
18	JAGADHRI	DUDHLA	421431	XVFC	4059000105047470 & PNB BANK
19	JAGADHRI	DUSANI	391252	XVFC	0471000102261909 & PNB BANK
20	JAGADHRI	GOLANPUR	145114	XVFC	0471000102261954 & PNB BANK
21	JAGADHRI	HAFIJ PUR	166518	XVFC	0471000102261972 & PNB BANK
22	JAGADHRI	HARIA BANS	144686	XVFC	0471000102262209 & PNB BANK
23	JAGADHRI	HARNOL	293225	XVFC	0471000102262005 & PNB BANK
24	JAGADHRI	ISHAR PUR	175079	XVFC	0471000102261608 & PNB BANK
25	JAGADHRI	JAI PUR	241215	XVFC	0471000102262227 & PNB BANK
26	JAGADHRI	JHINJRON	118360	XVFC	1945000111137294 & PNB BANK
27	JAGADHRI	KARERA KHURD-I	411586	XVFC	0471000102262254 & PNB BANK
28	JAGADHRI	KARERA KHURD-II	254699	XVFC	0471000102262263 & PNB BANK
29	JAGADHRI	KALANAUR	325544	XVFC	0471000102262245 & PNB BANK
30	JAGADHRI	KHAJURI	642741	XVFC	0471000102262281 & PNB BANK
31	JAGADHRI	KHURDI	434915	XVFC	0471000102262306 & PNB BANK
32	JAGADHRI	KUNJAL JATTAN	221952	XVFC	1945000111137276 & PNB BANK
33	JAGADHRI	KUNJAL KAMBOYAN	178718	XVFC	4059000105047276 & PNB BANK
34	JAGADHRI	MANDOLI	636106	XVFC	37010001021722 15 & PNB BANK
35	JAGADHRI	NAGAL	350586	XVFC	0471000102262078 & PNB BANK
36	JAGADHRI	NAHAR PUR	951590	XVFC	0471000102262096 & PNB BANK
37	JAGADHRI	RATTAN GARH	360217	XVFC	1945000111066668-PNB BANK
38	JAGADHRI	ROAD CHHAPAR	146184	XVFC	0471000102261918-PNB BANK
39	JAGADHRI	SABHAPUR	134627	XVFC	4059000105047267-PNB BANK
40	JAGADHRI	SUDHAIL	358078	XVFC	0471000102261990-PNB BANK
41	JAGADHRI	SUDHAL	156030	XVFC	0471000102261820-PNB BANK
42	JAGADHRI	SUKHPURA	249563	XVFC	0471000102262050-PNB BANK
43	JAGADHRI	TAPU KAMALPUR	376484	XVFC	0471000102262087-PNB BANK
44	JAGADHRI	TIGRA	366210	XVFC	0471000102262120-PNB BANK
45	JAGADHRI	TIGRI	222166	XVFC	0471000102262139-PNB BANK
46	JAGADHRI	TODARPUR	502764	XVFC	1945000111135551-PNB BANK
1	Radaur	Alahar	1141110	FFC	1355001702042730
	Radaur	ALAHAR	753000	HGVY	50100231426716
2	Radaur	Alipura	284192	FFC	1355001702042590
	Radaur	ALIPURA	1000000	HGVY	50100231067626
3	Radaur	Amloha	171808	FFC	1355001702042545
4	Radaur	Antawa	464044	FFC	1355000100047156
	Radaur	ANTAWA	200000	HGVY	50100231390060
5	Radaur	Baindi	566149	FFC	1355001702042369
	Radaur	BAINDI	438000	HGVY	50100236049753
6	Radaur	Bakana	836583	FFC	1355001702042420
7	Radaur	Bapa	601760	FFC	1355001702042554
8	Radaur	Bapoli	284431	FFC	1355001702042439
9	Radaur	Barheri	426366	FFC	1355001702042466
	Radaur	BARHERI	800000	HGVY	50100231066497
10	Radaur	Barsan	359515	FFC	1355001702042457
	Radaur	BARSAN	597000	HGVY	50100231066484
11	Radaur	Basant Pura	230535	FFC	1355001702042271
12	Radaur	Bhagu Majra	252382	FFC	1355001702042244
	Radaur	BHAGU MAJRA	400000	HGVY	50100231063672
13	Radaur	Bhagwangarh	211554	FFC	1355001702042484
	Radaur	BHAGWAN GARH	114000	HGVY	50100231286942
	Radaur	BHAGWAN GARH	305000	HGVY	50100231286942
14	Radaur	Bubka	548748	FFC	1355001702042563
	Radaur	BUBKA	650000	HGVY	50100231069148
15	Radaur	Chamroli	467861	FFC	1355001702042341
	Radaur	CHAMRORI	450000	HGVY	50100231963818
16	Radaur	Chhali	419039	FFC	1355001702042350

Sr No.	Name of the Block	Name of the Gram Panchayat In Assembly Constituency	Amount received in gram panchayat after 23-02-2021	Name of the Scheme	Account No. and Bank Name in which amount was received
17	Radaur	Daulat Pur	405820	FFC	1355001702042396
18	Radaur	Dhanupura	142174	FFC	4824000400004923
	Radaur	DHANUPURA	349000	HGVY	50100231963804
19	Radaur	Dholi	213502	FFC	1355001702042387
20	Radaur	Dholra	537420	FFC	1355001702042615
	Radaur	DHAULRA	797500	HGVY	50100231068718
21	Radaur	Fateh Garh	257542	FFC	1355001702042509
	Radaur	FATEHGARH	400000	HGVY	50100230951660
	Radaur	FATEHGARH	600000	HGVY	50100230951660
22	Radaur	Gheshpur	298883	FFC	1355001702042624
	Radaur	GHESPUR	500000	HGVY	50100231063768
23	Radaur	Ghilour	1014573	FFC	1355001702042378
	Radaur	GHILOUR MAJRI	500000	HGVY	50100231197813
24	Radaur	GUMTHALA RAO	1437117	FFC	1355001702042758
	Radaur	GUMTHALA RAO	396000	HGVY	50100231068122
	Radaur	GUMTHALA RAO	600000	HGVY	50100231068122
25	Radaur	Harlan	524091	FFC	1355000100021060
26	Radaur	Hiran Chappar	237862	FFC	1355001702042280
	Radaur	HIRAN CHHAPPAR	931000	HGVY	50100231282930
27	Radaur	Ismailpur	186236	FFC	1355000104012927
	Radaur	ISMAILPUR	500000	HGVY	50100231282942
28	Radaur	JATHLANA	500000	HGVY	50100231065672
	Radaur	JATHLANA	1813000	HGVY	50100231065672
	Radaur	JATHLANA	1000000	HGVY	50100231065672
	Radaur	Jathlana	1643615	FFC	1355001702042697
29	Radaur	Jhaguri	876764	FFC	1355001702042262
	Radaur	JHAGURI	700000	HGVY	50100231290988
30	Radaur	JHINWAR HERI	328000	HGVY	50100231290980
	Radaur	JHINWAR HERI	159000	HGVY	50100231290980
	Radaur	JHINWAR HERI	408000	HGVY	50100231290980
	Radaur	Jhinverheri	265025	FFC	1355001702042299
31	Radaur	Jubbal	785312	FFC	1355001702042749
	Radaur	JUBAL	667000	HGVY	50100231068336
32	Radaur	Kandroli	390495	FFC	1355001702042767
33	Radaur	Kanjnu	550527	FFC	1355001702042679
	Radaur	KANJNU	1000000	HGVY	50100231055605
34	Radaur	Karera M.T.	626564	FFC	1355001702042527
	Radaur	KARERA M.T.	600000	HGVY	50100231066636
35	Radaur	Kartarpur	221361	FFC	50100439595151
36	Radaur	Khajuri	361252	FFC	1355001702042633
37	Radaur	Kheri Lakha Singh	161183	FFC	1355000102035492
	Radaur	KHERI LAKHA SINGH	728000	HGVY	50100231192978
38	Radaur	Kherki Brahmnan	341275	FFC	1355000302042409
39	Radaur	Khurdban	451236	FFC	1355001702042660
40	Radaur	Lakshi Bans	241769	FFC	1355001702042785
	Radaur	Lakshi Bans	800000	HGVY	50100231257732
41	Radaur	LAL CHHAPAR	1256000	HGVY	50100231935094
	Radaur	Lal Chappar	294030	FFC	1355001702042721
42	Radaur	Madhobans	273632	FFC	1355001702042794
43	Radaur	Mandhar	336234	FFC	1355001702042651
44	Radaur	Mansoor Pur	240282	FFC	1355001702042305
45	Radaur	Marupur	248040	FFC	1355001702042703
	Radaur	MARU-PUR	718000	HGVY	50100231066191
46	Radaur	MASANA RANGHRAN	1000000	HGVY	50100231066741
	Radaur	Masana Rangran	356963	FFC	1355000102035298
47	Radaur	Mohri	443654	FFC	1355001702042776
48	Radaur	Nachron	700946	FFC	1355001702042688
	Radaur	NACHRAON	1439000	HGVY	50100231067869
49	Radaur	Nagal	239074	FFC	1355001702042314
	Radaur	NAGAL	565000	HGVY	50100231067218
50	Radaur	Nagla Sadhan	296946	FFC	1355000100031562
51	Radaur	Palaka	226586	FFC	1355001702042581
	Radaur	PALAKHA	500000	HGVY	50100231064669
52	Radaur	Palewala	413369	FFC	1355001702042448
	Radaur	PALEWALA	946000	HGVY	50100231064107
	Radaur	PALEWALA	950000	HGVY	50100231064107
53	Radaur	Passi Dera	176679	FFC	50100438865063
54	Radaur	Potli	463428	FFC	1355001702042642
	Radaur	POTLI	1000000	HGVY	50100231391712
55	Radaur	Purangarh (55)	294746	FFC	1355001702042819
56	Radaur	Radauri	397714	FFC	1355001702042800
	Radaur	RADAURI	691000	HGVY	50100231292422
57	Radaur	Rajheri	402161	FFC	1355001702042572
58	Radaur	Rapri	200972	FFC	4824000400004941
	Radaur	RAPRI	797500	HGVY	50100230943151
59	Radaur	Rattan Garh	257097	FFC	1355001702042475
60	Radaur	Sadhura	327710	FFC	1355001702042536
61	Radaur	Sagri	390364	FFC	1355001702036322
62	Radaur	Sandhala	422241	FFC	1355001702042411
	Radaur	SANDHALA	300000	HGVY	50100231391521
63	Radaur	Sandhali	411910	FFC	1355001702042518

81

Sr No.	Name of the Block	Name of the Gram Panchayat in Assembly Constituency	Amount received in gram panchayat after 23-02-2021	Name of the Scheme	Account No. and Bank Name in which amount was received
63	Radaur	SANDHALI	500000	HGVY	
64	Radaur	Sangi Pur	353748	FFC	1355001702042606
65	Radaur	Salgoli	194078	FFC	1355001702042253
66	Radaur	Sikandra	222724	FFC	1355001702042235
	Radaur	SIKANDERA	773000	HGVY	50100231387691
67	Radaur	SILI KALAN	1000000	HGVY	50100231067501
	Radaur	Silli Kalan	330852	FFC	1355001702042323
68	Radaur	Silli Khurd	281361	FFC	1355001702042332
69	Radaur	Thaska Khader	540193	FFC	1355001702042493
70	Radaur	Topra Kalan	489226	FFC	1355000100021042
	Radaur	TOPRA KALAN	1434000	HGVY	50100231388247
71	Radaur	UNHERI	425000	HGVY	50100231388216
	Radaur	Unheri	636799	FFC	1355001702042712
1	Saraswati Nagar	Akbarpur	252816	XVFC	1419000103104880
2	Saraswati Nagar	Badanpuri	204401	XVFC	1419000103104909
	Saraswati Nagar	Badanpuri	400000	HGVY	6396000100013081
3	Saraswati Nagar	Bhogpur	250419	XVFC	1419000103104954
	Saraswati Nagar	Bhogpur	300000	HGVY	6396000100013133
	Saraswati Nagar	Bhogpur	666000	HGVY	6396000100013133
4	Saraswati Nagar	Bhure ka Majra	408674	XVFC	1419000103104963
5	Saraswati Nagar	Bir BalSua	289856	XVFC	1419000103104972
	Saraswati Nagar	Bir BalSua	150000	HGVY	6396000100013142
	Saraswati Nagar	Bir BalSua	300000	HGVY	6396000100013142
	Saraswati Nagar	Bir BalSua	150000	HGVY	6396000100013142
6	Saraswati Nagar	Daulatpur Maliyan	278243	XVFC	1419000103105005
	Saraswati Nagar	Daulatpur Maliyan	1245000	HGVY	6396000100013179
	Saraswati Nagar	Daulatpur Maliyan	2000000	HGVY	6396000100013179
7	Saraswati Nagar	Faridpur	111939	XVFC	1419000103105023
	Saraswati Nagar	Faridpur	500000	HGVY	6396000100013188
	Saraswati Nagar	Faridpur	691000	HGVY	6396000100013188
8	Saraswati Nagar	Fatehpur - 448	317625	XVFC	1419000103105014
	Saraswati Nagar	Fatehpur - 448	495000	HGVY	6396000100013197
	Saraswati Nagar	Fatehpur - 448	500000	HGVY	6396000100013197
	Saraswati Nagar	Fatehpur - 448	919000	HGVY	6396000100013197
9	Saraswati Nagar	Garhi Sikandra	127564	XVFC	1419000103105078
	Saraswati Nagar	Garhi Sikandra	700000	HGVY	6396000100013230
10	Saraswati Nagar	Golni	447543	XVFC	1419000103105087
	Saraswati Nagar	Golni	500000	HGVY	6396000100013249
11	Saraswati Nagar	Gundiyana	538079	XVFC	1419000103105102
12	Saraswati Nagar	Gundiyani	107016	XVFC	1419000103105564
13	Saraswati Nagar	Hasanpur	188991	XVFC	6396000100054538
	Saraswati Nagar	Hasanpur	358000	HGVY	6396000100054529
	Saraswati Nagar	Hasanpur	898000	HGVY	6396000100054529
	Saraswati Nagar	Hasanpur	997000	HGVY	6396000100054529
14	Saraswati Nagar	Hudia	156841	XVFC	6396000100054538
	Saraswati Nagar	Hudia	65000	HGVY	6396000100054495
15	Saraswati Nagar	Jamalpur	157101	XVFC	1419000103105139
16	Saraswati Nagar	Jhar Chandana	153248	XVFC	1419000103131444
	Saraswati Nagar	Jhar Chandana	224000	HGVY	6396000100013328
17	Saraswati Nagar	Kabulpur	249348	XVFC	1419000103105157
	Saraswati Nagar	Kabulpur	249000	HGVY	6396000100013337
18	Saraswati Nagar	Kazi Bans	146613	XVFC	1419000103105166
19	Saraswati Nagar	Kool Pur	243141	XVFC	1419000103105263
	Saraswati Nagar	Kool Pur	1000000	HGVY	6396000100013434
	Saraswati Nagar	Kool Pur	643000	HGVY	6396000100013434
20	Saraswati Nagar	Massana Jattan	88181	XVFC	1419000103105360
	Saraswati Nagar	Massana Jattan	1445000	HGVY	6396000100013531
21	Saraswati Nagar	Mehmadpur	194556	XVFC	1419000103105333
22	Saraswati Nagar	Rapoli	426782	XVFC	1419000103105555
23	Saraswati Nagar	Ram garh	110655	XVFC	6396000100053973
	Saraswati Nagar	Ram garh	500000	HGVY	6396000100053955
24	Saraswati Nagar	Sahabpura	200763	XVFC	1419000103105458
25	Saraswati Nagar	Saran	966787	XVFC	1419000103105467
	Saraswati Nagar	Saran	500000	HGVY	6396000100013683
	Saraswati Nagar	Saran	500000	HGVY	6396000100013683
	Saraswati Nagar	Saran	500000	HGVY	6396000100013683
	Saraswati Nagar	Saran	120000	HGVY	6396000100013683
26	Saraswati Nagar	Topra Khurd	134413	XVFC	1419000103105537
27	Saraswati Nagar	Uncha Chandana	715294	XVFC	1419000103105546
	Saraswati Nagar	Uncha Chandana	397000	HGVY	6396000100013762
	Saraswati Nagar	Uncha Chandana	55000	HGVY	6396000100013762
	Saraswati Nagar	Uncha Chandana	81000	HGVY	6396000100013762
28	Saraswati Nagar	Tehi	0	Nil	Nil

Funds Released In Child Account					
	Name of the Block	NAME OF G.P. IN RADAUR CONSTITUENCY	Stato Financo Commission(SFC) AMT. IN CHILD ACOUNT (RECEIVED IN JAN. 2023)	Fifteenth FINANCE COMMISSION (FFC) GRANT (RECEIVED IN JAN. 2023)	
1	Saraswati Nagar	Akbarpur	614000	101678	Child Account
2	Saraswati Nagar	Badan Puri	494000	81776	Child Account
3	Saraswati Nagar	Bhogpur	454000	75197	Child Account
4	Saraswati Nagar	Bhure Ka Majra	200000	31311	Child Account
5	Saraswati Nagar	Bir Balsuha	415000	68785	Child Account
6	Saraswati Nagar	Daulatpur Maliyan	702000	116168	Child Account
7	Saraswati Nagar	Faridpur	277000	45801	Child Account
8	Saraswati Nagar	Fatehpur -448	786000	130158	Child Account
9	Saraswati Nagar	Gathi Sikandra	480000	79414	Child Account
10	Saraswati Nagar	Gehi	1127000	186618	Child Account
11	Saraswati Nagar	Gundiyana	1393000	230587	Child Account
12	Saraswati Nagar	Gundyani	321000	53212	Child Account
13	Saraswati Nagar	Hasanpur	429000	70950	Child Account
14	Saraswati Nagar	Hudia	221000	36558	Child Account
15	Saraswati Nagar	Jamalpur	423000	70034	Child Account
16	Saraswati Nagar	Jhar Chandana	387000	64121	Child Account
17	Saraswati Nagar	Kabulpur	605000	100096	Child Account
18	Saraswati Nagar	Kazi Bans	389000	64371	Child Account
19	Saraswati Nagar	Koolpur	574000	95100	Child Account
20	Saraswati Nagar	Masana Jattan	218000	36058	Child Account
21	Saraswati Nagar	Mehmad Pur	360000	59541	Child Account
22	Saraswati Nagar	Ramgarh	200000	32061	Child Account
23	Saraswati Nagar	Rapouli	1082000	179207	Child Account
24	Saraswati Nagar	Sahabpura	503000	83358	Child Account
25	Saraswati Nagar	Saran	2338000	387060	Child Account
26	Saraswati Nagar	Tehi	427000	70617	Child Account
27	Saraswati Nagar	Topra Khurd	338000	55960	Child Account
28	Saraswati Nagar	Ucha Chandna	1729000	286211	Child Account
29	JAGADHRI	Akalgarh	632000	104676	Child Account
30	JAGADHRI	Bahadurpur	995000	164800	Child Account
31	JAGADHRI	Damla	4028000	666862	Child Account
32	JAGADHRI	Daulatpur Jagir	814000	134821	Child Account
33	JAGADHRI	Dhorang	1087000	179956	Child Account
34	JAGADHRI	Dudhla	1105000	182871	Child Account
35	JAGADHRI	Dusani	953000	157722	Child Account
36	JAGADHRI	Golanpur	349000	57709	Child Account
37	JAGADHRI	Hafij Pur	400000	66203	Child Account
38	JAGADHRI	Haria Bans	363000	60124	Child Account
39	JAGADHRI	Harnol	695000	115085	Child Account
40	JAGADHRI	Ishar Pur	455000	75280	Child Account
41	JAGADHRI	Jai Pur	621000	102844	Child Account
42	JAGADHRI	Jhinjron	276000	45718	Child Account
43	JAGADHRI	Karera Khurd-I	1164000	192781	Child Account
44	JAGADHRI	Karera Khurd-II	460000	76196	Child Account
45	JAGADHRI	Kalanour	803000	132906	Child Account
46	JAGADHRI	Khajuri	1515000	250823	Child Account
47	JAGADHRI	Khurdi	1090000	180539	Child Account
48	JAGADHRI	Kunjal Jattan	558000	92435	Child Account
49	JAGADHRI	Kunjal Kamboyan	437000	72282	Child Account
50	JAGADHRI	Mandoli	1636000	270809	Child Account
51	JAGADHRI	Nagal	888000	146980	Child Account
52	JAGADHRI	Nahar Pur	2561000	423951	Child Account
53	JAGADHRI	Rattan Garh	728000	120582	Child Account
54	JAGADHRI	Road Chhapar	366000	60624	Child Account
55	JAGADHRI	Sabhapur	378000	62539	Child Account
56	JAGADHRI	Sudhail	820000	135821	Child Account
57	JAGADHRI	Sudhal	380000	62956	Child Account
58	JAGADHRI	Sukhpura	602000	99596	Child Account
59	JAGADHRI	Tapu Kamalpur	960000	158971	Child Account
60	JAGADHRI	Tigra	974000	161303	Child Account
61	JAGADHRI	Tigri	519000	85939	Child Account
62	JAGADHRI	Todarpur	620000	102677	Child Account
63	Radaur	Alahar	2032000	336346	Child Account
64	Radaur	Alipura	507000	83857	Child Account
65	Radaur	Amloha	289000	47883	Child Account
66	Radaur	Antawa	861000	142566	Child Account
67	Radaur	Baindi	1006000	166549	Child Account
68	Radaur	Bakana	1516000	250989	Child Account
69	Radaur	Bapa	1145000	189533	Child Account
70	Radaur	Bapoli	511000	84524	Child Account
71	Radaur	Barheri	762000	126078	Child Account
72	Radaur	Barsan	593000	98181	Child Account
73	Radaur	Basant Pura	419000	69368	Child Account
74	Radaur	Bhagu Majra	471000	77945	Child Account
75	Radaur	Bhagwangarh	377000	62373	Child Account
76	Radaur	Bubka	955000	158138	Child Account

82

	Name of the Block	NAME OF G.P. IN RADAUR CONSTITUENCY	State Financo Commission(SFC) AMT. IN CHILD ACOUNT (RECEIVED IN JAN. 2023)	Fifteenth FINANCE COMMISSION (FFC) GRANT (RECEIVED IN JAN. 2023)	
77	Radaur	Chamroli	712000	117917	Child Account
78	Radaur	Chhari	735000	121747	Child Account
79	Radaur	Daulat Pur	771000	127577	Child Account
80	Radaur	Dhanupura	255000	42220	Child Account
81	Radaur	Dholi	354000	58542	Child Account
82	Radaur	Dholra	989000	163718	Child Account
83	Radaur	Fateh Garh	475000	78611	Child Account
84	Radaur	Ghoshpur	569000	94267	Child Account
85	Radaur	Ghilour	1792000	296707	Child Account
86	Radaur	Gumthala	2483000	411043	Child Account
87	Radaur	Harlan	1046000	173211	Child Account
88	Radaur	Hiran Chappar	454000	75197	Child Account
89	Radaur	Ismailpur	338000	55960	Child Account
90	Radaur	Jathlana	3816000	631721	Child Account
91	Radaur	Jhaguri	693000	114752	Child Account
92	Radaur	Jhinverheri	467000	77362	Child Account
93	Radaur	Jubbal	1081000	178957	Child Account
94	Radaur	Kandroli	660000	109256	Child Account
95	Radaur	Kanjnu	886000	146646	Child Account
96	Radaur	Karera M.T.	1132000	187368	Child Account
97	Radaur	Kartarpur	220000	36474	Child Account
98	Radaur	Khajuri	798000	132073	Child Account
99	Radaur	Kheri Lakha Singh	257000	42470	Child Account
100	Radaur	Kherki Brahmnan	341000	56377	Child Account
101	Radaur	Khurdban	1004000	166299	Child Account
102	Radaur	Lakshi Bans	405000	67036	Child Account
103	Radaur	Lal Chappar	550000	91102	Child Account
104	Radaur	Madhobans	453000	75030	Child Account
105	Radaur	Mandhar	663000	109756	Child Account
106	Radaur	Mansoor Pur	454000	75114	Child Account
107	Radaur	Marupur	361000	59791	Child Account
108	Radaur	Masana Rangran	750000	124246	Child Account
109	Radaur	Mohri	501000	83025	Child Account
110	Radaur	Nachron	1535000	254071	Child Account
111	Radaur	Nagal	414000	68618	Child Account
112	Radaur	Nagla Sadhan	359000	59375	Child Account
113	Radaur	Palaka	412000	68202	Child Account
114	Radaur	Palewala	685000	113420	Child Account
115	Radaur	Pasai Dera	200000	31894	Child Account
116	Radaur	Potli	849000	140567	Child Account
117	Radaur	Purangarh (55)	346000	57293	Child Account
118	Radaur	Radauri	933000	154474	Child Account
119	Radaur	Rajheri	867000	143482	Child Account
120	Radaur	Rapri	325000	53879	Child Account
121	Radaur	Rattan Garh	456000	75447	Child Account
122	Radaur	Sadhura	498000	82525	Child Account
123	Radaur	Sagri	610000	100929	Child Account
124	Radaur	Sandhala	746000	123496	Child Account
125	Radaur	Sandhali	920000	152392	Child Account
126	Radaur	Sangi Pur	670000	111005	Child Account
127	Radaur	Satgoli	296000	48965	Child Account
128	Radaur	Sikandra	473000	78278	Child Account
129	Radaur	Silli Kalan	547000	90519	Child Account
130	Radaur	Silli Khurd	230000	38140	Child Account
131	Radaur	Thaska Khader	708000	117251	Child Account
132	Radaur	Topra Kalan	1221000	202107	Child Account
133	Radaur	Unheri	1545000	255819	Child Account

83

Annexure

Annexure-B (Un-Starred Question no. 14/15/119) Amount Released to Gram Panchayats								
Completed Works								
Sr No.	Name of the Block	Name of the Gram Panchayat in Radaur Assembly Constituency	Amount received in gram panchayat after 23-02-2021	Name of The Scheme	Amount Received	Account No. and Bank Name in which amount was received	Detail of Development work executed	Detail of work which are incomplete
1	Radaur	ALAHAR	753000	HGVY	753000	50100231426716	IPB street from badi dharamshala to house of waryam	
2	Radaur	BAINDI	438000	HGVY	438000	50100236049753	Street from hosue of puran to mam charan	
3	Radaur	Bapoli	284431	FFC	284431	1355001702042439	E-Riksha and fogging	
4	Radaur	Barsan	359515	FFC	359515	1355001702042457	Instalation of Nalka and repair, Sanitation etc.	
5	Radaur	Basant Pura	230535	FFC	230535	1355001702042271	Const. of street ,Riksha	
6	Radaur	BHAGU MAJRA	400000	HGVY	400000	50100231063672	IPB street from main street to jasbir saini	
7	Radaur	BHAGWAN GARH	305000	HGVY	305000	50100231286942	Const. of street from house of chiranji lal via house of anil to bir singh	
8	Radaur	BUBKA	650000	HGVY	650000	50100231069148	Const. of boundary wall of ambedkar bhawan	
9	Radaur	Dhanupura	142174	FFC	142174	4824000400004923	Riksha ,Sanitation , Kit	
10	Radaur	DHANUPURA	349000	HGVY	349000	50100231963804	B/wall of community centre	
11	Radaur	FATEHGARH	400000	HGVY	400000	50100230951630	Const of Street from inder Raj Towards h/o Schan	
12	Radaur	FATEHGARH	600000	HGVY	600000	50100230951660	Const. of b/wall and yard of community centre	
13	Radaur	GHESPUR	500000	HGVY	500000	50100231033763	Const of Room Near Choupal in Chungi Colony	
14	Radaur	Ghilour	1014573	FFC	1014573	1355001702042378	Const. of Shiv Dham shed and Rasta, Sweepar and chowkidar honorarium	
15	Radaur	GUMTHALA RAO	1437117	FFC	1437117	1355001702042758	Const. of street from Main Road to school gate, mahboob to Gurnam, Varyam wali Street, Sita ram wali Street, Sonu Member wali gali, Sanitation and electric work	
16	Radaur	GUMTHALA RAO	396000	HGVY	396000	50100231063122	IPB street from aggarsain school to house of thath singh	
17	Radaur	Hartan	524091	FFC	524091	1355000100021060	Const. of pipe line from main gali to h/o Prem Chand and Street in Community Center	
18	Radaur	ISMAILPUR	500000	HGVY	500000	50100231282942	Street from house of niranjan to pala ram	
19	Radaur	Jathlana	1643615	FFC	1643615	1355001702042697	Const. of Angal round the Johar, const. of 6 street,	
20	Radaur	Jhaguri	876764	FFC	876764	1355001702042262	Street Repair in Gram Sabha Arear	
21	Radaur	JHINWAR HERI	328000	HGVY	328000	50100231290980	PB street from house of shanti to main street	
22	Radaur	JHINWAR HERI	159000	HGVY	159000	50100231290980	Laying of paver in yard of harijan choupal	
23	Radaur	JHINWAR HERI	408000	HGVY	408000	50100231290980	Laying of paver in yard of ambeckar bhawan	
24	Radaur	Jhinverheri	265925	FFC	265925	1355001702042299	Honorarium of village sweepar	
25	Radaur	KANJNU	1000000	HGVY	1000000	50100231055605	Laying of pipe line from house of pirthi singh to pond	

Sr No.	Name of the Block	Name of the Gram Panchayat in Radaur Assembly Constituency	Amount received in gram panchayat after 23-02-2021	Name of The Scheme	Amount Received	Account No. and Bank Name in which amount was received	Detail of Development work executed	Detail of work which are incomplete
26	Radaur	Kheri Lakha Singh	161183	FFC	161183	1355000102035492	Pipe Line lekage, Riksha	
27	Radaur	KHERI LAKHA SINGH	728000	HGVY	728000	50100231192978	Laying paver block in yard and b/wall of ambedkar bhawan	
28	Radaur	Khurdban	451236	FFC	451236	1355001702042660	Pipe Line in Passi dera near Anganwari Center	
29	Radaur	Lal Chappar	294030	FFC	294030	1355001702042721	Sanitation and Repair	
30	Radaur	Marupur	248040	FFC	248040	1355001702042703	Const. of street	
31	Radaur	Masana Rangran	356963	FFC	356963	1355000102035298	Riksha, pond water	
32	Radaur	NAGAL	565000	HGVY	565000	50100231067218	Street from main road to government school	
33	Radaur	PALAKHA	500000	HGVY	500000	50100231064669	Const of Street from h/o Ranbeer Valmiki to Balinder Kamboj.	
34	Radaur	PALEWALA	946000	HGVY	946000	50100231064107	Const of Street from h/o Ram Kumar to Naveen Sharma	
35	Radaur	PALEWALA	950000	HGVY	950000	50100231064107	Street from house of gaje singh to khera baba	
36	Radaur	POTLI	1000000	HGVY	1000000	50100231391712	Street from house of niranjan singh to manmeet	
37	Radaur	Radauri	397714	FFC	397714	1355001702042800	E-Riksha, Sanitation and fogging	
38	Radaur	Sandhali	411910	FFC	411910	1355001702042518	Const. of street	
39	Radaur	SANDHALI	500000	HGVY	500000		Regarding installation of chaupal rooms and paver blocks.	
40	Radaur	Silli Khurd	281361	FFC	281361	1355001702042332	Riksha ,Sanitation , Kit	
41	Radaur	UNHERI	425000	HGVY	425000	50100231388216	IPB Street from house of Asra to Tasim	
42	Radaur	Unheri	636799	FFC	636799	1355001702042712	Street Repair	
43	Saraswati Nagar	Akbarpur	252816	XVFC	252816	1419000103104880	const of paver block tiles work in ground of BC Chaupal tehi,	
44	Saraswati Nagar	Badanpuri	204401	XVFC	204401	1419000103104909	cleaning work in public places, purchase E- Riksha,	
45	Saraswati Nagar	Bhogpur	300000	HGVY	300000	6396000100013133	const of street from pwd road to ambedkar bhawan	
46	Saraswati Nagar	Bhure ka Majra	408674	XVFC	408674	1419000103104963	pwd road near tiles work, saintation work, demarcation fees, and etc	
47	Saraswati Nagar	Bir BalSua	289856	XVFC	289856	1419000103104972	water harvesting system near school and part time sweeper sallary, and demarcation fees bl dera	
48	Saraswati Nagar	Bir BalSua	300000	HGVY	300000	6396000100013142	Const of street Gurudwara	
49	Saraswati Nagar	Bir BalSua	150000	HGVY	150000	6396000100013142	Const. of street from h/o Devender Singh to h/o Arjun Singh	
50	Saraswati Nagar	Daulatpur Maliyan	278243	XVFC	278243	1419000103105005	PVC Pipe and poliya nirman of Hukam singh,Repair of Drain. Saintation work Completion work toielt etc	
51	Saraswati Nagar	Faridpur	111939	XVFC	111939	1419000103105023	sanitation work and purchage e- rikshaw, and other drinking water works	
52	Saraswati Nagar	Fatehpur - 448	500000	HGVY	500000	6396000100013197	Const of street from PWD road to village khan ahmad road via geat of karmjeet saini	

84

Sr No.	Name of the Block	Name of the Gram Panchayat in Radaur Assembly Constituency	Amount received in gram panchayat after 23-02-2021	Name of The Scheme	Amount Received	Account No. and Bank Name in which amount was received	Detail of Development work executed	Detail of work which are incomplet
53	Saraswati Nagar	Garhi Sikandra	127564	XVFC	127564	1419000103105078	Pipe line repair main to panchayati land, repair drinking water pipe line	
54	Saraswati Nagar	Garhi Sikandra	700000	HGVY	700000	6396000100013230	Const. Of street from mata sthan to h/o Isam Singh	
55	Saraswati Nagar	Golni	447543	XVFC	447543	1419000103105087	saintation work and motar and pipe line maintance work	
56	Saraswati Nagar	Gundiyana	538079	XVFC	538079	1419000103105102	const of street near public health tubewell, Const of Street Pawan number to s/ghat, Const of street public health tubewell to field of pawan numberdar and sanitation work	
57	Saraswati Nagar	Gundiyani	107016	XVFC	107016	1419000103105564	Pipe line repair main pond to panchayati lan, drinking water work	
58	Saraswati Nagar	Hasanpur	188991	XVFC	188991	6396000100054538	Maintance of water supply pipe line and tubewell and other work	
59	Saraswati Nagar	Hudia	156841	XVFC	156841	6396000100054538	Nala repair Phirni to Nahar singh,	
60	Saraswati Nagar	Jamalpur	157101	XVFC	157101	1419000103105139	Drinking water supply motor repair and public health tubewell paint work in room, drinking water supply pipe line repair	
61	Saraswati Nagar	Jhar Chandana	153248	XVFC	153248	1419000103131444	Moter winding starter repair,Pipe line likag repair	
62	Saraswati Nagar	Jhar Chandana	224000	HGVY	224000	6396000100013328	Const. of street from Kheda Baba to h/o Inder Jeet	
63	Saraswati Nagar	Kabulpur	249348	XVFC	249348	1419000103105157	saintation work and drinking water work	
64	Saraswati Nagar	Kabulpur	249000	HGVY	249000	6396000100013337	Const of ground with IPB in BC choupal	
65	Saraswati Nagar	Kazi Bans	146613	XVFC	146613	1419000103105166	sanitation work sc chaupal, and cleaning of nala near govt school, water supply pipe line repair etc	
66	Saraswati Nagar	Kool Pur	243141	XVFC	243141	1419000103105263	cleaning of school and SC chaupal, cleaning main phirni, cleaning of main nala etc	
67	Saraswati Nagar	Massana Jattan	88181	XVFC	88181	1419000103105360	Drinking water supply pipe line maintance and cleaning of street and drain	
68	Saraswati Nagar	Mehmadpur	194556	XVFC	194556	1419000103105333	water pipe line work in panchayati land and sanitation	
69	Saraswati Nagar	Rapoli	426782	XVFC	426782	1419000103105555	drinking water work, sanitation work door to door collection,	
70	Saraswati Nagar	Ram garh	110655	XVFC	110655	6396000100053973	Sewerge and phrini repair, drinking water pipe line and motar repair	
71	Saraswati Nagar	Sahabpura	200763	XVFC	200763	1419000103105458	repair main street in village, sanitation and drinking work in village	
72	Saraswati Nagar	Saran	966787	XVFC	966787	1419000103105467	Const of Rasta Maggerpur Road to field of Subay Singh ,Water Supply Pipe line repair, part time sweeper sallary and sanitation work	
73	Saraswati Nagar	Saran	500000	HGVY	500000	6396000100013683	Tilling work in Ambedkar Bhawan and Reparing work in SC choupal	
74	Saraswati Nagar	Saran	500000	HGVY	500000	6396000100013683	Tilling in P/L and ground near Mandir	

Sr No.	Name of the Block	Name of the Gram Panchayat in Radaur Assembly Constituency	Amount received in gram panchayat after 23-02-2021	Name of The Scheme	Amount Received	Account No. and Bank Name in which amount was received	Detail of Development work executed	Detail of work which are incomplete
75	Saraswati Nagar	Saran	120000	HGVY	120000	6396000100013683	Const of street from Raj Gujjar Bethok to Nagar Khera tile work	
76	Saraswati Nagar	Topra Khurd	134413	XVFC	134413	1419000103105537	computer level in panchayati land sanitation work, motar and pipe line maintance	
77	Saraswati Nagar	Uncha Chandana	715294	XVFC	715294	1419000103105516	Const of Street from pwd road to pritam singh, and saintation work	
78	Saraswati Nagar	Uncha Chandana	55000	HGVY	55000	6396000100013762	Const. of street from h/o Dayal Harijan to main street	
79	JAGADHRI	RATTAN GARH	211000	HGVY	211000	50100230921996-HDFC BANK	Const. of Rasta from Sawan singh to F/o Omparkash	
80	JAGADHRI	SUDHAIL	42000	HGVY	42000	50100230960900 & HDFC BANK YNR-II	Street from main road to House of Sachin	
81	JAGADHRI	SUDHAIL	786000	HGVY	786000	50100230934586-HDFC BANK	Const. of Rasta from F/o Kuldeep to F/o Aatma Ram	
						In Progress Works		
1	Radaur	ANTAWA	200000	HGVY	200000	50100231390060		Const. of balmiki choupal In Progress (40% work Compl.)
2	Radaur	DARHERI	800000	HGVY	800000	50100231066497		(Boundary wal of community centre, toilet and const. of kitechen)wip
3	Radaur	BARSAN	597000	HGVY	597000	50100231066484		(Shed of kitechen in BC Choupal)wip
4	Radaur	BHAGWAN GARH	114000	HGVY	114000	50100231288942		(Const. of nala from house of manga ram to school)wip (10%)
5	Radaur	CHAMRORI	450000	HGVY	450000	50100231963818		Const. of nala from dispensary to house of mahinder singh (WIP)
6	Radaur	DHAULRA	797500	HGVY	797500	50100231068718		(Const. of BC chaupal)under allotment process
7	Radaur	GHILOUR MAJRI	500000	HGVY	500000	50100231197813		(Brick pavement rasta from main street to house of satpal)site dispute
8	Radaur	HIRAN CHHAPPAR	931000	HGVY	931000	50100231282930		(Const of Park)work changed as per recommendation by Hon'ble MLA Radaur
9	Radaur	JATHLANA	1813000	HGVY	1813000	50100231065672		(Cost of Community Center)WIP
10	Radaur	JHAGURI	700000	HGVY	700000	50100231290988		(IPB street from house sushil to silla)wip
11	Radaur	JUBAL	667000	HGVY	667000	50100231066336		(Const. of BC chaupal)WIP
12	Radaur	Lakshi Bans	800000	HGVY	800000	50100231257732		(Const. of kitchen in community centre)wip
13	Radaur	MARU-PUR	718000	HGVY	718000	50100231066191		(Completion of community centre)wip

85

Sr No.	Name of the Block	Name of the Gram Panchayat in Radaur Assembly Constituency	Amount received in gram panchayat after 23-02-2021	Name of The Scheme	Amount Received	Account No. and Bank Name in which amount was received	Detail of Development work executed	Detail of work which are incomplete
14	Radaur	NACHRAON	1439000	HGVY	1439000	50100231067860		(Const. of big size hall adjoining community centre)wip
15	Radaur	RADAURI	691000	HGVY	691000	50100231292422		(Const. of rasta from BC choupal [illegible])wip
16	Radaur	SANDHALA	300000	HGVY	300000	50100231391521		(Street from house of rajesh to narender)wip
17	Radaur	TOPRA KALAN	1434000	HGVY	1434000	50100231388247		(Const. of community centre in saini mohalla)wip
18	Saraswati Nagar	Dadanpuri	400000	HGVY	400000	63960001000013061		Const of IPB in SC and BC choupal (WIP [illegible] % work complete at site)
19	Saraswati Nagar	Hudia	65000	HGVY	65000	63960001000051495		Const of street from h/o Nahar Singh to PWD Road (WIP 40 % work complete at site)
20	Saraswati Nagar	Saran	500000	HGVY	500000	63960001000013683		Const of Baranda in P.L. in Mandir With Gate WIP 30 % complete at site)
21	Saraswati Nagar	Uncha Chandana	397000	HGVY	397000	63960001000013702		Const of shed in choupal (WIP 40 % complete at site)
22	Saraswati Nagar	Uncha Chandana	81000	HGVY	81000	63960001000013762		From Rasoli Road to F/o [illegible] (WIP 50 % complete at site)
23	JAGADHRI	GOLANPUR	652000	HGVY	652000	50100231079621 & HDFC BANK JORION		Const. of CC Paver Block Street from Dera of Rampal to House of Rampal) WIP 15% Work Complete at site) (Amt. Transferd to XEN PR)
24	JAGADHRI	KHJURI	693000	HGVY	693000	50100231198894 & HDFC BANK SHADIPUR		Const. of completion of community hall (WIP 90% Work Complete at Site)(Amt. Transferd to XEN PR)
25	JAGADHRI	NAGAL	1000000	HGVY	1000000	50100231065238 & HDFC BANK SHADIPUR		Const. of Community Centre (Work Alloted to Agency but with held due to dispute at Site) (Amt. Transferd to XEN PR)
					Yet to Start			
1	Radaur	ALIPURA	1000000	HGVY	1000000	50100231067626		Const. of community centre (Under tender process)
2	Radaur	GUMTHALA RAO	600000	HGVY	600000	50100231068122		(Const. fo BC choupal)under allotment process
3	Radaur	JATHLANA	500000	HGVY	500000	50100231065672		(Const of Street from Main Road to h/o Ramesh Chand)Under tender process

Sr No.	Name of the Block	Name of the Gram Panchayat in Radaur Assembly Constituency	Amount received in gram panchayat after 23-02-2021	Name of The Scheme	Amount Received	Account No. and Bank Name in which amount was received	Detail of Development work executed	Detail of work which are incomplete
4	Radaur	JATHLANA	1000000	HGVY	1000000	50100231065672		(RCC severage line from harijan choupal masjid colony)under allotment process
5	Radaur	KARERA M.T.	600000	HGVY	600000	50100231068636		(Const. of bramda in community centre)under allotment process
6	Radaur	LAL CHHAPAR	1256000	HGVY	1256000	50100231935094		(Const. of community centre)site to be changed.
7	Radaur	MASANA RANGHRAN	1000000	HGVY	1000000	50100231068741		(Const. of community centre)under allotment process
8	Radaur	RAPRI	797500	HGVY	797500	50100230943151		(Completion of Panchayat Ghar in Village Rapri)Under tender process
9	Radaur	SIKANDERA	773000	HGVY	773000	50100231387691		(Const. of hall in SC choupal)under allotment process
10	Radaur	SILI KALAN	1000000	HGVY	1000000	50100231067501		(Const of Bramada Near Community Center)under allotment process
11	Saraswati Nagar	Bhogpur	666000	HGVY	665000	63960001000013133		Rasta from village Gadi Adda to F/o powan (Work Alloted to be Started by Agency)(Amt. Transferd to XEN PR)
12	Saraswati Nagar	Bir BalSua	150000	HGVY	150000	63960001000013142		Const. of B/wall Ambedkar Bhawan (WIP 70 % work complete as site)
13	Saraswati Nagar	Daulatpur Mafivan	1245000	HGVY	1245000	63960001000013179		Cons. of Community Hall (Dhiman)(Work in progress)(Amt. Transferd to XEN PR)
14	Saraswati Nagar	Faridpur	500000	HGVY	500000	63960001000013188		Cons. of small one Room in SC Choupal and B/wall gate (work alloted and to be started soon Amt. Transferd to XEN PR)
15	Saraswati Nagar	Faridpur	691000	HGVY	691000	63960001000013166		From village Faridpur toward village Daulatpur to saran road (work alloted to be started soon) (Amt. Transferd to XEN PR)
16	Saraswati Nagar	Fatehpur - 448	495000	HGVY	495000	63960001000013197		Const. of SC Choupal (work alloted to be started soon) (Amt. Transferd to XEN PR)
17	Saraswati Nagar	Fatehpur - 448	919000	HGVY	919000	63960001000013187		Const. of SC Choupal (work alloted to be started soon) (Amt. Transferd to XEN PR)
18	Saraswati Nagar	Colni	500000	HGVY	500000	63960001000013249		Const of one Room in SC Choupal (work in progress) (Amt. Transferd to XEN PR)
19	Saraswati Nagar	Hasanpur	358000	HGVY	358000	63960001000054529		Laying IPB tiles in campus of meeting hall (in Tender Process By XEN PR)
20	Saraswati Nagar	Hasanpur	898000	HGVY	898000	63960001000054529		Const. of Nala in market from Gurudwara Sahib to pond (in Tender Process By XEN PR)
21	Saraswati Nagar	Hasanpur	997000	HGVY	997000	63960001000054529		Const. of Community hall (in Tender Process By XEN PR)
22	Saraswati Nagar	Kool Pur	1000000	HGVY	1000000	63960001000013434		Const of dmi (work to be started after Earth Filling from MGNREGA) (Amt. Transferd to XEN PR)

86

Sr No.	Name of the Block	Name of the Gram Panchayat in Radaur Assembly Constituency	Amount received in gram panchayat after 23-02-2021	Name of The Scheme	Amount Received	Account No. and Bank Name in which amount was received	Detail of Development work executed	Detail of work which are incomplete
23	Saraswati Nagar	Kool Pur	643000	HGVY	643000	6396000100013454		[illegible] Singh [illegible] work alloted to be started soon) (Amt. Transferd to XEN PR)
24	Saraswati Nagar	Massana Jattan	1445000	HGVY	1445000	6396000100013631		Const. of Community hall (work alloted to be started soon) (Amt. Transferd to XEN PR)
25	Saraswati Nagar	Ram garh	500000	HGVY	500000	6396000100053055		Const of SC chaupal's work alloted to be started soon (Amt. Transferd to XEN PR)
26	JAGADHRI	HATU PUR	352000	HGVY	352000	50100231065659 & HDFC BANK SHADIPUR		Const of boundary wall of SC-Chaupal, Toilet, Tile works in package (work to be executed has been changed as per recommended by Hon ble MLA Radaur and estimate submitted to competent authority (Amt. Transferd to XEN PR)
27	Radaur	LAL CHHAPAR	1256000	HGVY	1256000	50100231936094		(Const. of community centre/site to be changed
28	JAGADHRI	KAREHA KHURD-II	352000	HGVY	352000	50100231062867 & HDFC BANK		Const. of brick on edging rasta from Jathlana road shadipur f/o inder singh to f/o somnathi Work alloted to be started soon) (Amt. Transferd to XEN PR)
29	JAGADHRI	SABHAPUR	667000	HGVY	667000	50100231065251-HDFC BANK SHAD PUR		Const. of SC Chaupal (Work alloted to be started soon))(Amt. Transferd to XEN PR)
30	JAGADHRI	TAPU KAMALPUR	313000	HGVY	313000	50100231291188-HDFC BANK		Const. of Rasta from Sushil Kumar to F/o basehar S/o Sadhu (Work alloted to be started soon) (Amt. Transferd to XEN PR)
31	JAGADHRI	TAPU KAMALPUR	646000	HGVY	646000	50100231291188-HDFC BANK		Const. of Rasta from Akalgarh Road H/o Rajeshwar to F/o Charmender s/o Rajinder (Work alloted to be started soon) (Amt. Transferd to XEN PR)

86-A

Sr No.	Name of the Block	Name of the Gram Panchayat in Radaur Assembly Constituency	Amount received in gram panchayat after 23-02-2021	Name of The Scheme	Amount Received	Account No. and Bank Name in which amount was received	Detail of Development work executed	Detail of work which are incomplete
32	JAGADHRI	TODARPUR	1500000	HGVY	1500000	50100131063850-HDFC BANK		Const. of Rasta from todarpur-khajuri Road to F/o Najir Work alloted to be started soon) (Amt. Transferd to XEN PR)

चौकीदार–सह–सेवादारों को नियमित करना

5. श्री बिशन लाल सैनी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2007 में राज्य के स्कूलों में कुछ चौकीदार–सह–सेवादारों को अस्थाई आधार पर नियुक्त किया गया था; यदि हां, तो उनके प्रति माह वेतन का ब्यौरा क्या है,तथा

(ख) उपरोक्त चौकीदार सह सेवादारों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): (क) एवं (ख) नहीं, श्रीमान जी।

.....

डिपो धारकों की आयु सीमा

6. श्री बिशन लाल सैनी : क्या उप मुख्यमंत्री कृप्या बताएगें कि सरकार द्वारा डिपोधारक के रूप में कार्य करने के लिए आयु सीमा 60 वर्ष तक निर्धारित की गई है; यदि हां, तो उक्त नियम द्वारा लाभ कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला): जी हां, सरकार द्वारा नये हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति एवं नियंत्रण) आदेश, 2022 में डिपोधारक के रूप में कार्य करने के लिए 60 वर्ष तक की आयु सीमा निर्धारित की गई है। युवाओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और युवाओं को आजीविका का अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने यह नियम बनाया है ताकि वह अपनी आजीविका का साधन बना सकें और अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। यह युवाओं को रोजगार का एक अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है।

सड़क के गड्ढों को भरना

7. श्री भारत भूषण बतरा: क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) रोहतक शहर में कितनी सड़कें हैं जिनमें गड्ढे हैं तथा उक्त गड्ढों को भरने के लिए नगर निगम, रोहतक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; तथा

(ख)क्या शहर में उपरोक्त गड्ढों को भरने के लिए विभाग द्वारा कोई विशेष अनुदान दिया गया है अथवा इस संबंध में सरकार ने अनुदान उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है ?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): (क) श्रीमान जी, नगर निगम, रोहतक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, नगर निगम, रोहतक के अधिकार क्षेत्र में कुल 24 सड़कों की पहचान की गई है, जिनमें गड्ढे है। तदनुसार, नगर निगम, रोहतक ने गड्ढों को भरने के लिए 3 एजेंसियों को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 10.01.2023 को सूचीबद्ध किया है। एजेंसियों द्वारा गड्ढों को भरने का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य दिनांक 31.03.2023 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।

(ख) 2021 में सरकार द्वारा नगर निगम, रोहतक को 210.00 लाख रुपये जारी किए गए थे, जिसमे से 165.00 लाख रुपये पहले ही 92 कार्यों के माध्यम से गड्ढों को भरने के लिए खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा, नगर निगम, रोहतक ने 83.00 लाख रुपये से गड्ढों को भरने के विभिन्न कार्य आवंटित किये है। शेष व्यय नगर निगम, रोहतक द्वारा अपने स्वयं के कोष से वहन किया जाएगा।

.....

सड़कों की मरम्मत

8. श्री भारत भूषण बतराः क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) क्या यह तथ्य है कि रोहतक में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर 1, 2, 2–ए, 3 तथा 4 की सभी सड़के क्षतिग्रस्त हो गई हैं; तथा

(ख) क्या उपरोक्त सड़कों की मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; यदि हां, तो उक्त सड़कों के कब तक मरम्मत किए जाने की संभावना है?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): (क) श्रीमान जी, आयुक्त नगर निगम रोहतक ने प्रस्तुत किया है कि रोहतक में एच.एस.वी.पी के सेक्टर –1, 2, 3 और 4 की कुछ आंतरिक सड़कें अच्छी स्थिति में नहीं हैं। इसके लिए नगर निगम रोहतक ने जेट पैचर तकनीक से गड्ढों को भरने के लिए 10.01.2023 को तीन एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है। गड्ढों को भरने का कार्य प्रगति पर है।

(ख) नगर निगम रोहतक द्वारा एच.एस.वी.पी. के सेक्टर 1, 2, 2 ए, 3 और 4 की आंतरिक सड़कों का जेट पैचर तकनीक द्वारा मरम्मत करवाने के कार्य 42.85 लाख रुपये सें आंवटित किए हैं, जो कि 31.03.2023 तक पूर्ण किये जाएगे।

.....

मृत पशुओं के लिए बिजली शवदाह गृह

9. **श्री अमित सिहाग :** क्या पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) क्या यह तथ्य है कि माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि मृत पशुओं के शव दहन क्रिया के लिए प्रत्येक जिला/खण्ड में बिजली के शवदाह गृह आरम्भ किए जाएगें;

(ख) क्या जिला सिरसा में सम्बन्धित विभागों ने इसको बनाने के लिए स्थानों को चिन्हित किया है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) इन शवदाह गृहों के कब तक निर्मित किए जाने तथा क्रियाशील किए जाने की संभावना है ?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): (क) हां श्रीमान् जी, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता में दिनांक 08.05.2020 को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में संबंधित जिला परिषद द्वारा प्रत्येक जिले में एक बिजली के शवदाह गृह स्थापित करने का निर्णय लिया गया था।

(ख) जिला सिरसा में उपयुक्त भूमि चिन्हित की जा रही है।

(ग) निविदा आवंटन के बाद बिजली के शवदाह गृह को पूर्ण/स्थापित करने में लगभग 4–6 महीने का समय लगता है।

.....

फसल बीमा के रूप में एकत्रित राशि

10. श्री अमित सिहाग: क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) वर्ष 2021 तथा 2022 के लिए जिला सिरसा के किसानों से फसल बीमा के रूप में एकत्रित अधिमूल्य का विधानसभा वार ब्यौरा क्या है; तथा

(ख) उन किसानों की संख्या कितनी है जिन्होने फसल बीमा लिया था तथा जिला सिरसा में खराब फसलों के लिए मुआवजा दिया गया था तथा वर्ष 2021 तथा 2022 में मुआवजे के रूप में कुल कितनी राशि वितरित की गई तथा जिला सिरसा के लिए विधानसभा-वार ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) जिला सिरसा में उन किसानों की संख्या कितनी है जिन्हे वर्ष 2021 तथा 2022 के लिए अभी मुआवजा मिलना है तथा मंडी डबवाली विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र की गांववार मुआवजे की राशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री **जय प्रकाश दलाल**) महोदय, (क) वर्ष 2021 व 2022 के लिए जिला सिरसा के किसानों से (दोनों मौसम, खरीफ एवं रबी में) एकत्रित किये गये अधिमूल्य अंश का विधानसभा क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:-

विधानसभा क्षेत्र का नाम	**(अधिमूल्य) किसानों का हिस्सा) (राशि लाख में)**	
	2021	**2022**
डबवाली	1515.36	1832.86
ऐलनाबाद	2113.47	2518.35
कालांवाली	1246.95	1464.56
रानियां	1370.97	1694.85
सिरसा	703.21	907.68
कुल	**6949.96**	**8418.3**

(ख) वर्ष 2021 और 2022 (दोनों मौसम, खरीफ और रबी) में विधानसभा क्षेत्र वार बीमित किसानों की संख्या, लाभार्थियों की संख्या और किसानों को वितरित किया गया क्लेम निम्नानुसार है :

विधानसभा क्षेत्र का नाम	**बीमित किसानों की संख्या**		**लाभार्थियों की संख्या**		**किसानों को किये गये क्लेम का भुगतान (राशि लाख में)**	
	2021	**2022**	**2021**	**2022**	**2021**	**2022**
डबवाली	41365	46641	25678	प्रक्रियाधीन है	5044.61	प्रक्रियाधीन है
ऐलनाबाद	72380	74487	59989		14679.33	
कालांवाली	36929	39277	24562		10855.54	
रानियां	45909	50083	32640		8231.13	
सिरसा	23486	25972	16789		5618.41	
कुल	**220069**	**236460**	**159658**		**44429.02**	

(ग) सिरसा जिले में वर्ष 2021 और 2022 के 1,31,539 किसानों को 722 करोड़ रुपये के अनुमानित क्लेम का भुगतान किए जाने की संभावना है। मंडी डबवाली विधानसभा **निर्वाचनक्षेत्र** के **गांवों** में **वितरित किया जाने वाला** अनुमानित क्लेम इस प्रकार है:

क्रमांक	**ग्राम का नाम**	**अनुमानित क्लेम (राशि लाख में)**
1	अबुब शहर (271) विभाजित गांव।	238.30
2	अहमदपुर दारेवाला (261)	371.25
3	अलिकां (276)	202.97
4	आसा खेड़ा (268)	114.42
5	असिर (310)	235.90
6	बनवाला (223)	564.89
7	भारूखेड़ा (266)	175.46
8	बीजूवाली (258)	252.73

क्रमांक	ग्राम का नाम	अनुमानित क्लेम (राशि लाख में)
9	चकजालू (257)	48.00
10	चट्ठा (297)	99.40
11	चोरमार खेड़ा (252)	307.17
12	चौटाला (267)	1128.67
13	डबवाली (ग्रामीण) (भाग) (278)	114.82
14	देसु जोधा (281)	365.40
15	दीवान खेड़ा (292)	159.62
16	फरीदपुर (259)	117.53
17	गंगा (264)	915.65
18	घुकांवाली (221)	440.64
19	गिदड़ खेड़ा (287)	186.98
20	गोबिंदगढ़ (285)	174.67
21	गोदेकां (262)	504.11
22	गोरिया वाला (255)	258.67
23	हबुआना (295)	259.06
24	हासु (311)	150.51
25	जगमालवाली (309)	324.71
26	जंडवाल जट्टान (253)	231.45
27	जंदवाला बिश्नोइयां (265)	408.79
28	झूटी खेड़ा (289)	170.74
29	जोगे वाला (279)	109.64
30	जोत्तनवाली (274)	63.95
31	कालुआना (238)	795.30
32	खोखर (300)	218.27
33	खुईयां मलकाना (293)	121.10
34	किंगरा (306)	334.04
35	लखुआना (286)	192.35
36	लंबी (288)	263.02
37	लोहगढ़ (273)	60.04
38	माखा (301)	103.01
39	मालकपुर (305)	254.52
40	मंडी डबवाली (MC)	0.64
41	मंगियाना (282)	231.33
42	मसिटान (284)	311.84
43	मटदादू (290)	357.85
44	मौजगढ़ (291)	298.56

क्रमांक	ग्राम का नाम	अनुमानित क्लेम (राशि लाख में)
45	मिठडी (304)	282.29
46	मोडी (256)	304.99
47	मुनावाली (263)	217.29
48	नई डबवाली (277)	39.42
49	नौरंग (299)	160.59
50	न्यू राजपुरा (329)	35.52
51	नीलांवाली (294)	117.12
52	नुईयांवाली (249)	487.87
53	ओढ़ां (204)	311.86
54	पाना (302)	270.02
55	पन्नीवाला मोटा (280)	73.51
56	पन्नीवाला रूलदू (303)	287.43
57	फुल्लो (296)	300.57
58	पिपली (308)	322.79
59	राजपुरा (248)	189.68
60	रामगढ़ (245)	329.16
61	रामनगर (206)	153.89
62	रामपुरा बिश्नोइयाँ (254)	240.39
63	रत्ता खेड़ा (247)	340.89
64	रिसालिया खेड़ा (246)	495.01
65	सकताखेड़ा (272)	216.12
66	सलाम खेड़ा (250)	153.46
67	सावंत खेड़ा (283)	165.95
68	शेरगढ़ (275)	224.85
69	सुखेरांवाला (269)	114.99
70	टप्पी (307)	220.67
71	तेजा खेड़ा (270)	69.55
72	टिगरी (298)	103.90
कुल डबवाली निर्वाचन क्षेत्र		**18467.75**

सामान्य अस्पताल को एफ.आर.यू. में बदलना

11. श्री अमित सिहाग : क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) गांव चौटाला में सामान्य अस्पताल में आवश्यकताओं तथा नौकरियों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या पग उठाए गए हैं ताकि इसे एफ.आर.यू. में बदला जा सके; तथा

(ख) अनेक अजन्मे बच्चों की मौतों से सम्बन्धित शिकायत के विरूद्ध उपरोक्त अस्पताल के चिकित्सा अमलों/चिकित्सकों के विरूद्ध स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

स्वास्थ्य मंत्री (अनिल विज) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) सिविल अस्पताल, चौटाला को प्रथम रैफरल यूनिट बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

i. सिविल अस्पताल, चौटाला, सिरसा में विशेषज्ञ (संविदा आधार पर) डॉक्टरों यथा स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिस्ट, जनरल सर्जन, फिजिशियन के 5 पद स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों पर भर्ती सिविल सर्जन सिरसा द्वारा शुरू कर दी गई है।

ii. सिविल अस्पताल, चौटाला में अतिरिक्त डॉक्टर और पैरामेडिक्स तैनात किए गए हैं, यानी एक एसएमओ, दो चिकित्सा अधिकारी, एक दंत चिकित्सक, एक बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) और एक नर्सिंग अधिकारी।

iii. चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

(ख) विस्तृत जांच के बाद, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है।

.....

नालों तथा सड़कों का निर्माण करना

12. श्री नीरज शर्मा : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) क्या यह तथ्य है कि फरीदाबाद एन.आई.टी के वार्ड न. 9 में लालू एस.टी.डी., नंगला इन्कलेव से गजीपुर तक पानी की निकासी के लिए नाले तथा सड़क बुरी अवस्था में है; यदि हां, तो उक्त नालों तथा सड़क के कब तक निर्मित किये जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह तथ्य है कि वार्ड न. 9 में अटल चौक से सोनिया चौक तक सड़क के दोनों ओर पानी की निकासी के लिए नाले बुरी अवस्था में है; यदि हां, तो उक्त नालों तथा सड़कों के कब तक निर्मित किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह तथ्य है कि वार्ड न. 9 में सुभाष चौक से अन्तराम चौक तक सड़क के दोनों ओर पानी निकासी के लिए बुरी अवस्था में है; यदि हां, तो उक्त नालों एवं सड़कों के कब तक निर्मित किये जाने की संभावना है; तथा

(घ) क्या यह भी तथ्य है कि वार्ड न. 9 में सुभाष चौक से गजीपुर तक सड़क के दोनों ओर पानी की निकासी के लिए नाले बुरी अवस्था में है; यदि हां, तो उक्त नाले एवं सड़कों के कब तक निर्मित किये जाने की संभावना है?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता) (क) श्रीमान जी, नगर निगम फरीदाबाद के वार्ड नंबर 9 में लालू एस.टी.डी., नंगला इन्कलेव से गजीपुर तक की कच्ची सड़क है और इस सड़क के साथ कोई जल निकासी प्रणाली मौजूद नहीं है। वर्तमान में नगर निगम फरीदाबाद के पास सड़क व नाली निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा उक्त सड़क व नाली निर्माण के कार्य को करवाने के प्रस्ताव पर सीवरेज एवं जलापूर्ति लाईन डालने उपरांत व राशि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा।

(ख) श्रीमान जी, वार्ड न. 9 में अटल चौक से सोनिया चौक तक सड़क के दोनों ओर पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। इस सड़क व दोनों ओर नाली/नाले

के निर्माण का कार्य नगर निगम फरीदाबाद द्वारा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।

(ग) श्रीमान जी, वार्ड न. 9 में सुभाष चौक से अन्तराम चौक तक सड़क के दोनों ओर पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। इस सड़क व दोनों ओर नाली/नाले के निर्माण का कार्य नगर निगम फरीदाबाद द्वारा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।

(घ) श्रीमान जी, वार्ड न. 9 में सुभाष चौक से गजीपुर तक सड़क के दोनों ओर पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। इस सड़क व दोनों ओर नाली/नाले के निर्माण का कार्य नगर निगम फरीदाबाद द्वारा धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर किया जायेगा।

सीवरेज लाइन तथा गलियों के निमार्ण कार्य

13. श्री नीरज शर्मा : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) क्या यह तथ्य है कि फरीदाबाद एन.आई.टी. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वार्ड न0–5 की एक बेटी द्वारा अपनी बारात के स्वागत के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को ट्विटर पर अनुरोध किए जाने के पश्चात सीवरेज अस्थाई तौर पर साफ किया गया था;

(ख) क्या यह तथ्य है कि वार्ड न0–5 के बाल कल्याण स्कूल पॉकेट की स्थिति नरक के समान है क्योंकि गलिया पूर्णतः क्षतिग्रस्त हैं तथा आवागमन का रास्ता नहीं है; तथा

(ग) यदि हां, तो वार्ड न0–5 के बाल कल्याण स्कूल पॉकेट की सीवरेज लाईन तथा गलियों का निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जाने की संभावना है?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता) :(क) हां श्रीमान जी।

(ख) हां श्रीमान जी, बाल कल्याण स्कूल पॉकेट की गलिया क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं।

(ग) नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा उक्त जगह के अनुमान तैयार किया जा रहा है। सीवर लाईन व गलियों का कार्य राशि की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण करवा लिया जाएगा।

विकास कार्यों के लिए जारी की गई राशि

14 श्री नीरज शर्मा : क्या उप- मुख्यमंत्री कृपया **बतायेंगे कि** :-

(क) फरीदाबाद एन.आई.टी. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा जनवरी, 2020 से 28 फरवरी, 2023 तक कितनी राशि जारी की गई तथा विकास कार्यों की सूची क्या है; तथा

(ख) उपरोक्त कार्यों के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):(क) तथा (ख) महोदय, विस्तृत उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है।

उत्तर

जनवरी, 2020 से अब तक फरीदाबाद एन.आई.टी. विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 383.97 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इस अवधि के दौरान जिन कार्यों के लिए भुगतान जारी किए गए है निम्नानुसार सारणीबद्ध है :-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख रुपये में)	जनवरी, 2020 से अब तक हुआ व्यय (लाख रुपये में)	कार्य की वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
सड़क के कार्य					
1	जिला फरीदाबाद में पहुँच मार्ग से पावटा तक किमी 0.00 से 2.10 की विशेष मुरम्मत द्वारा चौड़ीकरण / मजबूतीकरण का कार्य। (रोड़ आई.डी. : 3305)	69.69	60.69	काम पूरा हो गया है।	कुल व्यय 60.69 लाख रुपये है।
2	जिला फरीदाबाद में कुरैशीपुर से नंगला गुजरान तक किमी 0.635 से 2.85 की विशेष मुरम्मत द्वारा चौड़ीकरण / मजबूतीकरण का कार्य। (रोड़ आईडी : 10749)	114.09	112.16	काम पूरा हो गया है।	कुल व्यय 112.16 लाख रुपये है।

3	पहुँच मार्ग मांगर (रोड़ आईडी 3281) पर प्रीयोडिक्ल मरम्मत का कार्य।	53.36	52.41	काम पूरा हो गया है।	कुल व्यय 52.41 लाख रुपये है।
4	बल्लभगढ़-सोहना रोड़ के किमी 04.00 से किमी 6.00 तक पीक्यूसी सड़क प्रदान करके सुधारीकरण तथा सड़क पर स्ट्रॉम वाटर / गंदे पानी का भराव, तथा एम.सी. फरीदाबाद द्वारा किए गए रोड़ कट की मरम्मत का कार्य।	243.26	0.00	कार्य प्रगति पर है।	शून्य
	कुल योग	**480.4**	**225.26**		
भवन के कार्य					
1	फरीदाबाद जिले के सिरोही गांव में सरकारी पशु औषधालय का निर्माण।	32.58	25.49	काम पूरा हो गया है।	जनवरी, 2020 से पहले रुपये 6.63 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं और अब तक का कुल व्यय 32.12 लाख रुपये है।
2	ग्राम फतेहपुर तेगा में पशु चिकित्सालय का	35.83	2.24	काम पूरा हो गया है।	जनवरी, 2020 से पहले रुपये 17.90 लाख

	निर्माण (मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 11108 के तहत) ।				रुपये खर्च किए जा चुके हैं और अब तक का कुल व्यय 20.14 लाख रुपये है। 15.69 लाख रुपये का भुगतान किया जाना अभी बाकी है।
3	फरीदाबाद जिले के गांव पाली में आई.टी.आई. [कार्यशाला ब्लॉक] का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति योजना के तहत का निर्माण कार्य।	301.32	90.46	काम पूरा हो गया है।	जनवरी, 2020 से पहले रुपये 183.71 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं और अब तक का कुल व्यय 274.17 लाख रुपये है। 27.03 लाख रुपये का भुगतान किया जाना अभी बाकी है।
4	फरीदाबाद जिले के पाली गांव की सीएचसी में अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण।	223.45	40.52	काम पूरा हो गया है।	जनवरी, 2020 से पहले रुपये 112.24 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं और अब तक का

					कुल व्यय 152.76 लाख रुपये है। 70.69 लाख रु. का भुगतान किया जाना अभी बाकी है।
	कुल योग	**593.18**	**158.71**		
	महा योग	**1073.58**	**384.41**		

आय सीमा बढ़ाना

15. श्री राकेश दौलताबाद : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम के अंर्तगत प्रत्येक योजना के लिए आवंटिंत बजट कितना है;

(ख) हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम के अंतर्गत विभिन्न बैंको की टाई–अप योजना की आय सीमा कितनी है; तथा

(ग) क्या बैंको की टाई–अप योजना की आय सीमा को 1.80 लाख रूपये की बी. पी.एल. सीमा तक बढाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : महोदय जी, (क) वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, हरियाणा सरकार द्वारा निगम के प्रशासनिक खर्चों के रूप में 10.00 करोड़ रूपये और सफाई कर्मचारी व उनके आश्रितों को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान राशि उपलब्ध करवाने के लिए 05.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया हैं। अन्य योजनाओं के लिए राशि की मांग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त तथा विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम से राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के विरूद्ध की जाती है।

(ख) निगम द्वारा बैंक टाई–अप योजनाओं के अंतर्गत उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है जिनकी वार्षिक आय 49,000 रूपये (ग्रामीण क्षेत्र में), 60,000 रूपये (शहरी क्षेत्र में) और जिनका नाम बीपीएल की सूची में भी शामिल हैं।

(ग) हां, यह मामला हरियाणा सरकार के विचाराधीन हैं।

.....

सरकारी वैबसाइटों का ब्यौरा

16. श्री राकेश दौलताबाद : क्या मुख्यमन्त्री कृपया बताएंगे किः–

(क) हरियाणा सरकार की सभी वैबसाइटों का ब्यौरा क्या है तथा उनके रख–रखाव की तकनीकी टीम के प्रभारी के संपर्क का ब्यौरा क्या है ?

(ख) वित्त वर्ष 2022–23 में हरियाणा सरकार की वैबसाइटें कितने घंटे बन्द रही ; तथा

(ग) यह सुनिश्चत करने की प्रक्रिया क्या है कि सरकारी वैबसाइटों पर अधिकारियों के संपर्क ब्यौरे तथा अन्य सूचना में सुधार किया गया है?

मुख्यमन्त्री (श्री मनोहर लाल) : (क) हां, हरियाणा में कुल 378 वैबसाइटें हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

1. सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) डेटा केन्द्रों पर होस्ट की गई हरियाणा सरकार की 180 वैबसाइटों का विवरण अनुबंध 'ए' पर संलग्न है ।
2. हारट्रोन द्वारा हरियाणा सरकार की 8 बैबसाइट होस्ट की गई, जिसका विवरण अनुबंध 'बी' में संलग्न है ।
3. हरियाणा राज्य डाटा सेंटर में होस्ट की गई हरियाणा सरकार की 152 वैबसाइटों का विवरण अनुबंध 'सी' में संलग्न है।
4. हरियाणा राज्य डाटा सैंटर के बाहर होस्ट की गई हरियाणा सरकार की 38 वैबसाइटों का विवरण अनुबंध 'डी' में संलग्न है।

(ख) सभी विभागीय वैबसाइटों का रख–रखाव सम्बन्धित विभाग अपने स्तर पर करते हैं और वैबसाईट सामग्री क्लाउड संसाधन और वैबसाइट स्त्रोत कोड आदि की देखभाल संबंधित विभाग करते हैं। वैबसाइट का डाउनटाईम का विवरण उन सम्बन्धित विभागों से प्राप्त किया जा सकता है ।

(ग) सभी संगठनों को पीपीएन/सीएमएस/एफटीपी का विवरण प्रदान किया जाता है, जिसका उपयोग करके वे वैबसाइटों का अद्यतन/नवीनतम सामग्री को बनाए रख सकते हैं। संबधित संगठन अपनी वैबसाइटों पर जानकारी अपडेट करते हैं। वैबसाईट पर उपलब्ध जानकारी को अपडेट करने के लिये संबंधित वैबसाइट के तकनीकी अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है, जो कि अपने विभागाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत वैबसाइट को अपडेट कर सकता है।

Sr. No.	Deptartment Name	Application/Website URL	Name of Technical Contact	Email ID	Contact No. Of Technical Contact
1	Pollution Control Board	http://hspcb.org.in	Vanita	hspcb@hry.nic.in	9463040006
2	Mewat Development Agency	http://mda.nic.in	CEO MDA	ceomda@yahoo.co.in	01267-271461
3	Chandigarh Judicial Academy	http://cja.gov.in	Aman Kumar	admn@cja.gov.in	9855998721
4	Chief Secretary Haryana Portal	https://csharyana.gov.in	Pardeep Kaushal	p.kaushal@nic.in	7696012076
5	Chief Secretary Haryana Har Aadesh Portal	https://haraadesh.nic.in	Pardeep Kaushal	p.kaushal@nic.in	7696012077
6	CM Office Haryana	http://transfer.cmofficehry.gov.in	Sanjay Sharma	s.sanjay@nic.in	9417850505
7	CM Office Haryana	http://budget.cmofficehry.gov.in	Sanjay Sharma	s.sanjay@nic.in	9417850505
8	Finance Department Haryana	http://vikasnidhi.finhry.gov.in	Prabhat Bisht	prabhat.bisht@nic.in	9582808028
9	Public Health Engineering Department	https://phedharyana.gov.in	Vivek Garg	vivek.garg-p-hry@phedharyana.gov.in	9315810160

10	Public Health Engineering Department	https://biswas.phedharyana.gov.in	Vivek Garg	vivek.garg-p-hry@phedharyana.gov.in	9315810160
11	Public Health Engineering Department	https://services.phedharyana.gov.in	Vivek Garg	vivek.garg-p-hry@phedharyana.gov.in	9315810160
12	Public Health Engineering Department	https://watercomplaint.phedharyana.gov.in	Vivek Garg	vivek.garg-p-hry@phedharyana.gov.in	9315810160
13	Public Health Engineering Department	https://sewercomplaint.phedharyana.gov.in	Vivek Garg	vivek.garg-p-hry@phedharyana.gov.in	9315810160
14	Public Health Engineering Department	https://works.haryana.gov.in	Vivek Garg	vivek.garg-p-hry@phedharyana.gov.in	9315810160
15	Haryana Tourism	http://booking.haryanatourism.gov.in	Munish Kapoor	tourism@hry.nic.in	9216400446
16	PM Kusum Yojna	https://pmklive.hareda.gov.in	S K Yadav	sureshk.yadav-hry@hry.gov.in	9888329860
17	PM Kusum Yojna	https://pmkrms.hareda.gov.in	S K Yadav	sureshk.yadav-hry@hry.gov.in	9888329860
18	PM Kusum Yojna	https://pmkapi.hareda.gov.in	S K Yadav	sureshk.yadav-hry@hry.gov.in	9888329860
19	PM Kusum Yojna	https://pmkusum.hareda.gov.in	S K Yadav	sureshk.yadav-hry@hry.gov.in	9888329860
20	Lokayukta Haryana	http://crms.hrlokayukta.gov.in	Deepak Sawant	sawant.deepak@nic.in	9425180912
21	Lokayukta Haryana	http://hrlokayukta.gov.in	Jitender Kumar	supdt.lokayukta@hry.gov.in	9780333026

22	Micro Small and Medium Enterprises	http://sisiharyana.gov.in	Meenu Dhiman	dcdi-karnal@dcmsme.gov.in	9416228279
23	Urdu Department	http://haryanaurdu.nic.in	Director	haryanaurduakademi@gmail.com	172-2561412
24	CM Haryana Office	http://cmofficehry.gov.in	Sanjay Sharma	s.sanjay@nic.in	9417850505
25	Horticulture Department	http://polynet.hortharyana.gov.in	Ajmer Mahla	sseithort-hry@nic.in	7015241695
26	Farm Training Institute	http://nrfmtti.gov.in	Director	fmti-nr@nic.in	01662 276824
27	Health Department	http://haryanahealth.gov.in	DGHS Haryana	dhs.dghs@hry.nic.in	1722562414
28	Horticulture Department	http://minet.hortharyana.gov.in	Ajmer Mahla	sseithort-hry@nic.in	7015241695
29	Department of Technical Education	http://onlinetesthry.gov.in	Krishan Kumar Kataria	dtehry@hry.nic.in	1722583259
30	AG Haryana	http://aghry.gov.in	A G Haryana	agaeharyana@cag.gov.in	0172-2613211
31	CEO Haryana	http://ceoharyana.nic.in	Naresh Kumar	ceo_haryana@eci.gov.in	9888998625
32	Irrigation Department	http://hid.gov.in	Kamal jeet	kamaljeet.agri@hry.gov.in	9996195599
33	Haryana Police website	http://haryanapolice.gov.in	Vijay Raghav	insp.ithq@hry.nic.in	7015003110
34	PWD Department	http://haryanapwd.gov.in	Harish Bhatia	itcellpwd-hry@nic.in	1726181218
35	Tourism	http://haryanatourism.gov.in	Munish Kapoor	tourism@hry.nic.in	9216400446
36	CADA Haryana	http://cadaharyana.nic.in	Hanuman Jha	hrcada@chd.nic.in	7973279418

37	Shivalik Development Agency	http://sda.gov.in	CEO	shivalikdevagency@gmail.com	171-2533651
38	Vidhan Sabha	http://haryanaassembly.gov.in	Sunil Nain	itcellvs@hry.nic.in	9467708000
39	High Court	http://haryanajudiciary.gov.in	Registrar	cpc-phc@indianjudiciary.gov.in	0172-2740071
40	High Court	http://highcourtchd.gov.in	Registrar	cpc-phc@indianjudiciary.gov.in	0172-2740072
41	High Court	http://punjabjudiciary.gov.in	Registrar	cpc-phc@indianjudiciary.gov.in	0172-2740073
42	High Court	http://mediationcentrephhc.gov.in	Registrar	cpc-phc@indianjudiciary.gov.in	0172-2740074
43	Haryana State Rural Livelihoods Mission	http://hsrlm.gov.in	CEO	ceohsrlm-hsrlm@nic.in	**0172-2581590**
44	Dept of Agricultural Meteorology CCS Haryana Agricultural University, Hisar	http://emausamhau.gov.in	DR M L Khichar	mlkhichar.hau-hry@gov.in	9416995529
45	Haryana Samvad Society	http://haryanasamvad.gov.in	Vikas Dangi	edsamvad@gmail.com	1725055973
46	Haryana Public Service Commission	http://hpsc.gov.in	Ajay Khera	info.hpsc@gmail.com	0172-2560755

47	Welfare of SCBC Department	http://haryanascbc.gov.in	Ritu Gupta	ritugupta.woscbc@hry.gov.in	8699725891
48	Directorate of Horticulture	http://hortharyana.gov.in	Ajmer Mahla	sseithort-hry@nic.in	7015241695
49	Technical Education Department	http://techeduhry.gov.in	Krishan Kumar Kataria	dtehry@hry.nic.in	1722583259
50	Department of Environment	http://harenvironment.gov.in	Arvind Kumar	environment@hry.nic.in	9041939237
51	Animal Husbandry	http://pashudhanharyana.gov.in	Dr Sukhdev Rathee	dg.ahd@hry.nic.in	0172-2574663
52	Archaeology & Musems Department	http://archaeologyharyana.nic.in	Director	archaeology@hry.nic.in	0172-2924495
53	Fisheries Department	http://harfish.gov.in	P S	fisheries@hry.nic.in	0172-256574
54	Rural Development Department	http://haryanarural.gov.in	Sundeep Wahi	drd@hry.nic.in	9876843638
55	Registrar Cooperative societies	http://rcsharyana.gov.in	Sonia	cooperatives@hry.nic.in	9996345083
56	Prisions Department Haryana	http://haryanaprisons.gov.in/	Shamsher Singh	office_dg.prisons@hry.nic.in	1722585721
57	Housing Board haryana	http://hbh.gov.in/	Sapna Gautam	hbh@hry.nic.in	0172-2585233
58	Development and Panchayats	http://haryanadp.gov.in	Veenus Nathalia	panchayats@hry.nic.in	9356925623

59	Ayush Department	http://elicence.ayushharyana.gov.in	Prachi	itcell.hry-ayush@nic.in	7015995142
60	Ayush Department	http://www.ayushharyana.gov.in	Prachi	itcell.hry-ayush@nic.in	7015995142
61	Registrar Cooperative societies	http://cooponline.rcsharyana.gov.in	Sonia	cooperatives@hry.nic.in	9996345083
62	Sainik Welfare Department of General Adm	http://sainikwelfareharyana.gov.in	Col Rahul Yadav(Retd)	dir.sasw-hry@gov.in	9815425714
63	PGIMS Rohtak	http://pgimsrohtak.nic.in	Sukhdev Chandla	sukhdevchandla@uhsr.ac.in	9992425915
64	PGIMS Rohtak	http://uhsr.ac.in	Sukhdev Chandla	sukhdevchandla@uhsr.ac.in	9992425916
65	SocialJustice Department	https://pension.socialjusticehry.gov.in	Parvesh Kumar	parvesh.kumar19-hry@hry.gov.in	7009427721
66	Employment Department	http://hrex.gov.in	Ritu	saksham.emp-hry@gov.in	0172-2570054
67	Haryana Electricity Regulatory Commission	https://herc.gov.in	Rishi Parwanda	sm.herc@nic.in	(172) 258253
68	Chandigarh Legal Services Authority	http://www.chdslsa.gov.in	Sahil	slsa_utchd@yahoo.com	9815113457
69	Direct Benefit Transfer (SJE)	http://dbtharyana.gov.in	Pooja Tyagi	dbt.finance-hry@gov.in	9501525115

70	Home Guards Haryana	http://homeguardsharyana.gov.in	Commandant	homeguards.hgncd-hry@gov.in	0172 - 2701206
71	HAFED Haryana	http://hafed.gov.in	Karnail Singh Lathar	hafed@hry.nic.in	0172-2585912
72	Department of Technical Education	https://intrahstes.gov.in	Krishan Kumar Kataria	dtehry@hry.nic.in	1722583259
73	Department of Technical Education	https://techadmissionshry.gov.in	Krishan Kumar Kataria	dtehry@hry.nic.in	1722583259
74	Haryana Human Rights Commission	http://hhrc.gov.in	Sapna	hhrc-hry@nic.in	172-2600566
75	Employment Department	http://hreyahs.gov.in	Ritu	saksham.emp-hry@gov.in	0172-2570054
76	RERA Haryana	http://haryanarera.gov.in	Prakash Kala	prakash.kala@nic.in	9871940123
77	Hospitality Department Haryana	http://hryguesthouse.gov.in	Yashpal	yashpal@nic.in	9417869424
78	AG Haryana	http://odms.aghry.gov.in	A G Haryana	agaeharyana@cag.gov.in	0172-2613211
79	Haryana Seeds	http://haryanaseeds.org.in	MD	mdhsdcl@gmail.com	0172-2577755
80	Haryana Azadi Ka Amrit Mahotsav	https://akam.haryana.gov.in	Munish Chandan	munish.chandan@semt.gov.in	9797654321
81	Vigilance Department	http://haryanavigilance.gov.in	Kanwar Singh	dgsvb-hry@nic.in	9872762345
82	Revenue and Disaster	http://revenueharyana.gov.in	Jasvir Singh	support.revenue-hry@gov.in	8288895554

	Management Department				
83	Forest Deaprtment	http://haryanaforest.gov.in/	Shiwali Sharma	shiwali.sharma-hry@hry.gov.in	9876240304
84	Supplies & Disposal	http://dsndharyana.gov.in	Tara Chand	tarachand.dsnd@hry.gov.in	8219825309
85	Secondary Education	http://schooleducationharyana.gov.in	Anil Rangi	anilrangi.secedu@hry.gov.in	9216252225
86	Haryana State Portal	https://haryana.gov.in	Jaganpreet Kour	jaganpreet.kour@nic.in	9796004697
87	Electronics and Information Technology	http://haryanait.gov.in	Vishwas	vishwas.ditech@hry.gov.in	7696091020
88	Directorate of Micro, Small and Medium Enterprises	http://msme.haryana.gov.in	Munish Singhal	rahulvig.msme@hry.gov.in	7986622462
89	Haryana Gau Seva Aayog	http://hargauseva.gov.in	Bharat Bhushan Suneja	bharatsuneja.hldb@hry.gov.in	9466209488
90	State Council of Educational Research & Training	http://scertharyana.gov.in	Ankur Bhardwaj	icet.scert-hry@gov.in	8527447644
91	Department of Architecture	http://architecturehry.gov.in	Devender Singh	to-web.arch@hry.gov.in	9815962398
92	Department of New and Renewable Energy	http://hareda.gov.in	S K Yadav	sureshk.yadav-hry@hry.gov.in	9888329860

93	State Finance Commission	http://sfc.haryana.gov.in	Kuldeep Singh	info-6sfc@hry.gov.in	7018482896
94	ENVIS Hub	http://envis.haryana.gov.in	Suresh Chand	sureshchand.env@hry.gov.in	8054572286
95	State Wetland Authority	http://swa.haryana.gov.in	Arvind Kumar	arvindkumar.env@hry.gov.in	9041939237
96	Environment and Climate Change Department	http://hrccc.harenvironment.gov.in	Arvind Kumar	haryana-envis@hry.gov.in	9041939237
97	Haryana State Biodiversity Board	http://sbb.haryanaforest.gov.in	Sunil Kumar	sunilkumar.hsbb@hry.gov.in	9855089929
98	Swarna Jayanti Environment Training Institute	http://sjeti.haryana.gov.in	Arvind Kumar	arvindkumar.env@hry.gov.in	9041939237
99	Social Justice & Empowerment Department	http://socialjusticehry.gov.in	Parvesh Kumar	parvesh.kumar19-hry@hry.gov.in	9803358703
100	Haryana Right to Service Commission	http://haryana-rtsc.gov.in	Julie	rtsc-hry@gov.in	9501105541
101	Food, Civil Supplies and Consumer Affairs	http://haryanafood.gov.in	Japinder Kaur	compcell.food-hry@gov.in	7986748689
102	Primary Education	http://harprathmik.gov.in	Anil Rangi	anilrangi.secedu@hry.gov.in	9216252225
103	Women and Child Development	http://wcdhry.gov.in	Baghel Ashwani Kumar	itwcd-hry@nic.in	8837824904

104	Treasuries & Accounts Department	http://hrtreasuries.gov.in	Sunil Bahal	treasuries@hry.nic.in	9467555388
105	Development of Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Audit CAMPA	https://campa.haryana.gov.in	Atul Sirsikar	hr066@ifs.nic.in	9466158158
106	AB-HHPA State Health Authority	https://ayushmanbharat.haryana.gov.in	Ripudaman Guleria	ripudamanguleria.dhs@hry.gov.in	9653996748
107	Panchkula Metropolitan Development Authority	https://pmdahry.org.in	Sapna Gautam	sapna.gautam@hbh.gov.in	7009731552
108	Haryana Parivar Suraksha Nyas	https://hpsn.haryana.gov.in	Kulwant Khullar	kulwant.kumar-hry@hry.gov.in	9872025979
109	Haryana Forest Development Corporation Limited	https://hfdc.gov.in	Surinder Kumar	surinder1399@hfdc.gov.in	9478131232
110	Haryana Raj Bhavan	http://haryanarajbhavan.gov.in	Vivek Garg	vivek.garg@nic.in	9888513030
111	Civil Aviation Department	http://haraviation.gov.in	Pankaj Gulati	pankajgulati.cavn@hry.gov.in	8699757008

112	Finance Department Haryana	http://finhry.gov.in	Prabhat Bisht	prabhat.bisht@nic.in	9582808028
113	State Police Complaint Authority Haryana	https://spcahry.nic.in	Rakesh Kumar	spca.haryana@nic.in	9416365923
114	Haryana State Legal Services Authority	https://hslsa.gov.in	Vijay Pal Singh	kavitakamboj@aij.gov.in	9781800974
115	Archives Department Haryana	https://haryanaarchives.gov.in	Pinki	archives@hry.nic.in	9817664365
116	Art and Cultural Affairs Department Haryana	https://artandculturalaffairshry.gov.in	Anil Sharma	cultural@hry.nic.in	9876795767
117	State Transport Department	https://hartrans.gov.in	Manisha Bansal	manishabansal.dst@hry.gov.in	8295402122
118	State Election Commission Haryana	https://secharyana.gov.in	K.S. Jaggi	sec@hry.nic.in	7009427721
119	Haryana Shehri Vikas Pradhikaran	https://hsvphry.org.in	Anirudh Gupta	anirudhgupta.he@hry.gov.in	8901206105
120	Haryana State Seed Certification Agency	https://hssca.org.in	Harpreet Kaur	dcsco-hq@hssca.org.in	9780125929

121	Social Justice, Empowerment Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes and Antyodaya (SEWA)	https://sewa.haryana.gov.in	Parvesh Kumar	parvesh.kumar19-hry@hry.gov.in	9803358703
122	ESI Department	https://hryesi.gov.in	Pardeep Kumar	pradeep.2019-hry@hry.gov.in	9501718037
123	Department of Economic and Statistical Analysis	https://esaharyana.gov.in	Kanwal	rajinder.bhatia-hry@hry.gov.in	7988086871
124	District website	http://ambala.gov.in	Dio Ambala	dioamb@hry.nic.in	9466133233
125	District website	http://bhiwani.gov.in	Dio Bhiwani	diobhw@hry.nic.in	9996027960
126	District website	http://charkhidadri.gov.in	Amit Lamba	lamba.amit@nic.in	8607881100
127	District website	http://faridabad.nic.in	Dio Faridabad	diofbd@hry.nic.in	9953553500
128	District website	http://fatehabad.gov.in	Dio Fatehabad	dioftb@hry.nic.in	9468488477
129	District website	http://gurugram.gov.in	Dio Gurugram	diogrg@hry.nic.in	9416111969
130	District website	http://hisar.gov.in	Dio Hisar	diohsr@hry.nic.in	9416700051
131	District website	http://jhajjar.nic.in	Dio Jhajjar	diojjr@hry.nic.in	9355805581
132	District website	http://jind.gov.in	Dio Jind	diojnd@hry.nic.in	9416561786

133	District website	http://kaithal.gov.in	Dio Kaithal	dioktl@hry.nic.in	9992326999
134	District website	http://karnal.gov.in	Dio Karnal	diokrl@hry.nic.in	9416484286
135	District website	http://kurukshetra.gov.in	Dio Kurukshetra	diokrk@hry.nic.in	9466137300
136	District website	http://mahendragarh.gov.in	Dio Narnaul	dionrl@hry.nic.in	7678555454
137	District website	http://nuh.gov.in	Dio Mewat	dionuh@hry.nic.in	9729423298
138	District website	http://palwal.gov.in	Dio Palwal	diopwl@hry.nic.in	8930223444
139	District website	http://panchkula.nic.in	Dio Panchkula	diopkl@hry.nic.in	9991173200
140	District website	http://panipat.gov.in	Dio Panipat	diopnp@hry.nic.in	9896263722
141	District website	http://rewari.gov.in	Dio Rewari	diorwr@hry.nic.in	9466997181
142	District website	http://rohtak.gov.in	Dio Rohtak	diortk@hry.nic.in	9812876764
143	District website	http://sirsa.gov.in	Dio Sirsa	diosrs@hry.nic.in	8814022494
144	District website	http://sonipat.nic.in	Dio Sonipat	diosnp@hry.nic.in	9813637599
145	District website	http://yamunanagar.nic.in	Dio Yamunanagar	dioynr@hry.nic.in	9416195018
146	District Police website	http://ambala.haryanapolice.gov.in	SP Ambala	spamb@hry.nic.in	
147	District Police website	http://bhiwani.haryanapolice.gov.in	SP Bhiwani	spbhw@hry.nic.in	
148	District Police website	http://charkhidadri.haryanapolice.gov.in	SP Charkhi Dadri	spdadri.pol-hry@gov.in	

149	District Police website	http://faridabad.haryanapolice.gov.in	SP Faridabad	cp.fbd@hry.nic.in	
150	District Police website	http://fatehabad.haryanapolice.gov.in	SP Fatehabad	spftb@hry.nic.in	
151	District Police website	http://gurgaon.haryanapolice.gov.in	CP Gurugram	cp.ggn@hry.nic.in	
152	District Police website	http://hisar.haryanapolice.gov.in	SP Hisar	sphsr@hry.nic.in	
153	District Police website	http://jhajjar.haryanapolice.gov.in	SP Jhajjar	spjjr@hry.nic.in	
154	District Police website	http://jind.haryanapolice.gov.in	SP Jind	spjnd@hry.nic.in	
155	District Police website	http://kaithal.haryanapolice.gov.in	SP Kaithal	spktl@hry.nic.in	
156	District Police website	http://karnal.haryanapolice.gov.in	SP Karnal	spkrl@hry.nic.in	
157	District Police website	http://kurukshetra.haryanapolice.gov.in	SP Kurukshetra	spkrk@hry.nic.in	
158	District Police website	http://mewat.haryanapolice.gov.in	SP Mewat	spmwt@hry.nic.in	
159	District Police website	http://narnaul.haryanapolice.gov.in	SP Narnaul	spnrl@hry.nic.in	
160	District Police website	http://panchkula.haryanapolice.gov.in	CP Panchkula	cppkl.pol-hry@nic.in	
161	District Police website	http://panipat.haryanapolice.gov.in	SP Panipat	spppt@hry.nic.in	
162	District Police website	http://rewari.haryanapolice.gov.in	SP Rewari	sprwr@hry.nic.in	

163	District Police website	http://rohtak.haryanapolice.gov.in	SP Rohtak	sproh@hry.nic.in	
164	District Police website	http://sirsa.haryanapolice.gov.in	SP Sirsa	spsrs@hry.nic.in	
165	District Police website	http://sonipat.haryanapolice.gov.in	SP Sonipat	spsnp@hry.nic.in	
166	District Police website	http://yamunanagar.haryanapolice.gov.in	SP Yamunanagar	spynr@hry.nic.in	
167	Haryana Police website	http://commando.haryanapolice.gov.in	SP Commando	spcommando.krl@nic.in	
168	Haryana Police website	http://scrb.haryanapolice.gov.in	Director	dir.scrb@hry.nic.in	
169	Haryana Police website	http://railways.haryanapolice.gov.in	SP Railways	sp.rail@hry.nic.in	
170	Haryana Police website	http://hpa.haryanapolice.gov.in	Director	directorhpambn@yahoo.co.in	
171	District Police website	http://palwal.haryanapolice.gov.in	SP Palwal	sppwl@hry.nic.in	
172	Haryana Police website	http://traffic.haryanapolice.gov.in	SP Traffic	sp.traffic@hry.nic.in	
173	Haryana Police website	http://1stbnhapambala.haryanapolice.gov.in	Commandant	comdt.2bn@hry.nic.in	
174	Haryana Police website	http://hap3rdbn.haryanapolice.gov.in	Commandant	comdt.2bn@hry.nic.in	
175	Haryana Police website	http://1stbnirb.haryanapolice.gov.in	Commandant	comdt.2irb@hry.nic.in	
176	Haryana Police website	http://igirb.haryanapolice.gov.in	IG IRB	ig.irb-hry@nic.in	

177	Haryana Police website	http://3rdbnirb.haryanapolice.gov.in	Commandant	sunaria.3irbpol-hry@gov.in	
178	Haryana Police website	http://2ndirb.haryanapolice.gov.in	Commandant	comdt.2irb@hry.nic.in	
179	Haryana Police website	http://ptcsunaria.haryanapolice.gov.in	IG	igpptc.sunaria-hry@nic.in	
180	Haryana Police website	http://rtcbhondsi.haryanapolice.gov.in	IG	igprtc.pol-hry@gov.in	

16(a) List of Department's Websites is being Developed/Maitained By The HARTRON

#	Department	URL	Technical Team Contact Details
1	Government of Haryana Ministry of Home and Administration of Justice	https://homeharyana.gov.in/	Santosh Kumar 9023562306
2	Science and Technology Department, Haryana	https://dstharyana.gov.in/	Gurwinder Singh 9815863063
3	Haryana State CSR Trust	http://haryanacsr.org/	Akshat Sharma 9418102584
4	State Information Commission, Haryana	https://cicharyana.gov.in/	Santosh Kumar 9023562306
5	Aids Control Society	http://haryanasacs.in/	Surender Kumar 9876496506
6	Local Audit Haryana	http://localaudithry.gov.in/	Surender Kumar 9876496506
7	Institution of Panchayati Raj Bhiwani	http://riprcdhry.gov.in/	Surender Kumar 9876496506
8	Chief Electrical Inspector, Haryana	http://ceiharyana.in/	Santosh Kumar 9023562306

16(b) No such detail is available at our end.

16© Hartron take care of the technical aspects of websites, all the contents on the website are updated by the concerned department itseft.

WEBSITES HOSTED IN SDC (Help desk contact no. **0172- 2546417**)

Sr. no	Domain Name	Department Name	Email id
1	advocategeneralhry.gov.in	Advocate General, Haryana	surinder.longia@nic.in , chauhan2081991@gmail.com
2	agriharyana.gov.in	Agriculture Department Haryana	haryana.itdept@gmail.com,agriharyana2009@gmail.com,agriprogrammer@gmail.com, ranajdast@gmail.com,adaschry@gmail.com ; mukeshsaini.agri@hry.gov.in
3	intra.agriharyana.gov.in		
4	haims.agriharyana.gov.in		
5	cadaharyana.nic.in	Command Area Development Authority, Haryana	cmda@hry.nic.in
6	cicharyana.gov.in	State Information commission (CIC)	ussichry@yahoo.co.in
7	dpmuhry.gov.in	HMSCL	rahul.jain@nic.in, ddipd-nrhm@nic.in
8	android.dpmuhry.gov.in		
9	demo.dpmuhry.gov.in		
10	dstharyana.gov.in	Director General Science &Technology Deptt. Haryana	gurvinder5@hotmail.com; vishalgulia@gmail.com ; dsthry@gmail.com
11	edisha.gov.in	E-Distt. Haryana	alok.s@nic.in, ashish.dhingra@nic.in ; amit.gupta@nic.in ; sio@hry.nic.in
12	citizen.edisha.gov.in		
13	saral.edisha.gov.in		
14	umang.edisha.gov.in		

15	ws.edisha.gov.in		
16	ws1.edisha.gov.in		
17	esachivalaya.edisha.gov.in		
18	haryanareliefcamps.edisha.gov.in		
19	citizenstg.edisha.gov.in		
20	saralstg.edisha.gov.in		
21	staging.edisha.gov.in		
22	umangstg.edisha.gov.in		
23	wsstg.edisha.gov.in		
24	unorgworker.edisha.gov.in		
25	erpcrid.edisha.gov.in		
26	egazetteharyana.gov.in	Printing and Stationary	sanjurana29@gmail.com ; chadhav1@gmail.com
27	epossr.hry.gov.in	Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department	guru@nic.in, gurvinder5@hotmail.com; sumit.garg@gov.in; seo.fcsca.ditech-hry@nic.in
28	fdaharyana.gov.in	Department of Food and Drug Administration	haryanafda@gmail.com
29	forestharyana.gov.in	Forest Department Haryana	anur@cdac.in, cfplg-hry@nic.in, gdeepak@cdac.in, cfplg@yahoo.com
30	harpathharyana.gov.in	NIC	moudgil.s@nic.in,amit.gupta@nic.in, ramandeep@nic.in
31	harsamay.gov.in	Haryana Police (CCTNS)	cctns.haryana@nic.in, srivatsan.sowmynarayanan@hpe.com, chattrapal.singh@hpe.com; spmu-cctns.pol@hry.gov.in

32	harspagy.gov.in	Rural Development Department Haryana	gaurhamesh@gmail.com (9815997090)
33	**hartrans.gov.in**	Transport Department Haryana	transport.haryana@gmail.com,transport@hry.nic.in
34	**ors.hartrans.gov.in**		
35	hartronskill.org.in	DITECH	fms.hartron@gmail.com , 9466191991
36	**haryanabpas.gov.in**	Human Resource mgt system(Treasury dept.)	ermsharyana@yahoo.com; iso.it.tcp@gmail.com; obpas.support3@capricot.com
37	**haryanacmoffice.gov.in**	Haryana CM Office	cmwebportal@gmail.com
38	haryanafcd.gov.in	Foreign co-operation department Haryana	surender_khatkar@yahoo.com ;
39	haryanafood.gov.in	Food & Supplies Department, Haryana	gurvinder5@hotmail.com ,compcell.food-hry@gov.in, hrfoods@hotmail.com ; foods@hry.nic.in ; seo.fcsca.ditech-hry@nic.in
40	bk.haryanafood.gov.in		
41	epos.haryanafood.gov.in		
42	kharif.haryanafood.gov.in		
43	lm.haryanafood.gov.in		
44	haryanaismo.gov.in	INFORMATION SECURITY MANAGEMENT OFFICE, HARYANA	amit.beniwal@haryanaismo.gov.in
45	haryanapoliceonline.gov.in	Haryana Police (CCTNS)	cctns.haryana@nic.in, srivatsan.sowmynarayanan@hpe.com, chattrapal.singh@hpe.com
46	mail.haryanapoliceonline.gov.in		
47	haryanapwd.gov.in	PWD B&R Branch	eegeneralbranch@gmail.com, itcellpwd-hry@nic.in, harishbhatia.ditech@hry.gov.in
48	haryana-rtsc.gov.in	Haryana Right To Service Commission	haryana.it@gmail.com

49	haryanasacs.in	AIDS Control Society	surender_khatkar@yahoo.com
50	haryanatax.gov.in	Excise & Taxtion Department	helpdesk@haryanatax.gov.in; saket.rohilla@haryanatax.gov.in; amit.arora@haryanatax.gov.in
51	mail1.haryanatax.gov.in		
52	mail2.haryanatax.gov.in		
53	mailgw.haryanatax.gov.in		
54	vanijya.haryanatax.gov.in		
55	www.haryanatax.gov.in		
56	hbcc.nic.in	Haryana Backward Classes Commision Dept.	bjaj.gd@nic.in,backwardccharyana@gmail.com
57	hbckn.org.in	Haryana Backward Classes And Economically Weaker Sections Kalyan Nigam	hbckn22@gmail.com
58	hmscl.org.in	Haryana Medical Services Corporation Ltd.	support-dpmu-hry@nic.in rahul.jain@nic.in
59	demo.hmscl.org.in		
60	hospitalityharyana.gov.in	Hospitality Haryana	surender_khatkar@yahoo.com
61	hrtransport.gov.in	Transport Department Haryana	transport@hry.nic.in
62	epay.hrtransport.gov.in		
63	mis.hrtransport.gov.in		
64	api.hrtransport.gov.in		
65	buspass.hrtransport.gov.in		
66	dts.hrtransport.gov.in		
67	etickets.hrtransport.gov.in		
68	hryedumis.gov.in	Department of School Education	vickyredhu@gmail.com; bangar_ss@yahoo.com
69	mail1.hryedumis.gov.in		
70	mtms.hryedumis.gov.in		

71	support.hryedumis.gov.in		
72	training.hryedumis.gov.in		
73	tremp.hryedumis.gov.in		
74	trreports.hryedumis.gov.in		
75	trsch.hryedumis.gov.in		
76	trstu.hryedumis.gov.in		
77	emp.hryedumis.gov.in		
78	stu.hryedumis.gov.in		
79	sch.hryedumis.gov.in		
80	report.hryedumis.gov.in		
81	training.cas.hryedumis.gov.in		
82	cas.hryedumis.gov.in		
83	hryrevenuecourts.gov.in	Department of Revenue Court Caese	amit.gupta@nic.in; deepak.bhardwaj@gov.in
84	hscsk.org.in	Haryana State Commission for Safai Karamcharis (DITECH)	To: vishwas.ditech@hry.gov.in; Cc: info.hscsk@hry.gov.in; hscskpanchkula@gmail.com
85	hsdc.gov.in	HSDC	supportsdc.swan-hry@gov.in
86	mail.hsdc.gov.in		
87	testssl.hsdc.gov.in		
88	mx-1.hsdc.gov.in		
89	hsfdc.org.in	Haryana Backward Classes And Economically Weaker Sections Kalyan Nigam	hbckn22@gmail.com
90	hshrc.gov.in	Haryana state Health Resource Centre	smohshrc@gmail.com

91	hsiidc.org.in	Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation LTD	rameshkumarverma68@gmail.com ; ravinder.sahni@hsiidc.org.in
92	hssc.gov.in	Haryana Staff Selection Commission	secretary.hssc-hry@gov.in
93	intrahry.gov.in	Intra Haryana, Govt. of Haryana	amit.gupta@nic.in ; gaurhamesh@gmail.com
94	lawandlegislativehry.gov.in	LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT	surender_khatkar@yahoo.com
95	localauditthry.gov.in	Director Local Audit Haryana/Site Defaced on october 2017	localaudit@hry.nic.in
96	medleaprhry.gov.in	Health Nodal Office Medleapr and office of Director General of Health ,Sector 6, Panchkula-134109	sawant.deepak@nic.in, rahul.jain@gov.in , support-medleapr@nic.in
97	android.medleaprhry.gov.in		
98	covid19.medleaprhry.gov.in		
99	demo.medleaprhry.gov.in		
100	demo1.medleaprhry.gov.in		
101	demo2.medleaprhry.gov.in		
102	fsl.medleaprhry.gov.in		
103	courts.medleaprhry.gov.in		
104	madhuban.medleaprhry.gov.in		
105	meragaonmeragaurav.gov.in	Rural Development Deptt Haryana Chandigarh	gaurhamesh@gmail.com

106	minesharyana.gov.in	Mines & Geology Department	mines.hrms@gmail.com ; dmg.mines-hry@nic.in; minesitcell@gmail.com
107	mmiyharyana.gov.in	Health Nodal Office Medleapr and office of Director General of Health ,Sector 6, Panchkula-134109	dhs.dghs@hry.nic.in
108	nhmharyana.gov.in	National Health Mission, Haryana	programmer.rt@gmail.com, po-it.nhm-hry@gov.in
109	midrs.nhmharyana.gov.in		
110	hr.nhmharyana.gov.in		
111	sihfw.nhmharyana.gov.in		
112	main.nhmharyana.gov.in		
113	asha.nhmharyana.gov.in		
114	ss.nhmharyana.gov.in		
115	app.nhmharyana.gov.in		
116	nrhmharyana.gov.in	National Health Mission, Haryana	programmer.rt@gmail.com, po-it.nhm-hry@gov.in
117	pandsharyana.gov.in	Printing & Stationery Department, Haryana	printing@hry.nic.in printingharyana@gmail.com ; Vishal Chadha" <egazette-haryana@hry.gov.in>
118	pcpndtharyana.gov.in	Director General Health Services	dhs.dghs@hry.nic.in;dhs.ddpndt@hry.nic.in
119	pdsharyana.gov.in	Public Distribution System	guru@nic.in ; pdsharyana@gov.in ; sumit.garg@nic.in

120	prharyana.gov.in	Directorate of Information, Public Relation and Languages, Haryana	itcell.dipr-hry@nic.in ujjwal.kumar.singh@rvsolutions.in prhrywebportal@gmail.com
121	prosecutionhry.gov.in	Haryana State Prosecution Department	surender_khatkar@yahoo.com
122	riprcdhry.gov.in	Panchayati Raj Bhiwani	surender_khatkar@yahoo.com
123	saralharyana.nic.in	NIC	alok.s@nic.in
124	status.saralharyana.nic.in		
125	scertharyana.gov.in	State council of educational Research and training	manoj_kaushik6171@yahoo.com bhardwaj12.ankur@gmail.com
126	secharyana.gov.in	State Election Commission, Nirvachan Sadan, Plot No.2, Sector 17, Panchkula, Haryana	secitcell@gmail.com
127	tcpharyana.gov.in	Director General Town & Country Planning Department	iso.it.tcp@gmail.com, dm.swit.tcp@gmail.com, pmit.tcp@gmail.com; isoit-tcp@hry.gov.in>
128	dfs.tcpharyana.gov.in		
129	mis.tcpharyana.gov.in		
130	ofa.tcpharyana.gov.in		
131	eapplication.tcpharyana.gov.in		
132	roauction.tcpharyana.gov.in		
133	eauction.tcpharyana.gov.in		
134	edraw.tcpharyana.gov.in		
135	ccma.tcpharyana.gov.in		
136	cis.tcpharyana.gov.in		
137	ulbharyana.gov.in		itcell-ulb@hry.gov.in , alok.s@nic.in ;

138	biswas.ulbharyana.gov.in	Directorate of Urban Local Bodies Department, Haryana	ashish.na.dulb@gmail.com ; gmit.ulbhry@gmail.com
139	saralserstg.ulbharyana.gov.in		
140	clu.ulbharyana.gov.in		
141	online.ulbharyana.gov.in		
142	grs.ulbharyana.gov.in		
143	waterstg.ulbharyana.gov.in		
144	Staging.ulbharyana.gov.in		
145	saralservices.ulbharyana.gov.in		
146	adv.ulbharyana.gov.in		
147	ndc.ulbharyana.gov.in		
148	ulbshops.ulbharyana.gov.in		
149	shopsmis.ulbharyana.gov.in		
150	nagardarshan.ulbharyana.gov.in		
151	subdivision.ulbharyana.gov.in		
152	vmsharyana.gov.in	Vigilance Department Haryana Civil secretariat	vikashartron17@gmail.com

WEBSITES NOT HOSTED IN SDC BUT USING SDC DNS SERVER
(Help desk contact no. **0172- 2546417**)

Sr. no	Domain Name	Department Name	Email id
1	Harudhyam.edisha.gov.in	NIC	bi-expert-hppa.crid@hry.gov.in ; acc-hppa.crid@hry.gov.in ; ceo-hppa@hry.gov.in
2	cridhry.edisha.gov.in		
3	shaadi.edisha.gov.in		
4	opsanction.edisha.gov.in		
5	cridverify.edisha.gov.in		
6	bankvalidation.edisha.gov.in		
7	pppapi.edisha.gov.in		
8	property.edisha.gov.in		
9	cridlc.edisha.gov.in		
10	grievance.edisha.gov.in		
11	chatbot.edisha.gov.in		
12	researchdelft.egazetteharyana.gov.in	Printing and Stationary	sanjurana29@gmail.com ; chadhav1@gmail.com
13	forestgis.forestharyana.gov.in	Forest Department Haryana	anur@cdac.in, cfplg-hry@nic.in, gdeepak@cdac.in, cfplg@yahoo.com
14	awas.haryanapwd.gov.in	PWD B&R Branch	eegeneralbranch@gmail.com, itcellpwd-hry@nic.in, harishbhatia.ditech@hry.gov.in
15	cform.haryanatax.gov.in	Excise & Taxtion Department	helpdesk@haryanatax.gov.in; saket.rohilla@haryanatax.gov.in; amit.arora@haryanatax.gov.in

16	discussion.haryanatax.gov.in		helpdesk@haryanatax.gov.in; saket.rohilla@haryanatax.gov.in; amit.arora@haryanatax.gov.in
17	mail3.haryanatax.gov.in		helpdesk@haryanatax.gov.in; saket.rohilla@haryanatax.gov.in; amit.arora@haryanatax.gov.in
18	hmrtc.org.in	Haryana Mass Rapid Transport Corporation Limited (HMRTC).	sohuda.rakesh@gmail.com; vijayramola1@gmail.com; sohuda.vikas@gmail.com; nehuda.yogesh@gmail.com; ntadm.huda@gmail.com
19	homeharyana.gov.in	Superintendent/Chief IT Officer Home & Administration of Justice Deptt.	toitcell.home-hry@gov.in
20	ns0015.hsdc.gov.in	HSDC	supportsdc.swan-hry@gov.in
21	ns0016.hsdc.gov.in	HSDC	supportsdc.swan-hry@gov.in
22	hsvphry.org.in	Haryana Urban Development Authority(HUDA)	sohuda.rakesh@gmail.com; vijayramola1@gmail.com; sohuda.vikas@gmail.com; nehuda.yogesh@gmail.com; ntadm.huda@gmail.com
23	mail.hsvphry.org.in		
24	cctns.hsvphry.org.in		
25	clubs.hsvphry.org.in		
26	communitycentre.hsvphry.org.in		
27	laocctns.hsvphry.org.in		
28	oabp.hsvphry.org.in		
29	waterbilling.hsvphry.org.in		
30	lfss.hsvphry.org.in		
31	Datac.hsvphry.org.in		
32	API.hsvphry.org.in		
33	ALLOTTEE.HSVPHRY.ORG.IN		
34	ALLOTTEEAPI.HSVPHRY.ORG.IN		

35	filmcell.prharyana.gov.in	Directorate of Information, Public Relation and Languages, Haryana	itcell.dipr-hry@nic.in ujjwal.kumar.singh@rvsolutions.in prhrywebportal@gmail.com
36	singlero.tcpharyana.gov.in	Director General Town & Country Planning Department	iso.it.tcp@gmail.com, dm.swit.tcp@gmail.com, pmit.tcp@gmail.com; isoit-tcp@hry.gov.in>
37	wms.ulbharyana.gov.in	Directorate of Urban Local Bodies Department, Haryana	itcell-ulb@hry.gov.in , alok.s@nic.in ; ashish.na.dulb@gmail.com ; gmit.ulbhry@gmail.com
38	urbanestateshry.gov.in	Urban Estate Department,	ntadm.huda@gmail.com

.....

अग्निशमन केन्द्र स्थापित करना

17. श्री राकेश दौलताबाद : क्या राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) किस नियम के अंतर्गत हरियाणा में अग्निशमन केंद्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या अधिकतम दूरी के संबंधित कोई नियम या नीतियां हैं जिसमें अग्निशमक इकाई होनी चाहिए;

(ग) क्या आग के खतरे से संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई आकलन करवाया गया है;

(घ) हरियाणा अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा विधेयक, 2022 तथा इसकी पुनः प्रस्तुतीकरण की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या एक नगर पालिका में कम से कम एक अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई नियम या प्रस्ताव हैं; तथा

(च) फारूख नगर की नगरपालिका के समीप अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं अधिनियम, 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत हरियाणा में दमकल केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ख) हाँ महोदय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, खंड 1 (8.4.9 सुरक्षा प्रबंधन) द्वारा शहरी और क्षेत्रीय विकास योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन मुद्दों के दिशा निर्देशों के अनुसार दमकल केन्द्र स्थापित करने का निम्न प्रावधान हैः–

"2 लाख आबादी या 5–7 किलोमीटर के दायरे में "

(ग) विभाग द्वारा ऊंची इमारतों, औद्योगिक ईकाइयों, ज्वलनशील उद्योगों, उच्च घनत्व क्षेत्र आदि की उपस्थिति के आधार पर मूल्यांकन किया गया है, तदानुसार दमकल केन्द्रो पर वाहन/अग्निशमन उपकरण उपलब्ध करवाये गये है।

(घ) हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2022 को हरियाणा विधानसभा द्वारा 04.03.2022 को पारित किया गया तथा हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम, 2022 दिनांक 08.04.2022 को अधिसूचित किया गया।

(ङ) नगर पालिका में दमकल केन्द्रों की स्थापना हरियाणा नगरपालिकाओं (फायर ब्रिगेड का गठन और कार्य) नियम, 1985 के नियम 4 के अनुसार की जाती है, जो निम्नानुसार हैः–

"प्रत्येक ए श्रेणी समिति आवश्यक उपकरण एवं कर्मियों के साथ एक दमकल केन्द्र का रख–रखाव करेंगी और बी श्रेणी या सी श्रेणी समिति अपने विकल्प पर दमकल केन्द्र का रख–रखाव कर सकती है।

(च) नगर पालिका फारुख नगर का निकटतम दमकल केन्द्र, पटौदी है।

(छ) हां महोदय, वर्ष 2024–25 में फारुख नगर में दमकल केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

.....

अस्पताल का दर्जा बढ़ाना

18. श्री सुभाष गांगोली : क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) क्या सफीदों के सामान्य अस्पताल का दर्जा 50 बैड से 100 बैड तक करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो इसका दर्जा कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): (क) तथा (ख) नहीं, श्रीमान जी।

.....

अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कार्य

19. श्रीमती नैना सिंह चौटाला : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बतायंगे कि बाढ़डा में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत प्रस्तावित अग्निशमन केंन्द्र का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : वर्ष 2024–25 में बाढ़ड़ा या उसके आसपास के क्षेत्र में एक दमकल केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

.....

कैथ लैब का निर्माण करना

20. श्रीमती नैना सिंह चौटाला : क्या स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाढडा में कैथ लैब का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : पी0एच0सी0 स्तर पर कैथ लैब शुरू करने का प्रावधान नहीं है।

.....

बाढ़डा उपमण्डल का दर्जा बढ़ाना

21. श्रीमती नैना सिंह चौटाला : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बाढ़डा उप-मण्डल का दर्जा मण्डल के रूप में बढाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो बाढ़डा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी उप-मण्डल का दर्जा मण्डल के रूप में कब तक बढाए जाने की संभावना है ?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री (डॉ० बनवारी लाल): नहीं श्रीमान जी।

(क) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह सवाल उत्पन्न नहीं होता है।

आगंतुकों के लिए पीने के पानी तथा बैठने के प्रबंध

22. श्री प्रदीप चौधरी: क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या जिला पंचकुला में उप-तहसील, ब्लॉक बरवाला में सरकार द्वारा आगंतुकों के लिए पीने के पानी तथा बैठने के लिए प्रबन्ध किए गए हैं?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): हाँ, श्रीमान जी। यद्यपि, संबंधित जिला प्राधिकारियों को इसकी समीक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

सीवरेज प्रणाली का दर्जा बढ़ाना

23. श्री प्रदीप चौधरी: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या कालका तथा पिंजौर क्षेत्र के सीवरेज प्रणाली का दर्जा बढाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इसका दर्जा कब तक बढाए जाने की संभावना है?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डॉ. बनवारी लाल): कालका तथा पिंजौर क्षेत्र के सीवरेज प्रणाली का दर्जा बढाने के लिए चार प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

कालका शहर

कालका शहर के मौजूदा 4.5 एम.एल.डी मल शोधन सयंत्र के उन्नयन का कार्य 368.45 लाख रुपये के अनुमान के अंतर्गत प्रगति पर है व कालका शहर में सीवरेज प्रणाली के उन्नयन का कार्य 822.70 लाख रुपये के अनुमान के अंतर्गत प्रगति पर है। यह दोनों कार्य जून 2024 तक पूर्ण होने की संभावना है।

पिंजौर शहर

पिंजौर शहर की नई स्वीकृत कॉलोनियों/शेष बचे हुए क्षेत्रों में सीवरेज प्रणाली के उन्नयन का कार्य 630.10 लाख रुपये व 280.08 लाख रुपये

के 2 अनुमानों के अंतर्गत प्रगति पर है। यह दोनों कार्य जून 2024 तक पूर्ण होने की संभावना है।

वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र

24. श्री प्रदीप चौधरी : क्या वन मन्त्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि कालका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मोरनी ब्लॉक के गांवों में घर/दुकानों के निर्माण के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। यदि हां तो इसके कारण हैं?

वन मंत्री (श्री कंवर पाल): मोरनी ब्लॉक के ऐसे क्षेत्र जो पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम, 1900 की विशेष धारा 4 व धारा 5 अथवा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत अधिसूचित है, इन क्षेत्रों में कोई भी गैर वानिकी गतिविधि हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। गैर अधिसूचित क्षेत्रों में वन विभाग की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

.....

पंजीकृत आपराधिक मामलों की संख्या

25. श्री अभय सिंह चौटाला : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:-

(क) 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी) की धाराओं तथा स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों (एल.एस.एल) के तहत दर्ज आपराधिक मामलों की कुल संख्या- तथा

(ख) बिंदु (क) पर दर्शाए गए दर्ज मामलों का विवरण जैसे- हत्या, बलात्कार, सामूहिक-बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध:

गृहमंत्री (श्री अनिल विज): श्रीमान् जी, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

वक्तव्य

श्रीमान जी, बिन्दु-वार उत्तर निम्नलिखित प्रकार से है-

(क) 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी) की धाराओं तथा स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों (एल.एस.एल) के तहत दर्ज आपराधिक मामलों की कुल संख्या इस प्रकार है: -

भारतीय दंड संहिता	स्थानीय एवं विशेष अधिनियम	कुल

1,24,004	35,436	1,59,440

(ख) बिंदु (क) पर दर्शाए गए दर्ज मामलों का विवरण जैसे- हत्या, बलात्कार, सामूहिक-बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध निम्न-प्रकार से है: -

हत्या (302 IPC)	1,007
बलात्कार (376-376E IPC)- गैंगरेप (376D/DA/DB IPC) के 275 केस सहित	1,968
पॉक्सो (4&6)	1,358
अपहरण (363-369 IPC)	3,980
डकैती (395,396,397 IPC)	105
लूट (392,394,397, 379B IPC)	1,525
महिलाओं के खिलाफ अपराध (304B, 312-314, 354-354-D, 366-366B, 376-376E, 498A, 509 IPC)	12,208
अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध (सभी मामले जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 लागू किया गया है)	1,525

नोट: सभी आंकड़े सीसीटीएनएस से दिनांक 01.01.2023 को निकाले गए हैं । अपराध-शीर्ष की परिभाषा 'भारत में अपराध' तैयार करते समय एन.सी.आर.बी. द्वारा उपयोग किए जाने वाले 'मुख्य अपराध नियम' के अनुसार है।

स्वीकृत पदों की कुल संख्या

26. श्री अभय सिंह चौटाला: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) वर्तमान में राज्य में सरकारी नौकरियों में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तथा ग्रुप डी के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों में से रिक्त पड़े पदों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में वर्णित स्वीकृत तथा रिक्त पदों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) वर्ष 2014 में उपरोक्त भाग (क) मे वर्णित उपरोक्त पदों का ब्यौरा क्या है ?

19.2.23 139

मनोहर लाल
MANOHAR LAL

D.O. No. CMH-2023......810......

मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़।
CHIEF MINISTER, HARYANA,
CHANDIGARH.

Secy. 19/2/23 D.S (Q)

Dated ......19/02/2023......

Subject: Regarding un-starred question No. 14/15/117.

....

Respected Speaker Sahib,

I would like to request that question No. 14/15/117 is asked by Chaudhary Abhay Singh Chautala, MLA (Ellenabad) regarding provision of total number of sanctioned and vacant posts of Group-A, B, C & D. The information asked is required from all Heads of Departments / Boards / Corporations etc. and will need compilation which takes more time. It is, therefore, requested to grant three months' time for preparing the reply of the said question, which is scheduled to be asked on 21.2.2023 at Sr. No.26.

With Regards

Yours sincerely,

मनोहर लाल

(Manohar Lal)

Hon'ble Gian Chand Gupta,
Speaker,
Haryana Vidhan Sabha

Office : 4th Floor, Haryana Civil Secretariat, Chandigarh - 160001, Ph. 0172-2749396, 0172-2740995 (Fax)
Resi. : H.No. 1, Sector-3, Chandigarh - 160001, Ph. 0172-2749394, 0172-2740596 (Fax)
email : cmharyana@nic.in

....

पंचायत निधि का ब्यौरा

27. श्री मेवा सिंह : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या पंचायतों के भंग होने तथा नई पंचायतों के गठन के समय के बीच पंचायत भूमि से एकत्रित

कुल राशि कितनी है तथा पंचायत के खाते में एकत्रित कुल राशि कितनी है तथा कार्यों पर खर्च की गई उपरोक्त राशि कितनी है तथा राज्य में जहां राशि खर्च की गई है उसका ग्रामवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है?

***विकास एवं पंचायत मन्त्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली):** श्रीमान जी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों से प्राप्त सूचना अनुसार विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

पात्र परिवारों का सर्वेक्षण

28. श्री मेवा सिंह: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) राज्य में परिवार पहचान पत्र के जारी होने के पश्चात उन परिवारों की संख्या कितनी है जिनके राशन कार्ड और पेंशन बंद कर दी गई है; तथा

(ख) क्या सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण करवाया गया है, जिन पात्र परिवारों के राशन कार्ड तथा पेंशन काटे गए हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) परिवार पहचान पत्र में पंजीकरण के समय परिवारों द्वारा प्रदान किए गए स्व-घोषित डेटा के सत्यापन पर, दिसंबर 2022 में 9,60,235 परिवारों के पीले राशन कार्ड बंद कर दिए गए थे। पुनः सत्यापन निवेदन पर 1,30,068 परिवारों को पुनः पीले कार्ड जारी किया गए हैं। मई 2022 में पीपीपी में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर केवल 21,034 नागरिकों का वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और अन्य पेंशन रोक दी गई है।

(ख) पीपीपी डेटाबेस में स्व-घोषित आय का सत्यापन निम्नलिखित तरीकों से किया जाता हैः

.....

*उपरोक्त अतारांकित प्रश्न के उत्तर के अनैक्चर्ज 415 पेजिज के होने के कारण चेयर के आदेशानुसार पूर्व प्रथा के अनुसार हरियाणा विधान सभा के पुस्कालय में रखवाये गए।

(क) पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) के आधार पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से;

(ख) हरियाणा सरकार, उसके बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों के डेटा का मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) से एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से;

(ग) सरकार में सेवा के बाद सरकार से पेंशन या मानदेय प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त सरकारी पेंशनरों का डेटा एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से;

(घ) राज्य सरकार, उसके बोर्डों और निगमों में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों का डेटा का एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से;

(ङ) निजी क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिकों को भुगतान की गई मजदूरी के आंकड़ों का एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से, जिसके संबंध में पंजाब उपकर अधिनियम के तहत एक उपकर देय है, जैसा कि हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है;

(च) ई-खरीदी पर कृषि उपज की खरीद के लिए किसानों को किए गए भुगतान का एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से,

(छ) बिजली निगमों से प्राप्त वार्षिक बिजली खपत और उस आधार पर आय का अनुमान लगाने का एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से,

(ज) सरकारी कर्मचारी, एक स्थानीय कंप्यूटर ऑपरेटर, एक स्थानीय स्वयंसेवक, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक छात्र की टीम से मिलकर बने पांच सदस्यों वाली स्थानीय समितियों द्वारा आय सत्यापन के माध्यम से प्रत्येक सदस्य ने स्वतंत्र रूप से आय का आकलन किया है और अंतिम सत्यापित आय तर्क-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होती है।

पीपीपी में दी गई आय का सत्यापन परिवार नामित ऑनलाइन तंत्र, नामतः 'सुधार' और 'शिकायत' पोर्टल के माध्यम से नाम हटाने को चुनौती दे सकते हैं। प्रत्येक नाम हटाने की चुनौती इलेक्ट्रॉनिक रूप से और

स्वचालित रूप से ऑनलाइन सत्यापन के लिए उपयुक्त स्थान पर भेज दी जाती है। स्थानीय समिति द्वारा निर्धारित आय को चुनौती देने वाले अनुरोधों को समान संरचना वाली उच्च स्तरीय समितियों, जिन्हें सेक्टर समितियाँ कहा जाता है, को भेजा जाता है।

पात्र परिवारों का सर्वेक्षण

29. श्री आफताब अहमद : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) राज्य में परिवार पहचान पत्र के कारण वर्ष 2022 तथा 2023 में बंद की गई पेंशन (बुढ़ापा, अपंग, विधवा तथा अन्य) की जिलावार संख्या कितनी है; तथा

(ख) क्या सरकार ने कोई नया सर्वेक्षण करवाया है अथवा परिवार पहचान पत्र के आधार पर केवल उक्त पेंशन बंद की गई है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : महोदय, उत्तर निम्न प्रकार से हैः –

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
(क)	राज्य में परिवार पहचान पत्र के कारण वर्ष 2022 तथा 2023 में बंद की गई पेंशन (बुढ़ापा, अपंग, विधवा तथा अन्य) की जिलावार संख्या कितनी है; तथा	लाभार्थीयों द्वारा स्वयं परिवार पहचान पत्र डाटाबेस में उपलब्ध करवाई गई जानकारी के आधार पर वर्ष 2022 और 2023 (दिनांक 18.02.2023 तक) में 1,04,655 पेंशन रोकी गई थी। इन रोकी गई पेंशन में से 67,614 पेंशन नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड), हरियाणा द्वारा पुनः सत्यापन उपरान्त बहाल कर दी गई है। रोकी गई पेंशन (वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा व अन्य) की जिलेवार सूची अनुलग्नक–I पर संलग्न है। स्थिति दिनांक 18.02.2023 की है।
(ख)	क्या सरकार ने कोई नया सर्वेक्षण करवाया है अथवा परिवार पहचान पत्र के आधार पर केवल उक्त पेंशन बंद की गई है तथा उसका ब्यौरा क्या है?	जिन पात्र परिवारों की पेंशन बंद कर दी गई थी, उनका पुनः सत्यापन नागरिक संसाधन सूचना विभाग, हरियाणा द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि ऊपर उतर (क) में उल्लेख किया गया है, पुनः सत्यापन उपरान्त 67,614 पेंशन को बहाल कर दिया गया है। यदि कोई रोकी हुई पेंशन नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड), हरियाणा द्वारा पुनः सत्यापन उपरान्त योग्य पाई जाती है तो उसे पुनः बहाल कर दिया जाएगा।

अनुलग्नक–I

2022–2023 के दोरान (दिनांक 18.02.2023 तक) रोकी गई जिलावार पेंशन

जिला	2021.22			2022.23			कुल		
	रोकी गई	बहाल	शेष	रोकी गई	बहाल	शेष	रोकी गई	बहाल	शेष
अम्बाला	2239	1304	935	343	75	268	2582	1379	1203
भिवानी	2070	1140	930	833	133	700	2903	1273	1630
चरखी दादरी	1216	611	605	328	81	247	1544	692	852
फरीदाबाद	2054	1466	588	592	133	459	2646	1599	1047
फतेहाबाद	3143	1739	1404	420	130	290	3563	1869	1694
गुरूग्राम	1279	808	471	752	131	621	2031	939	1092
हिसार	3724	2505	1219	1924	256	1668	5648	2761	2887
झज्जर	2070	1165	905	944	134	810	3014	1299	1715
जीन्द	3278	1982	1296	1911	236	1675	5189	2218	2971
कैथल	2649	1778	871	1370	365	1005	4019	2143	1876
करनाल	3768	2440	1328	550	192	358	4318	2632	1686
कुरूक्षेत्र	3046	1796	1250	1456	296	1160	4502	2092	2410
महेन्द्रगढ़	2029	1094	935	451	81	370	2480	1175	1305
मेवात	956	712	244	302	65	237	1258	777	481
पलवल	1378	950	428	423	133	290	1801	1083	718
पंचकुला	661	478	183	172	52	120	833	530	303
पानीपत	1772	1208	564	587	119	468	2359	1327	1032
रेवाड़ी	1760	985	775	529	162	367	2289	1147	1142
रोहतक	2666	1575	1091	1540	220	1320	4206	1795	2411
सिरसा	3525	2128	1397	685	174	511	4210	2302	1908
सोनीपत	3128	1808	1320	2144	427	1717	5272	2235	3037
यमुनानगर	2453	1606	847	35535	32741	2794	37988	34347	3641
कुल	**50864**	**31278**	**19586**	**53791**	**36336**	**17455**	**104655**	**67614**	**37041**

दिनांक 18.02.2023 तक रोकी गई जिलावार बकाया पेंशन (वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा तथा अन्य)

जिला	वृद्धावस्था	दिव्यांग	विधवा	अन्य	कुल
अम्बाला	902	38	192	71	1203
भिवानी	1293	41	243	53	1630
चरखी दादरी	715	20	86	31	852
फरीदाबाद	714	19	218	96	1047
फतेहाबाद	1342	54	241	57	1694
गुरूग्राम	897	29	155	11	1092
हिसार	2115	104	561	107	2887
झज्जर	1385	52	196	82	1715
जीन्द	2191	94	608	78	2971
कैथल	1455	60	305	56	1876
करनाल	1269	43	284	90	1686
कुरूक्षेत्र	1916	87	333	74	2410
महेन्द्रगढ़	1139	21	97	48	1305
मेवात	291	10	176	4	481
पलवल	563	16	109	30	718
पंचकुला	218	11	47	27	303
पानीपत	759	34	190	49	1032
रेवाड़ी	987	20	85	50	1142
रोहतक	1781	81	455	94	2411
सिरसा	1525	55	280	48	1908
सोनीपत	2384	86	455	112	3037

यमुनानगर	2884	112	546	99	3641
कुल	**28725**	**1087**	**5862**	**1367**	**37041**

———————————

चालक प्रशिक्षण स्कूल की कार्यात्मकता

30. श्री आफताब अहमद : क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे किः

(क) गत 9 वर्षों में नूंह के गांव छपेड़ा में प्रस्तावित चालक प्रशिक्षण स्कूल के संबंध में राज्य सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए; तथा

(ख) उक्त स्कूल के कब तक कार्यात्मक बनाए जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

परिवहन मन्त्री (पंडित मूल चन्द शर्मा): (क) श्रीमान जी, गांव छपेड़ा, नूंह में चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर) के निर्माण हेतु उठाए गए कदमों का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता हैः–

क. गांव छपेड़ा, नूंह में आईडीटीआर स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री घोषणा दिनांक 23.10.2016 को की गई।

ख. गांव पंचायत से 87 कनाल भूमि ली गई तथा वर्ष 2017 में परिवहन विभाग के नाम हस्तांतरित की गई।

ग. मैसर्स मारुति सुजुकी इंडिया ने शुरुआत में एक निजी खिलाड़ी के रूप में कार्य करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

घ. तत्पश्चात्, मैसर्स टाटा मोर्टस को 27.02.2018 को मूल उपकरण निर्माता (OEM) भागीदार के रूप में चुना गया था और आईडीटीआर के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 03.01.2019 को एक सोसायटी का गठन किया गया।

ड. माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए दिनांक 03.03.2019 को आधारशिला रखी।

च. इसके उपरांत वास्तुकार सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदा प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, इसलिए केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी), पुणे से आईडीटीआर के निर्माण हेतु विस्तृत परिस्थिति योजना को तैयार करने एवं भेजने हेतु सम्पर्क किया गया।

छ. केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी), पुणे से अपेक्षित प्रस्ताव काफी लम्बे समय के बाद हाल ही में 26.12.2022 को प्राप्त हुई। सीआईआरटी पुणे के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

ज. परियोजना की कुल लागत रुपये 13.96 करोड़ थी जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समान अनुपात में वहन की जानी थी। कुल 698 लाख रुपये की राशि जिसमें से 349 लाख रूपये राज्य सरकार से तथा 349 लाख रूपये भारत सरकार से प्राप्त हुए।

(ख) उपरोक्त परियोजना के पूरा होने की समय सीमा इस समय सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। तथापि, इसे पूरा होने में एक साल और लगने की संभावना है।

.....

मेवात मॉडल स्कूल की कार्यात्मकता

31. श्री आफताब अहमदः क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) क्या यह तथ्य है कि जिले नूंह के ग्राम चिलावली (जयसिंहपुर) में वर्ष 2020 में निर्मित मेवात मॉडल स्कूल आज तक चालू नहीं हो पाया है, तथा

(ख) यदि हां, तो 3 वर्षों से देरी के क्या कारण हैं तथा इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): (क) हां श्रीमान जी।

(ख) मेवात विकास बोर्ड की दिनांक 12.11.2020 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, मेवात मॉडल स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अधिग्रहित किया जाना था। हालांकि, चिलावली (जयसिंहपुर) नूंह स्थित मेवात मॉडल स्कूल का भवन, मेवात विकास एजेंसी द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को नहीं सौंपा गया है। एक बार भवन, पूरी तरह से पूर्ण होने पर, स्कूल शिक्षा विभाग को सौंप दिए जाने के बाद स्कूल को कार्यात्मक बना दिया जाएगा।

.....

ऊपरि पुल का निर्माण करना

32 श्री सीता राम यादव : क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि रेवाड़ी से सादुलपुर रेलवे लाइन एल-87 पर ऊपरि पुल की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 16.02. 2020को दोगंडा अहीर रैली में की गई घोषणा के अनुसार कब तक निर्मित किये जाने की संभावना है?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) हाँ, श्रीमान् जी, सरकार के पत्र क्रमांक 13/28/2020-2 बी. एंड आर. (डब्ल्यू) दिनांक 21.04.2022 के तहत 36.57 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। रेलवे द्वारा दिनांक 16.06.2022 को जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग (जीएडी) को मंजूरी दे दी गई थी। तदानुसार, हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर इस कार्य का विस्तृत अनुमान/डीएनआईटी प्रक्रियाधीन है। इसके बाद जल्द ही इसकी निविदा आमंत्रित की जाएगी।

जर्जर उप–स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या

33. श्री सीता राम यादव : क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या अटेली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है तथा उपरोक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से जर्जर अवस्था में पड़े उप–स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है तथा इनके कब तक मरम्मत किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) श्रीमान जी, अटेली निर्वाचनक्षेत्र में कुल 51 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से 18 जर्जर अवस्था में हैं। 16 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में मरम्मत का

कार्य शुरू किया जा चुका है तथा 02 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जारी है।

.....

स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मत करना

34. श्री सीता राम यादव : क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि अटेली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में गांव धनौन्दा के स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जर्जर अवस्था में है; यदि हां, तो इसके कब तक मरम्मत किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) नहीं श्रीमान जी, गांव धनौन्दा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत के भवन में कार्यरत है जोकि जर्जर अवस्था में नहीं है।

नए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर की गई कार्यवाही

35. श्री वरुण चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में स्कूल जाने वाले 25 लाख बच्चों की वर्ष में दो बार जांच करने तथा डेटा को ई–उपचार पोर्टल से जोडने के लिए नए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर क्या कार्यवाही की गई?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : महोदय, महामहिम राज्यपाल, हरियाणा द्वारा, दिनांक 05.09.2022 को **"सेहत"** (हरियाणा स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य एवं उपचार) कार्यक्रम **"सेहत"**का शुभारम्भ किया गया । तदानुसार, वर्ष 2022–23 में केन्द्रीय परियोजना समग्र शिक्षा के बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मद विद्यार्थियों की भलाई के अन्तगर्त 827.04 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया। जिसके तहत सभी राजकीय विद्यालयों में हीमोग्लोबिन मीटर, परीक्षण स्ट्रिप्स, लैंसेट्रस, अल्कोहल स्वैब, ऊंचाई मापन स्केल, वजन स्केल एवं आंखों की जांच का स्नेलन चार्ट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत निर्धारित स्क्रीनिंग स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार **अवसर** पोर्टल पर **सेहत** सॉफ्टवेयर मॉडयूल को एकीकृत कर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य जांच रिकार्ड को डिजिटाइज करने का प्रावधान

कर लिया गया है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए एन.एच.एम. की ओर से डॉक्टरों की टीम विद्यालयों का दौरा कर रही है। स्क्रीन किए गए विद्यार्थियों का डेटा अवसर पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। अवसर पोर्टल पर अब तक (अर्थात 16.02.2023 तक) कुल 3,88,990 विद्यार्थियों का स्वास्थ्य डाटा अपलोड किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, कुल 19663 स्कूल शिक्षकों को स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एंबेसडर (एच.डब्ल्यू.ए.) के रूप में नामित किया गया है । एन.एच.एम. की स्वास्थ्य टीमों की मदद से इन हेल्थ एंड वेलनेस एंबेसडर (एच.डब्ल्यू.ए.) के लिए ऊंचाई, वजन, दृष्टि, हीमोग्लोबिन आदि की जांच के सम्बन्ध में एक दिवसीय अभिमुखी कार्यक्रम भी आयोजित किये गए हैं। उनके लिए निर्देशात्मक मॉडयूल भी तैयार किया गया है ।

.....

ट्विनिंग कार्यक्रम पर की गई कार्यवाही

36. श्री वरुण चौधरी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में विद्यार्थियों के लिए ट्विनिंग कार्यक्रम पर क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कंवर पाल) : महोदय, स्कूल ट्विनिंग कार्यक्रम की षुरूआत राजकीय विद्यालयों और निजी विद्यालयों सहित औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों (आई.टी.आईज़), बहुतकनीकी संस्थानों (पॉलीटैकनिक्स), इंजीनियरिंग महाविद्यालयों आदि संस्थानों के मध्य संवाद स्थापित करने, अन्तराल को पहचानकर उसे दूर करने और षैक्षणिक भ्रातृत्व के आधार पर संस्थानों को एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ विद्यार्थियों को एक दूसरे से सीखने व एक दूसरे संस्थानों के सीखने के संसाधनों का 'बाँट, संभाल व एकजुटता' की भावना से उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है।

विभिन्न सरकारी विद्यालयों से हर वर्श कक्षा 6 से 8 के 25 विद्यार्थी निकटवर्ती निजी विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों आदि में और कक्षा 9 से 12 के 25 विद्यार्थी निकटवर्ती निजी विद्यालयों के साथ–साथ औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों (आई.टी.आईज़), बहुतकनीकी संस्थानों (पॉलीटैकनिक्स), इंजीनियरिंग महाविद्यालयों आदि में जाकर विभिन्न पाठ्यक्रमों बारे अपने ज्ञान को अद्यतन करने के लिए वहाँ

की प्रातः कालीन सभा, पुस्तकालय कालांष, भाशा कक्षा और विद्यालयों/संस्थानों द्वारा आयोजित विषेश कार्यक्रमों जैसे – पर्व, खेल और सांस्कृतिक उत्सवों आदि में भाग लेते हैं।

.....

स्वामित्व अधिकारों के लिए पंजीकृत पट्टेदारों के संबंध में ब्यौरा

37. श्री वरुण चौधरी : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या राज्य में 20 वर्षों से अधिक से किराए/ पट्टे/ लाइसेंस फीस पर चल रही नगर निगम की दुकानों तथा घरों का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए पंजीकृत पट्टेदारों की निगम–वार संख्या कितनी है तथा उन पट्टेदारों की संख्या कितनी है जिनको स्वामित्व अधिकार स्थानांतरित किए गए हैं?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता) : श्रीमान जी, राज्य में 20 वर्षों या उससे अधिक से किराये या पट्टे या लाईसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों तथा घरों का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए पंजीकृत आवेदकों की पालिका–वार संख्या तथा जिन्हें स्वामित्व अधिकार स्थानांतरित किए गए है उन आवेदकों की संख्या ''अनुबंध ए'' पर संलग्न है।

Annexure-A

Municipality-wise number of occupants registered and the number of occupants who have been transferred the ownership rights

Sr. No.	ULB Name	No of Application received/Registered	No. of ownership rights transferred
1	Adampur	0	0
2	Ambala Sadar	932	0
3	Ambala City	212	53
4	Assandh	19	0
5	Ateli Mandi	0	0
6	Bahadurgarh	269	12
7	Barara	3	0
8	Barwala	77	52
9	Bawal	147	0
10	Bawani Khera	53	0
11	Beri	19	0
12	Bhiwani	Nil	0
13	Bhuna	56	0
14	Charkhi Dadri	60	0
15	Cheeka	27	0
16	Dharuhera	0	0
17	Ellenabad	2	0
18	Faridabad	1451	89
19	Farukh Nagar	24	15
20	Fatehabad	72	22
21	Ferozpur Jhirkha	65	0
22	Gannaur	7	0
23	Gharaunda	65	0
24	Gohana	83	0
25	Gurugram	540	245
26	Hansi	81	0
27	Hathin	2	0
28	Hisar	203	78
29	Hodal	40	0
30	Indri	62	0
31	Ismailabad	0	0
32	Jakhal Mandi	117	0
33	Jhajjar	136	0

Annexure-A

Municipality-wise number of occupants registered and the number of occupants who have been transferred the ownership rights

Sr. No.	ULB Name	No of Application received/Registered	No. of ownership rights transferred
34	Jind	205	0
35	Julana	39	0
36	Kaithal	82	35
37	Kalanaur	24	1
38	Kalanwali	50	0
39	Kalayat	1	0
40	Kalka-Pinjore	121	6
41	Kanina	19	0
42	Karnal	271	0
43	Kharkhoda	22	0
44	Kundli	0	0
45	Ladwa	127	0
46	Loharu	NIl	0
47	Mahendragarh	78	0
48	Mandi Dabwali	296	0
49	Manesar	0	0
50	Meham	84	0
51	Nangal choudhary	0	0
52	Naraingarh	50	0
53	Narnaul	261	0
54	Narnaund	22	0
55	Narwana	31	0
56	Nilokheri	44	0
57	Nissing	0	0
58	Nuh	159	0
59	Palwal	235	44
60	Panchkula	15	1
61	Panipat	68	0
62	Pataudi Mandi	225	107
63	Pehowa	24	0
64	Pundri	20	0
65	Punhana	51	0
66	Radaur	65	6

Annexure-A			
Municipality-wise number of occupants registered and the number of occupants who have been transferred the ownership rights			
Sr. No.	**ULB Name**	**No of Application received/Registered**	**No. of ownership rights transferred**
67	Rajound	0	0
68	Rania	40	17
69	Ratia	152	7
70	Rewari	221	0
71	Rohtak	458	47
72	Sadhaura	33	0
73	Safidon	73	0
74	Samalkha	52	0
75	Sampla	6	2
76	Shahbad	20	0
77	Sirsa	134	0
78	Siwan	0	0
79	Siwani	Nil	0
80	Sohna	58	34
81	Sonipat	97	6
82	Taoru	5	0
83	Taraori	19	0
84	Thanesar	142	0
85	Tohana	3	0
86	Uchana	15	0
87	Uklana	16	0
88	Yamunanagar	674	12
TOTAL (88 ULBs)		**9731**	**891**

पांच करम सड़कों को पक्का करना

38. **श्री वरूण चौधरी**: क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में जिलावार पांच करम सड़कों की संख्या कितनी हैं जो गत 2 वर्षों में पक्की

की गई हैं तथा अब तक पक्की की गई उन सड़कों की संख्या कितनी है जो पक्की होनी हैं ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

151

ब्यौरा

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 38 से सम्बन्धित ब्यौरा

राज्य में पांच करम चौड़ाई वाले 1296 किलोमीटर लम्बाई के 505 कच्चे रास्ते चिन्हित किए गये है । जिलावार पांच करम के रास्तों की संख्या जो गत 2 वर्षों में पक्की की गई है तथा अभी पक्की की जानी है का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रमांक संख्या	जिले का नाम	गत 2 वर्षो में पक्के किए गये रास्ते		सड़कों की निर्माण प्रकिया जारी है		अभी पक्के किए जाने वाले रास्ते	
		संख्या	लम्बाई (कि.मी. मे)	संख्या	लम्बाई (कि.मी. मे)	संख्या	लम्बाई (कि.मी. मे)
1.	अम्बाला	1	1.55	5	9.10	10	14.39
2.	भिवानी	16	62.97	19	69.01	36	140.00
3.	दादरी	2	8.59	--	--	4	9.33
4.	फरीदाबाद	1	1.40	6	14.22	6	8.07
5.	फतेहाबाद	1	1.75	2	2.76	30	70.09
6.	गुरूग्राम	5	6.58	13	27.23	8	16.19
7.	हिसार	3	8.37	8	24.09	34	118.72
8.	झज्जर	1	1.49	--	--	9	25.52
9.	जीन्द	15	42.22	7	9.76	11	30.10
10.	कैथल	15	20.98	26	53.26	13	32.56
11.	करनाल	7	12.03	8	12.48	4	8.60
12.	कुरूक्षेत्र	2	2.78	7	12.94	1	1.18
13.	महेन्द्रगढ़	11	37.81	13	25.34	13	35.37
14.	नूह	7	10.23	11	20.15	8	11.56
15.	पलवल	2	4.66	3	3.90	1	2.55
16.	पंचकूला	--	--	1	2.66	2	2.32
17.	पानीपत	1	2.36	3	6.26	7	15.84
18.	रेवाड़ी	4	7.49	16	29.96	5	15.31
19.	रोहतक	--	--	1	2.37	3	3.92
20.	सिरसा	5	19.60	4	16.62	42	127.73
21.	सोनीपत	1	1.10	1	1.63	--	--
22.	यमुनानगर	--	--	1	3.52	3	5.78
कुल जोड़		**100**	**253.96**	**155**	**347.26**	**250**	**695.13**

सड़कों की वर्तमान स्थिति

39. श्रीमती गीता भुक्कल : क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि झज्जर निर्वाचन क्षेत्र की निम्न सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या हैः-

(क) मातनहेल से साल्हावास सड़क वाया अकेहड़ी मदनपुर तथा लदैन;
(ख) झज्जर शहर की आन्तरिक सड़कें; तथा
(ग) दादरी चौक से रामलीला ग्राउंड तक सड़क वाया अम्बेडकर चौक?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) मातनहेल से साल्हावास वाया अकेहड़ी मदनपुर और लदैन सड़क की स्थिति यातायात योग्य है और जिसका रख-रखाव नियमित पैचवर्क के माध्यम से किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव चंडीगढ़ यादि क्रमांक 09/266/2022-3 बीएण्डआर(डब्लयू) दिनांक 16.01.2023 द्वारा एन.सी.आर.पी.बी. ऋण सहायता योजना के तहत झज्जर जिले में 0.00 किमी से 19.00 किमी तक मातनहेल साल्हावास कोसली सड़क के चौड़ीकरण के लिए लगभग 64.00 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। प्रोजेक्ट स्वीकृति और निगरानी समूह-1 (पी.एस.एम.जी.-1), एन.सी.आर.पी.बी, नई दिल्ली के अनुमोदन के बाद काम शुरू किया जाएगा।

(ख) झज्जर शहर की आंतरिक सड़कों की स्थिति यातायात योग्य है। झज्जर शहर की सभी सड़कों का रख-रखाव नियमित पैच वर्क के माध्यम से किया जा रहा है।
(ग) दादरी चौक से रामलीला मैदान वाया अम्बेडकर चौक तक सड़क की स्थिति यातायात योग्य है और जिसका रख-रखाव नियमित पैचवर्क के माध्यम से किया जा रहा है। इस सड़क के सुधार के लिए 867.71 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति सरकार के यादि क्रमांक 09/89/2023-3 बीएण्डआर(डब्लयू) दिनांक 17.02.2023 द्वारा प्रदान की गई है। (विधायक की प्राथमिक कार्य सूचि के अंतर्गत)

आरोही मॉडल विद्यालयों की संख्या

40. श्रीमती गीता भुक्कल :क्या शिक्षा मंत्री कृप्या बताएंगे किः—

(क) राज्य में चल रहे आरोही मॉडल विद्यालयों की संख्या कितनी है तथा क्या इन विद्यालयों को बंद करने या समायोजित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) इन विद्यालयों में स्वीकृत सीटों की संख्या कितनी है तथा वहां विद्यालय वार विद्यार्थियों की संख्या कितनी है; तथा

(ग) अध्यापकों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है तथा स्टाफ की स्थिति क्या है तथा कितनी रिक्तियां उपलब्ध हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : श्रीमान जी, (क) राज्य में 36 आरोही मॉडल स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों को बंद करने या समायोजित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) इन विद्यालयों में स्वीकृत सीटों की संख्या 20160 है। विद्यालय वार स्वीकृत सीटों की संख्या व पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	जिला	स्कूल कानाम	छात्रों की स्वीकृत संख्या	पढ़ रहे छात्रों की संख्या
1	भिवानी	आरोही मॉडल स्कूल, सिवानी खेडा	560	165
2		आरोही मॉडल स्कूल, तोशाम	560	328
3	फतेहाबाद	आरोही मॉडल स्कूल, बनगांव	560	194
4		आरोही मॉडल स्कूल, डूलट	560	364
5		आरोही मॉडल स्कूल, जल्लोपुर	560	345
6		आरोही मॉडल स्कूल, कन्हड़ी	560	233
7		आरोही मॉडल स्कूल, सरवरपुर	560	217
8	हिसार	आरोही मॉडल स्कूल, अग्रोहा	560	363
9		आरोही मॉडल स्कूल, भिवानी रोहिल्ला	560	273
10		आरोही मॉडल स्कूल, गैबीपुर	560	248
11		आरोही मॉडल स्कूल, घिराय	560	378
12		आरोही मॉडल स्कूल, खेड़ी लोहचब	560	282
13		आरोही मॉडल स्कूल, उकलाना गांव	560	393
14	जींद	आरोही मॉडल स्कूल, घसोखुर्द	560	250
15		आरोही मॉडल स्कूल, हसनपुर	560	264
16		आरोही मॉडल स्कूल, नारायणगढ़	560	143
17	कैथल	आरोही मॉडल स्कूल, ग्योंग	560	365
18		आरोही मॉडल स्कूल, रामगढ पांडवा	560	241

19		आरोही मॉडल स्कूल, सोंगरी	560	277
20	महेन्द्रगढ़	आरोही मॉडल स्कूल, मंढाना	560	354
21	नूंह	आरोही मॉडल स्कूल, बावला	560	238
22		आरोही मॉडल स्कूल, हसनपुर बिलोंडा	560	71
23		आरोही मॉडल स्कूल, मोहम्मदपुर नगर	560	130
24		आरोही मॉडल स्कूल, मुन्ढेता	560	58
25		आरोही मॉडल स्कूल, रेवासन	560	242
26	पलवल	आरोही मॉडल स्कूल, अली ब्राह्मण	560	122
27		आरोही मॉडल स्कूल, गदपुरी	560	389
28		आरोही मॉडल स्कूल, लड़ियाका	560	154
29		आरोही मॉडल स्कूल, रामगढ़	560	122
30	पानीपत	आरोही मॉडल स्कूल, छाजपुर कलां	560	448
31	सिरसा	आरोही मॉडल स्कूल, जलालाना	560	261
32		आरोही मॉडल स्कूल, झिरी	560	418
33		आरोही मॉडल स्कूल, कालुआना	560	375
34		आरोही मॉडल स्कूल, खारी सुरेरा	560	238
35		आरोही मॉडल स्कूल, मोहम्मदपुरिया	560	236
36		आरोही मॉडल स्कूल, नाथुसरी कलां	560	277
कुल			**20160**	**9456**

(ग) अध्यापकों के स्वीकृत पदों की संख्या तथा स्टाफ की स्थिति का रिक्तियों सहित विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	**पद का नाम**	**स्वीकृत पद**	**भरे हुए पद**	**रिक्त पद**
1	प्रधानाचार्य	36	18	18
2	पी0जी0टी0	756	369	387
3	टी0जी0टी0	576	0	576
कुल		**1368**	**387**	**981**

.....

सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि–

(क) डॉ0 कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने मुझे पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि उनके परिवार में विवाह समारोह होने के कारण वे दिनांक 21 से 23 फरवरी, 2023 तक सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ख) इसी प्रकार से श्री सोमबीर सांगवान, विधायक ने ई–मेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि उन्हें व्यक्तिगत कार्य के कारण शहर से बाहर जाना है, इसलिए वे आज दिनांक 21 फरवरी, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ग) इसी प्रकार से श्री संदीप सिंह, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, राज्य मंत्री ने ई–मेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वे बीमार होने के कारण दिनांक 21 फरवरी, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

————————

शून्यकाल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शून्य काल शुरू होता है। मैं सभी माननीय विधायकों से एक परामर्श करना चाहता हूँ कि शून्य काल में बोलने के लिए 22 माननीय सदस्यों ने अपनी पर्ची डाली है। यदि सभी सदस्य 3–3 मिनट्स का समय लेना चाहेंगे तो तीन मिनट का समय निर्धारित कर देंगे। यदि प्रत्येक सदस्य 5 मिनट बोलना चाहेंगे तो बाकी के बचे हुए 10 माननीय सदस्यों को कल बोलने का मौका दिया जा सकता है।

आवाजें: ठीक है। प्रत्येक सदस्य को कम से कम 5 मिनट का समय तो बोलने का मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: आज जो 12 माननीय सदस्यगण शून्य काल में बोलेंगे, उनके नाम इस प्रकार से हैं– श्री अभय सिंह चौटाला, श्री भव्य बिश्नोई, श्री राम कुमार गौत्तम, श्री बिशन लाल सैनी, श्री नीरज शर्मा, श्री लक्ष्मण सिंह यादव, श्री जयवीर सिंह, श्री मोहन लाल बडौली, श्री शीश पाल सिंह केहरवाला, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री आफताब अहमद और श्री लक्ष्मण नापा। अब श्री अभय सिंह चौटाला अपनी बात रखेंगे। (विघ्न) यदि दोबारा पर्ची डालेंगे तो उनका बोलने का नम्बर नहीं आयेगा। (विघ्न) फिर तो सभी माननीय सदस्यों को केवल तीन मिनट ही बोलने के लिये दिया जा सकता है। (विघ्न) हाउस की जैसी सहमति होगी वैसी ही समय–सारणी निर्धारित कर देंगे।

आवाजें: ठीक है, पांच मिनट का समय निर्धारित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, बाकी बचे हुए 10 माननीय सदस्यों को कल बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रश्न काल के दौरान 'परिवार पहचान पत्र' के ऊपर लगभग आधे घंटे का समय हाउस का लिया है लेकिन चेयर ने कोई इंट्रप्ट नहीं किया। यदि कोई अन्य माननीय सदस्य इस तरह से सप्लीमैंट्री करता तो चेयर जरूर उसको इंट्रप्ट करती।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, यह सदन के नेता का प्रोरोगेटिव है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई भी बोलने से रोक नहीं सकता। क्या सदन के नेता को ऐसा कहा जा सकता है कि आप बैठ जाइये? अभय जी, आप केवल अपनी बात सदन के पटल पर

रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर का जवाब दिया है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जगह दूसरा माननीय सदस्य दूसरी सप्लीमैंट्री के लिये किसी जरूरी विषय पर खड़ा होता है तो उसको कहा जाता है कि यह प्रश्न काल है। सत्ता पक्ष की तरफ से यह बात रिप्लाई के माध्यम से भी बताई जा सकती थी। चेयर द्वारा उसके लिये प्रश्न काल में टाइम देकर के जो उस समय दूसरे संबंधित माननीय सदस्यों का प्रश्न लगना चाहिये था, वह समय तो नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदन के नेता हैं । यह उनका प्रोरोगेटिव है कि वे जब चाहें तब सदन में बोल सकते हैं और किसी भी बात का जवाब दे सकते हैं । (विघ्न) उन्होंने सदन में माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दिया है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कम–से–कम क्वैश्चन आवर का तो ध्यान अवश्य रखना चाहिए । स्पीकर महोदय, हिसार में एक इंटरनैशनल एयरपोर्ट बनाने की बात थी । इसकी आज भी चर्चा चल रही थी । माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय एवियेशन मिनिस्टर और वहां के लोकल एम.एल.ए. ने बहुत सारे पोस्टर छपवाये जिन पर इंटरनैशनल एयरपोर्ट का नाम लिया गया था । वहां पर इंटरनैशनल एयरपोर्ट बनने की बात की पोल तो लोक सभा में खुल गई कि इस प्रदेश में कोई भी इंटरनैशनल एयरपोर्ट नहीं बनना है । इंटरनैशनल एयरपोर्ट के नाम पर वहां पर एक बहुत बड़ा भू–माफिया खड़ा कर दिया गया । लोगों से वहां पर जमीन तो इंटरनैशनल एयरपोर्ट बनाने के नाम पर कौड़ियों के भाव पर ले ली गई लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उन जमीनों की अपने और अपनी कम्पनियों के नाम पर रजिस्ट्रियां करवाकर लोगों के साथ ठगी करने का काम किया

है । वहां पर लम्बे समय से एक धरना चल रहा था जिसकी अवधि 34 दिन थी । बरवाला के विधायक उस धरने पर बैठे हुए लोगों को माननीय एवियेशन मिनिस्टर के पास लेकर गये और माननीय एवियेशन मिनिस्टर ने उनको आश्वासन दिया कि हम आपके लिए एक सड़क बनाएंगे । इसके बाद वहां पर करोड़ों रुपये की लागत से एक टैम्पोरेरी सड़क बनाई गई । वहां की सारी जमीन कम्पनियों के नाम पर खरीदी गई । अब उस सड़क को बन्द कर दिया गया । वहां पर जहाज तो उतरेगा या नहीं यह तो नहीं पता लेकिन उस सड़क के बन्द होने की वजह से अब लोगों को 30–30 किलोमीटर का एक्स्ट्रा सफर तय करना पड़ रहा है । मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना है कि वे इसकी जांच करवायें कि वहां पर किन–किन लोगों ने जमीन खरीदी है । जो जमीनें करोड़ो रुपये प्रति एकड़ के भाव की थी और जिन गांवों की जमीनें हिसार शहर के साथ लगती थी तथा जिनसे हिसार शहर केवल 6 किलोमीटर दूर था आज उसको 32 किलोमीटर दूर लेकर जाकर खड़ा कर दिया गया । वहां पर जो कारखाने लगे हुए थे और जो शॉप्स बनी हुई थी उनकी कीमत करोड़ो रुपये की थी आज उन शॉप्स को कोई लाखों रुपये में भी लेने को तैयार नहीं है । उस रास्ते के बन्द होने के कारण 12–14 गांवों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई । स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली जो बच्चियां हिसार में साइकिल पर पढ़ने के लिए जाती थी आज उनको 32 किलोमीटर का सफर तय करके हिसार शहर जाना पड़ता है, जो पहले केवल 6 किलोमीटर दूर था । यह कार्य केवल अपनी जेबें भरने के लिए और भू–माफिया खड़ा करने के लिए किया गया । माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस भू–माफिया की जांच करनी चाहिए और एयरपोर्ट की डैडलाइन है जहां पर इसकी आखिरी दीवार आती है उसके साथ एक रास्ता देकर उन लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए । इससे उनका रास्ता भी कम हो जाएगा और उनको राहत भी मिल जाएगी । मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर अवश्य संज्ञान लेने का काम

करेगी । इसके अलावा आज प्रदेश की ऐसी हालत है कि समय पूरा होने के बाद भी 2 वर्षों तक तो पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये गए । जब समय पूरा होने के बाद भी 2 वर्षों तक तो पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये गए तो जो पैसा ग्राम पंचायतों द्वारा विकास कार्यों में खर्च होना चाहिए था वह पैसा केवल कागजों में ही दिखाया गया । कागजों में दिखाये गए उस पैसे को अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार के सहयोगियों और साथियों ने डकारने का काम किया है । सरकार पर ये आरोप अनेक जगहों पर लगे हैं । (घंटी) ऐसे आरोपों की कोई कमी नहीं है । जब पंचायतों के चुनाव सम्पन्न हो गये तो ई–टैंडरिंग लागू करने की बात की गई । यह सरकार पहले पंचायतों को और अधिक अधिकार देने की बात कर रही थी लेकिन इस ई–टैंडरिंग प्रणाली के द्वारा सरकार ने उनके अधिकारों को खत्म करने का काम किया है । इस बारे में सरकार और माननीय मंत्री जी तो कह रहे थे कि 2–4 लुटेरे किस्म के लोग इसका विरोध कर रहे हैं । कल जीन्द में महिला सरपंच और पुरूष सरपंच और बुजुर्ग तथा अनेक लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल थे जो इस प्रणाली का विरोध कर रहे थे । वे लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, इसलिए सरकार को उनकी बात को सुनना चाहिए था और उनका मैमोरैंडम लेकर उस पर एक्शन लेना चाहिए था। (घंटी)

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आपने 5 मिनट बोलने के लिए समय दिया था।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आपको बोलते हुए 5 मिनट का समय हो चुका है। हाउस में घड़ी लगी हुई है, इसलिए आप उसमें समय देख लें। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री भव्य बिश्नोई जी अपनी बात रखेंगे।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हिसार के एविएशन हब के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि वहां पर सस्ती जमीन ली गयी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वहां पर सारी 7200 एकड़ जमीन गवर्नमैंट की थी और वह विद्ईन डिपार्टमैंट ट्रांसफर की गयी थी। यह फैक्चूअली इनकरैक्ट बात हाउस में कही गयी है। मैं चाहता हूं कि इस बात को हाउस की प्रोसिडिंग्ज से हटवाया जाए। दूसरी जगह पर जो अलटरनेटिव रोड बनाया गया है वह हमारे फ्यूचर एक्सपैंशन प्लान का भी पार्ट है और उसका अलटरनेट यूज करेंगे। वहां पर सरकार का कोई भी पैसा मिस– यूटिलाईज नहीं हुआ है क्योंकि वहां पर रिटेनिंग वाल एयरपोर्ट अथॉरिटी के परिमिसिज को सिक्योर करना था, इसलिए संबंधित रास्ता बन्द किया गया है। उसके साथ– साथ फॉर्मर्ज से अलटरनेट लैंड प्रक्योर की है जिसमें ई–भूमि पोर्टल के माध्यम से लगभग 110 एकड़ लैंड 157 करोड़ रुपये में खरीदी है। उसका भी आज के दिन रजिस्ट्रेशन प्रोसैस चल रहा है। इस हाउस को इस तरीके से मिसगाईड किया जाता है और फैक्चूअल इनकरैक्ट बात कही जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि इन सारी बातों को हाउस की प्रोसिडिंग्ज से एक्सपैंज किया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपकी बात बिल्कुल सही है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ये जो आपके मिनिस्टर साहब बात कह रहे हैं, मैं उसके बारे में अपनी बात रखना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, पहले आप मेरी बात सुन लें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी मेरा और आपका नहीं है। आप सम्मान के साथ अपनी बात करें। यह आपका मिनिस्टर क्या होता है ?

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको मिनिस्टर ही कहा है।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आप सम्मान के साथ अपनी बात रखें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैंने आपका मिनस्टिर कहा है। इससे और सम्मान क्या होगा? माननीय उप मुख्यमंत्री जी मेरा भतीजा है और क्या इनको काका बोलूं?

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, यहां पर सभी माननीय सदस्य बराबर हैं। फिर चाहे उनमें कोई चाचा हो या कोई भतीजा हो।

श्री देवेन्द्र सिंह बबलीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात का जवाब देना चाहता हूं, इसलिए मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं सभी बातों के जवाब दे दूंगा, इसलिए माननीय मंत्री जी से पहले मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, इसलिए मुझे अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने संबंधित जमीन के बारे में अपनी बात कही है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं माननीय सदस्य की ही बात कर रहा हूं। यह हाउस में क्या हो रहा है? माननीय सदस्य और माननीय उप मुख्यमंत्री जी एक दूसरे को कह रहे हैं। एक बार रेल में दो आदमी जा रहे थे और उनमें से एक रेल की सीट के ऊपर वाली सीट पर बैठा हुआ था और दूसरा रेल की नीचे वाली सीट पर बैठा हुआ था। नीचे की सीट पर

बैठा आदमी ऊपर वाली सीट पर बैठे आदमी को बोला कि तुसी किथो आए, तो उसने कहा कि मैं दिल्ली तो आया हूं। फिर उसने पूछा कि कौन सी जगह से आये हो तो बताया कि पंथमार्ग से आया हूं। फिर उसने पूछा कि कौन से नम्बर से आये हो तो उसने कहा कि 10 नम्बर से आया हूं। फिर उसने पूछा कि आप कहां पर जा रहे हैं तो उसने कहा कि मैं अमृतसर जा रहा हूं। फिर उसने पूछा कि अमृतसर में कहां पर जाएंगे तो उसने कहा कि पापड़ वाली गली में जाउंगा। फिर उसने पूछा कि कौन से मकान में जाओगे तो उसने कहा कि 77 नम्बर मकान में जाउंगा। इसके बाद ऊपर की सीट पर बैठे व्यक्ति ने नीचे की सीट पर बैठे वाले व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा कि मैं भी दिल्ली से आया हूं और पंथमार्ग से 10 नम्बर से आया हूं और पापड़ वाली गली में 77 नम्बर मकान में जाना है। इन बातों को सुनकर साथ में बैठे तीसरे व्यक्ति ने कहा कि आप दोनों एक ही जगह से आये हो और एक ही जगह पर जाना है तो क्या आपस में जानते नहीं हो तो इस पर उन्होंने कहा कि हम प्यो– पुत्र हैं और अभी टाईम काट रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार ये दोनों टाईम काट रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, आपने एक वक्तव्य दिया था कि वहां पर लोगों से जमीन खरीदी गयी थी, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कहना है कि वहां पर सरकारी जमीन थी। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सदन के अन्दर वही चीज प्रस्तुत करें, जो फैक्चूअल हो। अगर कोई बात बिना फैक्ट्स के रखेंगे तो वह बात सदन को गुमराह करने वाली बात होगी और संबंधित माननीय सदस्य के खिलाफ सदन की अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना है कि वे पहले मुझे अपनी बात रखने दें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। पहले माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी अपनी बात रखेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही बात कह रहा था कि वहां पर बहुत सारी जमीनें खरीदी गयी और इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर भूमि माफिया खड़ा किया गया। वहां पर 3 वर्ष के अन्दर अनेकों रजिस्ट्रीज अलग– अलग कम्पनीज के नाम पर हुई हैं। आप कह रहे हैं कि अगर कोई फैक्चूअल बात होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्या आप इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं कि मैं अगर आपको कल संबंधित रजिस्ट्रीज की कॉपी लाकर दूंगा तो उन पर कार्रवाई करेंगे?

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, वहां पर हजारों रजिस्ट्रीज हुई होंगी। मैं एयरपोर्ट वाली जमीन की बात कर रहा हूं। एयरपोर्ट के लिए जमीन ली गयी तो क्या उनकी कोई रजिस्ट्रीज हुई हैं?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एयरपोर्ट के साथ जो रास्ते बनाये गये हैं और जो रास्ते बंद किये गये हैं। वहां लोगों की जमीनें नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, वहां पर लोगों की जमीनें हैं उसकी रजिस्ट्रियां हुई होंगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गलत बात बोल रहे हैं। एयरपोर्ट के साथ जो रास्ता बनाया गया है, वह रास्ता एयरपोर्ट की जमीन में है और उसके साथ लगती हुई जमीन सारी फोरेस्ट विभाग की है। ये फिर हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अगर वहां जमीनें खरीदी गई हैं और तेरी कम्पनी के नाम पर जमीन खरीदी हुई मिल गई तो क्या करेगा? (शोर एवं व्यवधान) तेरी अपनी कम्पनी के नाम जमीन खरीदी हुई है, औरों की बात क्या करता है, सबसे बड़ा चोर तो तू ही है। (शोर एवं व्यवधान) सारा प्रदेश लूट कर खा गया। (शोर एवं व्यवधान) सफाई और देता है इसलिए अध्यक्ष महोदय आप इसकी इन्क्वायरी करवाओगे या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए ऐफिडेविट दे दूंगा।

श्री जोगी राम सिहाग : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय से संबंधित अपनी बात कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जोगी राम जी, आप प्लीज बैठ जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप इसकी इन्क्वायरी करवाओगे या नहीं। (शोर एवं व्यवधान) मैंने आपको पहले भी ऐफिडेविड दिये थे।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप हाउस को मिसलीड कर रहे हो। आप पहले ऐफिडेविट दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको ऐफिडेविड दिये थे लेकिन आपने उनको हंस कर टाल दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आपने मुझे कोई ऐफिडेविट नहीं दिये। आपने पिछली बार भी कहा था कि मैं आपको ऐफिडेविट दूंगा। आपने मुझे अभी तक कोई ऐफिडेविट नहीं दिया है। आप पहले ऐफिडेविट दीजिए। मैं इसकी इन्क्वायरी करवाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप हाउस में बैठकर कुछ बोलते हो और फिर आप उस चीज से दूर भागते हो। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको रजिस्ट्रियां

लाकर दूंगा फिर मैं आपको देखता हूं कि आप क्या कार्रवाई करवाते हो। आप कार्रवाई करवाने के बजाए लुटेरों के पक्ष में खड़े हो जाते हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए आप प्लीज बैठ जायें। अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तो आप ऐफिडेविट दे दीजिए। (शोर एवं व्यवधान) आप मुझे ऐफिडेविट देंगे तो मैं इसकी इन्क्वायरी करवाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान) मैं यहां पर कमेटी बनाकर इन्क्वायरी करवाऊंगा।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जब यह बात on the floor of the House कह रहे हैं तो इसको आप ऐफिडेविट ही मानें। It is more than affidavit. (शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय सदस्य डॉ. कादियान जी ने कही है कि हाउस की floor पर जो बात कही जाती है उसको ऐफिडेविट माना जाये। मैं इनको कहता हूं कि जो एयरपोर्ट के रनवे के साथ सड़क बनाई गई है उस पर टोटल लैंड दोनों तरफ गवर्नमैंट की है। अध्यक्ष महोदय, आप इसकी इन्क्वायरी करवाईये। अगर फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी के खिलाफ हाउस में प्रिवलेज मोशन मूव करें। मैं इसका प्रस्ताव प्रस्तावित करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कर रहा था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप विदआउट फैक्ट्स बात करते हो और फिर आप अपनी जस्टिफिकेशन देने लग जाते हो, बिना फैक्ट्स के बात हाउस के अंदर नहीं चलेगी।

श्री जोगी राम सिहाग : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हो और आप सारा समय विपक्ष के माननीय सदस्यों को दे रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जोगी राम जी, प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भव्य बिश्नोई (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। सदन का माहौल कुछ गर्मागर्मी का है और कुछ हंसी मजाक का भी है लेकिन इसके बीच में मैं दो तीन महत्वपूर्ण बातें अपने निर्धारित समय में करने का प्रयास करूंगा लेकिन इससे पहले मैं विकास पुरूष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहता हूं । जो अपनी जनहितेषी, पारदर्शी और ईमानदारी कार्यशैली के माध्यम से हरियाणा की 36 बिरादरी की कायाकल्प करने का काम कर रहे हैं। इसी कार्यशैली की व्याख्या माननीय राज्यपाल महोदय ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से की है इसलिए मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आदमपुर से जुड़ी हुई दो तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आदमपुर में सरकारी अस्पताल की स्थिति बहुत ही दयनीय है, इससे पहले युग पुरूष चौधरी भजन लाल जी ने अपने कार्यकाल में इसको बनवाया था लेकिन आज वहां पर पर्याप्त डॉक्टर, स्टाफ और मैडीकल इक्विपमैंट्स उपलब्ध न होने की वजह से भारी संख्या में लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि आदमपुर के सिविल अस्पताल को एक State of the Art Multispecialty Hospital के तौर पर अपग्रेड करने का काम करें ताकि आदमपुर व आदमपुर के आसपास के इलाकों के हजारों मरीजों को गम्भीर रोगों के इलाज के लिए दूर–दराज के क्षेत्र में न जाना पड़े। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा बिन्दु आदमपुर हल्के में पीने के पानी के साथ–साथ सिंचाई के पानी की समस्या के संबंध में है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है कि आदमपुर की नहरों में महीने में कम से कम 16 दिन लगातार पानी उपलब्ध करवाएं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि आदमपुर में व आदमपुर के साथ–साथ जितने भी हमारे हल्के लगते हैं यहां पर तकरीबन किसानों का जीवन निर्वाह कृषि कार्य से चलता है और आदपपुर

के कई गांव टेल से भी जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ किशनगढ़ ब्रांच नहर से एक छोटी नहर बननी प्रस्तावित है जो गांव लाडपुर से लेकर शिशवाल, काबरेल, बगला, डोबी, खारिया, बालसमंद और बांडाखेडी तक ये छोटी नहर बनाई जानी है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि किसानों की जरूरत को देखते हुए इस नहर की प्रपोजल को भी जल्द से जल्द इम्प्लीमैंट करने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, आदमपुर में सरकारी रजबाहो और खालों की रिमॉडलिंग हमारी जनहितैषी सरकार कर रही है लेकिन इसके साथ–साथ आदमपुर में बड़ी संख्या में छोटे किसान भी हैं जिनके निजी खाल या तो कच्चे पड़े हुए हैं या बहुत ही बुरी अवस्था में है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि किसानों के निजी खालों को पक्का करने के नियमों में संशोधन करके उनको 20 साल से घटाकर 10 साल किया जाए जिससे न केवल आदमपुर में बल्कि प्रदेश के तकरीबन सभी हल्कों के किसानों को राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा विषय जिस पर मैं बहुत ही संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा कि आदमपुर, हिसार व भिवानी जिले में खासतौर पर खेल प्रतिभाओं का भंडार है लेकिन इन खेल प्रतिभाओं को पर्याप्त स्पोर्ट फैसिलिटी व इंफ्रास्ट्रक्चर न उपलब्ध होने की वजह से हम प्रतिभा को निखार नहीं पा रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वे राई में हमारा जो स्पोर्ट्स स्कूल है उसकी तर्ज पर अथवा उससे भी बेहतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आदमपुर हल्के में खोलने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, मुझे यकीन है कि आदमपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने से आदमपुर हल्के के साथ–साथ जितने भी हल्कों के खिलाड़ी आते हैं उन खिलाड़ियों को हम आपको ओलम्पिक स्तर के खिलाड़ी तैयार करके देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन सदन के समय का सम्मान करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री रामकुमार गौतम (नारनौद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए समय दिया इसलिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, अपनी जो बात माननीय सदस्य अभय चौटाला जी ने रखी थी उस पर मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि जो रास्ता बंद किया है मेरे पास टेलिफोन आए थे तलवंडी राणा में धरना चला हुआ है, वह रास्ता एक बार खोल दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस पर जैसा कि उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी ने बताया है कि अल्टरनेट अरेंजमैंट करें जब तक वह सड़क न बने तब तक वह रास्ता चालू रखा जाए क्योंकि वहां लोग बहुत जबरदस्त समस्या से जूझ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा विषय सरपंच विरोध कर रहे हैं उस बारे मेरा कहना यह है कि इसे 2 लाख की बजाय थोड़ा सा बढ़ाकर वाया मीडिया निकालकर इस राड़ को बंद करना चाहिए और इस राड़ की बाड़ करनी चाहिए। आप चाहे इसे थोड़ा सा ही बढ़ाकर उनके साथ आपसी सहमति करें क्योंकि माहौला बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। सरपंच का चुनाव लड़ा जिसने 1–1, 2–2 करोड़ रुपये पहले वाली चीजें दिमाग में सोचकर के खर्च किए हैं।

श्री अध्यक्ष: गौतम जी, क्या दो करोड़ रुपए इसमें से ही निकालना है।

श्री रामकुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा बीच–का रास्ता निकालकर इस समस्या को दूर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा विषय ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे बारे है कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी वह 10 साल रही तब इन्होंने यह मुद्दा नहीं उठाया जबकि यह सोनिया गांधी जी व मनमोहन सिंह के हाथ में ही था तब कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने यह मुद्दा नहीं उठाया, इस पर ध्यान नहीं दिया। अब कांग्रेस ने तीन राज्यों में ओल्ड पेंशन लागू कर दी है जिससे ऐसी आग लगी हुई है। यह विषय स्टेट से संबंधित नहीं है यह केन्द्र से संबंधित है इसलिए इस संबंध में मोदी जी से बात करके ओल्ड पेंशन के बारे में बात करें। एक कर्मचारी की जिन्दगी के लिए ओल्ड पेंशन बहुत महत्वपूर्ण है।

हम भी सारे पेंशन लेते हैं, एम.पी. भी पेंशन लेते हैं इसलिए कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन भी उम्मीद है। अब कांग्रेस पार्टी आउट ऑफ पावर है और आम आदमी पार्टी वाले भी इसे सब जगह लागू करेंगे और ये सरकार को भी ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए हर सूरत में मजबूर कर देंगे। इसलिए इस संबंध में मोदी जी से बात करके ओल्ड पेंशन लागू करवाएं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी करनाल में भगवान परशुराम के जलसे में गए थे तब वहां वायदा करके आए थे कि ई.बी.पी.जी. कैटेगरी की पोस्टें हैं वे 400 से ऊपर हैं इस संबंध में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जाते ही उसका फैसला करवाउंगा लेकिन आज तक उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। मेरा कहना यह है कि इस वक्त का जो माहौल है सब जगह रिजर्वेशन–रिजर्वेशन है यह अच्छी बात है कोई बुरी बात नहीं है जैसा भी चल रहा है लेकिन 10 परसैंट दोबारा ई.बी.पी.जी. की और 10 परसैंट जो जाट समेत जो चार जातियां हैं उनकी टोटल 20 परसैंट रिजर्वेशन जरूर लागू करो। जनरल कैटेगरी की 30 परसैंट बहुत हैं। जब सारा ही सौदा रिजर्व हो गया तो फिर इनका क्या कसूर है। ई.डब्ल्यू.एस. से किसी को भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश संस्कृत भाषा के साथ बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। अभी तक बहुत मुद्दत बीत गई कोई संस्कृत भाषा की पोस्ट एडवरटाईज नहीं हुई है और न ही संस्कृत के लैक्चरार की कोई प्रोमोशन ही हुई है। इस तरफ भी ध्यान दिया जाये। इसी प्रकार से एम.पी.एच.डब्ल्यू. की पोस्टों की एडवरटाईजमैंट भी कई साल से नहीं हुई है। इसकी तरफ भी पूरा ध्यान दिया जाये। इसी प्रकार से पिछले 11 साल से आई.टी.आई. में अस्थायी तौर पर इंस्ट्रक्टर लगे हुए थे अब जो भी परमानैंट नियुक्ति की जाती है उनको निकाल दिया जाता है। उनको न निकाला जाये। 11 साल का अरसा बहुत ज्यादा होता है। इतने समय तो बेचारा आदमी बुढ़ा हो जाता है। अगर उनके साथ इस स्टेज पर ऐसा

किया जायेगा तो ऐसी स्थिति में वे कहां पर जायेंगे। इसी प्रकार से हुड्डा साहब के समय में पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट में पम्प ऑपरेटर्ज की नियुक्ति भी अस्थायी तौर पर की गई थी। कायदा तो यही था कि हुड्डा साहब ही उनकी नियुक्ति को स्थायी करते लेकिन किसी कारणवश यह सम्भव नहीं हो पाया लेकिन खट्टर साहब को तो यह काम सत्ता सम्भालते समय ही करना चाहिए था। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी इम्पोर्टैंट बातें कह रहा हूं। इस समय हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला यह है कि प्रदेश में और पूरे देश में कैंसर बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। इसका इलाज यही है कि जो लोग खाने–पीने की चीजों में मिलावट करते हैं और जो लोग दवाईयों में मिलावट करते हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाये जायें। मैंने पहले भी इस मामले को उठाया था। इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यह समय की एक बहुत ही जबरदस्त मांग है कि इस तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाये। इस प्रकार का अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान किया जाये। मेरा तो इतना कहना है कि अगर इस प्रकार के अपराधियों को सजा–ए–मौत का प्रावधान किया जाये वह भी ठीक होगा क्योंकि यह इंसानी नस्ल को कमजोर करने वाला काम है। कैंसर की बिमारी देश के लिए बहुत खतरनाक और हानिकारक है। (घंटी)

श्री बिशन लाल सैनी (रादौर) : स्पीकर सर, आपको एक छोटी सी बात याद होगी कि आपने एक बार यह कहा था कि जिस भी विधान सभा क्षेत्र के अंदर जो काम होता है या सरकार जो काम करवा रही है उसके ऊपर स्थानीय जनप्रतिनिधि को अपनी नजर रखनी चाहिए कि वह काम ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब सरकार ने जो रूपये रादौर विधान सभा क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों के लिए भेजे चाहे वे खेत किसान सड़क योजना के हैं चाहे विकास कार्यों के लिए पांच करोड़ रूपये देने की बात हो। अगर हम वहां पर चक्कर लगाकर देखते हैं तो जो सामग्री

उन कामों में यूज की जा रही है उसको देखकर रोना आता है। हम इसके बारे में वहां के एग्जीक्युटिव इंजीनियर को भी बोलते हैं। जे.ई. को भी कहते हैं कि वह यह क्या करवा रहा है? कहता है जी कोई बात नहीं ठेकेदार को बोल देंगे और बाद में ठेकेदार को कह देता है कि तू कर ले एम.एल.ए. से क्या लेता है। इस प्रकार से ठेकेदार लगातार घटिया सामग्री यूज कर रहा है। मैं विशेष तौर पर पंचायत मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो खजाने के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है उसके ऊपर पंचायत मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिए। जैसे आपने कहा कि एक कमेटी बना दी। एक कमेटी बना रखी है। उस कमेटी को विशेष तौर से रादौर के अंदर जरूर भेजें और हमें जरूर बतायें कि वह कमेटी आई हुई है। (विध्न)

श्री अध्यक्ष : आप लिखित में दो कमेटी को भेजेंगे।

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष जी, यह जो मैं बोल रहा हूं वह लिखित रूप में ही है।

श्री अध्यक्ष : आपकी पर्टीकूलर कम्पलेंट किस एरिया की है और कौन सी सड़क की है उसके बारे में सारी की सारी डिटेल लिखकर दें।

श्री बिशन लाल सैनी : अध्य़क्ष जी, हमने वहां के डी.सी. साहब को भी कहा और ए. डी.सी. साहब को भी कहा उन्होंने अधिकारियों को वहां पर भेजा भी है।

श्री अध्यक्ष : सैनी साहब, आपने कहा हमने मान लिया। आप लिखकर दें, हम कमेटी को वहां पर जरूर भेज देंगे।

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष जी, ठीक है मैं लिखकर भी भेज दूंगा। हम आपकी यह ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : यह मेरी ख्वाहिश नहीं है, यह तो आपकी ख्वाहिश है। मैं तो आपकी ख्वाहिश पूरी करने की बात कर रहा हूं। यह आपने कहा है कि वहां पर कमेटी को भेजा जाये। (विघ्न)

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष जी, मंत्री जी सामने बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप पर्टीकूलर रोड का नाम बतायें। कौन सी रोड का है और किस एरिया का है यह तो आपको बताना पड़ेगा। जनरल तौर पर यह नहीं किया जा सकता।

श्री बिशन लाल सैनीः अध्यक्ष महोदय, हमारे बी.एण्ड आर. मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी जो सड़कें बन रही हैं वे बनती बाद में हैं और टूट पहले जाती हैं। इस बारे में भी एक कमेटी का गठन होना चाहिए जो सड़कों की जांच कर सके। हम उन सड़कों के बारे में बता देंगे कि कौन सी सड़क कब बनी है और कब टूटी है। इसी प्रकार से रादौर से पिपली की जो सड़क है उसके ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी तथा गृह मंत्री श्री अनिल विज भी गुजर चुके हैं और मेरे ख्याल से उप–मुख्यमंत्री जी भी वहां से गुजर चुके होंगे। उस सड़क की इतनी बुरी हालत है और उसमें इतने गड्ढे हैं कि हर तीन–चार दिन के बाद दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग मर रहे हैं। वहां पर बड़े–बड़े ट्रॉले चलते हैं जिसके कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। उसका टैंडर भी हो चुका है तथा टैंडर अलॉट भी हो चुका है लेकिन इसके बावजूद भी 3 महीने हो चुके, इस सड़क पर काम शुरू नहीं हो रहा है। क्या मंत्री जी इसकी वजह बतायेंगे कि उस सड़क का काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है ताकि हम भी लोगों को समझा सकें? हर बार यही कह दिया जाता है कि एक हफ्ते में काम शुरू हो जायेगा। इसी प्रकार से वर्ष 2007 में ऐजुसैट के 7000 मासिक के रेट पर चौकीदार लगाये गये थे और 2007 से लेकर आज वर्ष 2023 आ गया है लेकिन उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उनसे 24 घंटे काम लिया जाता है और उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उनसे रात को चौकीदार का काम लिया जाता है और दिन में उनसे चपरासी का काम लिया जाता है इसलिए उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाये क्योंकि 7 हजार रुपये मासिक में उनका

गुजारा नहीं हो पा रहा है। आपने मुझे शून्यकाल पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमने टैंडर के माध्यम से काम शुरू करवाये हैं और जिनके बारे में माननीय सदस्य गुणवत्ता में कमी की बात कह रहे हैं। उनके बारे में आम आदमी की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए हम हर गांव में एक निगरानी समिति भी बनवा रहे हैं। विधायक तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और ये स्वयं जा कर उस काम की समीक्षा कर सकते हैं। अगर कहीं पर कोई कोताही मिलती है तो आप उस काम को रुकवाने का काम करें, एक्शन लेने का काम करें। अगर लगता है कि उसके बाद भी कोई इम्पलीमैंटेशन नहीं हो रही है तो शिकायत कर दें हम उसकी जांच करवायेंगे। यह तभी रुकेगा जब हम सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसकी समीक्षा करेंगे। यह व्यवस्था परिवर्तन होने लग रहा है इसलिए इसमें समय लग सकता है। पहले जो पैसा खुर्दबुर्द होता था, हम इस सोच के साथ काम कर रहे हैं कि वह पैसा गांव के विकास में गुणवत्ता के साथ लगे। उसके लिए सभी माननीय सदस्यों का सहयोग बहुत जरूरी है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अगर आपको कहीं पर कोई कमी नजर आती है तो आप लिख कर व्हट्स ऐप पर भेज दीजिए। किसी माननीय साथी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है केवल व्हट्स ऐप पर भेज दीजिए और मैं उसको साथ के साथ विजिलेंस को दूंगा और उनको पकड़ने का काम करेंगे।

श्री बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, मैं तो अभी कह रहा हूं इसीलिए माननीय मंत्री जी को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि ये मुझे आज ही व्हट्स ऐप करें तो हम आज ही इसके आदेश जारी कर देंगे और कल से उसकी जांच शुरू हो जायेगी। कहीं पर भी अगर गड़बड़ है तो उसकी जांच होगी और उसको बख्शा नहीं जायेगा।

श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद, एन.आई.टी.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत दुःख होता है जब सदन के पटल पर झूठे आंकड़े दिये जाते हैं। आज मेरा तारांकित प्रश्न लगा हुआ था कि नगर निगम के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है और क्या पैसे के अभाव में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उसके जवाब में मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि राशि के अभाव में विकास कार्य प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से आज मेरे दो अतारांकित प्रश्न लगे हुए थे। मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के जवाब में मंत्री जी 4 बार क्या लिखते हैं। सड़क और नाली निर्माण के कार्य को करवाने के प्रस्ताव पर सीवरेज और जल आपूर्ति लाइन डालने उपरान्त व राशि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा। इसके बाद दोबारा फिर लिखते हैं कि नाली निर्माण का कार्य नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा। उसके बाद तीसरी बार फिर लिखते हैं कि नाली निर्माण का कार्य नगर निगम, फरीदाबाद के द्वारा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा। चौथी बार फिर लिखते हैं कि इस सड़क व दोनों ओर नाली–नाले के निर्माण का कार्य नगर निगम फरीदाबाद द्वारा राशि की जगह धनराशि लिख दिया, उपलब्ध कराए जाने पर किया जायेगा। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 13 में मंत्री जी लिखते हैं कि नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा उक्त जगह बाल कल्याण स्कूल पॉकेट, बेग रोड और जीवन नगर के अनुमान तैयार किये गये हैं जहां की बेटी ने ट्विटर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि मेरी शादी आ रही है इसलिए सीवरेज को अस्थाई तौर पर

साफ करवा दिया जाये। इस प्रश्न के जवाब मे यही लिखा हुआ है कि सीवरेज लाईन व गलियों का कार्य राशि की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण करवा लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, कौन से मंत्री जी सच्चे हैं जो तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे हैं या जो अतारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। यह बहुत गहन विषय है। आप इस विषय पर एक स्पेशल कमेटी बनाईये कि ऑफिसर्ज ने एक ही दिन में दो जवाब क्यों दिये? अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप और मंत्री जी उस प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके जवाब को देखते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है। नगर निगम के खाते में 645 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं । क्या यही 'सबका साथ, सबका विकास है।' एन.आई.टी. 86 के लिए फूटीकोड़ी भी सरकार के पास नहीं है। सरकार बार–बार यही झूठा नारा देती है और बार–बार हम विकास के लिए तरशते हैं। क्या मेरे क्षेत्र की जनता टैक्स नहीं दे रही है? क्या उस 645 करोड़ रुपये में एन.आई.टी. 86 की जनता का हक नहीं है? अध्यक्ष महोदय, जबकि मेरी विधान सभा में न एच.एस.वी.पी. का पैसा लग पा रहा है, न एफ.एम.डी.ए. का पैसा लग पा रहा है, न स्मार्ट सिटी का पैसा लग पा रहा है। मेरा निवेदन है कि नगर निगम में पड़े उस पैसे में से आधा पैसा मेरी विधान सभा के लिए ब्लॉक किया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक हमारे यहां हर्डवेयर प्याली रोड है जिसके ऊपर बच्चे तक शहीद हो गये हैं और मुख्यमंत्री जी को भी उस सड़क के बारे में पर्सनली पता है। वहां ये खुद देखकर भी आए हैं। कृपा उस रोड को टाईम लिमिट में बनवा दीजिए। वहां जो बच्चे सड़कों के गड्ढ़ों की वजह से मर गये हैं उसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कानून बने। हमारे क्षेत्र के विकास के लिए तो हमें तर्शाया जा रहा है और बाकी कोई ऐसी गंदगी की चीज होगी उसको धोने का काम एन.आई.टी. 86 करेगा। कोई ट्रीटमैंट प्लांट लगना है तो वह एन.आई.टी. 86 में लगेगा। गौंछी ड्रेन से कैंसर का पानी फसलों में ले जाना है तो एन.आई.टी. 86 से जाएगा। एन.

आई.टी. 86 को इतने अच्छे तोहफे देने से भी सरकार खुश नहीं होती। सरकार अब एक नया तोहफा और दे रही है कि हमारे यहां पाली में कूड़ा घर बना रही है। हमारे क्षेत्र में दो–चार गांव ही बचे हैं जिनका पानी शुद्ध और साफ है। अध्यक्ष महोदय, हम तो सरकार से यह कहते हैं कि हमारे क्षेत्र को ऐसे तोहफे देने पर रहम करो क्योंकि हमारे क्षेत्र की पूरी जनता त्राहि–त्राहि कर रही है इसलिए पाली में कूड़ा घर न बनाया जाए। उप मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं मैं उनसे चाहूंगा कि वे हमारे क्षेत्र पर विशेष कृपा करें और मेरी बात पर ध्यान दें कि पूरे हरियाणा में मेरी इकलौती विधान सभा एन.आई.टी. 86 ऐसी है जहां कोई तहसील नहीं है। पूरे हरियाणा में 178 तहसील हैं, एक तहसील हमारी एन.आई.टी. 86 को भी दे दीजिए। मेरी विधान सभा की 20 लाख से ज्यादा की आबादी है जोकि भरपूर रैवेन्यू दे रही है। वहां लोगों को अपने काम के लिए दूर जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज बिजली की समस्या की बात हो रही थी जिसमें प्रदेश के पैसे का बहुत नुकसान हुआ है। हुड़डा साहब, की सरकार के समय में अदानी के साथ प्रति यूनिट 2.94 रुपये में 25 साल का एग्रीमैंट हुआ था कि वह हमें प्रति दिन साढ़े तीन करोड़ यूनिट बिजली देगा लेकिन आज सरकार ने सप्लीमैंट्री एग्रीमैंट कर लिया जिसका सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया है कि हमें कम से कम एक हजार करोड़ रुपये अदानी से लेने हैं। पूरी कैबिनेट ने उस पर मोहर लगा दी है। अध्यक्ष महोदय, पीक टाईम में हम 12 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद रहे हैं जबकि अदानी से हमारा एग्रीमैंट 2.94 रुपये प्रति यूनिट का हुआ था। मैं चाहूंगा कि मेरे पास यह अंग्रेजी अखबार की कटिंग है इसको टेबल कर लें। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। इस घोटाले की भी जांच होनी चाहिए। मैंने इस संदर्भ में कालिंग अटैंशन मोशन भी लगाया है ताकि हरियाणा की जनता लुटने से बच सके। धन्यवाद।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव (कोसली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपके माध्यम से मुझे मेरी सरकार से निवेदन करना है कि वैसे तो एक सामाजिक बुराई की समस्या पूरे हरियाणा प्रदेश में है लेकिन मेरा ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते से देहात में भी यह समस्या चली गई है। जगह–जगह ओयो होटल के नाम से जो कारोबार चल रहे हैं वे सामाजिक ताने–बाने को भी खराब कर रहे हैं और हम पर पाश्चात्य सभ्यता को भी थोप रहे हैं। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, आप उन देशों को जाकर देखिये जिनमें ये समस्याएं थी वे तो आज उल्टे भारत की तरफ आ रहे हैं लेकिन हम उस पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं। आज जगह–जगह ये असामाजिक कार्य हो रहे हैं। मैंने उन होटलों में देखा है कि उनमें केवल पानी का गिलास तक भी नहीं होता है, वहां केवल मंजियां डली होती हैं, बैड डले होते हैं। वहां न खाने का कुछ होता है और न वहां कोई रेस्टोरैंट होता है लेकिन जगह–जगह इस तरह के अनैतिक कार्य हो रहे हैं, यह चिन्ता का विषय है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे हमारी सरकार ने एक ही रात में अवैध हथियार रखने वाले तस्करों के ऊपर छापे मार कर 1165 मुकदमें दर्ज किये हैं। उसी तरह से यह कार्रवाई भी आप करायें वरना तो जो हमारा समाजिक ढांचा है, जो भारतीय संस्कृति और संस्कार हैं, वे बिगड़ते चले जायेंगे। अतः इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि मैं दो साल से हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री जय प्रकाश दलाल साहब से निरंतर एप्लीकेशन दे रहा था कि मेरे यहां एन.एच. 71 पर एग्रीकल्चर की 23–24 एकड़ जमीन है तो यहां पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का काम किया जाये। मैंने दो साल पहले यह चिट्ठी लिखी थी तो कहा गया कि यह केन्द्र नहीं बन सकता। इसके बाद मैंने यह भी कहा कि जिस प्रकार लोहारू में बाजरे का एक्सीलेंस सैंटर बनाया गया है, ठीक उसी तरह चूंकि हमारे यहां सरसों की खेती बहुतायात में होती है, अतः

हमारे यहां सरसों का एक एक्सीलेंस सैंटर बनाया जाये लेकिन काम इसके उलट किया गया। मैंने तो इस जमीन के कागजात भी दे दिए थे लेकिन अभी मैंने हाल में पता किया है कि यहां की सात एकड़ जमीन को वेयरहाउस को दे दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि इस जमीन को बांटने का काम कर दिया गया है जबकि मैं नहीं चाहता कि यह जमीन टुकड़ों में बंटे। वह सरकारी जमीन है और इसका सदुपयोग केवल एग्रीकल्चर परपज के लिए ही होना चाहिए, किसी स्टोरेज के लिए नहीं होना चाहिए और यही कारण है कि मैंने इस संदर्भ में दो बार लिखकर भी देने का काम किया है लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है। ठीक उसी तरह से मेरा यह भी निवेदन है कि कोसली विधान सभा क्षेत्र के लोग काफी समय यह इंतजार कर रहे हैं कि गुरावड़ा और कोसली के कालेज में पी.जी. क्लासिज शुरू कर दी जाये। मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इन कालेजिज में यह सुविधा शुरू कर दी जाये। इसके अतिरक्ति कोसली विधान सभा क्षेत्र के कस्बे भाकली के संदर्भ में मैने पहले भी सदन में आवाज उठाई थी कि यहां पर जमीन अवेलेबल है अतः यहां पर एक आयुर्वेदिक कालेज का निर्माण करवाया जाये। कोसली विधान सभा क्षेत्र एक रूरल एरिया है और यही कारण है कि इसमें गांव और ढाणियां ज्यादा आती हैं। हमारे यहां की ढाणियों में बिजली कम दी जाती है और सबको मालूम है कि ढाणियों में लोग ट्यूबवैलों के साथ बनाये गए आवास में रहते हैं। ठीक है कि सरकार द्वारा 8 घंटे ट्यूबवैल चलाने के लिए थ्री फेस बिजली दी जाती है लेकिन चूंकि सरकार ने हर जगह पैट ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया है, के दृष्टिगत मैं अनुरोध करता हूँ कि यहां पर 16 घंटे सिंगल फेस की लाइट देने का काम तो जरूर किया ही जाये क्योंकि यहां पर पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं और लाइट न होने की वजह से उनकी पढ़ाई खराब होती है। उनको समय पर लाइट की बहुत जरूरत होती है। जिस प्रकार म्हारा गांव–जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान हमारी

सरकार ने किया है ठीक उसी तर्ज पर ढाणियों में भी बिजली की अबाधित सप्लाई देने का काम किया जाये। मेरा क्षेत्र भी ट्यूबवैल सिंचित क्षेत्र है। हमारे यहां वोल्टेज की बहुत प्राब्लम रहती है इसलिए मैंने 33 के.वी. सब–स्टेशनों की मांग की है। डिपार्टमैंट ने इस सबको चिन्हित करने का काम भी कर लिया है। अतः चिन्हित किए गए एरिया में 33 के.वी. सब स्टेशन लगाने की अनुमति जरूर दी जाये। हमारे यहां सबसे पहला 33 के.वी.सब–स्टेशन लूखी, इसके बाद भूरथला, आशियाकी गोरावा, जीवड़ा, निमोठ, देहलावास, गुलाबपुरा, दिदोली एवं नांगल भगवानपुर में क्रमवार तरीके से लगाने का कष्ट किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे डहीना खण्ड कार्यालय को उपमण्डल का दर्जा भी दिया जाये क्योंकि इस उपमंडल की चारो तरफ का जो डिस्टेंस है वह 40 ओर 45 किलोमीटर बनता है जोकि एरिया से संबंधित फिजिबिलिटी को पूर्ण करता है। अतः इस उपमंडल की कार्रवाई पर भी जल्द से जल्द अमल करने का काम किया जाये। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि जाटूसाना महाविद्यालय के भवन का निर्माण पूरा हो चुका है, इसका जल्द से जल्द शिलान्यास करने का काम किया जाये। यही नहीं भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय का रीजनल सैंटर का भवन, लूला अहीर में तैयार हो गया है, अतः इसका भी जल्द से जल्द उद्घाटन करने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री जयवीर सिंह (खरखौदा, अ.ज.): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब ने अपने शासन काल के दौरान खरखौदा विधान सभा क्षेत्र को एक वैली की तरह संवारा था और यहां पर हर तरह की सुविधायें देने का काम किया था। हमने यह तो सुना था कि पहले ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्ज बनती थी, इसके बाद रंगीन पिक्चर्ज बनने लगी और

इसके बाद डिजिटल का जमाना आ गया। कहने का मतलब यह है कि हमने समय के साथ साथ प्रोग्रैस होती तो देखी है लेकिन समय के साथ आगे न बढ़ने और पिछड़ने की कार्यवाही को होते हुए तो हमने इस सरकार के इस 8 साल के समय में ही देखा है। सरकार द्वारा खरखौदा विधान सभा क्षेत्र के संदर्भ में बड़ी–बडी बातें तो की जाती हैं। कभी आई.एम.टी. की बात करती है कभी कुछ और बातें की जाती हैं लेकिन असल में यही बात सामने निकलकर आती है कि इस सरकार के 8 सालों में हमारे खरखौदा विधान सभा क्षेत्र के लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। हुड्डा सरकार ने आई.एम.टी. इसलिए बनाई थी ताकि लोगों को रोजगार मिले लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके ऊपर 8 साल तक कोई काम न करके हमारे इलाके के साथ एक धोखा किया है। यह आई.एम.टी. इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को सही मायने में इसका फायदा मिले ना कि सरकार के फायदे के लिये यह बनाई गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार में तो सारे काम उल्टे हो रहे हैं। कंपनियों को मंहगें दामों पर जमीनें दी जा रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से अनुरोध है कि सरकार जो इस संबंध में कंपनियों से प्रोफिट ले रही है उस प्रोफिट का एक हिस्सा संबंधित किसानों को भी दिया जाना चाहिये। तभी जाकर आई.एम.टी. का सही मायने में फायदा लोगों तक पहुँचेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में यह कहना है कि आज प्रदेश के युवा रोजगार के मामले में सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। आज उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार में स्थाई भर्ती की तो कहीं पर जिक्र तक नहीं होता है। कहीं पर अग्निवीर की बात की जाती है और कहीं पर कौशल रोजगार की बात हो रही है, जिसका कोई भरोसा नहीं है कि यह कब तक चलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा काम तो राजस्थान सरकार ने किया है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि 30 हजार अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई तौर पर लगाया जायेगा।

जिसकी मैं भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूँ। इतना ही नहीं राजस्थान में 'वाल्मिकी समाज कल्याण बोर्ड' है, जिसका बजट पहले 20 करोड़ रुपये हुआ करता था लेकिन अब वहां के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसके बजट को 100 करोड़ रुपये करने की घोषणा की है। इससे संबंधित वर्गों के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुँचेगा। मैं चाहता हूँ कि हरियाणा में भी 'वाल्मिकी समाज कल्याण बोर्ड' का गठन किया जाये और उसके तहत संबंधित वर्गों के लोगों को फायदा दिया जाये। कांग्रेस सरकार के समय हुड्डा साहब ने गरीब समाज को आगे बढ़ाते हुए 11 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की थी लेकिन आज उनको लगे 8 साल के करीब हो गये हैं, उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही हैं। उनके वेतन का कोई ठिकाना नहीं है। उन बेचारों का आए दिन शोषण होता है। जनसंख्या के हिसाब से पहले के मुताबिक उनका काम बढ़ा है। अब सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी लगाने की बजाए उनमें से भी हटाये जा रहे हैं। इस विषय की तरफ भी सरकार का ध्यान जरूर से जरूर जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र खरखौदा शहर में सीवरेज व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। शहर की जो मुख्य सड़कें थी, उनकी सीवरेज के कारण खराब हालात हो गई हैं। मेरे खरखौदा शहर का बाईपास टूटा हुआ है। मैंने, विधायकों द्वारा दिये गये 25 करोड़ रुपयों के कामों की सूची में भी इसका उजागर किया हुआ है। हमारे इलाके की एक बहुत बड़ी डिमाण्ड यह है कि जो औचंदी बार्डर से भालोठ तक वाया खरखौदा होकर सड़क जाती है उसको चारमार्गी बनाया जाये क्योंकि वहां पर ट्रैफिक पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आई.एम.टी. का विस्तार सही तरीके से होना चाहिये। हमारे इलाके के हर रोज लगभग 15–16 हजार लोग काम के लिये या सरकारी व प्राईवेट विभागों में काम–धंधों के लिये दिल्ली आते–जाते हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आई.एम.टी. को मैट्रो के साथ जोड़ने का काम करें। यदि यह सरकार इस प्रकार का काम नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद चौधरी भूपेन्द्र सिंह

हुड्डा जी से भी रिक्वैस्ट करूंगा कि इस मैटर को प्राथमिकता के तौर पर रखें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ।

श्री शीश पाल सिंह केहरवाला (कालांवाली, अ.ज.): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्ष 2020 के अंदर सरकार ने स्पेशल गिरदावरी करवा कर सिरसा जिले के किसानों के लिये 258 करोड़ रुपये मुआवजे देने की घोषणा की थी। वर्ष 2021 के मुआवजा की भी घोषणा हो चुकी है। उसके बाद वर्ष 2021 का मुआवजा आया परन्तु वर्ष 2020 का जो मुआवजा है उसको 258 करोड़ रुपये से घटाकर 94.91 करोड़ रुपये कर दिया गया । यह किसानों के साथ सरासर अन्याय है । इसी प्रकार हरियाणा के तमाम हिस्सों में भी जहां 200–300 करोड़ रुपये मुआवजा था उसको एक चौथाई कर दिया गया । यह किसानों के साथ धोखा है, इसलिए इसे दुरूस्त किया जाए । सिरसा में पहले तीन काले कानूनों के खिलाफ एक पक्का मोर्चा लगा था । वहां पर आज भी पिछले 36–37 दिन से पक्का मोर्चा लगा हुआ है । इसी प्रकार हरियाणा के अन्य हिस्सों में भी किसानों के पक्के मोर्चे लगे हुए हैं । ये मोर्चे तब उठेंगे जब उनको उनका हक दे दिया जाएगा । कुछ किसानों ने बीमा करवाया हुआ है लेकिन बीमे का पैसा कुछ किसानों को मिलता है और कुछ किसानों को नहीं मिलता है । इसी के साथ–साथ मुआवजा देने में एक प्रावधान है कि अगर किसी इलाके में सरकार के द्वारा मुआवजा आता है तो जिन किसानों ने बीमे में अपनी किस्त कटवा दी उनको सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाता है । इसी तरह किसानों के साथ एक और अन्याय हो रहा है । जब उनको फसल की बुवाई के समय डी.ए.पी. खाद की जरूरत होती है तो उस समय उनको डी.ए.पी. खाद नहीं मिलती है । जब किसानों को यूरिया खाद की आवश्यकता होती

है तो उस समय डी.ए.पी. खाद के ढेर लगे होते हैं । उस समय किसानों को डी.ए.पी. खाद ले जाने के लिए कहा जाता है । यह सरकार इस प्रकार का काम कर रही है । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ई–टैंडरिंग पर अपनी ओर से बातें रख रही है और सरपंच अपने तरीके से अपनी मांगें रख रहे हैं । मांगें रखना उनका हक है । सरकार ने जिस प्रकार से फैसला लिया है हम चाहते हैं कि सरकार उस पर एक बार संज्ञान लें और सरपंचों के जो स्टेट पदाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी हैं, सरकार उनके साथ बैठकर बात और चर्चा करे तथा फिर इसका हल निकालें । पिछले 2 सालों से पंचायतों के चुनाव न होने की वजह से गांवों में विकास नहीं हो पा रहा था । इसके बाद जब पंचायत बन गई है तो भी गांवों में कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि सरपंच और मैम्बर्ज धरने पर बैठे हुए हैं । इसके अलावा गांवों के लोग दुखी हो रहे हैं । उन्होंने सरकार की ओर आंख लगाई हुई है कि शायद इस बार सैशन में सरपंचों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि को बढ़ा दिया जाए ताकि पंचायतों का काम भी चल सके । इसके अलावा एजुसैट के चौकीदारों की भी बात आई थी । वर्ष 2007–08 में उनकी भर्ती हुई थी और उनका मानदेय केवल 7000 रुपये प्रतिमाह है । इतने रुपये में उनका गुजारा नहीं होता है । डी.सी. रेट पर भी इससे ज्यादा रुपये दिये जाते हैं । अतः मेरा कहना है कि उनका मानदेय भी बढ़ाया जाए । इसी प्रकार से हरियाणा रोडवेज के कंडक्ट्र्स की वेतन विसंगतियों को भी दूर किया जाए । उनका भी पुराने पैटर्न पर चल रहा है । एफ.पी.एल. का पे–स्केल 19,900 रुपये है । जब वह वर्ष 1957 में लागू हुआ तो उनके बराबर में चाहे जे.बी. टी. का पे–स्केल है चाहे फॉरेस्ट गार्ड का पे–स्केल है, वह पहले बराबर था लेकिन औरों का पे–स्केल आज बढ़ चुका है । औरों का पे–स्केल 35,400 तक पहुंच चुका है परंतु उनका वहीं का वहीं पड़ा है । अतः उसको भी दुरूस्त किया जाए । सिरसा में एक ढाणी चांदमारी है । वह सिरसा का चतर पट्टी इलाका है । वहां पर मुजारा

को बटाई की जो जमीन मिली थी । उनका वहां पर सौ साल से वास है परंतु पिछले 3–4 दिनों से सरकार ने हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद सरकार ने रात–दिन लगाकर जबरदस्ती दीवारें निकालकर उनको बेघर करने का काम किया है । जो मामला सरकार के संज्ञान में लाया जाता है मेरा कहना है कि सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए । सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया है ।

13:00 बजे

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले ओ.पी.एस. वाले इम्पलॉयीज की मांगों का समर्थन करता हूं क्योंकि यह स्कीम इम्पलॉयीज के लिए बहुत जरूरी है। जैसे दूसरे राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओ.पी.एस. स्कीम को लागू किया है, उसी तरह से यहां पर भी लागू किया जाए। दूसरी बात यह है कि जींद में सरपंचों पर जो लाठी चार्ज हुआ है मैं उसकी निन्दा करता हूं। सरपंचों की बात सुनी जाए, वे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। वे सरकार से जो अधिकार मांग रहे हैं, वे अधिकार उनको दिये जाएं। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों का कोटा केवल तीन विभागों तक ही सीमित रखा गया है, वह बिल्कुल गलत है। एजुकेशन विभाग और पुलिस विभाग में नौकरियां ही नहीं हैं, इसलिए यह बात बेमानी है। इस प्रकार इनको पहले की तरह ही सभी विभागों में 3 प्रतिशत कोटा दिया जाए। राशन कार्ड होल्डर्ज की डिमांड्स को भी सुना जाए और इनको भी दूसरे राज्यों की तरह लागू किया जाए। आज सारे क्लर्क पुराने क्लर्क की तरह नहीं हैं क्योंकि आज के दिन सभी डिपार्टमैंट्स में कार्य का बोझ उन पर है। फिर उसमें चाहे कोई भी डाटा फीड करना हो या ऑनलाईन करना हो तो वह सारा काम इन्हीं को करना पड़ता है। आजकल यह टैक्नीकल जॉब हो गयी है, इसलिए इनके वेतन की भी वृद्धि की जाए। इसके अतिरिक्त स्पैशल बैकवर्ड क्लॉस के 600 बच्चों की पुलिस विभाग में ज्वाइनिंग की जानी है, उस पर भी सरकार संज्ञान ले। इसके अलावा जो 1983 पी. टी.आईज. को नौकरी से निकाल दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं इनका चूल्हा नहीं बुझने दूंगा, इसलिए इनका भी चूल्हा जलवाया जाए। इस संबंध में मेरे पास कुछ रिप्रजेंटेशंज आयी हैं और मैं उनको टेबल कर दूंगा। इनके अलावा मेरे हल्के की कुछ डिमांड्स हैं। मेरा कहना यह है कि पिछले 8 सालों में गोहाना हल्का बहुत पिछड़ गया है। इसके लिए कोई स्पेशल पैकेज देकर इस हल्के की पुरानी कमियों को ठीक किया जाए। इसके अतिरिक्त सरकार ने वहां पर वेस्टर्न बाईपास को यह कहकर बन्द कर दिया है कि इस पर पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। इसको बनवाया जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 'हां' की थी। यह सी.एम. अनाउंसमैंट थी। इसके लिए विधान सभा में भी दो बार हां हो चुकी है, लेकिन आज तक उसको नहीं बनाया गया है। उन बातों को 8 साल का समय हो चुका है। इसके अलावा मेरे हल्के की पीने के पानी की समस्या है जिसमें 44 गांव शामिल हैं। सरकार कहती है कि उन्होंने प्रदेश के हर गांव में पीने का पानी पहुंचा दिया है। मेरे पास संबंधित गांवों की लिस्ट है और मैं उसको टेबल्ड कर दूंगा। इन गांवों को पाईप्स

की शॉर्टेज की वजह से पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इस कारण संबंधित गांवों की बहुत बुरी हालत है। इसके अतिरिक्त किलोहड़ की आई.आई.आई.टी. की हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल में क्लॉसिज शुरू करवा दी गयी थी। लेकिन आज तक उसकी नींव नहीं भरी गयी है। इसके लिए जमीन आ चुकी है और दूसरी बातें भी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उसकी नींव भी नहीं भरी है। आज पब्लिक 3 बीमारियों से ज्यादा ग्रसित है जिसमें हार्ट अटैक, कैंसर और एक्सीडैंट शामिल है। लेकिन मेरे हल्के के मेडिकल कॉलेज में तीनों बीमारियों का एक भी डॉक्टर नहीं है। कॉर्डियोलॉजिस्ट नहीं है, एनकोलॉजिस्ट नहीं है और ब्रेन सर्जन भी नहीं है। इस प्रकार ये तीनों बीमारियों के डॉक्टर्ज नहीं हैं तो वह मेडिकल कॉलेज किसलिए है? पहले लोग कहते हैं कि वहां पर मरने के लिए भेजना हो तो भेज दें क्योंकि वहां पर कोई सुविधा नहीं है। वहां पर न तो डॉक्टर्ज हैं और न ही दवाइयां हैं। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के की एक और समस्या है। जो पौंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा है वह उस पर संज्ञान लें क्योंकि मेरे हल्के के जितने भी तालाब हैं। वे सभी बीमारी का घर बन चुके हैं क्योंकि उन सब में गंदगी है। इसको दूर करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम बनकार उस गन्दें पानी की निकासी का प्रबन्ध किया जाए ताकि लोगों का जीवन सुखी हो जाए। आप केवल यह मेरे हल्के का तो विशेष काम करवा दें। इसके अतिरिक्त रोजगार की बात आती है। मेरे हल्के में जो रेल कोच फैक्ट्री लगनी थी वह बनारस में चली गयी है, लेकिन उसकी जगह मेरे हल्के के लिए आई.एम. टी. मंजूर थी जिसको इस सरकार ने कैंसिल कर दिया। वहां पर युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत जगह खाली है, इसलिए वहां के लिए एक आई.एम.टी. की घोषणा की जाए। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के के किसानों की खराब फसलों का कई सालों का मुआवजा बकाया है। इस पर संज्ञान लेकर उन गरीब किसानों का मुआवजा दिया जाए। यह कहा जाता है कि हरियाणा प्रदेश ने बहुत सुधार किया है लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। हरियाणा प्रदेश का सामाजिक सुरक्षा में 33वां नम्बर है। इसके अतिरिक्त नाबालिक बच्चों की तस्करी का सबसे बड़ा मुद्दा है जिसमें पूरे देश में 2697 बच्चों की तस्करी बतायी गयी है और उनमें से हरियाणा प्रदेश के 1099 बच्चे हैं। इस प्रकार हरियाणा प्रदेश में 40 प्रतिशत से ज्यादा तस्करी हुई है। इसमें हरियाणा प्रदेश देश में नम्बर 1 पर है। इसी प्रकार से चार्जशीट करने में और बच्चों के खिलाफ केस फाईल करने में और प्रदुषण में भी 1 नम्बर पर है। शायद, हरियाणा प्रदेश स्कूल्ज मर्ज करने में भी 1 नम्बर पर है। इतने स्कूल्ज कहीं पर भी मर्ज नहीं हुए हैं।

श्री उपाध्यक्षः मलिक साहब, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश किसानों पर कर्ज के मामले में भी पूरे देश में चौथे नम्बर पर है।

श्री उपाध्यक्षः मलिक साहब, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

अब माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद जी अपनी बात रखेंगे।

श्री आफताब अहमद (नूंह) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था का हाल हो रखा है यह हमारे लिये दिन प्रतिदिन चिंता का विषय बनता जा रहा है क्योंकि अपराधी खुल्लेआम जघन्य से जघन्य अपराधों को बेखौफ अंजाम देते जा रहे हैं जैसे अभी मलिक साहब ने बताया कि केन्द्र सरकार की अपनी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा नागरिक सुरक्षा के मामले में 100 में से 33 अंक के साथ अंतिम पायदान पर है। अपराधियों के लिए हरियाणा प्रदेश सबसे सुरक्षित प्रदेश बनता जा रहा है। यह हमारे लिये बहुत ही चिंता की बात है। हाल ही में हरियाणा प्रदेश के लौहारू भिवानी में दो अल्पसंख्यक मुस्लिम युवकों को गाड़ी की बैल्ट से बांधकर जिंदा जलाकर मारने की घटना सामने आई है। यह घटना न केवल हमारे लिये शर्मसार करनी वाली है बल्कि हरियाणा प्रदेश की पूरी दुनिया में जो छवि बनी हुई है उसको भी खराब करने का काम करती है। इसमें जो आरोपित बताये जा रहे हैं वे अपने आपको गौ–रक्षक तथाकथित या अन्य उनसे संबंधित बताये जा रहे हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अपराधिक किस्म का है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की सरकार उनका कहीं न कहीं संरक्षण और बचाव करती है। भिवानी में घटित घटना जघन्य है और इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और इन्हीं घटनाओं के चलते तावडू में एक युवक की जान चली गई थी। हमारे नूंह में रवा, शेखपुर और रवाली आदि गांवों में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, कुछ घटनाओं में मुकदमें दर्ज हो चुके हैं और कुछ घटनाओं में अभी तक मुकद्मों की दरख्वास्त भी नहीं लग पाई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं को आज हरियाणा प्रदेश में असुरक्षित महसुस कर रहे हैं और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाये रखने की जिम्मेवारी सरकार की होती है ताकि लोगों का कानून में विश्वास कायम रह सके। मेरे कहने का मतलब यही है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सर्वोपरि होती है लेकिन

ऐसा नहीं हो रहा है और इस कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। हरियाणा के अन्य जगहों पर भी अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी घटनाएं कुछ सालों से ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं जिस पर हमें कार्रवाई संतोषजनक मालूम नहीं लगती है। इस ताजा घटनाक्रम से प्रदेश सरकार अपना दामन छुड़ाने का प्रयास कर रही है। इसमें पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाये गये हैं और उनकी कार्यशैली पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह भी लगाये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश अपने भाईचारे और सद्भाव के लिए हमेशा जाना जाता है लेकिन आज हरियाणा प्रदेश की धरती पर नफरत के बीज बोये जा रहे हैं और प्रदेश का माहौल बद से बदतर हो रहा है। इसमें हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए और उसकी प्राथमिकता भी होनी चाहिए। हमें इसमें लगता है कि सरकार कहीं न कहीं विफल हो रही है और इन चीजों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015 में हरियाणा में अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया था और उसको वर्ष 2015 में ही भंग कर दिया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने बहुत दिनों बाद एस.सी. कमीशन तो बना दिया गया है लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि माईनोरिटी कमीशन का गठन किया जाये। जिसके कारण उनकी जो समस्याएं या चिंताएं हैं और जो उनके विकास के लिए परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उन पर काम हो सके। मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि भिवानी में जो घटना घटित हुई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच भी करवाई जाये और इसमें प्रशासन के, पुलिस के जो भी अधिकारी/कर्मचारी इन्वॉल्व हैं या इस पूरी घटना में जिनकी भी लापरवाही हुई है और जिसके कारण इन दोनों युवकों की जान चली गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि समय रहते इन दोनों युवकों को बचाया जा सकता था। इसके साथ ही साथ मैं अपने हल्के की कुछ मांगें रखना चाहूंगा जो हमारी 8 सालों से परियोजनाएं शुरू की गईं थी, चाहे वह

आकेड़ा में यूनानी मैडीकल कॉलेज की बात हो, चाहे वह घासेड़ा में ड्राईविंग ट्रैनिंग स्कूल की बात हो और चाहे वह एन.एच. 254 नूंह से अलवर हाईवे की बात हो। **(घंटी)** उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक शेर बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगाः–

जो पासबान फूलों का वफादार नहीं है,

गुलशन की हिफाजत का हकदार नहीं है।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा (जींद): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल के दौरान बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जीन्द जिला मुख्याल्य 8 नैशनल हाईवेज से जुड़ा हुआ है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जिला मुख्यालय पर ट्रोमा सैन्टर बनाया जाए ताकि कोई दुर्घटना घटे तो कोई जन हानि न हो पाए। उपाध्यक्ष महोदय, जीन्द जिला मुख्यालय 8 नैशनल हाईवेज से जुड़ने के बाद जीन्द शहर के अन्दर भीड़–भाड़ काफी ज्यादा हो गई और इसके कारण ट्रैफिक का लोड काफी ज्यादा बढ़ गया है इसलिए एक रिंग रोड बाहरी तरफ से बनायी जाए जैसे नरवाना रोड से वाया जुलानी–दरियावाला–संगतपुरा–ईक्कस भिवानी रोड से होते हुए रोहतक रोड पर मिलाया जाए और इस वित्त वर्ष 2023–24 में ही जीन्द के रिंग रोड के लिए बजट का प्रावधान रखा जाए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अंत्योदय पर काम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जीन्द के अन्दर श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए ई.एस.आई. हेल्थ डिस्पेंसरी है। यह डिस्पेंसरी 30 बैड के अस्पताल में अपग्रेड होने की सरकार द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने का काम कर रही है। अतः श्रमिकों के उद्धार के लिए आवश्यक है कि ई.एस.आई. हेल्थ डिस्पेंसरी जीन्द को 30 बेड के अस्पताल में अपग्रेड किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, जीन्द में बिशनपुरा से पाण्डु–पिण्डारा तक रेलवे की बाईपास लाईन बनाने का प्रपोजल पिछले बजट में

रखा गया था। मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रोजैक्ट की डी.पी.आर. बड़ौदा हाऊस नॉरदन रेलवे चीफ इंजीनियर ऑफिस में पहुंच चुकी है। अतः उपरोक्त प्रस्तावित परियोजना को सिरे चढ़ाने के लिए उचित माध्यम से सम्पर्क साधते हुए वित्त वर्ष 2023–24 के बजट में परियोजना का बजट अलॉट किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, जीन्द की पुलिस लाईन में हरियाणा पुलिस दूर–संचार विभाग के सभी कोर्स वर्ष 1988 से लेकर वर्ष 2003 तक जीन्द पुलिस लाईन में होते थे जैसे कि पी.डब्ल्यू.ओ. –1, पी.डब्ल्यू.ओ.–2 तथा पी.डब्ल्यू.ओ.–3 आदि लेकिन टेलिकॉम के ट्रैनिंग सैंटर को पहले कुरुक्षेत्र और फिर पंचकुला में बदल दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, ये ऐसा पहली बार और एक विभाग में नहीं हुआ बल्कि लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियन्ता कार्यालय को जीन्द से बदल कर राजनीतिक फायदों के लिए कैथल में शिफ्ट कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी प्रार्थना और अनुरोध है कि इन दोनों को वापस से जीन्द में खोला जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं विशेष तौर पर व्यापारियों के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि प्रदेश में शार्ट सर्किट और अन्य प्राकृतिक कारणों से दुकानदारों को जिस भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है उसके लिए बहुत से दुकानदार किराये पर या लीज पर बैठे होते हैं जो सरकार की योजना के अनुरूप कागजी कार्यवाही को पूरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोई भी विभाग नुकसान की फाइल को स्वीकार नहीं करता है। अतः मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस पॉलिसी का सरलीकरण किया जाए ताकि व्यापारियों को इसका फायदा मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश भर के साथ–साथ जीन्द शहर की सड़कों पर भी बेसहारा पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है जो रात में कोहरे के कारण निरंतर दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं इसलिए मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि सड़कों पर बेसहारा पशुओं पर नियंत्रण किया जाए व जीन्द में बन्दरों का आतंक भीड़ होने के कारण बहुत ज्यादा है इससे भी लोगों को निजात दिलाई जाए। उपाध्यक्ष

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण लगभग 60 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक विभाग ने यह तय नहीं किया कि मेडिकल कॉलेज को नैशनल हाईवे बाईपास से सीधा रास्ता कैसे दिया जाएगा जो भविष्य में मैडिकल कॉलेज को शुरू करने में विलम्ब पैदा करेगा। अतः मेरा सदन के माध्यम से विभाग को अनुरोध है कि बाईपास से सीधा मैडिकल कॉलेज का रास्ता बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट कॉलेज जीन्द में आर्ट ब्लॉक में स्टूंडेट्स की स्ट्रैन्थ ज्यादा होने की वजह से आर्ट ब्लॉक के नए भवन का निर्माण किया जाए मैं आपसे ऐसी भी प्रार्थना और निवेदन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेष बात और कहना चाहूंगा कि गांव और शहर में पानी की जो काली टंकी कांग्रेस कार्यकाल में बांटी गई थी उस समय लोगों को यह नहीं बताया गया था कि आपको इनकी कोई फीस अदायगी करनी पड़ेगी लेकिन आज उनका बिल काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, पानी की टंकी के संबंध में बिल्कुल गलत स्टेटमैंट दे रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः गीता जी, आप बीच में न बोलें माननीय सदस्य को अपनी बात बोलने दीजिए प्लीज आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढाः उपाध्यक्ष महोदय, पूरे हरियाणा में ऐसा हुआ है क्योंकि इन टंकियों का अब ब्याज समेत बिल आ रहा है।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगी कि उस समय मैं पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर थी और ये पानी की टंकियां संबंधित बैनिफिशरिज को बिल्कुल मुफ्त में दी गई थीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः किरण जी, प्लीज आप बैठ जाएं।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढाः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन और प्रार्थना है कि इन बिलों को पूर्ण रूप से माफ किया जाए। धन्यवाद।

श्री लक्ष्मण नापा (रतिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि रविदास जयंती पर उन्होंने जो हमारे जिले में मैडीकल कॉलेज बनना है उसका नाम गुरू रविदास जी के नाम पर रखा और उसमें दो–तीन घोषणाएं की और एक वैंचुअल फण्ड बनाने की घोषणा की। हमारे अनुसूचित जाति के एंटरप्रन्योर को लोन लेने में काफी दिक्कत होती थी। इसके लिए सी.एम. साहब ने घोषणा की उसके लिए भी मैं सी.एम. साहब का धन्यवाद करूंगा। इसी प्रकार से प्रोमोशन में भी आरक्षण की घोषणा की उसके लिए भी मैं सी.एम. साहब का धन्यवाद करूंगा। हमारे रतिया शहर की मांग पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान ली और उन्होंने टोहाना–रतिया रोड के लिए 87 करोड़ रूपये की राशि मंजूर की। इसी में मैं टोहाना रोड से फतेहाबाद रोड तक एक बाई–पास बनाने की मांग करूंगा क्योंकि रतिया में ट्रैफिक का लोड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। इसी प्रकार से मैं मेरे नागपुर ब्लॉक में एक राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने की भी सरकार से मांग करूंगा। इस महिला कॉलेज के लिए वहां की पंचायत ने 10 एकड़ लैंड देने का प्रस्ताव पास कर दिया है ताकि हमारी लड़कियां वहां पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। ऐसे ही रतिया में पिछले तीन–चार वर्ष पहले एक आई.टी.आई. मंजूर हुई है। उसके लिए पांच करोड़ रूपये का फण्ड भी आ गया है लेकिन अभी तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि उसका निर्माण कार्य भी जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाये। अब मैं अपनी घुमंतू जातियों की बात करना चाहूंगा। जो अंत्योदय की योजनाओं की बात होती है हमेशा से उसमें हमारी जो घुमंतू जातियां हैं उनसे वंचित रह जाती हैं। इन घुमंतू जातियों के अभी तक अपने मकान नहीं हैं। उनके पास मकान बनाने के लिए कोई प्लॉट भी नहीं है। मैं

माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि 500 करोड़ रूपये का एक अलग से बजट बनाकर घुमंतू जातियों के लोगों को बसाया जाये। अभी हमारे बहुत से विधायक साथियों ने एक चिंता की कि जो सरपंचों का मामला है उसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाये। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायत मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विचार किया जाये। जो गांव का सरपंच होता है उसका भी एक बहुत बड़ा रूतबा होता है। वह भी जनप्रतिनिधि है और हम भी जनप्रतिनिधि हैं। इस प्रकार से उनका हमारे साथ नाता है। मैं कहना चाहूंगा कि जो ई–टैंडरिंग है वह बहुत अच्छा विषय है लेकिन दो लाख रूपये की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 10 लाख रूपये किया जाये। इसके साथ ही साथ मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि उनके प्रतिनिधियों को भी टेबल पर बुलाकर सौहार्दपूर्ण माहौल में उनके साथ बात करके उनकी समस्याओं को सुना जाये। मैं यह मांग सरकार से विशेष तौर पर करना चाहूंगा। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले यह घोषणा की थी कि जो घुमंतू जातियों के उम्मीदवार हैं उनको नौकरियों में पांच अंक दिये जायें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन हुआ और उसमें यह शब्द लिखा गया कि जो जाति एस.सी. या बी.सी. में नहीं आयेगी उनके उम्मीदवारों को ही पांच अंक मिलेंगे। मेरा यही कहना है कि ऐसी कोई भी जाति घुमंतू जातियों में नहीं है जो एस.सी. या बी.सी. में नहीं है। माननीय हाई कोर्ट ने भी इसकी प्रशंसा की है कि हरियाणा सरकार पहली ऐसी सरकार है जो इन जातियों के लोगों को नौकरियों में पांच अंक देने का काम कर रही है। मेरी सरकार से मांग है कि इस सम्बन्ध में जारी नोटिफिकेशन को ठीक किया जाये। मेरा यह भी कहना है कि जो परिवार पहचान पत्र है उसमें भी काफी त्रुटियां हैं उनको भी दूर किया जाये। हमारा जो डी.एन.टी. समाज है उनकी कोई आईडैंटीफिकेशन नहीं है। इसके लिए कोई अलग से कैम्प लगाकर इन त्रुटियों को

ठीक किया जाये। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डी.एन.टी. के बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने की घोषणा भी की थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी मांग करूंगा कि जो डी.एन.टी. के घुमंतू जातियों के बच्चे हैं इनके लिए अलग से हॉस्टल बनाये जायें ताकि वे अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। सरकार ने जो घुमंतू जाति विकास बोर्ड बनाया है मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करूंगा। इसी को डी.एन.टी. विकास निगम बनाया जाये ताकि जो केन्द्र सरकार से फण्ड मिलता है वह भी उसको मिल सके। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल समाप्त होता है।

———

श्री भव्य बिश्नोई, विधायक द्वारा माननीय सदस्यों को आज दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब भव्य बिश्नोई जी कुछ सूचना देना चाहते हैं।

श्री भव्य बिश्नोईः उपाध्यक्ष महोदय, स्नेह एवं आदरपूर्वक मैंने आज आप सभी के लिए हमारे बिश्नोई समाज के परम्परागत भोजन कढ़ी, चूरमा और हलवा के साथ बहुत ही विस्तृत भोजन की गवर्नर गेट के पास व्यवस्था की है जो कि स्वादिष्ट भी है और पौष्टिक भी है। अतः मेरी आप सभी सदस्यों, प्रेस के साथियों और अधिकारियों से विनम्र प्रार्थना है कि आप इस स्नेहभोज में शामिल होकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद।

———

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

"राज्य में कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाले की जांच के लिए गठित एस.ई.टी. की रिपोर्ट की स्थिति के संबंध में"

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा राज्य में कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाले की जांच के लिए गठित एस.ई.टी. की रिपोर्ट की स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 13 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है।

इसी प्रकार से ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–57 जो कि श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 13 के साथ जोड़ दी गई है।

इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि माननीय गृह मंत्री के दिनांक 21.02.2023 को सदन में उपस्थित न होने के कारण उपरोक्त ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब दे पाना सम्भव नहीं है और अनुरोध किया है कि इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं को सदन की अन्य तिथि की कार्यसूची के लिए सूचीबद्ध करने के लिए विचार किया जाये। इसलिए मैंने इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं को किसी अन्य तिथि की कार्यसूची के लिए तिथिबद्ध करने का निर्णय लिया है जिसकी सूचना माननीय सदस्यों को विधान सभा सचिवालय द्वारा भिजवा दी जायेगी।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना दी थी लेकिन आपने उसका कोई जिक्र नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्षः किरण जी, आपकी ध्यानाकर्षण सूचना आज सुबह ही प्राप्त हुई है इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है।

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो कल शाम को ही मेल के माध्यम से सूचना, हरियाणा विधान सभा सचिवालय को भेज दी थी।

श्री उपाध्यक्षः किरण जी, हमें तो उसकी सूचना आज सुबह ही मिली है।

श्री आफताब अहमदः उपाध्यक्ष महोदय, जिस ध्यानाकर्षण सूचना को आप एडमिट करते हैं उसका तो जवाब नहीं दिया जाता है और हम जो दूसरी ध्यानाकर्षण सूचनाएं देते हैं उनका हमें स्टेटस नहीं बताया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आफताब जी, आज मंत्री जी आ नहीं पाये इसलिए इसको किसी और दिन की कार्यसूची में सूचीबद्ध किया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, यह हर सत्र का ड्रामा हो गया है। ध्यानाकर्षण सूचना को एडमिट कर लिया जाता है और फिर उसका जवाब नहीं दिया जाता है। ध्यानाकर्षण सूचना एडमिट होने के बाद सदस्य का जवाब लेने का अधिकार है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः हुड्डा साहब, आज मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए उसको किसी और तिथि को टेकअप किया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब तो हम जो कहते हैं वह सही है कि this Government is non-performing Government. जब आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब ही नहीं देते हैं तो क्या करेंगे? (शोर एवं व्यवधान)

.....

वाक आउट

श्री आफताब अहमदः उपाध्यक्ष महोदय, न ही तो हमारी ध्यानाकर्षण सूचनाओं का स्टेटस बताया जाता है और न ही एडमिट हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दिया जाता है इसलिए हम सब सदन से वॉक–आउट करते हैं।

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब न दिये जाने और उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को स्वीकार न किए जाने के विरोध में सदन से वॉक–आउट कर गये।)

.....

बैठक का स्थगन

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन दोपहर के भोजन के लिए 1 घंटे के लिए *स्थगित किया जाता है।

***13.23 बजे**

(तत्पश्चात् सभा मध्याहन् पश्चात 14.23 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

.....

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी। श्री असीम गोयल नन्यौला, विधायक अपना धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करवाने से पहले आप हमें हमारे द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और एडजोर्नमैंट मोशन के स्टेटस के बारे में भी बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, सुबह बता देंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमें यह भी बता दीजिए कि अगर कोई अहम मुदा हो तो उस पर हम रिसैस पीरियड के दौरान कालिंग अटैंशन मोशन लगा सकते हैं या नहीं। बिकॉज कॉलिंग अटैंशन मोशन तो अहम मुद्दों पर ही होते हैं तो can we put Calling Attention Motion during recess?

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल लगा सकते हैं।

श्री असीम गोयल नन्योला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय जी का एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

.....

श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक के विरूद्ध विशेषाधिकार के कथित हनन का प्रश्न उठाना

श्री जोगी राम सिहागः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में प्रिविलेज मोशन का नोटिस मूव करना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः क्या कोई विशेष विषय है।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, जोगी राम जी प्रिविलेज मोशन का नोटिस मूव करना चाहते हैं।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, बिना आपकी परमिशन से माननीय सदस्य कैसे प्रिविलेज मोशन मूव कर सकते हैं।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, अगर कोई सदस्य प्रिविलेज मोशन लाना चाहता है तो इसके लिए चेयर की परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। (शोर एवं व्यवधान) कोई प्राइवेट मैम्बर प्रिविलेज मोशन कैसे ला सकता है ?

श्री आफताब अहमदः पार्लियामेंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर को प्रिविलेज मोशन लाना चाहिए।

श्री अध्यक्षः ऐसा किसने कहा कि पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टिर ही प्रिविलेज मोशन ला सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टिर ही प्रिविलेज मोशन ला सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, गीता जी को एक बार रूल पढ़ लेना चाहिए। गीता जी से यह पूछा जाये कि वे प्रिविलेज मोशन चाहती हैं या नहीं चाहती हैं तो बात क्लीयर हो जायेगी।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, सदन में जो कुछ भी हो एज पर रूल होना चाहिए। सदन में प्रिविलेज मोशन पढ़ने के लिए चेयर से परमिशन नहीं ली गई। अध्यक्ष महोदय, क्या आपने प्रिविलेज मोशन को पढ़ने की परमिशन दी है।

श्री अध्यक्षः गीता जी, मैंने प्रिविलेज मोशन को पढ़ने की परमिशन दी है।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, इस तरह से प्रिविलेज मोशन कैसे लाया जा सकता है।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि Privilege can be moved at any time. He can ask his Member. Shri Jogi Ram Sihag is taking permission of the Chair.

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, इस तरह हाउस को मिसलीड नहीं किया जा सकता। (शोर एवं व्यवधान) ऐसे हाउस कैसे चलेगा ?

श्री अध्यक्षः आफताब जी, तो आप ही बताओ कि हाउस कैसे चलेगा ?

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, आपने जोगी राम सिहाग को प्रिविलेज मोशन पढ़ने की परमिशन कब दी ? उन्होंने तो बिना आपकी परमिशन के ही पढ़ना शुरू कर दिया है।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, क्या हाउस इस तरह से चलेगा। हमारी किसी बात को अलाउ नहीं किया जा रहा है और जोगी राम जी को बिना परमिशन के ही प्रिविलेज मोशन पढ़ने की इजाजत दी जा रही है।

Shri Dushyant Chautala: Speaker Sir, how can he say that Shri Jogi Ram is moving the Motion without the permission of the Chair.

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, सदन में अगर प्रिविलेज मोशन पढ़ना है तो आपकी परमिशन से ही तो पढ़ा जा सकता है।

श्री अध्यक्षः गीता जी, मैंने तो परमिशन दी है।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो गई और अभिभाषण पर एक सदस्य ने बोलना भी शुरू कर दिया और अचानक प्रिविलेज मोशन लाया गया और वह भी बिना आपकी परमिशन के, ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्षः गीता जी, कोई बात नहीं अगर चर्चा शुरू हो गई है, बीच में भी किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रिविलेज मोशन आ सकता है।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, वास्तव में आपको भी नहीं पता था कि प्रिविलेज मोशन सदन में लाया जा रहा है। दुष्यंत जी ने पहले अनुप धानक को अपने पास बुलाया और फिर इसके बाद जोगी राम सिहाग को अपने पास बुलाया और पूछ रहे थे कि क्या वे इस कागज को पढ़ सकते हैं और बिना आपकी परमिशन से ही उन्होंने ही जोगी राम सिहाग को प्रिविलेज मोशन पढ़ने के लिए अलाउ कर दिया। अध्यक्ष महोदय, सदन में आपकी परमिशन से ही कुछ पढ़ा जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गीता जी, जोगी राम जी को मैंने परमिट किया है और उसके बाद ही उन्होंने बोलना शुरू किया है।

Shri Jogi Ram Sihag: Speaker Sir, I, Jogi Ram Sihag, Member and Shri Anoop Dhanak, Minister of State for Labour and Employment bring to your kind notice an urgent specific matter, which requires the intervention of the House.

Today, the 21st February, 2023 while speaking during Zero Hour, Shri Abhay Singh Chautala, MLA brought certain wrong and misleading facts regarding the land acquired near/for the purpose of Hissar Airport, etc. The Hon'ble Deputy Chief Minister, subsequently, with the permission of the Hon'ble Speaker, clarified the position there and then. Inspite of this, Shri Abhay Singh Chautala adamant with the aim to assert and brought certain wrong facts misleading the House, by using unparliamentary words too.

The act of the Hon'ble Member is unwarranted, unjust and undignified, particular when the Dy. CM clarified the position immediately in the House. Shri Abhay Singh Chautala, MLA, thus, mislead the House by giving false and wrong facts, knowingly, intentionally and deliberately. He has lowered the prestige, status and

dignity of the House particularly and members specially. The act of the said member, therefore, clearly constitutes Breach of Privilege, that too on the Floor of House. Besides this, the conduct of Shri Abhay Singh Chautala towards other member(s) remained unwarranted and unparliamentary, while he was speaking in the House.

In view of above facts, the Hon'ble Speaker may kindly give his consent to this question of privilege and send this specific matter to the Committee of Privileges for examination, investigation and report.

No proof in support of these averments is required to be annexed as evidence, as this matter pertains to the House itself.

अध्यक्ष जी, प्रिविलेज मोशन पढ़ने के बाद मैं आपसे एक क्वैशचन भी पूछना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, कल जब माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ा जा रहा था तो उसके तुरंत बाद आपने कहा था कि अभिभाषण की प्रति टेबल के उपर आधे घंटे के अंदर पहुंच जायेगी। यह कापी आंधे घंटे के बाद भी हमारी टेबल पर नहीं पहुंची है। इसलिए हम राज्यपाल जी के अभिभाषण को पढ़ नहीं पाये हैं। कृपया करके राज्यपाल अभिभाषण की कापी हमें भिजवा दी जाये।

श्री अध्यक्षः राज्यपाल अभिभाषण की कापी तो पोर्टल पर अवेलेबल है।

श्री जोगी राम सिहागः अध्यक्ष महोदय, पोर्टल पर किसी को निकालना नहीं आता है इसलिए हार्ड कापी का भी प्रावधान होना चाहिए।

श्री अध्यक्षः जोगी राम जी, यह जो प्रिविलेज मोशन मूव किया है, इसकी कॉपी तो मुझे दो।

(इस समय प्रिविलेज मोशन के नोटिस की कॉपी अध्यक्ष महोदय को दी गई।)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रिविलेज मोशन का नोटिस पढ़ा है क्या उसकी पढ़ने की परमीशन ली गई थी?

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मैंने उनको मूव करने के लिये अलाउ किया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय सदस्य को खड़े होने की परमीशन दी थी, नोटिस मूव की परमीशन नहीं दी थी।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, उन्होंने कहा कि मैं प्रिविलेज मोशन लाना चाहता हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड निकलवा लो।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, रिकॉर्ड निकलवा लो। प्रिविलेज मोशन मैंने अलाउ किया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, यदि उन्होंने यह कहा है कि मुझे प्रिविलेज मोशन मूव करने को अलाउ किया जाये, तो ठीक है। रिकॉर्ड निकलवा लो।

Mr. Speaker: I have received a Notice of the question of privilege under Rule 281 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. यह अभी हमें नोटिस मिला है। जो प्रिविलेज मोशन मूव होगा वो Parliamentary Affairs Minister की तरफ से होगा। यह उनकी तरफ से एक नोटिस आया है।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, नोटिस उनके पढ़ने के बाद आया है।

श्री अध्यक्षः मैडम, पढ़ने के बाद ही नोटिस देंगे। (विघ्न) मैंने उनको अलाउ किया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, फिर प्रोसीडिंग निकलवा लो। सब रिकॉर्ड है। अगर उन्होंने पूछा है कि मैं प्रिविलेज मोशन मूव कर रहा हूं और आपने परमीशन दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मुझे पता है कि मैंने अलाउ किया है। यह ठीक है कि माननीय सदस्य श्री असीम गोयल के बाद किया है। मैंने पहले असीम गोयल जी को माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिये बोला था, उसके बाद हुआ।

Shri Bhupinder Singh Hooda: Speaker Sir, then what is the occasion to allow him when once the discussion starts?

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, permit me to read the Rule 280. Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly says-

"280. A member may, with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a Committee thereof.

I also want to read out Rule 281. It is very important. It says-

"A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day the question is proposed to be raised. If the question raised is based on a document, the notice shall be accompanied by the document."

Both rules 280 and 281 are clear. क्वैश्चन ऑफ प्रिविलेज राईटिंग में सैक्रेटरी को देना पड़ेगा और before the commencement of the Sitting देना पड़ेगा। सैक्रेटरी को नोटिस कहां दिया गया है?

Mr. Speaker: Rule 281 says-

"If the question raised is based on a document, the notice shall be accompanied by the document."

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, सैक्रेटरी साहब को कहां नोटिस आया है?

श्री अध्यक्षः बतरा जी, जहां तक डाक्यूमैंट की बात है सदन के अन्दर आदरणीय सदस्य के द्वारा जो कहा गया है उसी को डाक्यूमैंट माना है।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, Rule 281 says-

"A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the

day the question is proposed to be raised." सैक्रेटरी को नोटिस कहां दिया गया है? जिस दिन हाउस की सीटिंग होगी नोटिस उससे पहले देना होगा ।

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य चाहें तो इस बारे में मैं रूल पढ़कर सुना सकता हूं ।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय को अवश्य रूल पढ़कर सुनाना चाहिए । Rules are to be interpreted in the House itself.

Shri Dushyant Chautala: Speaker Sir, Rule 282 says-

"282. The right to raise question of privilege shall be governed by the following conditions :-

(i) not more than one question shall be raised at the same sitting;
(ii) the question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence; and
(iii) the matter requires the intervention of the Assembly."

Mr. Speaker: The words 'specific matter of recent occurrence' are written in the Rule 282 (ii).

Shri Bharat Bhushan Batra: Then what is the relevancy of Rule 281? आप रूल 281 क्यों नहीं पढ़ते ?

Shri Dushyant Chautala: Speaker Sir, Rule 283 (1) says-

"283. (1) The Speaker, if he gives consent under Rule 280 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the question and before the list of business is entered upon, call the member concerned who shall rise in his place and while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto:"

Mr. Speaker: It is written in the Rule 283 (1) that-

> "…who shall rise in his place and while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto"

उन्होंने खड़े होकर स्टेटमैंट दी है ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, गवर्नर एड्रैस की डिस्कशन के बाद बीच में प्रिविलेज मोशन नहीं ला सकते ।

श्री अध्यक्ष : जगबीर सिंह जी, ऐसी कोई बार नहीं है कि Speaker can't admit it in between the Discussion on Governor's Address. ऐसा कोई बार नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रैसीडैंट है । ऐसा कहां लिखा है कि स्पीकर एडमिट नहीं कर सकता ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, आप हमें ऐसा कोई प्रैसीडैंट बता दो ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा कोई प्रैसीडैंट नहीं है तो ऐसा कोई बार भी नहीं है । आप कोई बार बता दीजिए कि इसके बीच में एडमिट नहीं कर सकते ।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, it is written in Rule 281 that-

> 'before the commencement of the sitting on the day the question is proposed to be raised.'

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, नियम 22 (1) के (ख) में लिखा है कि –

> "अभिभाषण पर सभा द्वारा चर्चा आरम्भ किये जाने या जारी रखे जाने से पूर्व ऐसे दिन औपचारिक रूप का अन्य कार्य किया जा सकता है ।"

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, but prior to the discussion starts. रूल में "पूर्व" है "बाद" का नहीं है । डिस्कशन तो स्टार्ट हो गई । आपने नाम दे दिया। You have already started the discussion. यह प्रायर है । अतः आप कहीं तो हमें संतुष्टि दें ।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप क्या चाहते हैं ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी तजुर्बा है, when discussion starts...(interruptions)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, मुझे नोटिस मिला है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपको बेशक नोटिस मिला हो । Tomorrow he should give it to the Secretary before the commencement of the House.

Mr. Speaker: Let me decide this application. Whether it is right or not? Let me decide it.

.....

सदस्य को नामित करना

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात भी सुन लीजिए । मैंने आपको लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाले की जांच से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एक सी.ए. का नोटिस दिया था ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मैंने आपके उस सी.ए. के नोटिस को किसी नेक्स्ट डेट के लिए पोस्टपोंड कर दिया है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात ठीक है लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने मेरे उस सी.ए. के नोटिस को यह कहकर डैफर कर दिया कि जब संबंधित मंत्री आएंगे तब इसको देखेंगे । आज सुबह जब क्वैश्चन आवर चल रहा था तब सदन में हैल्थ मिनिस्टर उपस्थित नहीं थे लेकिन जब हैल्थ डिपार्टमैंट से संबंधित कोई प्रश्न आया तो उसका किसी अन्य मंत्री ने जवाब दिया था । इसी तरह आज सदन में डॉ. कमल गुप्ता जी भी उपस्थित नहीं थे और जब उनके विभाग का प्रश्न आया तो उसका भी किसी अन्य मंत्री ने जवाब दिया था । अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एक सी.ए. नोटिस दिया था ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, हमने यह कब कहा कि उस सी.ए. नोटिस का इशू अहम नहीं है । मेरे पास सरकार की ओर से पत्र आया था कि इस सी.ए. नोटिस को आगे किसी अन्य दिन के लिए पोस्टपोंड कर दिया जाए । रूल्ज के अनुसार मैंने उस सी.ए. नोटिस को आगे के लिए पोस्टपोंड कर दिया है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आगे का क्या भरोसा है कि आप उस सी.ए. नोटिस को स्वीकार करोगे ? आप मुझे बता दें कि मेरे उस सी.ए. नोटिस को किस डेट के लिए स्वीकार करोगे ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर संबंधित मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उनसे संबंधित इशू को स्वीकार ही न किया जाए । अन्य माननीय मंत्री जी भी उसका जवाब दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अगर मेरे पास सरकार की ओर से रिक्वैस्ट आती है तो यह प्रावधान है कि उस मैटर को पोस्टपोंड किया जा सकता है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बता दें कि मेरे उस सी.ए. नोटिस को किस डेट के लिए स्वीकार किया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, हम आपको इसकी डेट बता देंगे ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार पर क्वैश्चन उठा रहा हूं । यह सरकार एक नॉन प्रफॉर्मिंग गवर्नमैंट है, इसीलिए सारा मामला गड़बड़ाया हुआ है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपको इसकी डेट आज ही बताने में क्या दिक्कत है ? आप मुझे इसकी डेट आज ही क्यों नहीं बता देते ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग पर क्वैश्चन नहीं उठा रहा हूं।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आपको आज डेट बताने में क्या दिक्कत है? आप इसके लिए आज ही डेट बता दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सरकार किसी दूसरे मिनिस्टर की ड्यूटी लगाकर जवाब दे सकती है। इसमें जवाब देने में क्या दिक्कत है?

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मैं इसके बारे में बिजनेस देखकर ही बताउंगा। अब माननीय सदस्य श्री असीम गोयल जी अपनी बात रखेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि मामला गड़बड़ है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी रूलिंग क्या है?

श्री अध्यक्षः किरण जी, मैंने अभी इसको पैंडिंग रखा है। इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आप इसके बारे में डेट तो बता दें।

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, यह कौन से दिन के बिजनेस के अन्दर फिट आ सकता है, उसके बारे में देखकर बता दूंगा। अब माननीय सदस्य श्री असीम गोयल जी अपनी बात रखेंगे।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी द्वारा जो भी बिना परमिशन बोला जा रहा है वह not to be recorded anything or anything.

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ****

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, मैं एक जन कवि की वाणी को अपने शब्दों में उद्धृत करते हुए कहना चाहूंगा। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ****

.....

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded. माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी बोल रहे हैं वह nothing is to be recorded.

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। अगर आप यहां पर गलत चीज बोलेंगे तो मैं बखशूंगा नहीं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, मैंने किसी को बचाने का क्या काम किया है? अभय सिंह जी, आप सदन से बाहर चले जाएं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, आप सदन से बाहर चले जाएं। क्या मैं चोर–उच्चकों को बचाने का काम कर रहा हूं? क्या बात करते हो? आप सदन से बाहर चले जाएं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, आप सदन से बाहर चले जाएं। आप सदन में इस प्रकार का बिहेवीयर करेंगे तो सदन के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, आप सदन से बाहर चले जाएं। मैंने आपको नेम कर दिया है। आप सदन से बाहर चले जाएं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आपने दो नाम लिये हैं।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, मैंने अभय सिंह चौटाला को नेम किया है। अभय सिंह चौटाला जी, आप सदन से बाहर चले जाएं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ****

.....

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

श्री अध्यक्षः अभय सिंह जी, आप सदन से बाहर चले जाएं।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्षः मैंने बोल दिया है कि Shri Abhay Singh Chautala, please go out of this Assembly Hall.

(इस समय श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक तर्क–वितर्क करते हुए सदन से स्वयं ही बाहर चले गये।)

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी। विधायक श्री असीम गोयल नन्योला अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री असीम गोयल नन्योला (अंबाला शहर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

> "कि इस सत्र में इक्ट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए माननीय राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 20 फरवरी 2023 को प्रातः 11:00 बजे सदन में देने की कृपा की है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में सरकार से संबंधित योजनाओं और अच्छे कार्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन करके इस महान सदन का जो मार्गदर्शन किया है उसके लिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का आभारी हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम जी की बातों का समर्थन करता हूं।

महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण भारत में अमृत काल और जिस समय भारत को जी–20 की अध्यक्षता करने का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है, उस अवसर के दौरान, हरियाणा विधान सभा के पहले सत्र में पेश किया गया एक ऐतिहासिक

.....

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

दस्तावेज है। मैं महामहिम जी की बातों का समर्थन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक जन कवि की वाणी को अपने शब्दों मे उदृत्त करते हुए कहना चाहूंगा किः–

यह महान सदन मुझसे पूछ रहा क्या बतालाउं,
भाजपा की रीति–निति से निकला एक मामूली जनसेवक हूँ,
सत्य ही कहूंगा क्यों हकलाउं।

(इस समय सदन में मेजें थपथपाई गई।)

अध्यक्ष महोदय, जो मैंने अभी कहा है यह भी एक तरह से सत्य ही है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी को वापिस सदन में बुला लें।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मैं उनको बिल्कुल वापिस नहीं बुलवाउंगा।

श्री असीम गोयल नन्योलाः अध्यक्ष महोदय, सत्य यह है कि हरियाणा प्रदेश में सरकारें तो बहुत आयी, राज और शासन तो बहुत से हुकमरानों ने किया, मगर सुशासन का सुख इस प्रान्त ने अपने जीवनकाल के पिछले 8–9 वर्षों में ही अनुभव किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं ढंके की चोट पर कह रहा हूं कि यह राज्य पहले नजराने, जबराने और शुकराने से चलता रहा है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो रिश्वत लेना, मंथली लेना और जबरदस्ती वसूली करना और सिफारिश लगाना आदि इन तीनों वाक्यों में हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा को तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कश्मीर से कन्या कुमारी तक हरियाणा की राजनीति का उपहास बनाया जाता रहा है। देश के सबसे कर्मठ किसानों और उद्यमियों की इस धरती को इस नजराने, शुकराने और जबराने ने बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसे में जब हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में सरकार बनाई थी तो मुद्दा केवल सरकार बदलने का नहीं था बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा था। अध्यक्ष महोदय, छोटे मोटे टिल्लों

को उखाड़ना बहुत आसान होता है परन्तु एक ऐसे बड़े विशाल पर्वत को हटाने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा की राजनीतिक व्यवस्था की चुनौतियां छोटे मोटे टिल्लों से नहीं अपितू भीमकाय पर्वतों जैसी थी। हम सिर्फ चुनाव दर चुनाव जीतने वाला दल नहीं बनना चाहते थे इसलिए हमारा ध्येय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास की बात की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा एक और हरियाणवी एक की बात की और उस सपने को बहाल करना और उस सपने को बहाल करने के बाद उसको स्थापित करने का हमारे दल का एक संकल्प था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नेताओं की एक संकुचित और निंदित छवि जनमानस के हृदय पटल पर अंकित हो चुकी थी कि नेता केवल चुनावी राजनीति करने के लिए आते हैं। नेता अपना घर भरने के लिए आते हैं।

.....

सदस्य को नामित करना (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : असीम जी, एक मिनट। अभय सिंह चौटाला जी को दो दिन यानी दिनांक 21.02.2023 और 22.02.2023 के लिए नेम किया गया है।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री असीम गोयल नन्योला : अध्यक्ष महोदय, अब तक हरियाणा में राजनीति एक व्यवसाय था फायदा उठाने का यंत्र मात्र था और छोटे–मोटे फायदों के लिए दूरदर्शी योजनाओं को कभी पुरानी सरकारों ने नहीं बनाया। अगर ये लोग दूरदर्शी योजनाएं बना भी लेते थे तो उनको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते थे और केवल कागजों में दिखाने के लिए प्लानिंग कमीशन के सामने एक आइडिया प्रस्तुत कर देते थे। मेरे

कहने का अभिप्राय यही है कि किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने किसी दूरदर्शी योजना को अमलीजामा नहीं पहनाया। अध्यक्ष महोदय, हमने इस व्यवस्था को, इस perception को जड़ से बदलने का न केवल संकल्प लिया बल्कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक ईमानदार कोशिश भी की। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनप्रतिनिधियों को नेता नहीं बल्कि सेवक बनने की एक सलाह दी और उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दल का कोई भी विधायक अपने आपको जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि जनता का एक सेवक समझें। मैं केवल दो बातें और कहना चाहूंगा नेता तो लगाते हैं अगले चुनाव पर घात किन्तु जन सेवक सोचते हैं अगली पीढ़ी और देश हित की बात। इसी नाते हमारी सरकार ने पिछले 8–9 वर्षों के अंदर हरियाणा की दशा और दिशा को बदलने की ऐसी विभिन्न योजनाएं चलाई और आज माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने सरकार की बहुत सी खूबियों का बखान भी किया जो निःसंदेह सत्य है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस संबंध में यह भी कहना है कि डी.पी.टी., ऑटो अपील प्रणाली, परिवार पहचान पत्र, स्वामित्व योजना, मेरा पानी मेरी विरासत, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम, हरियाणा कौशल रोजगार निगम जैसी सैंकड़ों योजनाओं ने पूरे भारतवर्ष के अंदर एक मिसाल प्रस्तुत की है। आज विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि इन योजनाओं का अध्ययन करके अपने राज्यों के अंदर भी इस नाते उन योजनाओं को लागू करना चाहते हैं। इन योजनाओं के पीछे केवल एक विचार ने काम किया और वह विचार था minimum Government maximum governance यानी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा संकल्पित और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हरियाणा में संचालित इस पूरे मॉडल को पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। हमने इस मॉडल की कोई खोज नहीं की लेकिन पूरी ईमानदारी, तत्परता और प्रयत्न से इस मॉडल को अपनाया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता की कुंजी

को हमने सत्ता स्थलों से और अधिकारियों के कमरों से बाहर निकालकर एक आम आदमी के गरीब के गांव और शहर के सेवा केन्द्रों में स्थापित कर दिया। आम आदमी की पहुंच के अन्दर सरकार का बटन दे दिया। सर, ये योजनाएं पहले भी बन सकती थीं, इन योजनाओं को पहले भी लागू किया जा सकता था, लोगों को पहले भी सीधा बैनिफिट दिया जा सकता था। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा मानना था कि भ्रष्टाचार का एक मात्र इलाज(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गीता जी, जब आपको बोलने का समय दिया जाए, आप तब बोलना। आप इनको बोलने दीजिए।

श्री असीम गोयल नन्योलाः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की योजनाएं बता रहा हूं लेकिन जिन साथियों को इन योजनाओं से तकलीफ है, यह बिल्कुल ठीक बात है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि हमने सत्ता स्थलों से सत्ता की चाबी आम आदमी के हाथ में देने का काम किया। जो ये सेवा केन्द्र शहरों और गांवों के अन्दर बने हैं। जब आम आदमी के हाथ में सरकार की चाबी गयी तो तकलीफ होना स्वाभाविक है और वह तकलीफ सामने चमक भी रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा मानना रहा है कि भ्रष्टाचार का एकमात्र इलाज तकनीक के अन्दर छिपा है। हम जितना तकनीक को बढ़ावा देंगे भ्रष्टाचार उतना कम होगा। अध्यक्ष महोदय, हमने तकनीक पर इतना इनवेस्ट किया, इतनी मेहनत की है कि आज बिना पैसे दिए, बिना पर्ची और बिना खर्चे के लोग सीधे नौकरी लग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, साफ–सुथरे टेंडर नीचे के स्तर तक लग रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर जो पिछली सरकारों में एक उद्योग का रूप धारण कर चुका था आज यह बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो रहा है और हमने इस बदनुमा प्रणाली को एक झटके में उखाड़ फेंकने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

तकनीक के प्रति हमारी सरकार का आग्रह, दूरदर्शिता और संकल्प ने सत्ता को चंडीगढ़ की चौखट से निकालकर मोबाइल के कीपैड तक पहुंचाने का काम किया है। ये काम सिर्फ तकनीक से ही संभव नहीं था ये संभव था माननीय मुख्यमंत्री जी की साफ नियत और सही नीति से। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की नीति और नियत दोनों ही शुद्ध थी और जनता के नुमाइंदों को हमारी सरकार का संदेश भी बड़ा स्पष्ट था कि ठीक काम करो, साफ बोलो और बेधड़क जनता के हित की बात करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि हमने सदैव ही इस रीति नीति का पालन किया। अध्यक्ष महोदय, रामचरितमानस के प्रसंग में एक दोहा भी आता है कि–

''सचिव, बेद, गुरु तीनि जौ, प्रिय बोलही भय आस
राज धर्म तन तीनि कर, होई बेगिही नास''

यानी मंत्री, वैद्य और गुरु यदि भय के कारण प्रिय बोलने लग जाएं तो राज्य, धर्म और शरीर तीनों का नाश बहुत जल्दी हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पुराने समय में जो लोलीपोप की एक प्रथा चलती थी उनको देना बंद किया और धरातल पर काम करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं उतारीं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने हर तरह की मत विभिन्नता को ना केवल सुना बल्कि उस पर गौर भी किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देशहित में हमारी सरकार को जो बात ठीक लगी उस पर तुरंत कार्रवाई भी की और जनता के हितों में नियमों को भी बदला। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी आदरणीय सत्य प्रकाश जरावता जी इस सदन में ही हैं, मैं इनके हल्के का उदाहरण लेकर बताना चाहूंगा कि इनकी विधानसभा में कासन ग्राम के हमारे जो किसान भाई हैं, जब उनको जमीन का सही पैसा नहीं मिला यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी गया लेकिन उसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस हद तक जाकर प्रयास किया उसकी मिसाल आपको आज के समय आधुनिक

राजनीति में कहीं नहीं मिलेगी। यह केवल इस नाते संभव हुआ कि जनहित के अन्दर हमारी सरकार चल रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने देशहित में हर पक्ष और विपक्ष की बात को सुना और माना भी। हमने संवाद और विचार विनिमय का एक ऐसा प्लेटफार्म सदन के अन्दर और बाहर भी विकसित किया। अध्यक्ष महोदय, केन्द्र और बहुत से राज्यों में हमने बड़ी बहुमत वाली सरकार चलाई है मगर हमने सदैव संवाद, विचार–विमर्श और आम मत से सरकार चलाई है, धक्के शाही से नहीं। आरदणीय अध्यक्ष महोदय, हमने हर उस व्यक्ति को निर्भयता से अपनी बात कहने के लिए प्रेरित किया जो बात राष्ट्रहित में है। अध्यक्ष महोदय, आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जिन बातों पर चर्चा हुई अगर मैं संक्षेप में उन्हें सीमित करना चाहूं तो उन्हें आधारभूत संरचना, सुशासन का संकल्प, स्वाबलम्बन, निर्भरता और भविष्यवादी राजनीति के मुख्य बिंदुओं में बांटा जा सकता है। सुशासन के संकल्प की मैंने शुरू में ही बात की है और निर्भयता पर चर्चा भी की। हमने एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति विकसित करने की कोशिश की है जिसमें हर व्यक्ति बिना डरे बिना दबे अपनी बात कह सके। निर्भयता लोकतंत्र का एक जरूरी अंग होता है मगर जिस तरह की सरकारें अतीत में चलाई गई हैं उनसे निर्भयता का यह मूल कहीं खो गया था। मगर हमने इसे पुनर्जीवित करने का साहस किया और यही वजह है कि हमारी सरकार ने जनहित की बात को चाहे वह विपक्ष द्वारा भी की गई हो उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया बल्कि विवेक भाव से उस पर विचार किया।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, कल हम सभी ने एक बहुत ही गम्भीर मुद्दे पर अपनी बात सदन में रखने का प्रयास किया लेकिन आपने हमारा माईक ही ऑन नहीं किया। अब हमारे भाई झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। हमें इनको अभी और कितना सुनना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, जब आपको बोलने का समय दिया जायेगा आप उस समय बोल लेना। अभी आप बैठ जायें।

श्री असीम गोयल नन्योला : अध्यक्ष जी, इसमें मैं एक महत्वपूर्ण बात जो मैं रखना चाहता हूं वह आधारभूत संरचना है। आधारभूत संरचना का अर्थ होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेलवे इत्यादि सुविधाओं का विकास। सड़क–रेलवे जैसी व्यवस्थाओं पर तो शायद कुछ भी बोलना नाकाफी होगा। कभी हरियाणा में हाईवे के नाम पर एक दिल्ली–अमृतसर वाला रोड ही होता था और हम सब इसी पर ही इठलाते थे। मगर पिछले 8 वर्षों में हरियाणा में हाईवेज का जाल बिछ चुका है। इस समय हरियाणा में हाईवेज की संख्या दहाई में जा चुकी है। मेरी इस बात से सिर्फ सत्ता पक्ष के ही नहीं बल्कि मेरे विपक्षी दोस्त भी सहमत होंगे कि सड़कों के मामले में पिछले 8 वर्षों के दौरान चमत्कार जैसा ही कुछ हुआ है। इस बात को तो ये इसलिए नहीं झुठला सकते क्योंकि मेरे विपक्षी साथियों की गाड़ियां भी इन्हीं हाईवेज पर चलकर चण्डीगढ़ आती हैं।

श्री कंवर पाल : स्पीकर सर, गीता जी से यह भी पूछ लेना चाहिए कि इनकी सरकार के समय में झज्जर से चण्डीगढ़ आने में कितना समय लगता था और अब कितना समय लगता है?

श्री असीम गोयल नन्योला : अध्यक्ष जी, मैं इनकी मानसिक स्थिति को समझ सकता हूं कि ये हमारी सरकार के इस प्रकार के कामों पर ताली नहीं बजा सकते। केवल कोसना इनका काम है वह इनको करना ही है लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि हाईवेज के नाते केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने कमाल का काम किया है। (विघ्न) अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा क्षेत्र स्वास्थ्य का है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। हमने हरियाणा के हर जिले में एक मैडीकल कॉलेज खोलने का संकल्प लिया था और हम उसे पूरा करने के बहुत करीब हैं। शिक्षा के नाते मैं यह

कहना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण अंग है विकास का पूरे भारत को आगे ले जाने के लिए हरियाणा की महती भूमिका रही है। हम आशा करते हैं कि वह आगे भी रहेगी। सर, शिक्षा के मामले में मैं थोड़ा पीछे की अगर बात ध्यान कराउं पुराने समय में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरे विश्व में अपनी धाक जमा रखी थी। भारत का नाम रोशन कर रखा था। जब बाकी दुनिया को शास्त्रों और बाकी दुनिया का ज्ञान तक न था बेशक बाहर से आये बख्तियार खिलजी जैसे आतताईयों ने नालंदा जैसे शिक्षा के मंदिरों को उजाड़ दिया लेकिन हमारा संकल्प था कि हम उस पुराने वैभव को वापिस जरूर लायेंगे। हमने शिक्षण प्रणाली के साथ संस्कृति के पुराने वैभव को जोड़ने का प्रयास किया।

श्री अध्यक्ष : असीम जी, आप ये जो ज्यादा टाईम ले रहे हैं यह दूसरे मैम्बर्ज के टाईम में से कटेगा। आप जल्दी से जल्दी अपनी बात समाप्त करें।

श्री असीम गोयल नन्योला : अध्यक्ष जी, मैं जल्दी ही सम–अप कर देता हूं। सर, हमने मॉडल संस्कृति स्कूल के नाते नई पीढ़ी को एक बेहतर जीवन देने का प्रयास किया। हमने यह भी सदा प्रयास किया कि हम रोबोट विद्यार्थी नहीं बल्कि संस्कारी नागरिक तैयार करें। मैं अमेरिका के सम्बन्ध एक पुरानी रोचक बात आपको बताना चाहता हूं। अमेरिका के जो पुराने राष्ट्रपति थे बराक ओबामा उन्होंने कहा था कि मुझे भारत की थल सेना, वायु सेना या नौसेना से डर नहीं लगता, अर्थव्यवस्था या जनसंख्या से भी डर नहीं लगता लेकिन मुझे भारत के शिक्षित बच्चों और उनकी कार्यशैली से डर लगता है। सही मायनों में वह डॉक्टर बम, इंजीनियरिंग बम हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को अपने विचार और संस्कार से ओवरकम कर लेंगे। इस प्रकार से भारत के बच्चों का दबदबा पूरी दुनिया में बना रहे और उनका हुनर और रूझान देश की सेवा में भी काम आए इसके लिए हमने शिक्षा को संस्कारों से जोड़ा। शिक्षा ही भविष्य में भारत का, हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा रणनीतिक ऐसेट होने वाला है।

15:00 बजे

सामान्य शिक्षा 100 वर्षों तक एक समाज को आगे बढ़ाती है और संस्कार युक्त शिक्षा 500 वर्षों तक एक समाज के काम आती है। इसी विजन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर अगले प्वायंट की बात करें तो वह है निर्भरता और स्वावलम्बन, जनता का स्वावलम्बन। अब तक ऐसी राजनीति संस्कृति थी कि जनता को मुफ्त सामान बांटो, चुनाव जीतो और उसके बाद भूल जाओ। न अर्थव्यवस्था की समझ, न ही यह देखा गया कि जिसे वास्तव में जरूरत है उस तक कुछ पहुंच भी पा रहा है या नहीं। हमने इस संस्कृति को, इस विद्रुपता को बदलने की ठानी है। जनता का भरण–पोषण सरकार नहीं जनता खुद करेगी क्योंकि जनता मालिक है। हमने जनता का पैसा जनता के हितार्थ खर्च करने के लिए रोजगार मेले लगाए, मुद्रा लोन जैसी योजनाएं लाए, काम करने के लिए प्रेरित किया, उनके लिए व्यवसाय और रोजगार का मूलभूत प्रतियोगी वातावरण तैयार किया। मुफ्त बिजली का लोग क्या करेंगे, जब बिजली आएगी ही नहीं। हमने सुनिश्चित किया कि असली जरूरतमंद नागरिक तक सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचे और सक्षम व्यक्ति को प्रेरित किया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो। सरकार पर उसकी निर्भरता खत्म हो और एक समान समाज की स्थापना हो। अंत में मैं अपनी सरकार की भविष्यवादी राजनीति की बात करना चाहूंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारी सरकारों में बड़े पदों पर विराजमान ज्यादातर सदस्य नेपथ्य से उठ कर यहां तक आए हैं और अपने–अपने परिवारों में राजनीति में आने वाली पहली पीढ़ी हैं और बिल्कुल जमीन से उठ कर यहां सदन में पहुंचे हैं। हमारा विजन बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत को दुनिया का श्रेष्ठतम राष्ट्र और हरियाणा को भारत का श्रेष्ठतम राज्य बनाना है। हमारे लिए राजनीति समाज से जुड़ने का और देश के लिए कुछ कर गुजरने का साधन है। हमारी भारतीय सेना की ही तरह हम भी समाज के राष्ट्र के दुश्मनों से कड़ाई से पेश आएंगे। नशा तस्करों, राष्ट्र विरोधियों, समाज विरोधियों से

बुलडोजर से ही निपटा जाएगा मगर जनता के स्नेह का, विश्वास का हम सदैव पात्र बने रहना चाहेंगे। हम एक ऐसा समाज, ऐसा माहौल छोड़ कर जाना पसंद करेंगे जिस पर आने वाला युग नाज कर सके। हमारी सरकार की हर नीति, हर काम, हर सिद्धांत, हर कदम उसी दिशा की तरफ ही बढ़ाया गया है और भविष्य में भी हमारा यही मकसद, यही चाह है। इसका मैं इस महान् राज्य के महान् सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। अपनी बात को इन दो लाइनों के साथ समाप्त करना चाहूंगा।

"कुछ ऐसा करो के काम दोनों का चलता रहे–2
आंधियां भी चलती रहें और दिया भी जलता रहे।

धन्यवाद।

————————

आर.पी.एस. इंटरनैशनल स्कूल, करनाल के विद्यार्थियों तथा अध्यापकगण का स्वागत

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आर.पी.एस. इंटरनैशनल स्कूल, करनाल के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं।

————————

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा की जाने वाली चर्चा के समय के वितरण के बारे में सूचना।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि दिनांक 21.02.2023 और 22.02.2023 के लिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए कुल समय 6 घंटे यानी 360 मिनट है। भारतीय जनता पार्टी के 29 सदस्य 141 मिनट बोलेंगे और जननायक जनता पार्टी के 7 सदस्य 34

मिनट बोलेंगे। इसी प्रकार से कांग्रेस के 30 सदस्य हैं जो 145 मिनट बोलेंगे तथा इंडियन नैशनल लोकदल के एक सदस्य हैं जो 4.8 मिनट बोलेंगे। हरियाणा लोकहित पार्टी के एक सदस्य 4.8 मिनट बोलेंगे तथा 6 निर्दलीय विधायक 29 मिनट बोलेंगे। इस प्रकार से कुल मिला कर 358 मिनट बनते हैं इसलिए अगर सभी सदस्य बोलते हुए इस समय–सीमा को ध्यान में रखेंगे तो आगे कार्यवाही ठीक चलेगी।

———

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब श्री ईश्वर सिंह, विधायक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इस धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे।

श्री ईश्वर सिंह (गुहला चीका अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की सराहना करता हूं। इस प्रस्ताव के जरिये राज्यपाल महोदय ने हरियाणा को विकासशील ही नहीं बल्कि विकसित राज्य की संज्ञा देने की पूरी कोशिश की है। मैं उनकी नीतियों के बारे में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण का तात्पर्य यही है कि सरकार की पॉलिसी, व्यवस्था उसकी जानकारी, कल्याणकारी योजनाएं आदि जितनी भी संबंधित योजनाएं हैं उनको कैसे लागू करेंगे और उनको किस ढ़ंग से मूव करेंगे। मैं इस बात को कोई डिनाय नहीं कर रहा हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में कितनी योजनाएं बताई जाती हैं और उन योजनाओं पर कितना खर्चा होता है। यह 14वीं हरियाणा विधान सभा के चौथे बजट का राज्यपाल जी का अभिभाषण है। इसके अन्दर चाहे सुशासन हो, चाहे अन्त्योदय हो और चाहे अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग से संबंधित बात हो, चाहे सभी कल्याणकारी योजनाएं हों, कृषि व किसान कल्याण के संबंध में विचार गोष्ठी हो, पशु पालन डेयरी की बात हो, सहकारिता, शिक्षा व रोजगार की

बात हो, मानव संसाधन की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, ग्रामीण विकास की बात हो, शहरी, बिजली, परिवहन की बात हो। इस प्रकार से राज्यपाल के अभिभाषण में हर मुद्दे को टच किया गया है परन्तु इनको लागू करने की प्रक्रिया के संबंध में पहले जमाने के अन्दर एक कहावत थी। उससे हमारे स्पीकर साहब ने भी काफी कुछ समझा भी है और उस बात को कहा भी है। पहले जमाने के अन्दर सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान इन तीन चीजों की जरूरत थी जोकि एक बेसिक व बुनियादी जरूरत मानी जाती थी। वर्ष 1947 के बाद जब आजादी आई तो रोटी, कपड़ा और मकान से आगे जाकर नहरें खुदवाई गई, पुल बनवाए गये। इनके अलावा उस समय बाकी योजना तो नहीं थी। अब तो ये साईबर क्राईम है और साईबर क्राईम में नई पीढ़ी के जमाने की चीज आ गई हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में जो अन्त्योदय व सुशासन का जिक्र किया है यह भी नई पीढ़ी की चीजें हैं और ये सभी चीजें पुराने जमाने की चीजों से हटकर हैं। अब जैसे सुशासन के बारे में कहा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग या दूसरे सभी व्यक्तियों के लिए सुशासन वह है जिसमें पारदर्शिता हो, जिसमें कोई सिफारिश न हो, जिसमें कोई लाग–लपेट न हो, बनावट न हो इसलिए ही लोग सुशासन को ज्यादा पसंद करते हैं। आजकल लोग सुशासन को शासन से ज्यादा तरजीह देते हैं इसलिए ही इसको महत्व दिया गया है और कहा गया है कि हर प्रणाली को सुशासन के रूप में लागू किया जाए अर्थात शासन की बजाए सुशासन को लागू किया जाए। अब अन्त्योदय योजना के हिसाब से जो व्यक्ति पंक्ति के अन्दर आखिर में खड़ा है उसको पंक्ति में पहले नम्बर पर खड़े व्यक्ति की तरह वे सभी चीजें मिलें अर्थात पंक्ति में पहले नम्बर पर खड़े आदमी को जितनी राशि मिली थी उतनी ही राशि आखिरी आदमी तक भी पहुंचनी चाहिए तब तो अन्त्योदय है । उस अन्त्योदय योजना को लागू करने के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है उसको कहने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी की सिफारिश नहीं चलती,

इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस अन्त्योदय के अन्दर वही है जैसे गांधी जी ने कहा था कि –'मेरे सपनों का स्वराज, गरीबों का स्वराज है।' इसके अन्दर राज्य के सभी नागरिकों के प्रति करूणा हो, दया हो, मैत्रीपूर्ण भाव हो, सभी स्कीमों को पूर्ण रूप से लागू करने व देने के लिए सरकार अन्त्योदय के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है तो अन्त्योदय को लागू करने का फायदा है। उसी को हम अन्त्योदय कहेंगे। जैसे मैंने पहले कहा था कि इन सब से हट कर जो ये नई चीजें आई हैं इन्हीं को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी तरह एक मानव संसाधन योजना बनाई गई है। उस योजना के अन्दर हूमन रिसोर्स के अन्दर यह दर्शाया गया है कि कोई आदमी मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, भौतिक तौर से और अध्यात्मिक तौर से परिपूर्ण होगा उसी का विकास होगा। सही मायने में उसी आदमी का मानव संसाधनों का दायित्व बनता है और उसका अर्थ भी तभी निकलता है ताकि मानव का सर्वांगीण विकास हो। यही चीजें माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लाई गई हैं। इसी के साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं जिसमें कई चीजें हैं जैसे पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं और जिस वर्ग को इन योजनाओं से वंचित रखा गया है। उन योजनाओं को लागू करने की योजना तो बनाई है परंतु इसमें यह नहीं दर्शाया गया कि उनको लागू कैसे किया जाए? ये सारी की सारी योजनाएं अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए बनी थी उनमें जैसे 100–100 वर्ग गज के प्लॉट देने की योजना थी वह भी इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दर्शानी चाहिए थी। इसी तरह से आवास योजना थी उसका वर्णन भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कम दर्शाया गया है।(विघ्न) मैं यह मानता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ये योजनाएं दर्शाई गई हैं लेकिन कम दर्शाई गई हैं।(विघ्न) स्पीकर सर, मैं यह कहना चहता हूं कि उन चीजों को इन्होंने दूसरे तरीके से लागू किया है। उसमें

विकास की जो रूचि थी जैसे क्राईम बढ़ता गया उससे एट्रोसिटी एक्ट लागू हो गया और उसको एट्रो सिटी में दर्शाकर उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इस बात की मैं सराहना करता हूं। अब जैसे मर्डर के केस हैं उनकी डिटेल तो विभाग बता ही नहीं सकता है। जैसे रेप का मामला है उसमें पहले सरकार 4 लाख रुपये देती थी अब 8 लाख 25 हजार रुपये देती है। इसमें मेरा कहने का भाव यह है कि इस चीज के बारे में लोगों को विस्तार से कैसे पता लगे। इसी तरह शिक्षा और रोजगार से संबंधित सभी बातें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के जरिये ही बताई जाती हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वर्ष 2047 तक विकासशील देश को विकसित भारत बनाने का टारगेट रखा है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए रोजगार और शिक्षा को जोड़ा गया है। जैसे अब अलग–अलग योजनाओं के हिसाब से चीजें दर्शाई गई हैं। छात्रों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए जो शिक्षा की नीति है उसको निर्धारित करने के लिए कई पहल की गई हैं जो बच्चों को टैबलेट दिये गये हैं वे उसी पर आधारित हैं। इन सारी की सारी योजनाओं का उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया गया है। मैं इसकी तारीफ करता हूं, अनुमोदन करता हूं। स्पीकर सर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गरीब के लिए भी, बेरोजगार के लिए भी, देहात के लिए भी, मजदूर के लिए भी, छोटे दुकानदार के लिए भी जिन–जिन योजनाओं को लागू किया है उन सारी योजनाओं को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दर्शाया गया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अब मैं श्री असीम गोयल द्वारा रखे गये प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

''कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाएः–

'कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 20 फरवरी, 2023 को प्रातः 11:00 बजे सदन में देने की कृपा की है'।''

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, संसदीय प्रणाली के प्रति हम लोगों की जो मान्यताएं हैं, उसके अनुसार राज्यपाल अभिभाषण कैबिनेट एप्रूव करती है और माननीय राज्यपाल महोदय उसको सदन के पटल पर रखते हैं। मेरे हिसाब से माननीय राज्यपाल महोदय को भी अपना अभिभाषण समझ में नहीं आया है। इस अभिभाषण में ऐसी ट्रमिनॉलोजी है, जिसे इस विषय में कोई महारथ हासिल की हुई है केवल वही समझ सकता है। I have gone through it also. इस अभिभाषण में स्तुति, प्रशंसा, महिमामंडम आदि का जिक्र किया गया है। श्री असीम गोयल जी और श्री ईश्वर सिंह जी ने राज्यपाल अभिभाषण की प्रशंसा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रशंसा के साथ–साथ दूसरा पक्ष अर्थात् सरकार की कमियों का भी उल्लेख होना चाहिये। प्रजातंत्र में अच्छाई और बुराई दोनों का जिक्र जरूर होना चाहिये। इसमें यह भी होना चाहिये कि हमारी सरकार की ये–ये कमियां रही हैं और हम इन कमियों को इस हिसाब से दूर करने की कोशिश करेंगे लेकिन ऐसा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार से दूसरा पक्ष का भी इसमें जिक्र होना चाहिये था। यह सरकार का कोई सादा डॉक्यूमैंट नहीं है बल्कि यह विजनरी डॉक्यूमैंट है। आज पूरा हरियाणा इस बात को देख रहा है कि हमारे प्रदेश की दशा क्या है? सरकार हरियाणा प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहती है? सही मायने में इस प्रकार का उल्लेख अभिभाषण में होना चाहिये था। इस अभिभाषण में सरकार के कामों की जो प्रशंसा की गई है, वह धरातल पर कुछ और ही है। सरकार के काम धरातल पर बिल्कुल अलग हैं। यदि हम धरातल पर जायेंगे तो हमें मिलेगा कि समाज का

ताना–बाना टूटा हुआ है। जैसे पहले जमाने में राजा महाराजा अपना भेष बदलकर प्रजा में जाते थे, जिससे उनको धरातल का पता चलता था, इसी प्रकार से यदि सरकार जायेगी तो उसको भी हकीकत का पता चल जायेगा। आज किसान भाई अलग–अलग मुद्दों को लेकर परेशानी में हैं। आज किसान के.एम.पी. पर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर मुआवजे के लिये बैठा हुआ है कि उन्हें 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सदन से अनुरोध है कि एक कमेटी बनाकर उन किसानों को उनका वाजिब मुआवजा दिया जाये। इसके साथ–साथ कर्मचारियों के बहुत से संगठन आज सड़कों पर आंदोलनरत हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी आपके निर्वाचन क्षेत्र पंचकुला में हमारी जानकारी के अनुसार 50–60 हजार की संख्या में कर्मचारी ओ.पी.एस. के संबंध में बड़े ही शांति पूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे थे लेकिन सरकार की दमनकारी नीति के तहत उन बेचारे हजारों की संख्या में कर्मचारियों के ऊपर पुलिस द्वारा बेरहमी से वॉटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया गया। अध्यक्ष महोदय, आज चुनी हुई छोटी सरकार यानी जो सरपंच हैं, वे भी सड़कों पर आंदोलनरत हैं। आज आम आदमी पहचान पत्र के लिए चक्कर काट रहा है । आज आम आदमी कटी हुई बुढ़ापा पैंशन और बी.पी. एल. कार्ड को दोबारा बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा है । आज मजदूर चौराहों पर खाली हाथ खड़ा है। वह दोपहर 2 बजे के बाद काम न मिलने पर अपने घर वापिस चला जाता है। आज छोटा दुकानदार और व्यापारी हाथ पर हाथ धरे बैठा है । प्रदेश का युवा बहुत बुरे तरीके से बेरोजगारी की ओर धकेला जा रहा है । आज युवा नशे की चपेट में है । आज प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है । आज हर जगह रिश्वतखोरी का आलम है और प्रदेश के मंत्री पर यौन शोषण के आरोप हैं । इस यौन शोषण के मामले में महिलाएं, पंचायतें, खापें और अन्य संगठन आंदोलन करते हुए देखे जा सकते हैं । अतः धरातल पर

प्रदेश का हर वर्ग आज दुखी है । इसमें ऐसा लगता है कि when Rome was burning, Nero was playing the flute. अतः प्रदेश में कहीं राजकाज नजर नहीं आता है । स्पीकर सर, सत्ता पक्ष के विधायकों के दरबारों में खुलेआम हंगामे हो रहे हैं । मंत्रियों की गाड़ी को रूकवाकर और उनको गाड़ी से उतारकार उनका घेराव किया जा रहा है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय की रैली में काले झण्डे लहराये जा रहे हैं और विरोधी नारे लग रहे हैं । केवल 3 दिन पहले एम.डी.यू. में क्या हुआ था ? वहां पर इतना बड़ा तमाशा हुआ कि पुलिस के मेल मैम्बर्स ने वहां की लड़कियों को धक्के मारकर बाहर निकाला । आप देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है । स्पीकर सर, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि करोड़ों लोगों से वायदा किया गया था कि हिन्दुस्तान के लोगों आप हमें वोट दे दो, हम आपके खातों में 15–15 लाख रुपये डाल देंगे और 10 करोड़ नौकरियां देंगे । इसमें 20 लाख नौकरियां तो हरियाणा के भी बांटे में आनी थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ । मजदूरों और किसानों के साथ वायदा किया था कि हम वर्ष 2022 तक आपकी आय दोगुनी कर देंगे । अगर मैं फैक्ट्स से अलग बात कर रहा हूं तो आप मुझे बता दें । वायदा किया था कि हम महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को दूर करेंगे । वायदा किया था कि हम अमन और चैन की स्थिति पैदा करेंगे । वायदा किया था कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे । इस बारे में माननीय सदस्य गोयल साहब ने भी बताया है । स्पीकर सर, ऐसा नहीं हुआ । मैं करोड़ों लोगों की तरफ से एक शेर सुनाऊंगा ।

तेरे वादे पर जिये हम, तो मान लेना कि मैं झूठ बोल रहा हूं ।

ऐतबार होता तो खुशी से मर न जाता ।

इसका मतलब है कि अगर मैं तेरे वादे पर जीऊं तो समझ लेना कि मैं झूठ बोल रहा हूं क्योंकि ऐतबार ही नहीं है कि आप सच भी बोलते हो । क्या आपकी कथनी और करनी पर भी कोई विश्वास करेगा ? ऐतबार ही नहीं है कि आप सच भी

बोलते हो क्योंकि अगर ऐतबार होता तो मैं खुशी से मर ही जाता । करोड़ो लोगों की आवाज ये बात बता रही है कि अगर इतने वादे सच साबित हो जाते तो मैं मर जाता । मैं ज्यादा लम्बी–चौड़ी बात नहीं करूंगा । जो गवर्नर ऐड्रैस टेबल हुआ है और जो इवैंट्स चल रहे हैं ये सारी चीजें इसलिए चल रही हैं कि कहीं लोग उन वायदों को याद न दिला दें । अगर सरकार अभिभाषण में कोई कंस्ट्रक्टिव चीज लाती और अगर यह बैलेंस्ड होता तो हम भी झुककर नमस्ते करते लेकिन इसमें काफी गलतियां हैं । इस पर मेरा कहना है कि –

लम्हों ने गलतियां की थी और सदियों ने सजा पाई ।

स्पीकर सर, यह बहुत ही सीरियश मैटर है । हालांकि इसमें वस्तुस्थिति नहीं आई है । गवर्नर ऐड्रैस के पेज नं. 21 पर पैरा नं. 85 है । प्रदेश में पिछले 2 साल तक पंचायतें नहीं रही । हाई कोर्ट में झूठे–सच्चे केस डालकर पंचायतों के चुनाव को टाला गया । इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था । हिन्दुस्तान की डैमोक्रेसी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह से कभी पंचायतों के चुनाव को टाला गया हो । वे चुनाव कोर्ट केस का बहाना लेकर टाले गये थे । अतः जब पंचायतों के 2 साल तक चुनाव नहीं हुए थे तो उस समय गांवों में एक पैसा भी नहीं गया था । सरकार 'सबका साथ सबका विकास' की बात करती है । मेरा कहना है कि प्रदेश की 80 परसैंट आबादी हरियाणा के गांवों में रहती है । उनकी डिवैल्पमैंट के लिए 2 साल तक गांवों में कोई पैसा नहीं गया । सदन में विकास एंव पंचायत मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इनका 70–80 प्रतिशत बजट लैप्स हो गया है। एच.आर.डी.एफ. की तरफ से वहां पर कोई ग्रान्ट नहीं गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये चीजें इसलिए कहना चाहता हूं कि अब पंचायतों के चुनाव हो चुके थे, इसलिए उन पंचायतों को काम करने देना चाहिए था। उनको पिछले बैकलॉग की ग्रान्ट्स का पैसे देने चाहिए थे ताकि गांवों में विकास के

काम होते। लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक किया गया है। सरकार ने इलैक्टिड रिप्रजेंटेटिव्ज पर कानून थोप दिये हैं। ई– टैंडरिंग का कानून थोप दिया है और राईट टू रिकॉल का कानून थोप दिया है। सरपंच गांवों में 2 लाख रुपये से ज्यादा बिना ई–टैंडर के खर्च नहीं कर सकते। स्पीकर सर, गांधी जी का सपना था कि अगर गांव और पंचायतें मजबूत होंगी तो देश भी मजबूत होगा। यह एक बहुत बड़ी फिलोसॉपी की बात है। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी दो बातों के लिए जाने जाते हैं जिसमें लैपटॉप/कम्प्यूटर और पंचायती राज सिस्टम शामिल हैं। उनके टाईम पर एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था। हालांकि वह पास बाद में हुआ था। यह 73 अमैंडमैंट ऑफ दा कांस्टीच्यूशन ऑफ इंडिया सन् 1992 में पास हुआ था। लेकिन पंचायती राज का 73 वां अमैंडमैंट 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ था। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि it marks a defining moment in the history of decentralization of power to the grassroots, with the institutionalization of Panchayati Raj, through the Constitution (73rd Amendment) Act, 1992. स्पीकर सर, यह सारा मामला हुआ और यह 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ था। इस दिन को National Panchayati Raj Day बोलते हैं। यह सैलिब्रेट होता है। इसको भी पकड़ लिया है। स्पीकर सर, इस तरह गांवों की चुनी हुई पंचायतों को रोकेंगे तो किस तरह से काम चलेगा? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि for the time being जो डिवल्पमैंट रूकी हुई थी, वह चालू हो जाए। इससे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। इन पंचायतों के ऊपर जे.ई, बी.डी.पी.ओ., ए. डी.सी. के अलावा दूसरे ऑफिसर्ज भी बैठे हुए हैं तो कहां से भ्रष्टाचार होगा? मेरा कहना है कि एक बार रूके हुए विकास कार्यों को शुरू करवा दें। सरकार ने इसके उल्टा यह किया है कि 12,000–13,000 रुपये की फॉग मशीनें पूरे हरियाणा प्रदेश में 40,000 रुपये में खरीदकर सरपंचों को पकड़ा दी हैं। इसके अतिरिक्त डोंगल से पैमेंट

निकलती है। यह डोंगल 400 रुपये का आता है, लेकिन उसके लिए 2,000 रुपये चार्ज किया गया है। स्पीकर सर, आप देखें यह भी क्रप्शन है। यह सरकार का पोर्टल है। इनके लिए पोर्टल पर डाटा भरना पड़ता है लेकिन वह पोर्टल बन्द रहता है। वह पोर्टल आधे घंटे के लिए खोल दिया जाता है और उस दौरान अपने आदमियों को बता दिया जाता है कि पोर्टल खुल गया है। इसमें आधे घंटे में डाटा भरने के बाद वापिस बन्द कर दिया जाता है। यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। स्पीकर सर, मैं कह रहा हूं कि इसके लिए आप सर्वे करवा लें। मुझे इसके बारे में सरपंचों ने बताया है। स्पीकर सर, इसमें मेरा निवेदन है कि ई–टैंडरिंग और राईट टू रिकॉल का ऑर्डर वापिस लिया जाए। इनको कम से कम 50 लाख रुपये खर्च करने की पॉवर दी जाए। स्पीकर सर, इसके लिए थैंक यू। स्पीकर सर, सरकार द्वारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जाती है कि इसमें प्रदेश कन्ट्रीब्यूट करेगा। चूंकि हमारा प्रदेश कर्जे के नीचे दबा पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश पर 3.19 लाख करोड़ रुपये के करीब कर्जा है। वर्ष 2014 में यह कर्जा 70,000 करोड़ रुपये था और 8 सालों में यह बढकर 3.19 लाख करोड़ रुपये के करीब हो गया है और देनदारियां 1.15 लाख करोड़ रुपये की हैं। इस प्रकार 4.35 लाख करोड़ रुपये पर यह सारा का सारा काम है। यह लापरवाही है क्योंकि इसको देखने के लिए 2 एजेंसीज हैं। एक एजेंसी सी. ए.जी. है। सी.ए.जी. की तीनों रिपोर्ट्स के हर हैड में स्पष्ट कहा गया है कि इनमें कितना– कितना नुकसान हुआ है? इस रिपोर्ट के अुनसार 436 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, cases of GST, VAT and sale for discrepancies involving 524 crores. इसके अतिरिक्त 208 केसिज इन्वॉल्व थे लाईसेंस फी, पैनल्टी में और 715 केसिज स्टॉम्प ड्यूटी के थे। कॉमर्शियल रिपोर्ट में 15,216 करोड़ रुपये pending against the colonizers for development के हैं, इनसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। मैं इस बात पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आपकी कमेटी जो बजट पर

निगरानी रखती है मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं हालांकि वह जैंटलमैन सत्ताधारी पार्टी का है। वह मेरा अजीज है। उसने बहुत ही इंटैलीजैंट्स तरीके से रिपोर्ट दी है। आप उसको यह कहोगे कि यह डेयरिंग रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप कौन सी कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हो?

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात कर रहा हूं। यह कमेटी बजट की निगरानी रखती है।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, इस कमेटी का चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी से ही है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं इस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूं। विभागों में ऑडिटर जनरल ने 1873 ऑब्जैक्शन लगाये हैं और पी.ए.सी. ने 1280 ऑब्जैक्शंज पर कार्रवाई करने की सिफारिश भेजी थी। पी.ए.सी. की 67 परसैंट सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये ऑडिट के ऑब्जैक्शंज हैं। अगर सरकार ऑडिट के, डिपार्टमैंट्स के, सी.ए.जी. के, बोर्ड कारपोरेशंज के, यूनिवर्सिटीज के और को–ऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंज के ऑब्जैक्शंज रिमूव नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? चूंकि संबंधित विभागों के अधिकारी/कर्मचारी रिटायर होकर चले जाते हैं और उसके बाद वे मर जाते हैं और ऑब्जैक्शंज ऐसे के ऐसे ही पैंडिंग पड़े रहते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि लाखों, करोड़ों, अरबों और खरबों रुपये के मामले पैंडिंग पड़े रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप 5 ट्रीलियन के भागीदार कैसे बनोगे इसलिए जितने भी प्रोजैक्ट्स हैं, वे बगैर प्लानिंग और तालमेल के शुरू किये जाते हैं, इसमें न तो अधिकारी गंभीर हैं और न ही मंत्री गंभीर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 9 विभाग हैं और ऑब्जैक्शन 251 लगे और 139 पर एक्शन हुआ। अगर इसकी परसैंटेज देखें तो 55.7 परसैंट बनती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास 6 विभाग हैं और 847 ऑब्जैक्शंज आये और 108 पर एक्शन हुआ लेकिन बाकी ऑब्जैक्शंज पर एक्शन लेने की कोशिश तक नहीं की गई। अगर इसकी परसैंटेज देखें तो सिर्फ 13 परसैंट ही

बनती है। अगर मैं होम मिनिस्टर जी की बात करूं तो उनकी 30 परसैंट बनती है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की बात करूं तो इनकी 38 परसैंट बनती है। इसी तरह से पावर मिनिस्टर की बात करूं तो इनकी 78.9 परसैंट बनती है। इसी तरह से एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात करूं तो इनकी 32 परसैंट बनती है। इसी तरह से पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर की बात करूं तो इनकी 15 परसैंट बनती है। इसी तरह से लोकल बॉडीज मिनिस्टर के पास दो विभाग हैं इनकी 46.29 परसैंट बनती है। इसी तरह से डिवैल्पमैंट एंड पंचायत मिनिस्टर के पास दो विभाग की बात करूं तो इनकी 56 परसैंट बनती है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : कादियान जी, आप जो आंकड़े बता रहे हो क्या यह विभाग की तरफ से दिये गये हैं या मंत्री जी की तरफ से दिये गये हैं?

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमैंट को मंत्री कंट्रोल करते हैं। They are the controller agency. इनके नीचे सिस्टम खड़ा है। It depends upon the will power of the administrator. अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ यह भी बताना चाहूंगा कि 4 स्टेट मिनिस्टर्ज हैं। इनमें 38 ऑब्जैक्शंज आये और एक्शन जीरो परसैंट लिया गया। किसी भी शिकायत का जवाब स्टेट मिनिस्टर के डिपार्टमैंट ने नहीं दिया। इसमें अगर इस तरह की बड़ी–बड़ी नैग्लीजैंसी होती रहेगी तो कैसे बात बनेगी? अध्यक्ष महोदय, इस पर मैं एक शेर पढकर सुनाना चाहता हूं कि बेवफा बा–वफा नहीं होता, वर्ना इतना बुरा नहीं होता, जितना कि यह हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अनइम्पलॉयमैंट के बारे में बात करना चाहूंगा कि आज के दिन अनइम्पलॉयमैंट की हमारे प्रदेश में इतनी गंभीर सिचवेएशन बनी हुई है। ये कह रहे हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा गलत है और कोई कुछ कहता है लेकिन मैंने इसके बारे में अपने गांव से पता किया तो मेरे गांव में 35–36 परसैंट बेरोजगारी है। आपको हर घर से एक या दो लड़के बेरोजगार घुमते हुए मिल

जायेंगे। मैं आपको देश के स्तर पर बेरोजगारी के आंकड़ों के बारे में बताना चाहूंगा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कहती है कि देश में 8 परसैंट बेरोजगारी के आंकड़े हैं लेकिन हरियाणा में 37.4 परसैंट बेरोजगारी के आंकड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे 25 लाख के करीब युवा बेरोजगार हैं । आज के दिन हमारी इतनी स्थिति गंभीर बनी हुई है कि कोई युवा सुसाइड करने के लिए भाग रहा है, कोई नशा करने के लिए भाग रहा है तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचवेएशन की प्रॉब्लम क्रियेट कर रहा है। मैं तो नॉर्दन हरियाणा और सैंट्रल हरियाणा के इन 6–7 जिलों जैसे कैथल, अम्बाला, कुरूक्षेत्र, पानीपत और करनाल आदि की बात करना चाहता हूं। एक दिन अग्निवीर योजना को लेकर demonstration हो रहा था मैंने अशोक अरोड़ा जी से पूछा कि इन जिलों में अग्निवीर योजना को लेकर प्रदर्शन नहीं हुआ तो उन्होंने कहा इन जिलों में लड़के ही नहीं है। मैंने कहा कि लड़के कहां गये तो उन्होंने कहा कि इन जिलों के हर गांवों से 200–200 लड़के लड़कियां बाहर चले गये हैं। अध्यक्ष महोदय, कोई बच्चा आईलेट्स पास करके 30–30 या 50–50 लाख रुपये में अपना किल्ला बेचकर विदेश चले जाते हैं। यहां पर चार पांच जिलों के माननीय सदस्य भी बैठे हुए हैं। अगर मैं गलत बयानबाजी कर रहा हूं तो उठकर मुझे बता देना। मैं इनको रिकॉर्ड समेत जानकारी दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, इन जिलों से लड़के–लड़कियां विदेश जा रहे हैं। ये कनाड़ा में ट्यूरिस्ट वीजा पर जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कनाडा के टौरेंटो में मेरे साले की वाईफ विवेकता सिंह वकील रहती हैं उसने मुझे बताया कि यहां इनकी बहुत दयनीय स्थिति है। ये वहां रूक जाते है, इनके यहां डंडे मारे जाते हैं, कोड़े मारे जाते हैं तथा इनको रिहेबिलेटेशन असाइलम में भेजा जाता है, वहां इनकी बहुत दुर्गती की जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे को एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि अब तो वहां कुंवारी लड़कियों को भी भेज रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तो ये

मैक्सिको से पैदल अमरीका जा रहे हैं और वहां पर हमारे बच्चों को डॉंकी कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमें शर्म आती है कि हमारे बच्चों को अमेरिका में लोग डॉंकी कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह रिकॉर्ड की बात है यहां से एक लाख लड़के–लड़कियां गये हैं। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, क्या यह सरकार की नॉलेज में है ? क्या सरकार इस बात के लिए यहां कोई इंटरप्राइजेज ब्यूरो बनाएगी कि यहां से बच्चे बाहर जाएंगे वहां पर इंटरप्राइजेज ब्यूरो हो इनको एडजेस्ट करे और प्लेसमेंट का तरीका निकाले। ऐसे तो ये प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। इतनी जबर्दस्त बेरोजगारी है। उनके पास से टेलीफोन आ रहे हैं कि हम इतने पैदल चले, हम वहां से डोली कूदकर गए, वहां पर हमें पीटा गया लेकिन फिर भी वे वहां भाग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी शर्म की बात है, ये बेरोजगारी का हाल है। अध्यक्ष महोदय, पेज 6 और पैरा 17 पर यह दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, 25 लाख लोग बेरोजगार बैठे हैं जबकि 7 हजार व्यक्ति लगे होने की बात कही गई है, कोई शर्म आनी चाहिए। इस तरह से बेरोजगारी 6 प्रतिशत से लेकर 37 प्रतिशत तक बढ़ा दी और आप कर्जे पर कर्जा ले रहे हो।(शोर एवं व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, हमने सर्वे करवा रखा है उसमें बेरोजगारी दर प्रदेश में 6 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो बातें कहीं जा रही हैं उनमें कोई सत्यता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमने पंचायतों का सशक्तिकरण किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के हल्के के तीन गांव दुजाना, मातन तथा डीघल के बारे में बताना चाहूंगा माननीय सदस्य अभी हाऊस को बताएं कि यहां पर कितने पैसे चले गए। हमने बिना किसी भेदभाव के डायरेक्ट रूप से पंचायतों को पैसा देना शुरू किया है। एक–एक गांव में पैसा गया है। हमने पंचायतों का सशक्तिकरण करना शुरू किया है, इनकी सरकार के समय पंचायतों का सशक्तीकरण नहीं किया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूं, मेरा रास्ता बम्बई जाने का है जबकि मंत्री जी कलकत्ता जाने का रास्ता बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप एक काम करवा लीजिए सरपंचों से या दूसरी एजेंसीज से हर गांव से सर्वे करवा लें कि कितने बेरोजगार बच्चे प्रदेश में हैं और हर घर में कितने बेरोजगार हैं। इसकी रिपोर्ट तीन दिन में आ जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हर गांव से 150 से 200 व्यक्तियों की बुढ़ापा पेंशन कटी हैं। हर गांव से 150 से 200 व्यक्तियों के जैनुअन कार्ड काटे दिये गये हैं इसमें इन्कम का सॉलिड क्राइटेरिया नहीं अपनाया गया। क्राइटेरिया में बिजली बिल, जमीन आदि जैसे फलाना–डिकना करके लोगों के कार्ड काट दिये गये। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि बेरोजगारी पर सरकार ध्यान दे, नहीं तो प्रदेश बर्बादी की तरफ जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो कानून व्यवस्था खड़ी हो जाएगी क्योंकि कानून व्यवस्था और बेरोजगारी का डायरेक्टली प्रपोर्शन है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में महंगाई भी नम्बर वन पर है। Inflation without legislation बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी नहीं बैठे हैं। डिप्टी चिफ मिनिस्टर जी नहीं बैठे हैं। जब सरकार का एक विजन रखा है उस विजन के बारे में हमारी गलतियां कहां आती हैं, उसको हम इम्प्रूव कैसे करें। प्रजातंत्र में आलोचना भी सुननी चाहिए लेकिन आलोचना सुन नहीं सकते।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, आप जो समय ले रहे हैं वह समय आप अपने बाकी सदस्यों का ले रहे हैं। मेरे पास जो लिस्ट भेजी गई है मैं आपको उसी हिसाब से बोलने के लिए समय दूंगा, फिर आप मेरे को मत कहना कि ये सदस्य बोलने से रह गए।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, महंगाई फूड आर्टिकल की है, इलैक्ट्रिक गैजेट्स की है, टॉयलेट आर्टिकल की है और एग्रीकल्चर की है। मैं आपको 5–10 क्षेत्रों के बारे में बताना चाहूंगा। पहले 3 महीने का मोबाइल चार्ज 49 रूपये में होता

था और अब 700 रूपये में होता था। टी.वी. चैनल्ज का रिचार्ज 100 रूपये था अब 600 रूपये हो गया है। घरेलू गैस सिलेंडर 490 रूपये का था अब यह सिलैंडर 1100 रूपये का हो गया है। वाहन ए.सी. गैस रिफिल पहले 400 रूपये की थी अब 1600 रूपये हो गई है। स्टॉम पेपर फी पहले 10 रूपये थी अब 100 रूपये हो गई है। लाईट ड्राईविंग लाईसैंस पहले 275 रूपये का था अब 900 रूपये हो गया है। घरेलू पानी बिल पहले 50 रूपये था अब 700 रूपये हो गया है। वाहन रजिस्ट्रेशन फीस पहले 1500 रूपये थी अब 15000 रूपये हो गई है। पहले श्मसान घाट का कंस्ट्रक्शन टैक्स जीरो परसैंट था अब वह 18 परसैंट हो गया है। आर्म्ज लाईसैंस की फीस पहले 100 रूपये थी अब 7000 रूपये हो गई है। आर्म्ज लाईसैंस को रिन्यू करवाने के लिए पहले 100 रूपये लगते थे अब 2000 रूपये लगते हैं। अगर दूसरा आर्म्ज जोड़ना होता था तो पहले 100 रूपये लगते थे अब 5000 रूपये लगते हैं। पहले ड्राईविंग लाईसैंस 250 रूपये में बनता था अब 5500 रूपये में बनता है। स्पीकर सर, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि यह inflation without legislation है। ये जनता के ऊपर बड़ा भारी बोझ है। इस महंगाई ने आम घर के बजट को तोड़ दिया है। महंगाई सरकार इसलिए कम नहीं करेगी क्योंकि ऐसा करने से सरकार को जी.एस.टी. से होने वाली आमदन कम हो जायेगी। अगर 150 रूपये की चीज 100 रूपये में मिलेगी तो जी.एस.टी. 100 रूपये पर लगेगा इसलिए सरकार महंगाई कम नहीं करेगी। मेरा तो इतना कहना है कि सरकारें जी.एस.टी. के रूप में जनता के खून को चूस रही है। करप्शन का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सरकार द्वारा करप्शन के मामले में जीरो टॉलरैंस की बात की जाती है। मेरा यह कहना है कि जीरो टॉलरैंस नाम की कोई चीज नहीं है। आप नहर के दफ्तर में, बिजली के दफ्तर में, कंट्री एण्ड टाउन प्लॉनिंग के दफ्तर में, तहसील में और थाने में कहीं पर भी चलें जायें आपका बगैर पैसे कहीं पर भी काम

नहीं होगा। कितना कुछ आपने एच.पी.एस.सी. में देखा। यह तो इतना बड़ा तमाशा पूरे हरियाणा प्रदेश में हो रहा है इससे पूरे देश में हरियाणा प्रदेश का नाम खराब हो रहा है। हरियाणा प्रदेश के बारे में यही कहा जाता था कि हरियाणा दूध, दही का खाना। सरकार ने दूध दही पर भी टैक्स लगा दिया। वहां लोग अटैची लेकर मिल रहे हैं। हरियाणा में जो अब हो रहा है ऐसा हरियाणा में पहले कभी भी नहीं हुआ। अटैचियां जा रही हैं और तीन–तीन करोड़ रूपये की रिश्वतखोरी हो रही है। यह हमारे लिए शर्म की बात है। (विघ्न) मैंने 40 स्कैंडल के बारे में जानकारी मांगी थी लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। जो सरकार के द्वारा किसानों और बी.पी.एल. परिवारों के कार्ड काटे गये हैं सरकार को उसके बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। सरकार एजुकेशन सैक्टर में अटैंडैंस को इंश्योर करे। स्कूलों और कॉलेजिज में सिर्फ 40 परसैंट अटैंडैंस ही है। प्रोफैसर कहते हैं कि स्कूल/कॉलेजों में बच्चे नहीं आते। पेरेंट्स से पूछा जाये तो वे कहते हैं कि बच्चे कोचिंग लेने जा रहे हैं। कोई कोचिंग नहीं बल्कि वास्तव में तो यही होता है कि घर के कमरों में पड़े–पड़े मोबाइल फोन पर उल्टी–सीधी बात देखे जाते हैं। सरकार इस मामले में थोड़ी सख्ती बरते। इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एस.वाई.एल. नहर पर केवल मात्र एक ही लाईन लिख दी गई कि एस.वाई.एल. नहर एक मुद्दा है। यह भी कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। इंदिरा गांधी जी ने नहर खोदने के लिए कस्सी मारी थी। सरकार मोदी जी से एक कस्सी मरवा दे उसके बाद नहर भी खुद जायेगी और उसमें पानी भी आ जायेगा। मैं लॉस्ट में एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो और चाहे मजदूर वर्ग हो इस सरकार से हर वर्ग दुखी है और इस सरकार को बदलने के मूड में है। मैं यह सच्चाई आपको आज बताकर जा रहा हूं। आप याद कर लेना। सरकार के पब्लिक रिलेशंज डिपार्टमैंट द्वारा अखबारों में

और पोस्टरों में लाखों–करोड़ों रूपये की राशि को फूंक दिया गया। अखबारों में मुख्यमंत्री जी का फोटो मोदी जी के साथ आता है। मोदी जी की फोटो के साथ मुख्यमंत्री जी समुंदर पार करना चाहते हैं। मेरा यह कहना है कि इस बार किसी भी सूरत में समुंदर पार नहीं होगा। ये कहते हैं कि सड़कों में गड्ढे थे। राजीव गांधी ने यह कर दिया और नेहरू की पॉलिसी यह थी। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि साहब इंदौरी का एक शेयर है। मैं कहना चाहता हूं –

अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल।
हमारे कत्ल का इल्जाम हमारे ऊपर ही रख दो।

पुरानी सरकार ने यह कर दिया, पुरानी सरकार ने वह कर दिया और हम पुरानी सरकार के गड्ढे भर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जनता में जाओ और जनता की आवाज सुनो क्योंकि यह प्रजातंत्र का मूल मंत्र है। वहां से आपको आवाज आयेगी और आप उस आवाज के हिसाब से काम करना। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री नयन पाल रावत (पृथला): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार रखने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिछले 8 साल में प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने हर क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। चाहे वह सड़क की बात हो या शिक्षा की बात हो हर क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। अध्यक्ष महोदय, फिर भी कहीं न कहीं अमैंडमैंट की गुंजाइश रहती है। ग्राम पंचायतों में ई–टैंडरिंग के मुद्दे पर मेरा भी सरकार से आग्रह है चूंकि सरपंचों के चुनाव दो अढ़ाई साल देरी से हुए हैं इसलिए इसमें कम से कम सरपंचों को 20 लाख रुपये तक की पॉवर प्रदान की जाये। हमारे प्रदेश में लगभग 6500 पंचायतें हैं। योजना, परियोजना तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बहुत से सामाजिक कार्यों में भी सरकार ने

अग्रणी होने का कार्य किया है। आज कुरूक्षेत्र से चल कर गीता जयन्ती समारोह दुनिया के कई हिस्सों में मनाया जा रहा है। योग के क्षेत्र में भी हमने दुनिया के बहुत सारे देशों को अपने साथ जोड़ा है। जहां तक बेटी–बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की बात है तो कल हमारे विपक्ष के सदस्य एक केस के सिलसिले में इस अभियान का सदन में मजाक उड़ा रहे थे। हमारी सरकार ने बेटियों के लिए हर 15 किलोमीटर पर कॉलेज बनाने का काम किया है और अगर बेटियां पढ़ने के लिए दूर जाती हैं तो उनको 250 किलोमीटर तक मुफ्त परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई है। इस प्रकार से बेटियों के लिए हमारी सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। जहां तक बेटियों के खिलाफ होने वाली घटनाओं की बात करूं तो इससे पहले भी बहुत सारे केस हुए हैं। श्री एन.डी. तिवारी जो कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे हैं उन पर भी इस तरह के बहुत सारे आरोप लगे थे तथा उनकी जांच भी हुई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, जो आदमी इस हाउस का सदस्य नहीं है उनका नाम हाउस में नहीं लिया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नयन पाल रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि मेरी बात पूरी होने दी जाये क्योंकि इन्होंने कल हाउस में बहुत शोर मचाया था। मैं बेटी–बचाओ, बेटी–पढ़ाओ पर बोल रहा हूं और हमारे विपक्ष के साथियों ने कल इस नारे का बहुत मजाक उड़ाया है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्ष 2011 से यह अभियान शुरू होने के बाद लिंगानुपात में कितना सुधार हुआ है। बेटी–बचाओ, बेटी–पढ़ाओ अभियान के बाद हरियाणा प्रदेश में लिंगानुपात 833 से सुधर कर 917 हो गया है। मैं विपक्ष के साथियों से यही कहना चाहता हूं कि इनको अपनी बात अपने तरीके से रखनी चाहिए लेकिन अगर प्रदेश सरकार ने बेटियों के लिए कोई अच्छी स्कीम चलाई है तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये इस

केस की आड़ में यहां सदन में नारे लगा कर सरकार बदलना चाहते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, हमारा इस बात पर ऑब्जैक्शन है। वह हमारी झज्जर की बेटी है और जिसको लेकर सभी पंचायतें और खाप पंचायतें एक जुट हो गई हैं। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हम उसका तमाशा बना रहे हैं। इस केस में मंत्री जी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। इसका मतलब तो माननीय सदस्य मंत्री जी को प्रोटक्ट कर रहे हैं जबकि हम सरकार से निष्पक्ष जांच की उम्मीद करते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री नयन पाल रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से कहना चाहता हूं कि इन्होंने बेटी–बचाओ, बेटी–पढ़ाओ के नारे का दुरूपयोग किया है। हर केस की जांच होती है इसलिए इस केस की भी जांच हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गीता जी, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि आपने बेटी–बचाओ, बेटी–पढ़ाओ नारे का मजाक बनाया है। (शोर एवं व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री(श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक ऐसी योजना चलाई जिसका परिणाम सामने नजर आ रहा है। प्रदेश में लिंगानुपात 833 से बढ़कर 917 हो गया है और यह इस बेटी–बचाओ, बेटी–पढ़ाओ अभियान का ही असर है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मुझे तो लिंगानुपात में भी घोटाला नज़र आ रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, क्या यह लोग इस बात के पक्ष में हैं कि बहन–बेटियों को नहीं बचाना चाहिए ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री नयन पाल रावतः अध्यक्ष महोदय, गीता जी को अब बैठ जाना चाहिए। इन लोगों ने सदन में कल बहुत शोर मचा लिया है। अब इनको आराम से बैठ जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गीता जी, नयन पाल रावत जी ने जो कहा है वह शायद आपने सुना नहीं है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ के नारे का कल सदन में मजाक उड़ाने का काम किया है। पहले जो सैक्स रेशो 833 थी वह आज 917 के आंकड़े पर पहुंच गई है। माननीय सदस्य ने यह बात कही है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, सैक्स रेशो के संदर्भ में मुझे भी आब्जैक्शन है। 25 लाख लड़के बेरोजगार हैं और ब्याहे नहीं जा रहे है तो फिर ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि यदि लड़कियों की संख्या ज्यादा है तो फिर ये लड़कियां कहां पर हैं ?

श्री अध्यक्षः इसके ऊपर बहस की जरूरत नहीं है। ये सरकारी आंकड़े हैं इसके उपर सदन में बहस की कोई जरूरत नहीं है।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, कादियान जी को पता होना चाहिए कि यह जो लड़कियां हैं इनको बड़ा होने में टाइम तो लगेगा ही । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, अभी यें बच्चियां 6–7 साल की हैं। नयन पाल रावत जी ने कहा है कि सैक्स रेशो में सुधार हुआ है।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने एक बार भी समर्थन नहीं किया कि बहन बेटियों को बचाना चाहिए। महिलाओं की जो हालत हो रही है, वह किसी से छिपी नहीं है। महिलाओं की स्थिति बद से बद्तर हो गई है। विधायक ने एक बार भी खड़े होकर हमारी बात का समर्थन नहीं किया है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, भाजपा का प्रधान धनखड़ जी भी यह बयान दे रहा है कि बहू बिहार से ले आयेंगे और वहां ब्याह करवा देंगे। इनसे और क्या आशा की जा सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, सैक्स रेशो हमारा मुद्दा ही नहीं था। सरकार की चमचागिरी की भी हद होती है। नारी सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। राज्यपाल अभिभाषण में नारी सामंजस्य के संदर्भ में कितनी ही बातें लिखी गई हैं लेकिन असल में नारियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गीता जी, ऐसे थोड़े ही होता है कि आप कुछ भी बोलना शुरू कर दें। सैक्स रेशो में सुधार हुआ है और आप लोग उस बात का मजाक बना रहे हो। आप लोगों को नारे का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। अगर कहीं पर कोई घटना हुई है तो उसकी निन्दा करनी चाहिए। बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ का जो यह नारा दिया गया था, उस नारे का कितना फायदा हुआ है आप लोगों को उसको असेस करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नयन पाल रावतः अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को बैठ जाना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने कल सदन में बहुत शोर मचा लिया है। आज इन लोगों को सारी बातें सुननी पड़ेंगी। हमारी सरकार जो बेटियों के हक में काम कर रही है, मैं उसके बारे में ही बता रहा हूँ। इन लोगों के शासन काल में ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर महिलाओं के साथ जो अत्याचार करने का काम किया गया था, वह सब जग जाहिर है और पूरा हरियाणा इसके बारे में जानता है। इस तरह की चीजों पर रोकथाम के लिए ही हमारी सरकार द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी लाई गई है। ऑन लाइन ट्रांसफर पालिसी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार द्वारा इसी मकसद से लाई गई है कि किसी महिला को किसी नेता के सामने जाकर यह नहीं कहना पड़े कि उसकी ट्रांसफर कर

दो या उसकी कहीं पर पोस्टिंग कर दो। हमारी सरकार यह काम आन लाइन करती है। इन लोगों को मेरी बातें आराम से सुननी चाहिएं। इन लोगों ने कल सदन में बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ के नारे का बड़ा मजाक उड़ाया है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार संदीप सिंह के हक में है ?

श्री नयन पाल रावतः अध्यक्ष महोदय, मलिक साहब और कादियान जी को तो कांग्रेस वालों ने एक तरह से रिटायर ही कर रखा है और कांग्रेस वाले सदस्य भी इनके बारे में कहते हैं कि ये तो सदन में झूठे आंकडे पेश करते हैं। अतः मेरी इनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इनको बैठ जाना चाहिए। इनके ही लोग कहते हैं कि ये झूठे आंकड़े पेश करते हैं। अभी सैनी साहब हाथ जोड़कर कादियान जी को कह रहे थे कि ये झूठे आंकड़े पेश करते हैं अतः इनको बैठ जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो बात जायज है, मैंने वह जायज बात ही कही है। ये लोग बेटी बचाओ–बेटी पढाओ के नारे वाले बैनर सदन में लाकर बोलते हैं कि जो सरकार निकम्मी है–वह सरकार बदलनी है। इस तरह के नारे बाहर लगाये जाते हैं, सदन के अंदर इस प्रकार के नारे नहीं लगाये जाते हैं और इन लोगों को यह बात भी याद रखनी चाहिए कि इन लोगों के नारे से सरकार नहीं बदलती बल्कि सरकार जनता बदलती है। जनता इन विपक्ष के लोगों के आचारण को बाहर बैठे देख रही है।

श्री अध्यक्षः नयन पाल रावत जी, अब आप बैठिए और अभय सिंह यादव जी को अपनी बात रखने दें।

डा. अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, अभी मैं महामहिम महोदय के अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बड़ी तीखी गरमा गर्मी हो रही है और स्वाभाविक भी है क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने–अपने नजरिये से सरकार के कामों को देखते हैं। नजरिये का फर्क होता है किसी को पानी का गिलास आधा

भरा हुआ नजर आता है तो किसी को आधा खाली नजर आता है। नजरिये की बात है और इसमें बुरा मानने की बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि कुछ गलत बातें, तथ्यात्मक रूप से सदन में पेश नहीं करनी चाहिएं। सरकारों के सामने कुछ सामान्य सी प्रक्रियाएं होती हैं और हर सरकार के शासन में वे सामान्य त्रुटियां आती रहती हैं। इनका प्वायंट आउट होता रहता है और उनको ठीक किया जाता रहता है। बजट का घाटा सब सरकारों के समय रहा है। आडिट के पैरा सब सरकारों में बने हैं। विदेश में जो बच्चे इल्लीगल माइग्रेट करके जाते हैं उनकी संख्या भी हर सरकार में होती है। मैं सदन की सूचना के लिए बता दूं कि 2007 में मैं फ्रांस में गया था तो वहां शिराक रीवर के ब्रिज पर मुझे उस समय कुरूक्षेत्र के तीन बच्चे मिले थे जो कह रहे थे कि वे इल्लीगली यहां पर आये हुए हैं और उनके पास वीजा नहीं हैं। कहने की बात यह है कि यह सब कुछ चलता रहता है और इसमें किसी सरकार का दोष नहीं होता है बल्कि ऐसी चीजें समय की बातें होती हैं। जहां तक बेरोजगारी की बात है, हर सरकार अपने लैवल पर रोजगार देने के लिए प्रयास करती है और इस हिसाब से मैं कम से कम यह कह सकता हूँ कि इस सरकार में रोजगार किसी क्षेत्र या किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं दिया गया बल्कि सबका साथ–सबका विकास की तर्ज पर रोजगार सारे स्टेट में मिला है और हमारे नांगल चौधरी के सुदुर गांवों में भी हर गांव में 10–15 बच्चों को रोजगार मिला है। यह सिर्फ मेहनत से रोजगार मिला है, सिफारिस से नहीं और न ही पोलिटिकल एप्रोचिज से मिला है। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)** उपाध्यक्ष महोदय, कहने का मतलब यह है कि साफ सुथरी रिक्रूटमैंट हो रही हैं। मैं सरकार की एक पॉलिसी की बात कह रहा हूँ जिसको अंत्योदय योजना के नाम से जाना जाता है। अंत्योदय योजना, स्टेट का प्रोफाइल परिवर्तन करने वाली महत्वपूर्ण योजना है। हमारे समाज में शुरू से ही विषमता व्याप्त है और अगर मैं कहूं आदिकाल से यह विषमता

व्याप्त है तो गलत नहीं होगा और समाज में ऐसी चीजें मिलती ही रहती हैं। समाज की अंतिम पंक्ति में गरीब लोग आते हैं। आजादी के 75 साल बाद तथा प्रजातंत्र के लगभग 72 साल के बाद मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि समाज में जो विषमतायें हैं, हमें उनको खत्म करने का काम करना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अंत्योदय योजना की फिलोसफी और मूल दर्शन, इसी दृष्टिकोण पर आधारित है कि गरीब और अमीर का जो भेदभाव है, वह खत्म हो जाये और गरीब आदमी को कम से कम जीवनयापन करने में किसी तरह की कठिनाई न हो और यही कारण है कि सारे स्टेट का समान रूप से विकास हुआ है। आज कोई यह एलीगेशन नहीं लगा सकता कि किसी पार्टीकुलर रीजन को या क्षेत्र को ज्यादा पैसा दिया जाता है और अन्य को कम दिया जाता है या कही प्रोजेक्ट कम आये हैं और कहीं पर ज्यादा आये हैं। वास्तव में पूरे स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिवेल्प करने का काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बनाये जा रहे हैं, वह भी सरकार का एक सुंदर प्रयास है। अब नारनौल से लेकर अम्बाला तक जो बड़ा ही सुंदर राजमार्ग बनाया गया है, इससे नारनौल से चंडीगढ महज चार घंटे में पहुंच जाते हैं और राव दान सिंह जी भी इस राजमार्ग से आये होंगे और इनको भी यह बात मालूम होगी कि आज नारनौल से चंडीगढ़ महज चार घंटे में पहुंच जाते हैं तो ऐसी चीजों की मैं समझता हूँ कि प्रशंसा करनी ही चाहिए। आलोचना करना विपक्ष का काम है लेकिन विपक्ष को सकारात्मक आलोचना करनी चाहिए। झूठी बातें कहकर आलोचना नहीं करनी चाहिए। अब मैं इसके साथ ही दो तीन बातें अपने हल्के के बारे में भी कहना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अब दोबारा से सदन में आ गए हैं और मुझे यह बात उनकी उपस्थिति में ही कहनी थी। हमारे यहां महेन्द्रगढ में पाला पड़ने की वजह से सरसों की फसल का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे यहां तीन दिन तक टैम्प्रेचर माईनस में चला गया था और ऐसी भी स्थिति आई थी कि कुछ दिनों तक

माइनस एक–दो डिग्री तक भी टैम्प्रेचर पहुंच गया था। मैं सदन में इन सब बातों को दिखाने वाली खबरों से युक्त कुछ अखबार लेकर आया हूँ जिनमें साफ देखा जा सकता है कि खड़ी फसल में जमींदार ट्रैक्टर चला रहे हैं क्योंकि फसल में दाना ही नहीं बचा है और सौ प्रतिशत फसल बर्बाद हो गई है। सारे अखबारों में यह रिपोर्ट है। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि गिरदावरी होने लग रही है लेकिन जिला

16:00 बजे

प्रशासन में डिप्टी कमीशनर अभी तक इस संशय में है कि खराबे की रिकार्डिंग कैसी करनी है और कैसे सरकार को खराबे की रिपोर्ट भेजनी है या नहीं भेजनी है। इसके संदर्भ में सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश नहीं गए हैं तो मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी आज या कल उनके पास इस संदर्भ में स्पष्ट आदेश भिजवाने का काम करें ताकि जो खराबा हुआ है उसका सही असेसमैंट किया जा सके क्योंकि जो सामान्य गिरदावरी होती है उसमें सिर्फ फसल का आंकलन होता है कि फलां किल्ले या फलां खसरा नम्बर में कौन सी फसल है और कितनी फसल का नुकसान हुआ है। अतः खराबे की रिकार्डिंग के लिए थोड़ा सा स्पष्ट आदेश जारी करने की जरूरत पड़ेगी। मेरा दूसरा विषय यह है कि पहले भी हमारे यहां कपास की फसल पर एक दो बार व्हाइट फ्लाई का अटैक हो चुका है। वहां पर सारे इलाकों में इस संदर्भ में जो सर्वे हुआ, उसकी चिट्ठी भी मेरे पास अवेलेबल है। सरकार के सर्वे के बाद में चिट्ठी जारी की गई कि फतेहाबाद, भिवानी, सिरसा, चरखी दादरी, महेन्द्रगढ, जींद और हिसार जिलों में कीट के हमले की सर्वे हुई और डी.सी. महेन्द्रगढ ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें बताया गया है कि नुकसान 50 परसेंट से भी कम है। इसलिए वहां मुआवजा नहीं दिया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पूरी की पूरी फसल खराब हो गई थी। वहां के संबंधित कर्मचारी काम नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने रिपोर्ट आगे नहीं भेजी। मुआवजा देना पड़ता है, ए.पी.आर. तैयार करनी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है, इसलिए वे ऐसे कामों को करने के लिये अवॉइड

करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उनको बता दिया जाये कि इस विषय पर वे गंभीर होकर काम करें। हमारे यहां पर मैडिकल कॉलेज की बिल्डिंग लगभग तैयार हो गई है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस बिल्डिंग में उपकरण व फर्निचर आदि के लिये प्रिक्योरमैंट करने की व्यवस्था जल्दी से जल्दी शुरू की जाये ताकि अगले 6 महीने में उस मैडिकल कॉलेज में सुविधा प्रारंभ हो सके। एक ई.एस.आई. की तरफ से नर्सिंग कॉलेज, मैडिकल कॉलेज कोरिया के साथ खोला जाये जिसका पिछले बजट सत्र में भी जिक्र किया गया था, उसके बारे में भी सरकार के स्तर पर या ई.एस.आई. के स्तर पर जो भी कार्यवाही हो उसको जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं। सरकार ने बहुत ही अच्छी नीतियां का माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा किये गये कार्यों का उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से सदन में पेश किया जाए, यह हर प्रजातंत्र सरकार की प्रणाली रही है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से यह बताया जाता है कि सरकार ने कौन–कौन सी योजनाओं के तहत कार्य किये हैं और आगे भविष्य में कौन–कौन से कार्य करने जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की महान जनता ने बड़ी आशा और अपेक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी के हाथों सत्ता सौंपी थी कि वे कांग्रेस पार्टी द्वारा किये गये चहुँमुखी विकास को आगे बढ़ायेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे दिन लेकर आयेगी,

इस आशा में हरियाणा के लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि हमारे कब अच्छे दिन आयेंगे और हम कब विकसित देश और प्रदेश की श्रेणी में शामिल होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के माध्यम से मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, यह समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी सच्चाई को छुपा नहीं सकता है। आज की डेट में हर वह आशा जो हर मतदाता ने उस समय सोची थी, उसको आज निराशा में बदल दिया गया है। रोजगार के लिये हमारे युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया गया है। महँगाई एक वजन के रूप में हमारे सिर के ऊपर बैठ गई है। आज हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। प्रदेश का विकास सिमटता चला जा रहा है। फिर भी सरकार माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से कहती है कि 5G सेवाओं का शुभारंभ करेंगे, डिजिटल प्रदेश बनायेंगे और सुशासन से प्रदेश चलायेंगे। अब तो आजादी के 75वें वर्ष में हमारे महान राष्ट्र के 'अमृत काल' की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि फाइव ट्रिलियन इकनॉमी लेकर आयेंगे और देश और प्रदेश को विकसित करेंगे। असली बात तो यह है कि भूखे को रोटी और प्यासे को पानी की जरूरत रहती है। किसी की भी बिना रोटी के भूख नहीं मिटती और बिना पानी के प्यास नहीं बुझती। उपाध्यक्ष महोदय, सुशासन के विषय पर मेरे से पहले भारतीय जनता पार्टी के बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा था। उपाध्यक्ष महोदय, 'परिवार पहचान पत्र' आज 'परेशानी पहचान पत्र' हो गया है। इस स्कीम के तहत लाखों लोगों का पेंशन का काम रूक गया है। इस स्कीम के तहत ही कितने ही लाखों लाखों को जो बी.पी.एल. के माध्यम से सरकार से बेनिफिट लेते थे, उससे वे वंचित हो गये हैं। उसके बाद सरकार कहती है कि हमने स्वामित्व देकर बहुत बड़ा कार्य किया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक्स का वाई और वाई का जैड के नाम से स्वामित्व दे दिया और संबंधित व्यक्तियों को परेशानी में डाल दिया गया है। इस प्रकार से प्रदेश का कोई भला होने वाला नहीं है। 'मेरा पानी–मेरी

विरासत' की जो योजना है उसके बारे में मेरा कहना है कि जब हरियाणा में पानी ही नहीं है तो विरासत किस चीज की। हरियाणा में एक काम कौशल रोजगार के नाम से चल रहा है, जो आज भुलेखे का एक और हथियार बन गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि हमने प्रदेश में 1 लाख 6 हजार लोगों को कौशल रोजगार के माध्यम से रोजगार दिया है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदय, इस पोर्टल के माध्यम से लगभग 6 हजार युवाओं को रोजगार देने के लिये पत्र दिये गये हैं और उनमें से लगभग 4 हजार युवाओं ने ज्वाईन किया है। उपाध्यक्ष महोदय, 1 लाख 6 हजार लोगों की संख्या तो वह है जो पहले से ठेकेदारों के माध्यम से आउटसोर्सिंग पॉलिसी के माध्यम से लगे हुए थे, उस संख्या को कोट किया है। उनको आज नौकरियां दी गई हैं, ऐसा नहीं है।

राव दान सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, आज भी उनका भविष्य अंधकार में है। यदि कल को कोई भी स्थाई तौर पर कर्मचारी लगेंगे तो उनको उनकी सेवाओं से वंचित कर दिया जायेगा। यह किस प्रकार की सिक्योरिटी है ? इससे उस व्यक्ति के मन में यह विश्वास कैसे पैदा होगा कि मैं आज जिस रोजगार पर हूं, वह कल रहेगा या नहीं । सरकार ने केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि केन्द्र में भी आर्मी के साथ ऐसा ही काम किया है । मैं समझता हूं कि जब सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा जाता है तो शायद ही ऐसा कोई मौका हो जब हमारे क्षेत्र के सिपाही का नाम उसमें न आता हो । उसमें भी सरकार ने 4 साल के लिए अग्निवीर योजना चला दी । आर्मी में लगे हुए लड़कों के रिश्तों के लिए जब लोग गांव में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप पक्की फौज में हो या कच्ची फौज में हो । इस योजना से सरकार ने फौज पर भी एक क्वैश्चन मार्क कर दिया है । 'सबका साथ सबका विकास' में अब 'सबका प्रयास' भी जोड़ दिया गया है । इसमें मैं कहना चाहूंगा कि यह 'कुछ का साथ, अपना विकास

व जनता से विश्वासघात' है । सरकार ने 'हरियाणा एक हरियाणवी एक' को छोड़कर समाज को जाति, सम्प्रदाय और क्षेत्र में बांटने का काम किया है । उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता सब जानती है। मैं कहना चाहूंगा कि –

दीवारें भी सुन लेती हैं चीखें मेरी,
बस कुछ अपने हैं जो बहरे बन बैठे हैं ।
उनके देखने से तो आ जाती है मुंह पर रौनक
वे समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है ।
नौ वर्ष यही भूल करते रहे हम,
धूल चेहरे पर थी और आइना साफ करते रहे हम ।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने सदन में जो प्रस्ताव पेश किया है उसमें बहुत सारी बातें हैं । कुछ बातें तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐडमिट की हैं कि परिवार पहचान पत्र में कुछ गलतियां हुई हैं । उन्होंने कहा है कि कुछ को हमने ठीक कर लिया है और कुछ गलतियां अभी शेष हैं । (घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब, आपका समय पूरा हो गया है, इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइये ।

राव दान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा–सा समय और लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : दान सिंह जी, अगर आपकी पार्टी के अन्य सदस्य आपकी पार्टी को मिले हुए समय से ज्यादा नहीं बोलेंगे तो मुझे आपको ज्यादा देर तक बुलवाने में कोई दिक्कत नहीं है । आपकी पार्टी के अन्य सदस्य फिर मुझे यह बात न कहें कि उन्हें बोलने के लिए समय नहीं दिया गया ।

राव दान सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि 'पहला सुख निरोगी काया' अर्थात् जब शरीर ठीक होता है और शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती तो सब चीजें अच्छी लगती हैं । हमारा महेन्द्रगढ़ जिला ज्वायंट पंजाब के समय 6 जिलों में 1

जिला होता था आज उसकी दशा ठीक नहीं है । माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह जी अब सदन से चले गये हैं । वे कहते हैं कि हमने मैडिकल कॉलेज बना दिया है और अब हम उसके इक्यूपमैंट के लिए मांग कर रहे हैं । हमारे क्षेत्र को कांग्रेस के राज में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के समय पर एक सैंटर्ल यूनिवर्सिटी दी गई थी। उसमें एक मैडिकल कॉलेज प्रस्तावित था । हमारे पास जमीन उपलब्ध है । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे केन्द्र सरकार से उस व्यवस्था को बहाल कराने का प्रयास करें ताकि वहां के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएं । हमारे महेन्द्रगढ़ के हॉस्पिटल की हालत ऐसी है कि वह सिर्फ एक रैफरल हॉस्पिटल बनकर रह गया है । वहां पर जब भी कोई पेशैंट आता है तो सिवाय उसको वहां से रैफर करने के कोई दूसरी सुविधा नहीं दी जाती है । वहां पर सुपरस्पैशलिटी हॉस्पिटल नहीं है । बहुत दिनों से एक बात चली हुई है कि मनेठी में एम्स बनेगा । माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 8 साल से इसकी घोषणा की हुई है । इसका जिक्र हुआ था कि उसके लिए 210 एकड़ भूमि दे दी गई है लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक वह कार्य सम्पन्न नहीं हुआ है । मैं चाहूंगा कि सरकार की 'कथनी और करनी' में अंतर न हो । सरकार ने जो कार्य कहे हैं वे सभी कार्य पूरे होने चाहिएं । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मिड्डा जी ने कहा कि जीन्द को 8 नैशनल हाइवेज से जोड़ा हुआ है । यह बहुत अच्छी बात है लेकिन हमने ऐसी क्या गलती की है ? हमारे तो नैशनल हाइवे 148बी को डिनोटिफाई करके स्टेट हाइवे 17 बना दिया है । इस बारे में हमने सदन में 7 बार इसकी मांग की थी और अब जाकर सरकार ने इस पर कार्य शुरू किया है। (विघ्न) हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं । सरकार ने नैशनल हाइवे 152डी बनाकर एक अच्छा कार्य किया है । मैं इसको मानता हूं लेकिन जो काम नहीं हुए हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे । कहा गया कि पिछली सरकार के समय कोई काम नहीं हुआ और कोई नैशनल हाइवे उस

समय नहीं बना । जब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस समय एन.एच. 71 बनाया गया था, दिल्ली–हिसार हाइवे उनके समय पर बनाया गया था । ऐसा नहीं है कि हमारे समय पर कोई काम नहीं हुआ था । अगर आप अच्छे काम करेगे तो हम उसकी सराहना करेंगे और अगर सरकार बगैर अच्छे काम किये सिर्फ वाहवाही लूटना चाहेगी तो वह बात नहीं चल पाएगी । सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हैं । माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें बता दें कि उन्होंने मैट्रो रेल का कहीं एक पिल्लर भी लगवाया हो । आर.आर.टी.एस. की बात रिकॉर्ड पर है । यह प्रोजैक्ट कितने सालों से चला हुआ है । जब वर्ष 2014 में केन्द्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी यह प्रोजैक्ट तब से चला हुआ है । लेकिन आज तक उसको स्थापित करके ट्रेन चलाने का कोई काम नहीं किया गया है। मैं इन बातों को अनेकों बार कह चुका हूं। सदन में हमारे माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद जी बैठे हुए हैं। जब चुनाव आता है तो मेवात के अन्दर हर राजनीतिक आदमी आता है और वहां पर ट्रेन की सिटी बजवाने का वायदा करके चला जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि मेवात में आज तक ट्रेन की सिटी नहीं बजी है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के हालात आज दक्षिणी हरियाणा के हो रखे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हरिजन की, गरीब की और बैकवर्ड की व्यवस्थाएं ठीक करने की बात आती है तो उसके लिए हमारी पार्टी की सरकार के समय में 100 गज जमीन दी जाती थी।

श्री उपाध्यक्षः दान सिंह जी, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

राव दान सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने उनको 100 गज जमीन देना बन्द कर दिया है।

श्री उपाध्यक्षः दान सिंह जी, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री रणधीर सिंह गोलन जी अपनी बात रखेंगे।

राव दान सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरी कुछ बातें रखनी रह गयी हैं।

श्री उपाध्यक्षः दान सिंह जी, आपकी पार्टी के दूसरे माननीय सदस्यों ने लिखकर दिया हुआ है कि उनके हिस्से का टाईम उनको चाहिए। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

डॉ0 कृष्ण लाल मिद्डाः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर अपनी बात कही है। मैं कहना चाहूंगा कि पहले यह वक्त भी था कि जब जींद सिर्फ रैली का गढ बनकर रह गया था। आज मेरे एरिया में कार्य हो रहे हैं तो सामने वालों को तकलीफ हो रही है। यह बात बिल्कुल गलत है। विपक्ष के माननीय सदस्यों को उस समय को भी याद रखना चाहिए जिस समय जींद के अन्दर कुछ नहीं था। विपक्ष के माननीय सदस्यों को कुछ न कुछ दिया जा रहा है, उसके लिए खुशी महसूस करनी चाहिए।

श्री आफताब अहमदः उपाध्यक्ष महोदय, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

राव दान सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको एक बात कहना चाहूंगा कि आसमां इतनी बुलंदियों पर इतराता है, भूल जाता है कि जमींन से ही नजर आता है।

श्री उपाध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण, बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री रणधीर सिंह गोलन जी अपनी बात रखेंगे।

श्री रणधीर सिंह गोलन (पुण्डरी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। राज्यपाल के अभिभाषण में जी–20 की अध्यक्षता करने का अवसर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को मिला है। यह हमारे लिए और हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि आज हम जी–20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस जी–20 का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हरियाणा प्रदेश को भी

करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। पिछले 2 वर्षों के अन्दर कोविड–19 काल में जहां पूरा देश ग्रस्त था और उसी कड़ी मे ंहम भी ग्रस्त हुए। हमारे बहुत से साथी कोविड–19 वायरस की चपेट में आये थे। लेकिन हमारी केन्द्र सरकार ने वैक्सीन बनाने का बहुत बड़ा प्रयास किया और पूरे देश में वैक्सीन लगाने का काम किया है। यह भी हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिससे देश और प्रदेशवासियों को अपनी जान बचाने का मौका मिला। इस दौरान हमनें एक बुरा समय देखा है। उस दौरान हमारे बहुत से साथी बिछड़ भी गये। लेकिन जिस प्रकार का कार्य सरकार ने किया, वह बहुत ही सराहनीय कार्य है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो बुढापा पैंशन थी उसको ऑनलाईन कर दिया है। इसके लिए पहले कोई विधायकों के पीछे फिरता था और कोई सरपंचों के पीछे फिरता था। आज सरकार ने ओल्ड एज पैंशन को ऑनलाईन करके बहुत अच्छी शुरूआत की है जोकि बुजुर्गों के लिए काफी सराहनीय कार्य है।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि माननीय सदस्य के एरिया के बुजुर्गों की पैंशन बना दी और हमारे एरिया के बुजुर्गों की पैंशन काट दी है।

श्री रणधीर सिंह गोलनः उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी ने बात कही है। इसमें कुछ खामियां भी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र 63–64 साल के लगभग हो चुकी है, लेकिन उनका ऑनलाईन रिकार्ड नहीं मिलता है। इस काम को सुप्रिया दहिया जी देखती हैं और मैं उनसे मिला भी हूं। मैंने इस बारे में उनको कहा भी है और उन्होंने उनको ठीक करने का प्रयास भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास है कि ऑनलाईन पैंशन बने, लेकिन अधिकारियों का भी यह कर्तव्य बनता है कि उसको ठीक तरह से लागू करें ताकि ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास पूरा हो। यह बात भी मैं

सदन में रखना चाहता हूं कि जो खामियां हैं वे दूर हों, लेकिन बहन जी जो इसकी उपलब्धियां हैं, हमें उनका भी गुणगान करना चाहिए। इसी प्रकार से जन स्वास्थ्य विभाग के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाग्राम योजना चालू की थी जिससे शहरों की तर्ज पर गांवों में भी सीवरेज सिस्टम लागू हो और यह एक ऐसी योजना है जिसका गांवों के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा। मेरे क्षेत्र के गांव पाई, कोल, फतेहपुर, फरल और ढांड में इस योजना को लागू करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिसके कारण लोगों को सहूलियत मिलेगी। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना जो एक गरीब आदमी के लिए बहुत बढिया योजना बनाई है। केन्द्र सरकार ने शहरों के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.50 लाख रुपये की छूट देने का काम किया है और हरियाणा सरकार ने भी पंचायतों के अंदर आवास योजना के तहत यह योजना लागू करने का काम किया है। इस योजना से गरीब आदमी का भला होगा। **(घंटी)** उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जो परिवार गरीबी रेखा के तहत अपना जीवन यापन कर रहे थे उनके लिए हमारी सरकार ने जिनकी सालाना आय 1.20 लाख रुपये थी उसको बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.80 लाख रुपये करने का काम किया है। पंचायत और विभाग द्वारा जो योजना लागू की गई है जैसे ई–लाईब्रेरी, जिम, महिला सांस्कृतिक क्षेत्र खोलना और खेत खलिहान योजना के तहत रास्ते बनाने का काम भी पंचायत द्वारा किया गया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में पंचायत को लेकर भी अपनी बात रखना चाहूंगा कि गांव के सरपंच हमारे घरों के आगे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई ऐसा विधायक नहीं होगा जिसके घर के सामने मुर्दाबाद के नारे न लगाये गये हों। इसमें मेरा यही कहना है कि सरकार को बैठकर कोई सहानुभूति पूर्वक इस मामले का निपटारा करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि

नारेबाजी करने से कोई हल होने वाला नहीं है। हमें आपस में मिल बैठकर सरपंचों की बातों को सुनना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : गोलन जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए आप प्लीज बैठ जायें।

श्री रणधीर सिंह गोलन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के से संबंधित दो तीन बातें कहना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे हल्के में कोल गांव है, हमारे पास 65 एकड़ जमीन है और वहां पर क्वार्टर भी बने हुए हैं और इसमें लाईब्रेरी भी बनी हुई है। माननीय मंत्री जी जय प्रकाश जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कोल में भी जो राइस रिसर्च सैंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर बनी हुई है उसी तर्ज पर हमारे यहां पर भी एक यूनिवर्सिटी बनवा दी जाये ताकि उत्तरी हरियाणा के लोगों का भला हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : गोलन जी, अपनी स्पीच लिखित में दे दीजिए ताकि उसको प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया जा सके।

श्री रणधीर सिंह गोलन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। गवर्नमैंट मैडीकल कॉलेज के लिए पिछले बजट सत्र में भी घोषणा की गई थी। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर गवर्नमैंट मैडीकल कॉलेज बनाने का काम किया जाये क्योंकि मेरा हल्का सबसे पुराना विधान सभा क्षेत्र है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी मांग करता हूं कि वहां पर एक सब–डिवीजन भी बनाने का काम किया जाये। आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री सीताराम यादव (अटेली): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा विश्वास है कि ''सबका साथ सबका विकास

सबका विश्वास और सबका प्रयास'', ''हरियाणा एक हरियाणवी एक'' के नारे को लेकर'' कम शासन अधिक अभिशासन'' को लेकर चल रही, हमारी सरकार इस टर्म में चौथा बजट पेश करेगी। यह बजट प्रदेशवासियों के लिए नई सौगात लेकर आयेगा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कोरोना महामारी जैसे हालात में भी बुरे दौर में प्रदेश के विकास के पहिये को रूकने नहीं दिया यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी सरकार द्वारा कृषि उद्योग, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में शुरू की गई गवर्नेंस सेवा को न सिर्फ केन्द्र सरकार बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी सराहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। जिसमें गरीब व कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इसके अलावा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए बेहतरीन काम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार खासकर कृषि सुधार एवं किसानों के उत्थान के लिए एम.एस.पी. की गारंटी को लेकर प्राकृतिक आपदा से फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा देने के साथ–साथ ''मेरी फसल मेरा ब्यौरा'', ''हरियाणा भावांतर भरपाई योजना'', ''मेरा पानी मेरी विरासत योजना'', फसल बीमा योजना'' और ''हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना'' जैसी किसान हितैषी बहुत–सी योजनाएं शुरू करके यह कदम उठाकर के हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले और राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को उचित मान सम्मान देने का काम किया है। इसके अलावा हमारी सरकार ने युवाओं को प्राईवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने के बेहतरीन काम किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में चारों तरफ चहुमुखी विकास हो रहा है

इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की कुछ मांग आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखना चाहूंगा कि दौंगड़ा अहीर गांव में दिनांक 16.02.2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक प्रगति रैली का आयोजन किया गया था जिसमें दौंगड़ा अहीर के लोगों ने दौंगड़ा अहीर में उप तहसील बनाने की मांग की थी तब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दौंगड़ा अहीर के लोगों को आश्वासन दिया था कि दौंगड़ा अहीर को उप तहसील बनाएंगे इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि दौंगड़ा अहीर गांव को उप तहसील बनाने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, दौंगड़ा अहीर में 6 एकड़ जमीन पर चारदीवारी लगाकर स्टेज वगैरह बना रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस 6 एकड़ जमीन जिसमें चारदीवारी लगा रखी है वहां पर स्टेडियम स्थापित किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी अटेली विधान सभा क्षेत्र में 9 गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 10 हजार के आसपास है। ये गांव सेहलंग, बाघोत, खेड़ी, धनौदा, पाथेड़ा, भोजावास, दौंगड़ा अहीर, कांटी व मिर्जापुर बाछोद हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन गांवों में एस.टी.पी. लगाकर के इन गांवों को सीवरेज सिस्टम से जोड़ा जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इन गांवों में गन्दे पानी की निकासी का उचित प्रबंध नहीं है इसलिए मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन गांवों में सीवरेज सिस्टम लगाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से डॉ. अभय सिंह यादव जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और मैं भी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि रैगुलर गिरदावरी दिनांक 05 फरवरी से शुरू हो रखी है उसमें फसल के नुकसान का आंकड़ा मेरे हिसाब से ठीक नहीं हो रहा इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उस नुकसान का सही आंकलन किया जाए और जो

फसल का नुकसान हुआ है (घंटी) उसका सही ढंग से सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी अटेली विधान सभा के तोबड़ा गांव के लोग रेलवे अण्डर पास बनवाने के लिए कई दिनों से धरना देकर बैठे हैं क्योंकि वहां गांव के दूसरी तरफ श्मशान घाट है इसलिए मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अंडर पास बनवाने के लिए भारत सरकार को लैटर लिखें जिससे इस अंडर पास को बनाया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, गांव दुबलाना और बाघोत के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 152 डी है, गांव दुबलाना में भी और बाघोत के पास भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे भारत सरकार को लैटर लिखें कि गांव बाघोत और दुबलाना में कट लगवाया जाए जिससे यहां के 10–15 गांवों के लोगों को आने जाने की सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

श्री जयवीर सिंह (खरखौदा)(अ.जा.) : डिप्टी स्पीकर सर, गवर्नर एड्रैस पर सभी साथियों ने बातें की। इसमें सबसे पहले जिक्र आता है अमृतकाल का। अमृतकाल का मतलब होता है कि सभी सुखी हों। पीछे एक काल कोरोना काल के नाम का भी आया था। उसमें किस तरह की देश व प्रदेश में अव्यवस्था हुई यह बात किसी से छिपी नहीं है। चलो वह तो एक बिमारी थी। उससे जैसे कैसे निपट लिया गया। प्रदेश के लोगों की सरकार से एक उम्मीद होती है। अमृतकाल का नाम तो दिया गया लेकिन हमने तो देखा कि प्रदेश में हम जिस तरह से लोगों के बीच में जाते हैं और भारत जोड़ो यात्रा के तहत हमें किसान भी मिले, मजदूर भी मिले, गरीब आदमी भी मिले। प्रदेश में इस तरह की चीजें हैं उनके लिए न तो कहीं यह दिखाया गया कि किसान की जो सरकार कह रही थी कि वर्ष 2022 में किसान की आमदनी दोगुणी हो जायेगी उसके ऊपर कोई फोक्स नहीं कि किस तरह हो जायेगी। एस.सी. समाज के बारे में कोई ऐसी बात नहीं। हमारे युवा जो बेरोजगार हैं उनके बारे में सबने

चर्चा की उनके लिए स्थायी रोजगार की कोई बात नहीं की गई। मैं बात करना चाहूं जैसे अमृतकाल की बात की जा रही थी। डिप्टी स्पीकर सर, वर्ष 2014 में राज्य में भी और केन्द्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये अमृतकाल की बात कर रहे हैं। जब गरीबी रेखा के नीचे 40 करोड़ हिन्दुस्तानी थे जो आज बढ़कर 80 करोड़ हो गये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह संख्या दोगुणी कैसे हो गई? इसके बारे में भी सरकार को बताना चाहिए कि 8 साल में 40 करोड़ गरीब कैसे बढ़ गए। क्या मीडियम आदमी गरीब हुआ है? खुद प्रधानमंत्री जी भी इस तरह की बात करते हैं कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देता हूं। इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाये। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं उनकी संख्या को कम किया जाना चाहिए न कि बढ़ाया जाना चाहिए। अभिभाषण के प्वायंट नम्बर 97 पर के.एम.पी. के साथ जो रेलवे लाईन की बात हुई है। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि डिप्टी सी.एम. साहब ने भी दो–तीन दिन पहले इस बारे में जिक्र किया था। मैंने इस बारे में क्वैश्चन भी लगाया था। मेरा यही कहना है कि के.एम.पी. को आज तक कोई दर्जा नहीं दिया गया है कि के.एम.पी. नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है। आज वहां पर किसान धरने पर बैठे हैं। उनको यही नहीं पता कि उनको नेशनल का मुआवजा मिलेगा या स्टेट का। डिप्टी सी.एम. साहब ने दो तीन दिन पहले ब्यान दिया था कि उस रोड को स्टेट का दर्जा दिया जायेगा। अगर स्टेट का दर्जा होगा तो इसका मतलब तो यही हो गया कि उसका मुआवजा भी स्टेट रोड के हिसाब से मिलेगा। उसके ऊपर जो पलवल से कुण्डली तक तो नेशनल हाईवे का टोल लिया जाता है। फैसिलिटी के बारे में तो नेशनल हाईवे की बात की जाती है फिर स्टेट का दर्जा क्यों? इसके विपरीत के.जी.पी. को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया है। ये चीजें हैं। मुझे तो यह लगता है कि इसमें सरकार यह सोच रही होगी कि मुआवजा कहीं नेशनल हाईवे का न दिया जाये। मेरा यह कहना है कि इस बात को स्पष्ट

किया जाना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास की बात भी हुई है। राजीव जी ने यह फैसला लिया था क्योंकि उन्होंने देखा कि केन्द्र सरकार का जो पैसा है वह गांव के विकास के लिए नहीं पहुंच पाता इसलिए राजीव जी ने ग्रामीण पंचायत की स्कीम लागू की थी ताकि पंचायतों तक सही पैसा पहुंचे लेकिन आज हालत बहुत खराब है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथी श्री जयवीर सिंह जी ने एक प्वायंट उठाया था मैं उस बारे में क्लैरीफाई करना चाहता हूं। के.एम.पी. के साथ में ऑर्बिटल रेल कोरिडोर बनाया जा रहा है। इनका कहना ठीक है कि के.एम. पी. को न तो नैशनल हाईवे का दर्जा दिया हुआ है और न ही स्टेट हाईवे का दर्जा दिया गया है। वहां पर किसान इसीलिए धरने पर बैठे हुए हैं कि अगर उसको नैशनल हाईवे का दर्जा हो तो कलैक्टर रेट का दोगुना कम्पनसेशन मिलता है और अगर स्टेट हाईवे का दर्जा हो तो कलैक्टर रेट का डेढ गुना कम्पनसेशन मिलता है। इसके विपरीत उस एरिया में जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं उनमें कलैक्टर रेट की डबल स्टैम्प ड्यूटी ली जा रही है। इस प्रकार से यह डबल फेस काम चल रहा है। जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं वे तो डबल रेट लिया जा रहा है और कम्पनसेशन देने में न तो उसको नैशनल हाईवे काउंट किया जा रहा है और न ही स्टेट हाईवे काउंट किया जा रहा है इसलिए सरकार को इस बारे में क्लैरिफाई करना चाहिए।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा (जीन्द): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महामहिम का भाषण किसी भी प्रदेश की सरकार का विजन और रोडमैप होता है कि प्रदेश सरकार द्वारा क्या–क्या कल्याणकारी नीतियां प्रदेश में लागू की गई हैं। ठीक उसी प्रकार 8 वर्ष में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी भाजपा सरकार ने सुशासन के जरिये "हरियाणा–एक–हरियाणवी–एक"

सबका–साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास की नीति पर काम करते हुए "जीरो–टोलरेंस" पर काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की सुशासन नीति कि "शासन कम–सुशासन अधिकतम" की मार्फत जनता को डी.बी.टी. सुविधा, आटो अपील प्रणाली, परिवार पहचान पत्र योजना, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ई–खरीद प्रणाली, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की प्रदेश का हर गरीब, मजदूर, किसान, कमेरा युवा और व्यापारी खुले मन से सराहना कर रहा है और कह रहा है कि–

काम के काबिल है जो, उसको काम मिला है,
नाम के काबिल है जो उनको नाम मिला है।
हर एक दिल में, बस अब आप ही बसे हैं,
कहती जनता, हमें यह मुख्यमंत्री बड़ा खास मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह गरीबों की सरकार है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी की गरीब हितैषी सोच के अनुरूप हमारी सरकार अंत्योदय पर काम कर रही है। पूर्व की सरकारों में गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता फिरता था लेकिन इस सरकार में सरकार, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से गरीब व्यक्ति को ढूंढ रही है ताकि उन गरीब लोगों को सहूलियत दी जा सके। गरीब व्यक्ति को सभी मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय मिले इसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गरीब व्यक्ति को फ्री और बेहतर चिकित्सा प्रदान करने के लिए "चिरायु हरियाणा" योजना लागू करते हुए सच्चे गरीब हितैषी होने का प्रमाण दिया है जिसके तहत 29 लाख परिवारों को 46 लाख 70 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड प्रदान किए हैं। वहीं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना के तहत 31 लाख 60 हजार परिवारों को मुफ्त अनाज प्रदान करने का काम किया है क्योंकि हमने जो वायदे जनता से किए उनको पूरा किया है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि–

हम जो लेकर चले थे, उसूलों को निभाया है,

लोगों की सोई हुई उम्मीदों को जगाया है।
बातों से ही किसी का पेट नहीं भरता,
हमने प्यासे को पानी, भूखे को भोजन भी कराया है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की महात्मा गांधी जी की उस सोच के अनुरूप कि भारत गांवों में बसता है, ग्राम स्तर की मूलभूत संरचना को मजबूत करने के लिए "ग्राम दर्शन पोर्टल" के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकास की मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए जहां सुगम रास्ता प्रदान किया है वहीं नगर दर्शन पोर्टल के माध्यम से शहरी विकास को गति प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कानून व्यवस्था का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। बड़े गौरव की बात है कि प्रदेश पुलिस को 14 फरवरी, 2023 को माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, श्री अमित शाह जी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया है, वहीं हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के लिए देश में प्रथम स्थान मिलना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से अपराधी अब थर–थर कांपते हैं। डायल 112 के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि–

डर नहीं सुरक्षा का अब नाम है वर्दी,
हर जगह मौजूद सुबह शाम है वर्दी,
हर दीन दुःखी को सम्भालेगी अब तो,
एक फोन कॉल बस बाकी सब काम है वर्दी।

अंत में मैं अपनी कुछ मांगें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जीन्द विधान सभा क्षेत्र के गांव अहिरका कैरखेड़ी, झांझ कलां, झांझ खुर्द का पेयजल परियोजना हेतु एक कलस्टर बनाया जाए। गांव मनोहरपुर के जलघर का विस्तार करते हुए गांव लोहचब, बरसान का कलस्टर बनाया जाए। खोखरी माईनर की पुनर्स्थापना की जाए। इसी के साथ जीन्द में सीवरेज व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए सुपर शकर मशीन व जैटिंग

मशीन उपलब्ध करवाई जाए। वहीं पर एक नये 7 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का और निर्माण करवाया जाए। इसी के साथ मां जयन्ती देवी मन्दिर के सामने बागवानी विभाग की जमीन पर कॉम्यूनिटी सैंटर और लगभग 1500–2000 की कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम बनाया जाए जोकि जीन्द शहर में नहीं है। इसके साथ ही जीन्द विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मार्किटिंग बोर्ड की सड़कें जलालपुर कलां से संगतपुरा, मनोहरपुर से बरसाना, इटलखुर्द से संगतपुरा, निर्जन से माण्डो, मनोहपुर से बोहतवाला, माण्डो से खोखरी, जीतागढ़ से शाहपुर तक की सड़कों का पुनर्स्थापना की जाए। इसी के साथ जीन्द शहर में प्रस्तावित ऑटो मार्केट का निर्माण किया जाए जोकि माननीय हुड्डा साहब की सरकार के समय में इन्होंने बनाने के लिए कहा था लेकिन उसके बाद इनकी सरकार का समय पूरा हो गया था। अतः मेरा निवेदन है कि मेरी इस मांग को पूरा किया जाए। जीन्द ट्रक बोडी मेकर का उत्तर भारत का सबसे बड़ा हब बन चुका है इसलिए यहां एक ऑटो मार्किट का निर्माण किया जाए। इसके साथ ही बिशनपुर से पिण्डारा रेलवे बाईपास के निर्माण के लिए बजट की घोषणा की जाए। जीन्द–सफीदों सड़क का विस्तारीकरण किया जाए। तितरम–हांसी वाया जीन्द सड़क के विस्तारीकरण के लिए वित्त वर्ष 2023–24 में बजट अलॉट किया जाए। इसके साथ ही चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जीन्द में स्थाई नियुक्तियां की जाएं। इसके साथ जीन्द–जाजवान वाया रेलवे जंक्शन–जुलानी–दरियावाला–ढ़ांढ़ा खेड़ी सड़क को बनाया जाए। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि सरपंचों पर भी दरियादिली दिखाते हुए उनके साथ टेबल पर बैठकर कोई उचित फैसला लिया जाए। इसके साथ ही हरियाणा में लगभग 750 रोगी हिमोफिलिया की बिमारी से ग्रसित हैं जोकि लाईलाज बिमारी है। इसकी दवाईयां लगातार पूरा–पूरा महीना चलती रहती हैं इसलिए इसकी दवाईयां टूटने ना पाए इसलिए प्रयुक्त मात्रा में इनकी दवाईयों की खरीददारी की जाए ताकि दवाईयों की

वजह से किसी भी व्यक्ति को कोई हानि न पहुंचे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है जिसमें गांव रायचन्दवाला–दालमवाला–खूंगा–बोहतवाला को उचाना उप–मण्डल से जोड़ दिया गया है जो भौगोलिक स्तर पर बिल्कुल सही नहीं है। जीन्द मुख्यालय इन गांवों से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं उचाना 25 से 30 किलोमीटर पड़ता है। अतः मेरी मांग है कि जीन्द विधान सभा क्षेत्र के गांव रायचन्दवाला–दालमवाला–खूंगा–बोहतवाला को जीन्द उप–मण्डल से जोड़ा जाए। इन गांवों की विधान सभा–जीन्द, ब्लॉक–अलेवा और उप–मण्डल–उचाना लगता है इसलिए वहां की जनता को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा आप से निवेदन है कि जब अपोजिशन पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं तो मंत्री मंडल के कितने आदमी बैठे हुए हैं। मंत्री मंडल राज्यपाल के अभिभाषण को सीरियस नहीं ले रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मलिक साहब, अभी भी सदन में 6 मंत्री बैठे हुए हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री मंडल राज्यपाल के अभिभाषण को सीरियस नहीं ले रहा है, वह एक अलग बात है लेकिन मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री जी भी नहीं बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अमृत काल नहीं है। यह गरीबों का काल है। सरकार जो स्कीम्ज ला रही है, वे स्कीम्ज गरीबों का काल ला रही हैं। जो राज्यपाल का अभिभाषण है इसमें कोई विजन नहीं है। सरकार यह समझती है कि हरियाणा के लोगों की यादाश्त बहुत थोड़ी है। अब वे बातें कहां गई जब सरकार हरियाणा में मैट्रो लाने की बात करती थी, के.एम.पी. के साथ पांच शहर बनाने की बात करती थी, शहरों से आवारा पशुओं से मुक्त करने की बात करती

थी। खेलों में क्लास–1 और क्लास–2 की भर्ती की बात करती थी। पांच ग्राम प्राधिकरण की बात करती थी। पिंजौर में सेब की मंडी, कुडली में मसाला मंडी, गुरूग्राम में फूल मंडी बनाने की बात करती थी। अब वे बातें कहां गई?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पिंजौर में मंडी बन चुकी है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी मंडी बनने की बात कर रहे हैं उन्होंने तो गरीब किसानों की फसलों के मुआवजे भी नहीं दिये। सरकार किसानों के मुआवजे को भी खा गई। गौमाता के नाम पर आज इतना धोखा हो रहा है जोकि आपको पता ही नही कि आज कितनी गायें मर रही हैं। मैं गायों के चारे की बात करूं तो 900 गायों के चारे की जगह 2800 गायों की हाजिरी दिखाकर गायों का चारा भी खा गये। एक गैस्ट टीचर्स को पक्का करने की बात थी, सफाई कर्मचारियों की बात थी, दादूपुर नलवी नहर, एस.वाई.एल. नहर, बुटाना नहर आदि इन सारी बातों के वायदे सरकार ने वर्ष 2014 में किये थे लेकिन इन सभी का आज तक जिक्र क्यों नहीं आया। आप यह मानते हैं कि प्रदेश के लोग इन सभी वायदों को भूल गये हैं, लोग इन वायदों को भूले नहीं हैं? आगे आने वाले समय में ये सारी बातें बतायेंगे। मैं अपनी बात रखने के लिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ दो इशूज पर ही बात करना चाहता हूँ। कई साथियों ने कहा कि सरकार को अफसरों से निकालकर पब्लिक के पास लाने का काम किया गया है और अब पब्लिक ही सरकार की असली मालिक है। अब सरकार में अफसरों का वर्चस्व नहीं रहा है लेकिन मैं इस संदर्भ में सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय के खुद के महकमे के क्या हालात बने हुए हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के महकमे के क्या हालात बने हुए हैं। मेरे पास कुछ क्वारिज थी जिनको मैंने विधान सभा में लगाया था। हमारे टाइम में वर्ष 2013 में जमीन का एक पजेशन लिया गया था। इस जमीन पर तीन सैक्टर्ज बनने थे

लेकिन पजेशन लेने के बाद भी आज तक वहां पर कुछ नहीं बना है बल्कि आज तो वहां पर नाजायज कब्जे कायम हो चुके हैं और पूरी की पूरी जमीन पर खेती हो रही है लेकिन इस संदर्भ में मेरे को जो मैटीरियल रिप्लाई के रूप में सप्लाई किया गया है उसमें कहा गया है कि cultivation by some unknown farmers on approximate 55 acres of the acquired land. उपाध्यक्ष महोदय एक्वायर की गई लैंड के 55 किल्लों में खेती की जा रही है। यहां पर लगभग 700 किल्ले के करीब लैंड और सभी में खेती करने का काम किया जा रहा है। मेरे पास इन सभी के फोटोग्राफ्स व कागजात भी अवेलेबल हैं जिनमें खसरा/गिरदावरी व अन्य दूसरी चीजें वर्णित हैं। यही नहीं इस सबकी मेरे पास वीडियो भी अवेलेबल है। उपाध्यक्ष महोदय, इस 700 एकड़ की सारी की सारी जमीन पर खेती की जा रही हैं जबकि इंफारमेशन केवल 55 एकड़ के संदर्भ में ही दी गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मुख्यमंत्री महोदय का इतना भी अख्तियार नहीं है कि उनको प्रोपर इंफारमेशन दी जा सके। क्या उन्हें ऐसी बातों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। जब विधान सभा के क्वारीज के जवाब में इस तरह की गलत इंफारमेशन दी जायेंगी तो फिर और क्या बाकी रह जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय तो बड़े सीरियसली कहते हैं कि जो भी आफिसर्ज विधायकों की बातों का गलत जवाब देंगे, उन पर कार्रवाई करने का काम किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के महकमे की मेरी 68 नम्बर वाली दूसरी क्वारी भी थी जिसके जवाब में कहा गया कि 20 आदमियों के नाजायज कब्जे हैं। मतलब नाजायज कब्जे वाली बात स्वयं मानी गई है लेकिन मैं कहता हूँ कि यह संख्या 100 से उपर की है जबकि रिपोर्ट केवल 20 आदमियों की ही दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कब्जे भी वर्ष 2019 से हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रश्न उठता है कि जब मुख्यमंत्री जी को गलत इंफारमेशन दी जा सकती है तो फिर अफसर लाबी आम गरीब आदमी को कैसे बख्शेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिप्टी चीफ

मिनिस्टर साहब के संदर्भ में कुछ बताना चाहूंगा। इन्होंने मेरे एक सवाल का जवाब देते हुऐ कहा है कि वर्ष 2019 से लेकर अब तक जिला सोनीपत में कोई भी फर्जी राशन कार्ड नहीं पाया गया है और न ही कोई राशन कार्ड निरस्त किया गया है। इस तरह का जवाब विधान सभा में दिया गया था। इससे संदर्भित 60 की तो मैं फोटोस्टेट करवा कर लाया हूँ और 200 की मेरे पास सीडी है। उपाध्यक्ष महोदय, अकेले राई हल्के में 3400 फर्जी राशन कार्ड हैं और सारे सोनीपत जिले में कई हजार फर्जी राशन कार्ड हैं। आखिरकार इनका राशन कौन लिया करता था और कौन खाया करता था और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जवाब देते हैं कि कोई राशन कार्ड फर्जी नहीं पाया गया। 60 की तो मेरे पास फोटो कॉपी तक अवेलेबल हैं। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ठीक जवाब दे रहे हैं तो फिर यह क्या हैं ? क्या ऐसे जवाब विधान सभा में दिए जायेंगे ? इनसे पता चलता है कि अफसर लोग सरकार की कितनी परवाह करते हैं। अब यह पता नहीं कि यह जवाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कहने पर दिए गए हैं या अफसरों ने खुद दिए हैं। अगर ऐसे गलत जवाब दिए गए तो विधान सभा के सत्र का क्या फायदा होगा। मेरा एक अगला सवाल डिप्टी चीफ मिनिस्टर के महकमे का ही है। मैंने सवाल किया था कि खानपुर गांव में जहां मैडिकल कालेज है, वहां सड़क पर पानी खड़ा है। खानपुर की सड़कें तीनों साइड से बिल्कुल बेहाल हो चुकी हैं लेकिन इस संदर्भ में जो जवाब दिया गया है, उसमें कहा गया है कि खानपुर सड़क की स्थिति अच्छी है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसके सारे फोटोग्राफ्स हैं जिसमें सड़क पर पानी खड़ा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। आज इस विषय पर विधान सभा की कोई कमेटी बना दी जाये तो असल हालत का पता चल जायेगा। अगर वहां सड़क पर गड्ढे और पानी न हो तो यह कमेटी इसका पता करेगी और साफ पता चल जायेगा कि खानपुर की मेन रोड पर जहां से मैडिकल कालेज में जाते हैं वहां पर सड़क की क्या हालत हो गई है। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले हफ्ते यहां पर गया हूँ। यहां सड़क पर न तो कोई गड्ढे थे और न ही यहां पर पानी खड़ा था। मैं गोहाना से होकर खानपुर गया था।

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी तो एक बार गए होंगे मैं तो यहां से रोज जाता हूँ। आप मेरे हाथ में उस सड़क पर खड़े पानी तथा गड्ढों के फोटो देख सकते हैं।

श्री उपाध्यक्षः देखिए, वैसे अगर कोई रिकॉर्ड की चीज है तो उसकी रिपोर्ट तो मंगाई ही जा सकती है।

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी बता सकता हूँ कि जो सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं और पानी खड़ा हुआ है, यह किस–किस के मकान के सामने हैं। अगर मंत्री जी को विश्वास नहीं है तो विधान सभा की कमेटी बनवा दो तो साफ पता लग जायेगा। दूसरी बात लाठ गांव की है। उस गांव के बीचोबीच पानी लगभग 6 महीने से खड़ा है। हमारा हर रोज आना–जाना होता है, इसलिए हमें वास्तविकता का पता है। उसका जवाब भी ठीक–ठाक करके दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जब विभागों से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दिये जा रहे हैं, आम आदमी को अपने सवालों के जवाब कहां से मिलेंगे?

श्री उपाध्यक्षः मलिक साहब, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है, इसलिए आप बैठ जाइये।

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज आप मुझे दो मिनट का समय और दीजिए।

श्री उपाध्यक्षः मलिक साहब, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है, दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलना है, इसलिए कृपया करके आप अपनी सीट पर बैठ जाइये।

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भ्रष्टाचार के संबंध में भी सदन को बताना है। मेरे पास एक लिस्ट भ्रष्टाचार की है। इस लिस्ट के अनुसार सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्वाचन क्षेत्र करनाल के बारे में सदन को बताना चाहता हूँ। करनाल में बहुत से स्कैण्डल हुए हैं उनमें डी.टी.पी. विक्रम सिंह, तहसीलदार राज बख्श, आर.टी.ए. डॉ. सुभाष, श्री विजय किंगर, एक्सियन, नगर निगम, श्री राजीव जैन, एस.ई., लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), एस.एच.ओ., पुलिस स्टेशन, कुंजपुरा में श्री कुलदीप सिंह और राकेश कुमार, ए.एस.आई. शामिल हैं।

श्री जय प्रकाश दलालः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के पास जो लिस्ट है, उस पर कार्रवाई हो चुकी है और वह सबके पास है।

श्री उपाध्यक्षः मलिक साहब, यह अच्छी बात है कि जिसने गलत काम किये हैं, सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई की है।

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कौन भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि–

> 'यदि सांसद और विधायक सिफारिश करना छोड़ दे तो भ्रष्ट अधिकारियों में कार्रवाई करेगी सरकार।'

इस बात को भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने भी स्वीकार किया है।

श्री उपाध्यक्षः मलिक साहब, प्लीज आप बैठ जाइये। अब आपका माईक ऑफ कर दिया गया है, इसलिए आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं होगी।

श्री सुभाष सुधा (थानेसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका तहेदिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस गरिमामयी सदन में माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आजादी के 75वें साल में हमारे राष्ट्र के 'अमृत काल' में यह हरियाणा विधान सभा का पहला सत्र है और मैं स्वयं को

भाग्यशाली समझता हूँ और अपनी विधान सभा थानेसर की जनता का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उनके आर्शिवाद से मैं इस महत्वपूर्ण सत्र का हिस्सा बना हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिभाषण के माध्यम से प्रदेश व अपने विधान सभा क्षेत्र थानेसर में हुए विकास कार्य व नई योजनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ तथा साथ ही इस गरिमामयी सदन में सभी सदस्यों व प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के स्वस्थ शरीर व उन्नति के लिए कामना करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे पहले कुरूक्षेत्र के गांव दयालपुर में 'जगमग योजना' का काम शुरू किया था। जब उस गांव में पहला कार्यक्रम हुआ तो उस समय एक भी आदमी वहां पर आने के लिये तैयार नहीं था। लोग कहते थे कि हम तो कुंडी वगैरह लगाकर बिजली की चोरी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गांवों में 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से लोगों में एक ऐसी सोच पैदा हो गई है कि जब वे अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो वे अपने घरों की तमाम लाइटस ऑफ करके जाते हैं, ताकि उनका ज्यादा बिजली का बिल न आये। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने 1 लाख 80 हजार रूपये की इंकम से नीचे लगभग 46.7 लाख कार्ड बनायें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने हर आदमी को 5 लाख रुपये तक का मैडिकल फ्री देने का काम किया है, इस प्रकार के अनेकों सराहनीय कदम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उठाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पहले लोग काम करवाने के लिये सरकार के पास जाते थे और अब सरकार पोर्टल के माध्यम से लोगों के पास जाती है, ऐसी व्यवस्था प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ही कर सकते हैं। हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मैरिट पर नौकरियां देने का काम किया है। आज यहां पर बहुत–सी राजनीतिक पार्टियों के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं । वे अपने दिल पर हाथ रखकर गांवों में नजर लगायें तो पता चलेगा कि हर राजनीतिक पार्टी के लोगों को मैरिट के आधार पर नौकरियां मिली हैं । इसी

तरह से ट्रांसफर पोलिसी है । पहले किस तरह से लोग ट्रांसफर के लिए चक्कर काटते थे । अब ऑनलाइन स्टेशन भरकर घर बैठे ट्रांसफर होती है । प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने यह बहुत बड़ा कार्य किया है । सरकार ने ऑनलाइन पैंशन बनानी शुरू की है। पहले क्या होता था कि गरीब आदमी की पैंशन को लोग खा जाते थे । अगर पहली बार बैंक खाते में अगर किसी ने पैंशन डालने का काम किया है तो वह माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है । मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी और सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करूंगा । कुरूक्षेत्र में अभी गीता जयन्ती समारोह मनाया गया था । पहले इसमें केवल 10 हजार लोग आते थे लेकिन आज गीता जयन्ती के अवसर पर 50 लाख लोग आते हैं । आज सदन में पूरा विपक्ष और अन्य पार्टियों के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं । हमने कुरूक्षेत्र कें ज्योतिसर में भगवान श्रीकृष्ण का विराट स्वरूप बनाया है । वहां पर एक कम्पनी ने 22 मिनट और 15 मिनट के दो लाइट एण्ड साउण्ड श्यो बनाए हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी आकर उन कुल 37 मिनट्स के श्योज को अवश्य देखें । इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वहां पर 235 करोड़ रुपये की लागत से एक थीम पार्क का भी निर्माण करवाया जा रहा है । इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं । हमें वहां पर एक महिला कॉलेज भी प्राप्त हुआ है । इससे पहले हमारी बच्चियां लाडवा और शाहाबाद तक पढ़ने के लिए जाती थी । पहली बार हमारी 1000 बेटियां कुरूक्षेत्र के महिला कॉलेज में पढ़ रही हैं । एजुकेशन के बारे में मैं कहूंगा कि मेरे क्षेत्र के गांव किरमच में बच्चे वृक्ष के नीचे पढ़ते थे । वहां पर पहली बार 5 करोड़ रुपये की लागत से एक स्कूल बनाया गया है । इसी तरह से सब्जी मण्डी के पास हमारा एक राजकीय विद्यालय है जिसमें बेटियां सुबह शाम कक्षाएं लेती थी । उसके लिए भी 5 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है । खेलों की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां पर सिंथैटिक ट्रैक का निर्माण किया गया है । हमने वेलोड्रोम के

लिए रिक्वैस्ट की है और उसकी भी बनाने की तैयारी हो रही है । वहां पर एस्ट्रोटर्फ भी बन रहा है । हमारा जो 50 बैडिड हॉस्पिटल था उसको सरकार ने 100 बैडिड तक कर दिया है और उसके लिए 101 करोड़ रुपये भी सैंक्शन कर दिए हैं । इसके लिए मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं । हमारे क्षेत्र में 5 फाटकों को खत्म करके 250 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटिड ट्रैक्स का निर्माण किया गया है । मैं कहूंगा कि कुरूक्षेत्र में शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य की दृष्टि से सब कुछ मिला है । मैं सिर्फ एक डिमांड रखना चाहता हूं कि भारत माला प्रोजैक्ट–2 के वर्ष 2024 में हमारा एक बाइपास बना दिया जाए । वह बाइपास कुरूक्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है । (विघ्न) कुरूक्षेत्र में अभी राहुल गांधी जी आये थे । उन्होंने ब्रहमसरोवर पर बैठकर कहा कि देखो, कितना सुन्दर शहर है । इस समय सदन में माननीय परिवहन मंत्री जी बैठे हैं । मैं कहूंगा कि पीपली बस स्टैंड को पी.पी.पी. मोड पर बनाने के लिए दिया हुआ है । मेरा अनुरोध है कि उसे जल्दी से बनवा दिया जाए । हमारे वहां पर सौ बैड का एक हॉस्पिटल है और सौ बैड का एक हॉस्पिटल सैंक्शन किया हुआ है । अतः उसका काम भी जल्द ही शुरू करवा दिया जाए । सदन में माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं । मेरा कहना है कि वहां पर वी.एल.डी.ए. कॉलेज बनाने का काम भी शुरू करवा दिया जाए । विश्व की पहली आयुष यूनिवर्सिटी हरियाणा में बन रही है । मेरा कहना है कि वह सैंक्शन हो चुकी है, इसलिए उसका काम भी जल्द ही शुरू करवाया जाए । मैं कहूंगा कि हमारे रेलवे स्टेशन पर एक ब्रिज बनाया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो सके । आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका तहेदिल से धन्यवाद करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ बातें अभी कहनी रह गई हैं, इसलिए मैं उन्हें आपको लिखित रूप में दे देता हूं। आप उन्हें प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनवा देना ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है सुधा जी, आप हमें अपनी बातें लिखित रूप में दे दें । हम उन्हें प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनवा देंगे ।

***श्री सुभाष सुधा :**

Sh. Subhash Sudha ji MLA

21/2/23

माननीय राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष महोदय में आपका तह दिल से हार्दिक धन्यावाद करता हूँ कि आपने मुझे इस गरिमामयी सदन में ~~14वीं हरियाणा विधानसभा के चौथे बजट सत्र में~~ माननीय राज्यपाल हरियाणा जी के अभिभाषण पर बोलने पर अवसर प्रदान किया। आजादी के 75वें साल में हमारे राष्ट्र के अमृत काल में यह हरियाणा विधान सभा का पहला सत्र है और में स्वंय को भाग्यशाली समझता हूँ और अपनी विधानसभा थानेसर की जनता का भी हार्दिक धन्यावाद करता हूँ कि उनके आर्शिवाद से मैं इस महत्वपूर्ण सत्र का हिस्सा बना हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इस अभिभाषण के माध्यम से प्रदेश व अपने विधानसभा थानेसर में हुए विकास कार्य व नई योजनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ तथा साथ ही इस गरिमामयी सदन में सभी सदस्यों व प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के स्वस्थ शरीर व उन्नति के लिए कामना करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने स्वंत्रता दिवस के उपलक्ष पर अपने भाषण में एक विशेष बात कही कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए हमने अगले 25 वर्षो की स्वरुप व योजनाओं को हम अभी से तैयार कर रहे हैं और जी–20 सम्मेलन की अध्यक्षता का ताज इस बार माननीय प्रधनमंत्री जी के सर पर रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इन दोनों विशेष कार्यों में हमारी सरकार अपनी दूरदृष्टि, लगन, मेहनत, अपनी ईमानदार कार्यप्रणाली और प्रदेश के प्रत्येक नागिरक के सहयोग से हरियाणा प्रदेश सबसे आगे रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय भारत सरकार व हमारी सरकार द्वारा बीते वर्षों में कोविड जैसी महामारी से लड़ने के लिए हर प्रकार के विशेष निर्णयों को तुरन्त प्रभाव से लागू करवाया चाहे वो हर गरीब परिवार के घर में राशन व दवाईयां प्रदान करना था या करोना वैक्सीन की खोज कर दक्षिण ऐशिया और विश्व के कई अन्य देशों में वैक्सीन प्रदान करना हो। इसके साथ–2 हाल ही में तुर्की में आये भुकंप की वजह से आपदा पर भी राहत सहायता कर भारत देश ने वसुधैव कुटुम्बकम (पूरा विश्व एक परिवार है) के सिद्वांत को प्रस्तुत किया है। कोविड महामारी के कारण हर प्रदेश व हर एक देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। जी–20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत देश को गौरव प्रदान करता है और इसी जी–20 सम्मेलन के शुभ अवसर पर भारत देश अपनी विश्व शक्ति का प्रदर्शन कर विभिन्न देशों में आयी आर्थिक मंदी से समाधान व भ्रष्टाचार जैसे विशेष मुदों पर अपने महत्वपुर्ण सुझाव देगा। हरियाणा प्रदेश जी20 सम्मेलन से संबधित कार्यक्रमों के लिये विशेष रूप से जैसे IIM रोहतक या प्रदेश में अन्य विश्वविद्यालयों मे संगोष्ठी व सम्मेलन, फरिदाबाद में सूरजकुंड अंतराष्ट्रीय शिल्प मेले में राजदूतों के आगमन व उनके साथ संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय एक अक्तूबर, 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 5–जी सेवाओं का शुभारम्भ कर देश को टेक्नोलॉजी में गति प्रदान की है। हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से प्रदेश में गुरूग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार व रोहतक में 5–जी की सूविधा आरम्भ की जा चूकी है तथा अन्य जिलों में योजनावद्ध तरीके जल्द ही आरम्भ की जाएगी।

***चेयर के आदेशानुसार उपर्युक्त लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया ।**

माननीय अध्यक्ष महोदय इसके साथ–साथ हमारी सरकार समय–समय पर नई–नई याजनाओं को लागू करने पर अग्रसर रहती है। नए युग में प्रदेश के नागरिकों को नई सूविधा देने के लिए पेपरलेस जेसी योजना लागू कर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर सूविधा इसके साथ जोड़ दी गई है। परिवार पहचान पत्र सूचना आंकड़ों के हिसाब से 73.11 लाख परिवारों का पहचान पत्र बन चूका है जिसमें सदस्यों की संख्या 2.88 करोड़ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार हर प्रकार की योजनाओं को ईमानदार कार्यप्रणाली के तहत लागू करती है और भ्रष्टाचार के प्रति जीरों टोलरेंस की नीति रखते हुए सी0एम0 फलाईंग स्क्वेड लगातार काम कर रहा है। वर्ष 2022 के दौरान इनके द्वारा अवेध खनन, वाहनों की ओवर लोडिंग, नकली व अवेध शराब, बिजली की चोरी, खाने के पदार्थों में मिलावट पर कुल 1330 छापे मारे गये और इन पर 456 मामलों में केस दर्ज कर 555 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है। सरकार की प्रत्येक योजना का हर तरह से लाभ उस व्यक्ति तक पहूँच जाये जो पंक्ति में सबसे अंतिम से खड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय अंत्योदय का एक सबसे बड़ा उदाहरण 21 नवम्बर 2022 को चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना उन परिवारों के लिए शुरू की गई जिनकी वर्षिक आय 1.80 लाख रूपये या इससे कम है। इस योजना के तहत 46.7 लाख आयुषमान कार्ड बनवाये गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह बताना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास में हमारी सरकार द्वारा एक विशेष सराहनीय व प्रशंसनिय कदम उठाया गया जिसमें सरपंचों व पंचों का पढ़ा–लिखा होना निश्चित किया गया। एक पढ़ी–लिखी पीढ़ी को अपने क्षेत्र का विकास और सुधार करने का एक विशेष अवसर प्राप्त हुआ। हमारी सरकार द्वारा पंचायतों को मज़बूत व विकास कार्यों में गति लाने कि लिए तुरन्त प्रभाव से पंचायतों को ग्रांट जारी की गई यह विकास की दौड़ में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के बराबर है।

मैं हमारी सरकार का हार्दिक धन्याद करता हूँ कि मेरी विधान सभा थानेसर के प्रत्येक गांव में सुन्दर नवनिर्मीत चौपालें, जोहड़ों, नालियों, गलियों व बड़े समुदायिक केंद्रों का निर्माण आधुनिक सुविधाओं के साथ करवाया गया। ग्रामवासियों व सरकार के साथ सीधा सम्बंध स्थापित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल जारी किया गया जिस पर प्रत्येक ग्रामवासी अपनी मांगे व सुझाव सीधा सरकार तक पहूँचा सकता है। अब तक इस पोर्टल के माध्यम से 15,553 मांगें प्राप्त हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहता है इसलिए जीवन व कामयाबी का सबसे पहला कदम से शिक्षा। शिक्षा वह मंच है जहां बेठकर अपने जीवन के नैतिक मूल्यों, अपनी संस्कृति व अपना भविष्य तय करते हैं। इसलिए हमारी सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कदम उठाये और शिक्षा से संबंधित हर प्रकार के आधुनिक व उच्च स्तर की शिक्षा बच्चों को प्रदान की जा रही है।

1. स्कूली बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत टेबलेट बांटे गये।
2. 9वीं से 12वीं तक 1.9 लाख विद्यार्थियों को व्यवसासिक शिक्षा के तहत नामांकन किया गया।
3. हरियाणा के 1186 विद्यालयों में 15 व्यवसायिक कौशल शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है।
4. शिक्षा की दृष्टि से मेरी विधानसभा थानेसर में लगभग 3 स्कूलों के अपग्रेड करवाया गया जैसे– हथीरा, भिवानीखेड़ा के स्कूल थे।
5. गांव कीरमच में नये स्कूल भवन का निर्माण कार्य 4 करोड़ की लागत से करवाया गया
6. पुराने शहर में गर्ल्स सरकारी स्कूल में नये स्कूल भवन का निर्माण कार्य 3.5 करोड़ की लागत से करवाया गया
7. राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण गांव पलवल में करवाया गया। इन सभी कार्यों के लिए मैं हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी का हार्दिक धन्यावाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सस्ती सुगम व आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

1. इसके लिए हमारी सरकार द्वारा हरियाणा में 56 स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में ई–उपचार एपलिकेशन को लागू किया गया जिसमें लगभग 8.2 करोड़ रोगियों ने विजिट कर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त की हैं।
2. गांव कुटेल जिला करनाल में स्वास्थ्य विश्वविद्यालय को स्थापित किया जा रहा है जिसमें 730 बिस्तरों के साथ–साथ सुपरस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी बनवाया जायेगा।
3. थानेसर में 100 बेड का नया हस्पताल बनवाया गया है अन्य 100 बेड का हस्पताल जल्द बनाया जायेगा।
4. बारना में नई पी0एच0सी0 का निर्माण करवाया गया।
5. राजकीय नर्सिंग कॉलेज का निर्माण करवाया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय पर्यटन की दृष्टि से हमारी सरकार ने हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है इसके लिए हरियाणा सरकार केंद्र सरकार से सहयोग से हर एक पर्यटन स्थल का विकास कर रही है।

1. माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यावाद करना चाहूंगा जिन्होंने कुरूक्षेत्र को पर्यटन हब बनाने के लिए कुरूक्षेत्र को श्रीकृष्णा सर्किट के तहत बह्मसरोवर, सन्निहित सरोवर व ज्योतिसर तिर्थ का विकास करवाया।
2. 9 करोड़ की लागत से ज्योतिसर तीर्थ पर भगवान श्रीकृष्ण का विराट स्वरूप स्थापित किया।
3. 236 करोड़ की लागत से कुरूक्षेत्र में महाभारत थीम पर भव्य भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है।
4. गीताजयंती को अंतराष्ट्रीय स्वरूप हमारी सरकार द्वारा ही प्राप्त हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं फिर से आपका हार्दिक धन्यावाद करता हूँ कि हमारी सरकार की प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं व थानेसर विधानसभा के विकास कार्यों के बारे में बताने का अवसर प्राप्त हुआ।

श्री कुलदीप वत्स (बादली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । जैसी परिपाटी चली आ रही है उसी तर्ज पर उन्होंने सदन में एक सरकारी भाषण पेश किया । उन्होंने सरकारी असफलताओं, सरकारी नाकामियों और सरकारी चिंताओं को छिपाकर सरकार को मजबूत और कमेरी बताने का प्रयास किया । मैं सोच रहा था कि अगर महामहिम राज्यपाल जी लीक और परिपाटी से हटकर अपना अभिभाषण

स्वयं तैयार करवाते तो उससे पता लगता कि हरियाणा की हकीकत क्या है । मैं कहूंगा कि –

आज पी.पी.पी. के झमेले में जनता खड़ी लाचार
और सी.टी.ई.टी. के फेर में युवा हुए बेरोजगार
अपराध, नशा, भ्रष्टाचार चरम पर है
तो किस तरक्की की बात करे सरकार ।

डिप्टी स्पीकर सर, आज सरकार की वस्तु स्थिति ये है। सरकार ने अलग–अलग तरीके से पूरे हरियाणा प्रदेश को कागजों में उलझाया हुआ है। परिवार पहचान पत्र तो पूरे राज्य में 'परमानैंट परेशान पत्र' बन चुका है। आज हरियाणा प्रदेश के लाखों लोग बुरी हालत में हैं। हमारी बहन–बेटियों की चीखें वीडियो के माध्यम से देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हों या चाहे अखबार के माध्यम से देखते हों। हमारे लोगों की आए दिन यह डिमांड आती रहती है कि– पी.पी.पी. के झेल में, सारा खेल कर दिया फेल। लोगों की रोते– बिलखते–सिसकते वीडियों देखी जा सकती हैं। पी.पी.पी. में समस्या भयानक है क्योंकि किसी बच्चे की जाति बदल जाती है, किसी बुजुर्ग गरीब विद्यवा महिला की आमदनी 15 लाख रुपये कर दी जाती है, लेकिन उसकी आमदनी 50,000 रुपये भी नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि किसी दिव्यांग की कैटेगरी बदल दी जाती है। इस पी.पी.पी. की वजह से हजारों लोगों का राशन बंद हो चुका है, हजारों लोगों का बी.पी.एल. कार्ड रद्द हो चुका है। लाखों लोगों की आय अव्यवहारिक है जिसकी आय 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक है, उसको 15 लाख रुपये दिखा रहे हैं। महोदय, मजदूरों की आमदनी भी लाखों पार दिखायी गयी है, सबको मालूम है ये पी.पी.पी. का चमत्कार है। आज इस पी.पी.पी. की वजह से लाखों बुजुर्गों दिव्यागों, विधवाओं की पैंशन कट चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, पैंशन से याद आया अपने हरियाणा में कहावत है कि– 'दादा ले और पौता

बरतै' किन्तु इस सरकार में शामिल उप मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि यहां पर तो उल्टा काम हो गया है कि 'दादा दे और पौता खोसै'। श्रीमान् जी, चौधरी देवीलाल जी ने बुजुर्गों को पैंशन एक सम्मान भत्ते के रुप में दी थी। आज उस सम्मान भत्ते के चक्कर में हजारों बुजुर्गों और माताओं/बहनों की पैंशन काटी जा रही है। हालांकि बात तो बुढ़ापा पैंशन 5100 रुपया महीना देने की हुई थी, परन्तु वे 5100 रुपये महीना पैंशन तो मिले नहीं। आज लाखों लोग परेशान हैं क्योंकि उनकी पैंशन काटी जा रही है। डिप्टी स्पीकर सर, हरियाणा जैसा राज्य भी रोजगार के मामले में टॉप–5 बेरोजगार राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी से बड़ा कोई दंश नहीं है। हमारी सरकारों पर ये धब्बा है क्योंकि हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे लोग बेरोजगारी की वजह से अवसाद में हैं, परेशान हैं। भर्तियां सी.ई.टी. के झमेले में जाकर लटका दी जाती हैं। परीक्षाएं हो नहीं रही हैं। मां–बाप भी इस सरकारी रवैये से परेशान हैं। एक बाप को फिक्र नौकरी से ज्यादा बच्चों की है। किसी बाप ने कहा कि– नौकरी की इस सरकार से कोई आस तो नहीं, कोई काम शुरू करा दूं, पैसा बाप के पास तो नहीं। लड़का गुमसुम रहता है, तो कई बार फोन करता हूं कि फिक्र ये रहती है, बच्चे की जेब में सल्फास तो नहीं। आज इस प्रदेश की यह हालत है। आज यह इस प्रदेश के युवाओं की हालत है। गवर्नर एड्रैस में लिखा है कि यह प्रदेश बहुत खुशहाल है। हमें ऐसा खुशहाल प्रदेश नहीं चाहिए। डिप्टी स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त युवाओं की फौज एक आस थी। इस अग्निवीर योजना के नाम से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। डिप्टी स्पीकर सर, सरकार कह रही है कि ये 'अमृत काल है' किन्तु मेरे हिसाब से तो ये मृत काल है। इस हरियाणा प्रदेश के लिए सरकार की संवेदना मर चुकी है। सच्चाई मर चुकी है, सहनशीलता और सोचने की शक्ति मर चुकी है। हरियाणा प्रदेश में हर तरफ अपराध और नशा बढ़ रहा है। आये दिन मर्डर हो रहे हैं और आये दिन लूट–खसौट हो रही है और सरकार अमन–चैन

और भाईचारे की बात करती है। यह शर्म की बात है। अभी माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल जी सदन में नहीं है। शिक्षा व्यवस्था भी हमने अफसरशाही में उलझा दी है। पिछले साल लाखों बच्चे वर्दी, स्टेशनरी का इंतजार करते रहे। ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी है कि शहरी स्कूल्ज में स्टाफ सरप्लस है और गांवों के स्कूल्ज खाली हैं।

श्री उपाध्यक्षः वत्स जी, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री कुलदीप वत्सः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बोलने का 8 मिनट का समय है।

श्री उपाध्यक्षः कुलदीप जी, आपको यह 8 मिनट का टाइम किसने दिया है?

श्री कुलदीप वत्सः उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर

17:00 बजे

दूंगा। सरकार ने पेपर होने से पहले ही किताबें/टैब वापिस करने का फरमान जारी कर दिया है। हमारे हरियाणा पुलिस के नौजवान बहुत सेवा कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि एक जवान को 20 रुपया खाने का भत्ता मिलता है। मुझे उस रेहड़ी का या होटल का नाम बतायें जो 20 रुपये में पूरे दिन एक जवान का पेट भर सके। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में लिखा है और यह बहुत अच्छी बात भी है जैसे किसान की जल भराव से फसल खराब हो जाती है या डी.ए.पी. की किल्लत हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहां के नेताओं ने एक वायदा किया था कि हम पंजाब के बराबर हरियाणा में वेतन आयोग लागू करेंगे और हम आज उनसे पूछना चाहेंगे कि वे नेता कहां चले गये और हरियाणा से वेतन आयोग को कहां गायब कर दिया?

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी स्पीच लिखित में दे दीजिए ताकि उसको प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया जा सके।

श्री कुलदीप वत्स : उपाध्यक्ष महोदय, डॉ. राहत इंदौरी का एक शेर पढ़कर सुनाना चाहता हूं:–

झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो,

सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो,

घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है,

दरवाजे पर लिखा हुआ है कि सच बोलो।

मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि सच कौन सा है तो सच बोलकर दिखायें।

श्री उपाध्यक्ष : वत्स जी, आप प्लीज बैठ जायें।

श्री कुलदीप वत्स : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक शेर पढ़कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : वत्स जी, सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए 5–5 मिनट का ही समय दिया है इसलिए प्लीज आप बैठ जायें।

श्री कुलदीप वत्स : उपाध्यक्ष महोदय, **********

श्री उपाध्यक्ष : वत्स जी, आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं की जायेगी इसलिए बोलने का कोई फायदा नहीं है।

श्री दीपक मंगला (पलवल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे देश द्वारा जी–20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करने और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करने के लिए हमें गौरव का अनुभव हो रहा है। हमें गौरव का अनुभव क्यों न हो क्योंकि यह हमारा भारत देश पहले सोने की चिड़िया

———————————————————

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

कहलाता था उसी तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्व का सिरमौर बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यह जी–20 की अध्यक्षता उस कड़ी का एक हिस्सा है। इसी तरीके से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज प्रदेश विकास की दृष्टि से और हरियाणा में जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति बैठा है, उसके उत्थान को लेकर के आज हमारा प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज सरकार सभी स्कीमों का पूर्ण लाभ देने और अंत्योदय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गरीब से गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। हमारे विपक्ष के साथी पहले नारा लगाते थे कि गरीबी मिटाएंगे लेकिन गरीबी तो मिटी नहीं बल्कि इन्होंने गरीबों को ही मिटाने का काम कर दिया। अगर एक्चुअल में गरीबों के उत्थान के लिए कोई काम कर रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हरियाणा चिरायु योजना शुरू की गई है इसके माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को इलाज संबंधित सुविधा प्रदान की जायेगी। हमें यह पता है कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में 100–200 रुपये की दवाई न जाती हो। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश में 29 लाख अंत्योदय परिवारों को हरियाणा चिरायु योजना का लाभ दिया जा रहा है और 46.7 लाख से अधिक परिवारों के कार्ड बनाये जा चुके हैं। निरोगी हरियाणा स्कीम के तहत 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय से कम वाले परिवारों की भी व्यापक स्वास्थ्य जांच की जाती है। अभी मेरे साथी यह बात कह रहे थे कि हमारे बेरोजगार युवकों के लिए सरकार ने क्या किया तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पलवल के दुधौला गांव में 85 एकड़ भूमि में 850 करोड़ रुपये की लागत से देश की पहली ऐसी विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, पलवल में बनाने का काम किया जा रहा है और उस यूनिवर्सिटी का लगभग काम पूरा हो गया है। कुछ

ही दिनों के अन्दर उसका विधिवत उद्घाटन भी हो जाएगा लेकिन उसके बावजूद भी आज वहां पर बहुत से कोर्स चल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर 400 से ज्यादा कोर्सिज होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बेरोजगार युवा साथी चाहे कोई दसवीं पास हो, बाहरवीं पास हो अथवा ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो जो भी उस यूनिवर्सिटी के अन्दर पढ़ेगा उसे कोई न कोई रोजगार अवश्य मिलेगा। ऐसी यूनिवर्सिटी मेरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। इससे न केवल पलवल, हथीन, होडल, हसनपुर, जिला नूहं, फरीदाबाद, गुरुग्राम को ही फायदा नहीं होगा बल्कि इस यूनिवर्सिटी से निश्चित तौर पर हमारे सोनीपत, पानीपत तथा सारे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को फायदा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आज मैं पलवल की बात करूं तो यहां रोड्स की ऐसी कनैक्टिविटी हो गई है जिससे दूसरे जिले से आने वालों को भी कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की रोड वाली बात पर बताना चाहूंगा कि(शोर एवं व्यवधान)

श्री दीपक मंगलाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह विदेश में जाने की ही बात है और आज आप जाकर के भी देखिए एक कहावत भी है कि पलवल की सड़क पर घोड़ा दौड़ा–दौड़ा जाए। लेकिन आज घौड़ा ही नहीं आज यहां पर हवाई जहाज भी उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि माननीय सदस्य(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः गीता जी, आप शोर न करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आपको संबोधित करके कहें, हमें संबोधित करके न कहें।

श्री उपाध्यक्षः गीता जी, पहले आप बोल रही हैं, आप सीनियर मेम्बर हैं, आप ऐसे न करें।

श्री दीपक मंगलाः उपाध्यक्ष महोदय, स्वामित्य योजना के तहत जहां हमारे ग्रामीणों को लाल डोरे की जमीन का स्वामित्व दिया गया है वहीं मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की दुकान और मकानों की जो 20 वर्ष की लीज के दुकानदार थे, जो गरीब दुकानदार थे आज उनको भी मालिकाना हक देने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा क्योंकि सदन में समय की मर्यादा रहती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे छायसा से जेवर ऐयरपोर्ट तक बनने वाले फ्लाईओवर के लिए जमीन एक्वायर हो रही है। जमीन की मुआवजा राशि में बागपुर गांव और मोहना गांव के किसान हैं उनकी मुआवजा राशि अलग–अलग है। यह मुआवजा राशि हमारे बागपुर गांव के किसानों को भी गांव मोहना के किसानों के बराबर मिलनी चाहिए क्योंकि हमारे गांव मोहना और गांव बागपुर की जमीन का शामियाना एक ही है, परन्तु दोनों का सर्कल रेट अलग–अलग है इसलिए हमारे किसानों को कहीं कोई नुकसान न हो इसलिए समय रहते व्यापक स्तर पर हमारी इस समस्या का समाधान होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहकर के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि हमारा अच्छेजा से लेकर इन्द्रा नगर तक लगभग डेढ़ किलोमीटर का एक कच्चा रास्ता है। यमुना नदी में कटान की वजह से यूपी और हरियाणा प्रांत की सीमाएं निश्चित नहीं थीं और जब राजीव दीक्षित अवार्ड हुआ तब यह रास्ता तो बना परन्तु सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आया इसलिए आज तक यह रास्ता कच्चा है। अगर आज हम यहां पर जाएं तो यहां पर बीहड़ जैसा दृश्य और ऊंचे–ऊंचे रेत के टीले दिखाई देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस रास्ते को पक्का बनाया जाए

ताकि यह रास्ता सरकारी रिकॉर्ड में भी आ जाए और वहां हमारे ग्रामीणों को भी इससे सुविधा मिले। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री शमशेर सिंह गोगी (असंध): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी सेहत ठीक न होने की वजह से अगर मुझे अपनी बात रखने के लिए 5 से 7 मिनट का समय लग जाए तो आप बीच में मत रोकना।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है। आप अपनी बात रखिए।

श्री शमशेर सिंह गोगी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी सुन रहा था कि आपने बहुत से माननीय सदस्यों को बोलने के लिए समय दिया है और अब मेरे को भी बोलने का समय दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे पक्ष के लोगों को सुन रहा था जो पहले तो सरकार के गीत गाते हैं जिससे मुख्यमंत्री जी खुश हो जाएं, लेकिन ये जाते–जाते रोने लगे जाते हैं इसलिए मैंने भी सोचा है कि मैं भी सरकार की कुछ उपलब्धियां गिनवा दूं जिससे शायद मुख्यमंत्री जी खुश हो जाएं क्योंकि असंध को जिला बनाने के लिए कई दिनों से वादा किया हुआ है, लेकिन अभी तक बनाया नहीं गया, क्या पता शायद अब बना दें। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे सरकार इतनी अच्छी है कि जब मैं पहले बजट सैशन में वर्ष 2019 में एम.एल.ए. बनकर आया तब असंध में एक वेटरनरी हॉस्पिटल बनवाने के लिए हां भरी थी, आश्वासन दिया गया था, थोड़े बहुत पैसे भी भेजे, लेकिन वह आज तक बनी नहीं है, यह सरकार की उपलब्धि है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल बजट के अन्दर असंध में हॉस्पिटल पास किया गया था लेकिन आज तक इसका यह नहीं पता है कि इसकी फाईल कहां है सिर्फ इसकी अप्रूवल का एक कागज सा है कि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गयी और लोलीपोप दे दिया गया है। इस तरह के काम सरकार करेगी तो सरकार की इसके लिए तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। आज यह कह रहे थे कि जो व्यक्ति चार लाख की फसल बेचेगा मंत्री जी आप भी सुन लेना आपकी फसल भी चार लाख की तो होती ही होगी

अगर ऐसा होता है तो आपकी आमदनी 1.80 लाख मान ली जायेगी। सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि कभी आज से पहले हुई नहीं है। अगर इस हिसाब से आज जितनी फसल बिकती है इस रेशो से आप किसान को प्रॉफिट दे दें बाकी सारे पैसे सरकार रख ले। यह 45 परसैंट बनती है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर किसान को हर रोज धरने पर बैठने की या रोने की क्या जरूरत होगी। हर रोज जुत्ता बज रहा है। अगर ठेका 70 हजार रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष हो रहा है तो उसके बाद ही तो सरकार 45 हजार रूपये दे रही है। ठेके वालों को तो कुछ बचता ही नहीं। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर सर, मेरे हल्के में एक बड़ा गांव है उसमें 11000 वोट हैं। मैं सरकार की उपलब्धि के बारे में बता रहा हूं। वहां पर स्टेडियम के लिए पिछले तीन साल से मैं कह रहा हूं कि यह स्टेडियम पास हो गया है इसकी चारदीवारी बन गई है बाकी का काम क्यों नहीं हो रहा है? इसका मुझे अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। अब की बार मैंने सवाल भी लगाया था लेकिन उसका नम्बर ही नहीं आया। अब कह रहे हैं कि 50 लाख रूपये वर्ष 2012 में आये थे। अगर वर्ष 2012 में आपने नहीं बनाया चाहे उस समय कोई भी सरकार थी तो उसकी कीमत आज कितनी बन गई है? पिछले 8–9 साल से तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। अब मंत्री जी ने आज यह आश्वासन दिया है कि मैं उसको बनवा दूंगा। मैं देख लेता हूं। आगे भी सैशन आयेगा अगर नहीं बना तो उसमें मैं इस मुद्दे को फिर से उठाउंगा। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कहां–कहां उपलब्धि हुई। सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमैंट में यानि बेरोजगारी में हम नम्बर वन हो गये। यह सरकार कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने जो हरियाणा को दिया है हम सभी हरियाणावासी उससे बहुत खुश हैं। नशा पूरे प्रदेश के अंदर सिर चढ़कर बोल रहा है। नशा सरेआम बिक रहा है और पुलिस बिकवा रही है। यह बात मैं ऑन रिकार्ड कह रहा हूं। बेटियों पर अत्याचार भी निरंतर बढ़ रहे हैं। अगर

मैं नारे की बात करूंगा तो कईयों को तकलीफ हो जायेगी क्योंकि वे सोचते हैं कि इस नारे पर उनका ही पेटैंट है। अभी हमारी कमेटी ने कल्पना चावला मैडीकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, करनाल का निरीक्षण किया था। हमने वहां पर एक राक्षस का तो कल्याण किया है। अभी तक उसको हटवाया नहीं है लेकिन हमने रिकमण्ड किया है कि उसको डिसमिस किया जाये। वह छोटी–छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करता था। प्रदेश में क्राईम का लैवल क्या है इसको देखने के लिए इंडैक्स को देखा जा सकता है और लॉ एण्ड ऑर्डर तो इतना बढ़िया है कि करनाल में 14 तारीख को पुलिस को राष्ट्रपति कलर दिया गया था और 16 तारीख को भिवानी में दो भाईयों को जीप में जला दिया जाता है जबकि पुलिस भी उनको देख लेती है कि वे मरने वाले हैं वह ईलाज नहीं करवाती। मारने वाले कौन है अगर मैंने नाम ले दिया तो सत्ता पक्ष से कई सदस्य कां–कां करके बोल पड़ेंगे। सभी को पता ही है कि कौन मार रहा है। ऐसे भाई चारा बनेगा या टूटेगा? अगर प्रदेश में भाई चारा नहीं रहा तो प्रदेश कैसे रहेगा? महंगाई में हम नम्बर वन हैं। अगर कहीं कमी हो तो मुझे बता दिया जाये। जब गेहूं बोने का टाईम आता है तो डी.ए.पी. खाद नहीं मिलती और यूरिया की जरूरत होती है तो यूरिया नहीं मिलता और यह कहा जाता है कि सारे का सारा यूरिया कंवर पाल जी यमुना नगर में ले गए क्योंकि वहां पर प्लाईवुड नाम की एक इण्डस्ट्री है। उनको ज्यादा जरूरत थी इसलिए मंत्री जी की ज्यादा चलती है उधर चली गई। अपैक्स के अंदर जान बूझकर खाद की सप्लाई नहीं दी जाती ताकि किसान मजबूरी में प्राईवेट दुकान से खरीदनी पड़े। एक और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि गऊओं के नाम पर वोट मांगकर गऊओं की हत्या करने में कौन सबसे नम्बर वन है इसकी तो जांच होनी चाहिए। हरियाणा और यू. पी. में से अगर नम्बर वन देखा जाये तो हरियाणा ही नम्बर वन पोजीशन पर आयेगा। अभी–अभी चारे की जगह जहर देकर करनाल में 45 से 60 गऊओं की हत्या कर दी

गई। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि किसान की आमदनी दोगुणी हो चुकी है। उसमें अगर आपको किसी को हिस्सा देना हो तो मैं भारतीय किसान यूनियन वालों से कह दूंगा कि थोड़े बहुत इन बी.जे.पी. वालों को भी दे दो क्योंकि इन बेचारों ने बहुत मेहनत करके हमारी आमदनी को दोगुणा किया है। बाकी की बातें मैं कल जीरो ऑवर में कहूंगा।

श्री राजेश नागरः उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती सीमा त्रिखाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक मिनट की अनुमति चाह रही हूं। हमारे बड़े काबिल साथी श्री शमशेर सिंह गोगी हमारी शिक्षा समिति के सदस्य भी हैं इन्होंने करनाल का जिक्र किया है। पिछले 8 साल से हमारे प्रदेश की कमान माननीय श्री मनोहर लाल जी के हाथ में है और वे हमारे मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि मैं गोगी जी की बात को बढ़ा कर कह रही हूं। इन्होंने जो कहा है वह बिल्कुल दुरूस्त कहा है। वह इसलिए दुरूस्त कहा है क्योंकि 8 साल से इस प्रदेश की कमान आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के हाथ में है और इस राज में एक कमेटी सी.एम. सिटी में सी.एम. के निर्वाचन क्षेत्र में जाती है और वहां पर कुछ बेटियां समिति से बात करती हैं। इस प्रकार से 8 साल से इस राज्य से सामंतवाद का सिस्टम माननीय मनोहर लाल जी ने खत्म किया है। उस कर्मचारी के बारे में समिति ने मिल कर सिफारिश की कि अगर यह गलत पाया गया है तो उसको निस्कासित किया जाये और उस सिफारिश को आगे कबूल किया गया है। इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है। हमारी बहन गीता भुक्कल जी बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ के नारे के बारे में हमारे ऊपर कटाक्ष करती हैं।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि सी.एम. सिटी में बेटियों को बचाने के लिए समिति को जाना पड़ा।

श्रीमती सीमा त्रिखाः उपाध्यक्ष महोदय, हम बेटियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि कॉलेज में गये थे। यह भी सबूत है कि हमारी बहन गीता भुक्कल जी हर बात पर बोलती हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवरपाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे विपक्ष के साथियों को बताना चाहूंगा कि इनके 10 साल के कार्यकाल में रेप के केसिज में 136 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में बचियां कम्पलेंट कर रही हैं। मुख्यमंत्री जी उनके लोकल विधायक भी हैं लेकिन इसके बावजूद भी बेटियों को हरियाणा विधान सभा की समिति का संरक्षण लेना पड़ रहा है।

श्री राजेश नागर (तिगांव): उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 75वें वर्ष में आजादी के अमृतकाल में विधान सभा का यह पहला बजट सत्र है। अभिभाषण में सभी कल्याणकारी योजनाओं का ध्यान रखा गया है। जैसे अंत्योदय, शिक्षा, रोजगार, परिवार पहचान पत्र, बिजली, कृषि किसान कल्याण, खाद्य एवं आपूर्ति, सड़क परिवहन, उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायत, महिला सुरक्षा, पशुपालन, सिंचाई एवं जल संरक्षण, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण, सैनिक और पूर्व सैनिकों का कल्याण पर बहुत फोकस किया गया है। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक समस्या है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ग्रेटर फरीदाबाद बना है और उसमें प्राइवेट बिल्डर्स ने प्लाट, फ्लैट और फ्लोर बनाए हैं। ज्यादातर सर्विस क्लास और लोवर मिडल क्लास ने ये प्लाट, फ्लैट और फ्लोर खरीदे हैं। बिल्डर्स ने उनसे जो वायदे किये थे वे बिल्डर्स के द्वारा पूरे नहीं किये गये हैं जिसके कारण उनको बहुत कठिनाइयां हो रही हैं और सभी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कई बिल्डर्स ने ओ.सी. भी नहीं दिया है। उनमें से ज्यादातर लोगों ने लोन लेकर ये सभी प्लाट, फ्लैट

और फ्लोर लिए हैं। इन सभी बिल्डर्स ने मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवाई हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन सभी बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये तथा एक समिति बनाई जाये जो उसकी जांच कर सके। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई कॉलोनियां भी आती हैं जिनमें से कई कॉलोनियों में सीवरेज और पानी की पाइप लाइन डाली जानी हैं तथा कई कॉलोनियों में गलियों में खड़ंजे और नाली का काम भी करवाया जाये। वहां पर कोई पार्क नहीं है इसलिए वहां पर एक टाउन पार्क भी बनवाया जाये। वहां पर लाखों लोग रहते हैं इसलिए वहां पर एक कॉलेज भी बनवाया जाये। हमारे वहां एक अशोका इंक्लेव सैक्टर है जहां पर सीवरेज लाईन छोटी और पुरानी हो चुकी है। इस लाईन को बदलवाकर नई सीवरेज लाईन डलवाई जाए। उसी तरह से हमारे यहां पी.डब्ल्यू.डी. की कई रोड हैं जिनमें ज्यादातर की हालत ठीक नहीं है। उनमें एक बल्लबगढ़ से तिगांव–मंझावली रोड है जहां से प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। उसको भी ठीक करवाया जाए। ऐसे ही तिगांव से शाहबाद–जसाना रोड की हालत भी ठीक नहीं है उसको भी जल्दी बनवाया जाए। बाकी मेरे और जो काम हैं उनको मैं लिख कर दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आप लिखकर दे दीजिए।

राव चिरंजीव (रेवाड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का विजन होता है। राज्यपाल के अभिभाषण को देखने से महसूस हो रहा है मानो हरियाणा में राम राज्य चल रहा हो लेकिन जो हालात हैं वे उससे बिल्कुल विपरीत हैं। आज हरियाणा बेरोजगारी के अन्दर नम्बर–1 है। अपराध के मामलों में नम्बर–1 है। महिला उत्पीड़न में नम्बर–1 है। बड़े शर्म की बात है कि सरकार का नारा है 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' लेकिन सरकार के एक मंत्री के ऊपर इतने गम्भीर आरोप लगे हुए हैं उसके बावजूद भी उन्होंने अब तक

अपना इस्तीफा नहीं दिया है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की करनी और कथनी में कितना अन्तर है, वह हम सभी के सामने है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आज इस प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से पीड़ित है। उसमें चाहे किसान हो, मजदूर हो, जवान हो। आज से पहले हमने कभी नहीं देखा कि किसी सरकार के अन्दर हर वर्ग धरने पर बैठा हुआ हो। हम लोगों ने पिछले दिनों में भी देखा है कि हमारे जो कर्मचारी ओ.पी.एस. व अपनी वाजिब मांगों के लिए शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। उनके ऊपर जिस तरह से इतनी बर्बरता से लाठियां बरसाई गई उसकी मैं कड़े शब्दों के अन्दर निन्दा करता हूं और वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि हमारे प्रदेश के अन्दर अगर कोई शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखना चाहता है तो उसके ऊपर ऐसी बर्बरता की जाए। पिछले दिनों में हम सभी लोगों ने देखा ही था कि किस तरह से किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। अभी हमने देखा कि ई–टैंडरिंग के नाम के ऊपर तानाशाही सरकार सरपंचों के ऊपर दबाव डालकर उनकी शक्तियों को लेने का काम कर रही है। आपको पता ही है कि हमारे पंचायती राज सिस्टम में अगर कोई मजबूत स्तम्भ है तो वह सरपंच है और सरकार जो उनकी शक्तियों को कम करने का काम कर रही है उसको बंद करना चाहिए। यह सरकार एक ऐसी सरकार है जो हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पानी मिलता है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे रेवाड़ी शहर के अन्दर एक दिन छोड़कर एक दिन पानी मिलता है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर एक बहुत बड़ा झूठ साफ तौर पर नजर आता है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा गया है कि आज पूरे हरियाणा के अन्दर 24 घंटे बिजली मिलती है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारा कोई भी गांव व शहर ऐसा नहीं होगा जहां पर 24 घंटे बिजली दी जा रही हो। इस सरकार ने यह कहा है कि

5 जी सर्विस दी जाएगी लेकिन आज हरियाणा में 2 जी और 3 जी तो पूरी तरह से काम करता नहीं है और सरकार 5 जी सर्विस देने की बात करती है। (विघ्न) सरकार ने बस स्टैंड बनाने की बात की है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितने बस स्टैंड बनाए जाएंगे क्योंकि मैंने भी मंत्री जी के सामने बार–बार रेवाड़ी और धारूहेड़ा में बस स्टैंड बनाने की बात रखते हुए चार साल हो गये हैं। हर बार मैं इन बस स्टैंड को बनाने की आवाज उठाता हूं लेकिन आज तक उन बस स्टैंड के ऊपर एक ईंट भी नहीं लग पाई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि रेवाड़ी की जनता सरकार की तरफ देख रही है कि सरकार कब उन बस स्टैंड का काम शुरू करवाएंगे। उसके अलावा धारूहेड़ा के अन्दर आज भी गन्दा पानी आता है जबकि एन्वायरमैंट के ऊपर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इतनी बड़ी–बड़ी बात कही गई है लेकिन रेवाड़ी शहर के लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप लोग चंडीगढ़ से दिल्ली जायें जो रोडों पर जाम के अलावा कुछ भी नजर नहीं आयेगा। आज रोडों की हालत इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत ही दयनीय हालत में पहुंच गई है। शायद ही किसी और प्रदेश में रोडों की ऐसी हालत हो। मुझे लगता है कि सरकार को धरातल पर काम करने की जरूरत है। आज प्रदेश में जीरो इक्विल टू जीरो वाली स्थिति हो गई है।

श्री हरविन्द्र कल्याणः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को रोड़ों शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि सड़क शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हमारा रोड़ समाज तो ठीक ठाक है।

श्री उपाध्यक्षः चिरंजीव जी, माननीय सदस्य कह रह रहे हैं कि रोड़ों शब्द के स्थान पर सड़क शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए।

राव चिंरजीवः उपाध्यक्ष महोदय, हिंदी में सड़कों को रोड ही कहा जाता है अतः या तो इसको बदल दीजिए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे ठीक है, मैं सड़क शब्द का प्रयोग कर लेता हूँ। आज प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल है। सरकार यह तो मानती होगी कि प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल है। आज हरियाणा प्रदेश का कोई भी ऐसा विधान सभा क्षेत्र नहीं होगा जहां पर सड़कों की हालत खराब न हो। अतः सरकार को सड़कों की हालत सुधारने की दिशा में काम करने की जरूरत है। इसके अलावा जो अंत्योदय की स्कीम है, इसके संदर्भ में भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत बड़ी–बड़ी बातें कही गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ व्यापारियों की सरकार है। अडानी और अंबानी को यह सरकार अमीर करती जा रही है और गरीबों को और गरीब करती जा रही है। आज शायद ही कोई ऐसा विधान सभा क्षेत्र होगा जहां पर बुजुर्गों की बुढ़ापा पैंशन न काटी गई हो, बी.पी.एल. के कार्ड न काटे गए हों। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर शायद आखिरी सदस्य ही बोलने वाला रह गया हूँ, अतः मुझे मेरी बात पूरी रखने दी जाये। राज्यपाल अभिभाषण में एम्स की बात कही गई है। पिछले 8 साल से हम यह सुनते आ रहे हैं कि एम्स बनेगा, एम्स बनेगा और एम्स बनेगा। अभी भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यही लाइन फिर से लिखकर आई है कि एम्स बनेगा। आखिरकार यह एम्स कब बनेगा ? राम मंदिर के लिए भी सरकार द्वारा इस तरह की बात की जाती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह बताना चाहिए कि क्या राम मंदिर बना के नहीं बना ?

श्री उपाध्यक्षः चिरंजीव जी, राम मंदिर तो अब बन गया है।

राव चिरंजीवः उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो राम मंदिर भी नहीं बना है केवल सरकार बातें ही कर रही है।

श्री महीपाल ढांडा: उपाध्यक्ष महोदय, चिरंजीव जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है और जल्द ही साक्षात स्वरूप में हम सबके सामने भी होगा।

श्री उपाध्यक्ष: चिरंजीव जी, अब आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है। अतः आप प्लीज बैठिए।

राव चिरंजीव: उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने दे रहे हैं तो मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को इस बात के साथ समाप्त करूंगा कि 'सब झूठ है यहां–बस यही सच है'। मेरे कहने का यही भाव है कि सदन में जो कुछ पढ़ा गया है, यह केवल झूठ का ही पुलिंदा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिन्द ।

श्री बलराज कुंडू (महम): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने कल लिए जो मेरी सुध–बुध ली है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: कुडूं जी, मैंने तो आपका नाम आते ही आपको बुलवा दिया है। जब आपने नाम ही नहीं दिया था तो मैं क्या करता।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, यही तो दुर्भाग्य की बात है। मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन न मेरा कोई सवाल लगाया गया और न ही मुझे बोलने का समय दिया गया। मेरा नाम कहां से आयेगा क्योंकि मैं महम का विधायक थोड़े ही हूँ मैं तो धक्के से यहां पर आया हूँ ? उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का जो कल अभिभाषण पढ़ा गया और इसमें सरकार की उपलब्धियों और तारीफों का जो पुलिंदा पढ़कर सुनाया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि हरियाणा प्रदेश केवल मात्र हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे खुशहाल और बेहतर प्रदेश बन गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रदेश की 680 किलोमीटर यात्रा करके आया हूँ मैं इस प्रदेश के जर्रे–जर्रे को देखकर आया हूँ। (विघ्न)

परिवहन मंत्री (श्री मूल चंद शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, गुरूग्राम का नाम देश और विदेश में अग्रणीय है। यह बात भी माननीय सदस्य को ध्यान रखनी चाहिए।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, बिल्कुल प्रसिद्ध है लेकिन जो मैं अपनी यात्रा के दौरान देखकर आया हूँ, उसके बारे में सदन में बताना ही पड़ेगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सुशासन का प्वायंट है। परसों मेरे प्रदेश के कर्मचारी जो सुशासन चलाने का काम करते हैं, सुशासन में अहम रोल निभाने का काम करते हैं, उन पर वाटर कैनन और लाठियां बांझने का काम किया गया। उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ने का काम किया गया, इससे बढ़िया सुशासन तो और कही हो ही नहीं सकता ? उपाध्यक्ष महोदय, पूरे वर्ल्ड ने यह मंजर देखा है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सुशासन और सबका साथ– सबका विकास की बात कही गई लेकिन जिस प्रकार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए थी, उसकी बजाय सदन में माननीय सदस्य अपनी मांगे रखने का काम कर रहे हैं। यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर किस प्रकार की चर्चा है ? आखिर ऐसा करके क्या करने की कोशिश की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी की सीरियसनेस इस बात से भी झलकती है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन में चर्चा हो रही है और सदन में न तो मुख्यमंत्री जी और न ही उप–मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। ऐसा करके एक तरह से सदन का मजाक बनाने का ही काम किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। आज मेरा हरियाणा प्रदेश लहू–लुहान हो गया है। मेरा युवा बेरोजगार है और बेराजगारी की वजह से आत्म हत्या करने को विवश हो रहा है और कालेजों में अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए भी मजबूर हो रहा है। सी.ई.टी. के नाम पर बेरोजगारी को हटाकर रोजगार देने की बात की जा रही है। चार साल में एक बार सी.ई.टी. का पेपर लेकर इतिश्री समझ ली गई है। क्या यही सरकार की उपलब्धि है ? प्रदेश में किया कुछ भी नहीं गया है और

बातें बड़ी–बड़ी की जा रही हैं। आज प्रदेश में 40 लाख बेरोजगार युवाओं की फोज खड़ी हो गई है लेकिन यह सरकार प्रदेश के युवाओं की चिंता नहीं कर रही है। सदन में जिस प्रकार से एक–दूसरे पर लांछन और शेरो–शायरी का खेल, खेला जा रहा है और जिसको मैं सुबह से देख रहा हूँ निश्चित रूप से यह इस प्रदेश का ही दुर्भाग्य है। हरियाणा प्रदेश लहू–लुहान हो चुका है, बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नम्बर–1 है और सदन में शेरो–शायरी का खेल खेला जा रहा है। आज हरियाणा प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे अनसेफ स्टेट में से एक हो गया है। बड़े–बड़े गैंगस्टर्स, बेरोजगार युवाओं की बेरोजगारी का फायदा उठाकर उन्हें गैंग्स्टर्स बना रहे हैं और नशे के झंझाल में भी उन्हें झोंकने का काम कर रहे हैं लेकिन किसी को भी इनकी चिंता नहीं है। सदन में बड़ी–बडी बातें करके तारीफों का पुलिंदा बनाकर जो बातें कही जा रही है, इनको देखकर मन में सवाल उठता है कि हरियाणा प्रदेश में यह क्या हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की कुछ गरिमा भी होती है लेकिन बावजूद इसके, इस सबको दरकिनार करते हुए सबने चुप्पी साधी हुई है। जिस जनता की वोट लेकर हम इस सदन में आये हैं, हमें उनकी आवाज उठाने का काम करना चाहिए लेकिन जिस तरह की चुप्पी साधी गई है, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। जिस युवा ने जिस गरीब ने अपना वोट देकर हमें यहां भेजने का काम किया है, उसके बारे में सदन में कुछ कहा ही नहीं जा रहा है बल्कि मुख्यमंत्री महोदय को खुश करने के लिए बडी–बड़ी लाइनें पढ़कर सुनाई जा रही हैं जिन्हें सुन–सुनकर सुबह से कान पक गए हैं। आखिरकार यह क्या हो रहा है। कौन से ऐसे काम हुए हैं जिनकी तारीफों का पुलिंदा सदन में बयान किया जा रहा है। आज प्रदेश बेरोजगारी के मामले में नम्बर–1 पर पहुंच चुका है। आज अपराध के मामले में प्रदेश नम्बर –1 पर पहुंच चुका है। आज मेरे कर्मचारियों के ऊपर लाठियां बरस रही हैं। आफिशियली, गरीब के राशन कार्ड

कट रहे हैं। आज बुजुर्गों की पैंशन काटी जा रही है और कह रहे हैं कि प्रदेश उंचाइयों पर जा रहा है ? क्या प्रदेश में रोडों से ही सारी खुशहाली हो गई है ? प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने से ही खुशहाली होगी। आज गरीब की हालत बद से बद्तर हो गई है लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता और सदन का मजाक बनाने का काम किया जा रहा है। मैं हरिवन्द्र कल्याण जी से माफी चाहूंगा कि मैंने रोडों शब्द का प्रयोग किया लेकिन यह शब्द उनके लिए नहीं है। अतः वे इस शब्द को अपने उपर मत लें परन्तु चूंकि यह शब्द बना हुआ है ऐसी हालत में हम और करें भी तो क्या करें। (हंसी) उपाध्यक्ष महोदय, यह समय हसने का नहीं है बल्कि सीरियस होने का समय है और जिम्मेवारी के साथ काम करने का समय है। आज कितने बड़े झूठ बोले जा रहे हैं कि सबको आवास दे दिए गए। मेरे साथ चलिए मैं लेकर चलता हूँ। जिस भी मंत्री के एरिया में कहो मैं लेकर चलूंगा और असल हालत दिखाने का काम करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो वीडियो तक बनाकर लाया हूँ कि इस सरकार ने कितने आवास दिए हैं। अतः सरकार को झूठ का ड्रामा बंद कर देना चाहिए। कब तक झूठ के सहारे देश को बेवकूफ बनाने का काम किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नांगल चौधरी से अपनी पैदल यात्रा शुरू की थी। वहां के मेरे माननीय साथी ने बताया था कि नांगल चौधरी, नारनौल, महेन्द्रगढ व दादरी तक सरसों की फसल पाले की वजह से बर्बाद हो गई है जिसके लिए हमारे किसान भाई डी.सी. आफिस के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। सदन में किसान कल्याण की न जाने कितनी ही बातें कही जा रही हैं लेकिन हमारा किसान आज जल भराव की समस्या से परेशान है जिसकी वजह से हजारों–हजार एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। पिछले सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोकि अब हाउस में नहीं हैं, ने कहा था 7000 रूपये प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में दिए जायेंगे लेकिन आज तक कोई गिरदावरी तक नहीं हुई है

और पांच पैसे भी मुआवजे के रूप में देने का काम नहीं किया गया है। आज हमारे किसान गन्ने के भाव के लिए धरने पर बैठा है। आलू प्रति एकड़ में 12 से 15 हजार रूपये का हो रहा है लेकिन इस पर जो खर्च है, वह 40 हजार रूपये पर एकड़ आ रहा है जबकि दूसरी और माननीय मुख्यमंत्री जी किसान की आय को 45 परसेंट काउंट करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। सदन में मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन मुद्दों पर चर्चा न करके केवल शेरो–शायरी करके इस सदन का मजाक बनाने का काम किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्षः कुंडू जी, आप दूसरो को बात नहीं कह सकते, आप केवल अपनी ही बात करें।

श्री बलराज कुंडूः उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश बेरोजगारी में नम्बर–1 पर आ गया है। शिक्षा और रोजगार के बारे में राज्यपाल अभिभाषण में बड़ी–बड़ी बातें कही जा रही हैं। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लेट बोलने का समय मिला है तो मैं पूरी बात करके ही रूकूंगा।

श्री उपाध्यक्षः कुंडू जी, आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है। आप चाहें तो बाकी बातें लिखकर दे सकते हैं।

श्री बलराज कुंडूः उपाध्यक्ष महोदय, आप किसी सदस्य को तो 10–10 मिनट का समय बोलने के लिए दे देते हैं। मैंने बोलने के टाइम की अपने मोबाइल से फोटो भी उतार रखी है। आज मेरे प्रदेश का युवा मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, उसने पढ़ना–लिखना बंद कर दिया है लेकिन सरकार को इन युवाओं की कोई चिंता नहीं है जबकि सरकार को इसके उपर चिंतन करना होगा। पुलिस में ज्वायनिंग के लिए बच्चे धक्के खाते हुए फिर रहे हैं लेकिन उनकी ज्वायनिंग नहीं हो पा रही है और सरकार रोजगार देने की बात कर रही है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है,

कानून व्यवस्था के भी प्रदेश में ठाठ हो गए हैं ? आये दिन सरे आम मर्डर और अपराध हो रहे है और इस प्रकार अपराध के क्षेत्र में भी सबसे अनसेफ राज्यों की श्रेणी में मेरा हरियाणा प्रदेश एक नम्बर पर आ गया है। सरकार खेलो इंडिया की बात करती है। खेलों के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश की स्थिति एक नम्बर पर हुआ करती थी जोकि अब खिसककर नम्बर–तीन के पायदान पर पहुंच गई है। हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने खेलना छोड़ दिया है। हरियाणा प्रदेश का जो खिलाड़ी देश का नाम रोशन करने का जज्बा रखता था, आज इस सरकार ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः कुडू जी, आप बैठिए अब आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जायेगी।

श्री बलराज कूंडू: उपाध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री उपाध्यक्षः घनश्याम दास गर्ग जी अब आप अपनी बात रखें।

श्री घनश्याम दास अरोड़ा (यमुनानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया कि सरकार ने अमृत काल में किस प्रकार से समाज के हित में निर्णय लिये थे और आगे आने वाले समय में सरकार जिन विषयों को महत्वपूर्ण मानकर काम करना चाहती है महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उन विषयों को टच किया है । हमारे देश में वसुधैव कुटुम्बकम की बात की जाती है । जब तुर्किये में भूकम्प आया तो भारत सरकार ने वहां पर भूकम्प पीड़ितों के लिए सहायता भेजी । जब विश्व में कोविड महामारी का प्रकोप था तो हम वैक्सीन बनाने में सफल हो गये

*** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

थे । हमने 2–2 वैक्सीन बनाई और दुनिया के अनेक देशों को वैक्सीन भेजकर कोविड रोगियों की सेवा और मदद की । इसी प्रकार हरियाणा में भाजपा की सरकार श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में इस कार्य में लगी हुई है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है और ई–सिस्टम के माध्यम से सेवाओं में कैसे सुधार किया जा सकता है तथा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सभी का डाटा एकत्र करके उनके घर पर कैसे सुविधा प्रदान की जा सकती है । सरकार ने इस प्रकार के निर्णय लेकर निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास किये हैं । इन प्रयासों में सरकार को निश्चित रूप से सफलता मिली है । मेरे कुछ साथियों ने यह बात उठाई कि बी.पी.एल. कार्ड्स कट रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसे स्पष्ट किया है कि कुछ कार्ड कटे हैं लेकिन उससे ज्यादा कार्ड बने हैं । जो व्यक्ति वास्तव में हकदार है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है केवल उसी का राशन कार्ड बने और पिछले 20 वर्षों में जो व्यक्ति बी.पी.एल. से ऊपर उठ चुका है उसका राशन कार्ड परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कट जाए यह परिवार पहचान पत्र की उपयोगिता का एक जीवन्त उदाहरण है । सरकार उन लोगों की मदद करना चाहती है जो आज सालाना 1.80 लाख रुपये से कम कमाते हैं । सरकार उन लोगों को 'चिरायु कार्ड' दे रही है और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवा रही है । सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है । सरकार एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम आय वाले लोगों की आय को बढ़ाने और सभी के लिए आवास की व्यवस्था की चिंता कर रही है । हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे देश का 1.54 परसैंट है परंतु हम केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार में सहयोग करने में पूरे देश में दूसरे नम्बर पर हैं । यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहां का किसान कितना मेहनती है और उसको सरकार किस प्रकार हर सुविधा उपलब्ध करवाती है ताकि वह अपनी आय को दोगुनी करने की ओर आगे बढ़ सके । हमारा प्रदेश भावान्तर योजना लागू करने वाला पहला

प्रदेश है । हमारे यहां पर 14 जीन्स की उपज होती है और हम उनको एम.एस.पी. पर खरीद रहे हैं । इसमें हम देश में पहले स्थान पर हैं । यह प्रमाण है कि हम किसान की चिन्ता करते हैं । हम गांवों की चिंता करते हैं, इसलिए 5,682 गांवों में 24 घण्टे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है । यह बिजली निरंतर मिलती रहे इसके लिए हम यमुनानगर में 5,362 करोड़ रुपये की लागत से सुपर क्रीटिकल एक्सटैंशन यूनिट की स्थापना कर रहे हैं । राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रैस–वे बनाये जा रहे हैं । यह इस बात का प्रमाण है कि हम लोगों को अच्छी यातायात सुविधा प्रदान करने की चिंता करते हैं । हम पूरे देश की आबादी का केवल 2 प्रतिशत हैं लेकिन जी.एस.टी. संग्रह में हमारा योगदान 6 प्रतिशत है । यह इस बात का प्रमाण है कि यहां का उद्यमी अपने प्रदेश के विकास में कितना सहायक है । हमारे प्रदेश को राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार, 2022 से सम्मानित किया गया है । यह अपने आप में प्रदेश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । ग्राम दर्शन पोर्टल और नगर दर्शन पोर्टल के माध्यम से हर समस्या का समाधान हो, सरकार इस बात का प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है ताकि अधिक से अधिक डॉक्टर्ज रोगियों की सेवा के लिए उपलब्ध हो सकें। हर बीमार व्यक्ति मेडिकल सुविधा का लाभ उठा सकें, हम इसकी चिंता कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सभासदों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि प्राकृतिक खेती की और कैसे आगे बढ सकते हैं, वे उसकी चिंता करते हैं। पिछले बजट में भी और इस बार के अभिभाषण में भी प्राकृतिक खेती की ओर विशेष ध्यान देने की योजना बनायी गयी है। आज की वर्तमान स्थिति यह है कि हम खेतों में जहर बो रहे हैं, जहर काट रहे हैं और जहर खा रहे हैं। यदि हम प्राकृतिक खेती की और अग्रसर होते हैं तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। सदन में हमारे माननीय सभासद बैठे हुए हैं मैं आपके

माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपनी विधान सभा में एक गांव ऐसा चुन लें जहां पर वे प्राकृतिक खेती की चर्चा कर सकें, जैविक खेती की चर्चा कर सकें। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की मेरा पानी, मेरी विरासत, योजना एक ड्रीम प्रोजैक्ट है। ऑर्गेनिक खेती में पानी की भी कम आवश्यकता होती है यह प्रयोग मैंने स्वयं अपने फार्म हाउस में करके देखा है। इसलिए हम इसको चाहे जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती या जो भी नाम देना चाहें, वह नाम दे दें। इसके लिए सबसे पहले आधारभूत आवश्यकता खेत का होना है, उसके बाद देसी गाय का होना है और उसके बाद नीम का होना है क्योंकि नीम का प्रयोग करके, नीमअस्त्र को फिर नीम सहित चार अन्य चीजों का प्रयोग करके बनाया जाता है। अग्निअस्त्र को फिर 12 चीजों का प्रयोग करके बनाया जाता है। जोकि हमारे खेत में पैदा होती हैं। ये खेत के किनारे पर भी लगी हुई मिल जाएंगी या सड़कों के किनारे लगी हुई मिल जाएंगी। जो जैविक खेती/प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हैं, वे यह कहते हैं कि 12 ऐसी चीजें(उसमें 16 नाम हैं।) जिनको गाय न खाये। उनका प्रयोग करके ब्रह्मअस्त्र अपने खेत/घर में बनाकर, जो कड़े से कड़ा कीट किसी दवाई से नहीं मरता है उसको भी नियंत्रण में कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्षः अरोड़ा साहब, आपके बोलने का टाइम पूरा हो चुका है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री घनश्याम दास अरोड़ाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में ही अपनी बात पूरी कर लूंगा। यह सबके मतलब की बात है। इसलिए आप और हम सभी मिलकर प्राकृतिक खेती की और बढने का प्रयास करें और बढाने का प्रयास करें। इसके लिए कठिनाई कहां पर आती है? इसमें सबसे पहला काम तो इसको पैदा करना ही कठिन है। इसमें पहले 3 साल तक ऊपज कम होती है। फिर ऊपज सामान्य के आसपास आती है। फिर उसको बेचने के लिए मार्केट उपलब्ध न होने और कोई भी सर्टिफाईड एजेंसी

न होने के कारण किसान की विश्वसनीयता बन नहीं पाती है। लेकिन जिन किसानों ने इसमें अपनी विश्वसनीयता बना ली है, वे किसान रेगुलर/कैमिकल वाली खेती से अधिक लाभ प्राकृतिक खेती के माध्यम से उठा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यगण इसको ऑन करें/अडॉप्ट करें और इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती के ड्रीम प्रोजैक्ट को पूरा कर सकते हैं। उसमें सफल हो सकते हैं और उससे हमें कैंसर जैसे भयानक रोगों से छुटकारा मिल सकता है। हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। यह भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हम निरोग होंगे और स्वस्थ होंगे तो हम देश की अधिक सेवा कर सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

डॉ0 बिशन लाल सैनी (रादौर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। कल महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण को लगभग डेढ घंटे पढ़ा और पिछले साल भी पढ़ा था। मैंने घर पर जाकर जब दोनों किताबों को फिर से पढ़ा तो उसमें 65 प्रतिशत बातें तो ऐसी मिली जोकि पिछली बार के अभिभाषण में लिखी हुई थी और वही बातें अबकी बार भी लिखी हुई हैं। इसके अतिरिक्त 35 प्रतिशत बातें ऐसी हैं जोकि लगभग झूठी हैं। हमारे राज्यपाल महोदय जी एक बहुत अच्छे और बढ़िया आदमी हैं और उन्होंने इस अभिभाषण को पढ़ा है इन लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय को भी नहीं बख्शा क्योंकि यह किताब पढ़ाकर उनको भी पाप का भागीदार बना दिया गया। इस किताब के अंदर ऐसी–ऐसी बातें लिख रखी हैं जैसे इसमें पोर्टल का जिक्र किया गया है। दो पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाये थे और सभी को चिट्ठियां भी लिखी गई थी कि एक ग्राम दर्शन पोर्टल और दूसरा नगर दर्शन पोर्टल सरकार ने बनाये हैं। इन पोर्टल के माध्यम से गांवों के विकास कार्यों के लिए जो सुझाव या मांग लिखकर

भेजी जायेगी, वह सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आयेंगी, यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी और उन्होंने यह भी कहा था कि ये सुझाव या मांग उनके पास से होकर सीधा संबंधित विभागों के पास भेजी जायेगी। यह बात भी बहुत बढिया है कि गरीब आदमी को कहीं और चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उसको किसी काम के लिए परेशान होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें उन्होंने यह भी कहा था कि आप जो काम के बारे में लिखकर भेजेंगे तो वह आपका काम हो जायेगा लेकिन देखने में यह आया कि मैंने लगभग डेढ़ साल से 366 काम पोर्टल पर डाले थे और मैंने इसमें कुछ सुझाव भी दिये थे और कुछ मांगे भी लिखकर दी थी। मेरे 366 कामों में से एक भी काम नहीं हो पाया और न ही मेरे कामों का किसी संबंधित विभाग ने कोई ऐस्टीमेट बनाया और न ही किसी ने कोई काम करने की जरूरत समझी। मैं पूछना चाहूंगा कि फिर इन पोर्टल्ज को बनाने का क्या लाभ हुआ? हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल जी बैठे हैं, मेरा उनसे अनुरोध भी है क्योंकि मैं ये सारे काम इनको लिखकर भी भेज दूंगा। मुझे कम से कम यह बात जरूर लिखकर भेज देना कि कौन–कौन से काम लगा दिये गये हैं और कौन–कौन से काम कम्पलीट हो गये हैं और कौन–कौन से काम कम्पलीट नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार से पिछली बार 5–5 करोड़ रुपये देने की बात भी कही थी। हमने इसके लिए बकायदा तौर पर ऐस्टीमेट भी भेज दिये थे लेकिन उनको भी चंडीगढ़ से वापिस भेज दिया गया। उसमें क्या लिखा हुआ था कि आपने इसमें जोहड़ों से संबंधित वर्क्स नहीं डालने हैं चाहे वह खुदाई का काम हो या सफाई आदि का काम हो। इन वर्क्स के अलावा दूसरे वर्क्स डालो तभी आपके वर्क्स किये जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा कि हमने इनके लिए पौंड अथॉरिटी बना दी और पौंड अथॉरिटी द्वारा ही जोहड़ों की सफाई और खुदाई का काम किया जायेगा। यह बात भी बहुत अच्छी है। हमने सोचा कि इस प्रकार से तो सारी प्रॉब्लम ही दूर हो

जायेगी लेकिन डेढ साल से इस पौंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा ने भी मौके पर कोई काम करके नहीं दिखाया है।

श्री कंवर पाल : सैनी जी, आपके हल्के में 10 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की अमाउंट आ गई है। वह पैसा भी डिवैल्पमैंट के लिए है। उसके बारे में भी तो सदन को बता दीजिए।

डॉ. बिशन लाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, हमने कभी मना ही नहीं किया कि हमारे पास पैसे नहीं आये हैं। मैंने इस बात को मना नहीं किया है लेकिन पैसे किसी काम में लगाये नहीं गये। मैं पौंड अथॉरिटी की बात कर रहा हूं?

श्री कंवर पाल : सैनी जी, यह पैसा भी डिवैल्पमैंट के लिए है।

डॉ. बिशन लाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात माननीय मंत्री जी की ठीक है। 5 करोड़ रुपये की अमाउंट में से कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट पैंडिंग रह रही होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह कहना है कि यह चीज भी देख लेना कि जो टैंडर हो रखे हैं उन टेंडरों के माध्यम से क्या–क्या काम हुए हैं? इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि 23 फरवरी 2021 से पंचायतें भंग हो गई थी और सरपंचों से चार्ज वापिस ले लिये गये थे उसके बाद पंचायतों के इलैक्शन नहीं हुए और जब पौने दो साल के बाद इलैक्शन हुए और सरपंचों के पास चार्ज गया। मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायत मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस दौरान पंचायतें भंग होने के बाद और नये सरपंचों को चार्ज देने से पहले, पंचायतों के पास कितना पैसा बैलेंस था? सरपंचों का कहना है कि हमें तो जीरों बैलेंस ही मिला है, सारा पैसा पता नहीं कहां चला गया, किसने खर्च कर दिया? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कितना पैसा उनके पास गया और कितना पैसा पंचायत के पास था? यह सारा पैसा कहां चला गया? यह मेरा सवाल है। सरकार ने अभी एक ऑर्डर भी निकाला है।

श्री उपाध्यक्षः बिशन लाल जी, आप अपना बाकी मैटर लिखित में दे दीजिए वह रिकॉर्ड में आ जाएगा।

डॉ. बिशन लाल सैनीः ये जो डिपो वाले हैं, जो राशन डिपो का काम करते हैं, मंत्री जी, कृपा यह बताएं कि इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा दिया है ? मंत्री जी, इन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। फिर आपने इनकी उम्र 60 वर्ष कर दी है, क्या ये कोई सरकारी नौकरी में हैं ? ये तो शॉप कीपर हैं। ये इलैक्शन भी नहीं लड़ सकते।

श्री उपाध्यक्षः सैनी जी, आप आपनी बात मंत्री जी को सीधा एड्रेस न करके चेयर को एड्रेस करके कहें।

डॉ. बिशन लाल सैनीः ठीक है उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं अपनी बात माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कहने का काम करूंगा।(घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहूंगा इन्होंने इनकी उम्र 60 वर्ष क्यों कर दी है और अब ये चुनाव भी नहीं लड़ सकते। उपाध्यक्ष महोदय, कोविड–19 के दौरान जिन परिवारों के सदस्यों की मृत्यु हुई थी इन्होंने कोरोना काल में उनकी सेवा की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री लीला राम (कैथल): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसलिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां आकर के सदन के गौरव को बढ़ाने का काम किया और 1 घंटे से भी ज्यादा के समय में विस्तार से हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही इस सरकार के बारे में इसमें चाहे वह किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो अथवा शिक्षा नीति हो, उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, इस सबका उल्लेख यहां पर करने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने सबसे बढ़िया काम इन लाखों बेरोजगार के लिए किया है जो

कहीं न कहीं ठेके पर लगे हुए थे और उनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था उन्हें ठेकेदारी प्रथा से बाहर निकाल करके उनका उद्धार करने का काम किया है, इसमें लगभग 1.6 लाख के लगभग नौजवान हैं, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय महामहिम जी ने यहां पर जिक्र किया कि हरियाणा सरकार ने यहां पीने के पानी के लिए पूरे प्रदेश में हर घर में नल और उसमें जल की व्यवस्था की और यहां पर विपक्ष के साथी उस पर बहुत बोल रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार की भी सरकारें रही हैं कि जब कभी चुनाव आता था तो उस समय सड़ी–गली प्लास्टिक की 100–150 रुपये वाली टंकी गरीब लोगों में बांटकर वाह–वाही लूटने का काम करते थे। जबकि न कहीं पानी होता था न नल होता था और न कहीं जल की व्यवस्था होती थी।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः प्लीज आप सभी बैठ जाएं, शोर न करें।

श्री लीला रामः उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई साथी सड़कों के बारे में बोल रहे थे। इनमें से श्री बिशन लाल सैनी जी जो मेरे पुरानी साथी भी हैं। आज इनको एक आदत पढ़ चुकी है कि पुरानी किताब लेकर के यहां पढ़ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, असर भी होता है क्योंकि इसी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी हैं जो राजस्थान में पुराना बजट पढ़ रहे थे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः मलिक साहब, प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री लीला राम : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा सड़कों के बारे में जिक्र किया गया है। कुलदीप वत्स जी यहां पर बैठकर कह रहे थे कि कोई एक काम तो बता दिया जाये जो नरेन्द्र मोदी जी ने किया हो। इस पर मैंने उनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक नरेन्द्र मोदी जी पर किताब नहीं बल्कि एक ग्रंथ लिख सकता है। मेरा उनको यही कहना है कि वे पढ़े लिखे

साथी हैं इसलिए उनको अपनढ़ जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। विपक्ष के साथियों को कन्याकुमारी से चलकर श्रीनगर तक के हाईवेज को देखना चाहिए। हमने उनको यह भी कहा कि पिछले 70 साल में सड़कें बनी हैं लेकिन पिछले 8 साल के दौरान जो सड़कें देश में बनी हैं उनका पूरे विश्व में रिकार्ड है। मंत्री जी ने कहा कि यह बात पूरी तरह से सच है। बलराज कुण्डु जी ने भी माना कि यह बात पूरी तरह से सही है। उपाध्यक्ष महोदय हमारी सब्जैक्ट कमेटी के चेयरपर्सन श्री दीपक मंगला जी के नेतृत्व में हमारी सब्जैक्ट कमेटी का टूर अयोध्या गया था। मैं कुलदीप वत्स जी को यह बताना चाहता हूं कि 8 साल पहले हिन्दुस्तान के अंदर 12 बोर की बंदूक और कानपुर वाले रिवॉल्वर के सिवाये कुछ भी नहीं बनता था। आज आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान के अंदर 70–75 देशों को तोप, ब्रह्मोस, तेजस और अर्जुन टैंक इत्यादि की आपूर्ति कर रहा है। इसी प्रकार से हिन्दुस्तान द्वारा 110 देशों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन भिजवाई गई थी। वैसे ही आज हिन्दुस्तान 75 देशों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इसको कहते हैं वित्तीय तरक्की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे आगे यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में नये–नये आयाम स्थापित किये हैं। मैं कह रहा था पिछले दिनों यू.पी. में हमारी सब्जैक्ट कमेटी का टूर गया था हम वहां पर जिस भी शहर में जाते वहां पर जी–20 की धूम थी। हम आगरा गये तो वहां पर जी–20 की धूम थी। लखनऊ गये तो वहां पर भी जी–20 की धूम थी। वापिस आये तो ग्रुरूग्राम में भी जी–20 की धूम थी। मेरा कुलदीप जी को यह कहना है कि उनको उन सड़कों पर जाकर देखना चाहिए कहीं पर आगरा एक्सप्रैस–वे था, कहीं पर लखनऊ एक्सप्रैस–वे था, कहीं पूर्वांचल एक्सप्रैस–वे आ जाता था और कहीं पर बुंदेलखण्ड एक्सप्रैस–वे आ जाता था। मैं इनको यही कहना चाहता हूं कि इनकी पार्टी ने ऐसे ही 70 साल देश पर राज करने का काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों सरकार की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले क्लर्कों का शिष्ट मण्डल हम

सभी विधायको को आकर मिला था। उन्होंने यह कहा था कि सरकार के सामने उनकी मांग रख करके हमारे वेतनमान में भी बढ़ोतरी की जाये। हम सारे विधायक उनकी इस बात का समर्थन करते हैं। इसी प्रकार से आई.टी.आई. के इंस्ट्रक्टर थे। उनके बारे में भी हमारी सभी की सहमति है कि सरकार उनके मामले पर भी सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दे। इससे आगे जाकर मैं यह कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक गांव में पंचायत लोगों द्वारा चुनी गई है। हर गांव में सरपंच है। हम सभी को उन साथियों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हरियाणा के लोगों ने ही उनका भी चुनाव किया है। मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि जो दो लाख वाली बंदिश लगाई गई है उसको दूर करके इस सीमा को 11 लाख रूपये या 15 लाख रूपये तक बढ़ाया जाये। सरकार को इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी घोषणा करनी चाहिए ताकि हर गांव में विकास कार्यों को गति दी जा सके। उनको लोगों ने चुनकर भेजा है और हम सभी ने उनके लिए अपने वोट का प्रयोग किया है। हम सभी यही चाहते हैं कि उनका भी पूरा सम्मान इस प्रदेश में होना चाहिए। मेरे हल्के में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हजार करोड़ रूपये की लागत से मैडीकल कॉलेज बनाने की आधारशिला रख दी है। उसकी डी.पी.आर. बनकर तैयार हो चुकी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करता हूं कि वहां पर निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये।

————————

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

———

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री लीला रामः उपाध्यक्ष महोदय, कैथल में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय है और वहां पर कुछ कर्मचारी सिरसा, जीन्द इत्यादि जगह से डैपुटेशन पर आए हुए हैं और उन्होंने उस यूनिवर्सिटी का पूरा माहौल खराब किया हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उस माहौल को सुधारा जाये। उसमें सुधार की गुंजाइश है इसलिए वहां पर सुधार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कुछ मांगें हैं वे भी मैं इस महान् सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः लीला राम जी, आप अपनी मांगों को लिखित में दे दीजिए उनको सदन की आज की कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जायेगा।

श्री लीला रामः ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड लिखित में दे दूंगा।

.....

श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री जोगी राम सिहाग, विधायक और श्री अनूप धानक, विधायक से श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक के विरूद्ध आज एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मिला है। मैं इस विषय पर दिये गये विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर अपनी सहमति देता हूं। अब श्री जोगी राम सिहाग, विधायक इस सम्बन्ध में सदन की अनुमति लेंगे।

श्री जोगी राम सिहागः उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभय सिंह चौटाला, विधायक के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्षः मैं अनुरोध करता हूं कि जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया अपनी सीटों पर खड़े हो जायें।

(इस समय सत्ता पक्ष के सदन में उपस्थित सभी सदस्य उपरोक्त प्रस्ताव के समर्थन में अपनी सीटों पर खड़े हो गये।)

श्री उपाध्यक्षः इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या 15 से अधिक है इसलिए इस प्रस्ताव को मंजूर किया जाता है। अब श्री जोगी राम सिहाग, विधायक, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को रैफर करने के लिए प्रस्तुत करेंगे।

श्री जोगी राम सिहागः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि–

Today, the 21st February, 2023 while speaking during Zero Hour, Shri Abhay Singh Chautala, MLA brought certain wrong and misleading facts regarding the land acquired near/for the purpose of Hissar Airport, etc. The Hon'ble Deputy Chief Minister, subsequently, with the permission of the Hon'ble Speaker, clarified the position there and than. Inspite of this, Shri Abhay Singh Chautala adamant with the aim to assert and brought certain wrong facts misleading the House, by using unparliamentary words too.

The act of the Hon'ble Member is unwarranted, unjust and undignified, particular when the Dy. CM clarified the position immediately in the House. Shri Abhay Singh Chautala, MLA, thus, mislead the House by giving false and wrong facts, knowingly, intentially and deliberately. He has lowered the prestige, status and dignity of the House particularly and members specially. The act of the said member, therefore, clearly constitutes Breach of Privilege, that too on the Floor of House. Besides this, the conduct of Shri Abhay Singh Chautala towards other member(s) remained unwarranted and unparliamentary, while he

was speaking in the House. I request that the matter may be referred to the Committee of Privileges for presenting its report in the first sitting of the next session.

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

Today, the 21st February, 2023 while speaking during Zero Hour, Shri Abhay Singh Chautala, MLA brought certain wrong and misleading facts regarding the land acquired near/for the purpose of Hissar Airport, etc. The Hon'ble Deputy Chief Minister, subsequently, with the permission of the Hon'ble Speaker, clarified the position there and then. Inspite of this, Shri Abhay Singh Chautala adamant with the aim to assert and brought certain wrong facts misleading the House, by using unparliamentary words too.

The act of the Hon'ble Member is unwarranted, unjust and undignified, particular when the Dy. CM clarified the position immediately in the House. Shri Abhay Singh Chautala, MLA, thus, mislead the House by giving false and wrong facts, knowingly, intentially and deliberately. He has lowered the prestige, status and dignity of the House particularly and members specially. The act of the said member, therefore, clearly constitutes Breach of Privilege, that too on the Floor of House. Besides this, the conduct of Shri Abhay Singh Chautala towards other member(s) remained unwarranted and unparliamentary, while he was speaking in the House. I request that the matter may be referred to the Committee of Privileges for presenting its report in the first sitting of the next session.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है कि–

Today, the 21st February, 2023 while speaking during Zero Hour, Shri Abhay Singh Chautala, MLA brought certain wrong and misleading facts regarding the land acquired near/for the purpose of Hissar Airport, etc. The Hon'ble Deputy Chief Minister, subsequently, with the permission of the Hon'ble Speaker, clarified the position there and then.

Inspite of this, Shri Abhay Singh Chautala adamant with the aim to assert and brought certain wrong facts misleading the House, by using unparliamentary words too.

The act of the Hon'ble Member is unwarranted, unjust and undignified, particular when the Dy. CM clarified the position immediately in the House. Shri Abhay Singh Chautala, MLA, thus, mislead the House by giving false and wrong facts, knowingly, intentially and deliberately. He has lowered the prestige, status and dignity of the House particularly and members specially. The act of the said member, therefore, clearly constitutes Breach of Privilege, that too on the Floor of House. Besides this, the conduct of Shri Abhay Singh Chautala towards other member(s) remained unwarranted and unparliamentary, while he was speaking in the House. I request that the matter may be referred to the Committee of Privileges for presenting its report in the first sitting of the next session.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय को विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए रैफर किया जाता है तथा समिति को अगले सत्र की पहली बैठक तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन कल दिनांक 22 फरवरी, 2023 प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

***18.09 बजे**

(तत्पश्चात् सभा बुधवार, दिनांक 22 फरवरी, 2023 प्रातः 11:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)